राष्ट्रीय संस्करण

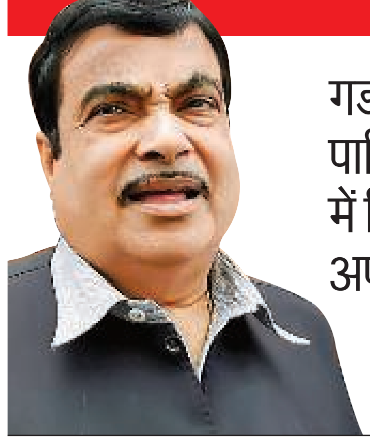

गडकरी बोले, पाकिस्तान में हिंदू होना अपराध जैसा है

>>5

वर्ष 3 अंक 195

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 23 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

स्लम के बच्चों के हाथों में आई किताब तो हो गया कमाल...

हिसार : सड़कों पर भीख मांग रहे बच्चों को हम कुछ सिक्के देकर मानवीय दायित्वों की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे नौनिहालों का जीवन ही बदल देते हैं। ऐसी ही हैं हिसार निवासी अनु चिनिया जिन्होंने भीख मांगते बच्चों के हाथ में कटोरा की जगह किताब पकड़ा दिया है। (पेज-11)

जागरण विशेष

फल-फूलों की खेती को बनाया उन्नति का आधार

टिहरी : उत्तराखंड के जौनपुर ब्लॉक के बसाण गांव के बिरवान सिंह रावत ने नौकरी छोड़ गांव में बागवानी शुरू की। 17 साल की मेहनत से विकसित किया उद्यान उनकी जिंदगी को महकाने के साथ ही मुनाफा भी दे रहा है। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

आज आएंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे

रांची : सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके साथ ही 81 सीटों पर भाग्य आजमा रहे 1,215 उम्मीदवारों का भी फैसला हो जाएगा। एग्जिट पोल में किसी भी दल को बहुमत न मिलने से पूरे देश की उत्सुकता नतीजों को लेकर है। मतों की गणना त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच सोमवार को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग व संबंधित जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे से ट्रेनों-उड़ानों पर असर

नई दिल्ली : पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर में हिमपात और बारिश के चलते पूरा दिल्ली, हरियाणा समेत समूचा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। कई हिस्सों में दृश्यता काफी कम रही। इससे सड़क यातायात, ट्रेनों का संचालन और हवाई सेवा पर असर पड़ा।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

डीओटी ने गेल से मांगा पौने दो लाख करोड़ बकाया

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने गेल इंडिया लिमिटेड से आइपी-1, आइपी-2 लाइसेंस के साथ-साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस के संबंध में 1,72,655 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने को कहा है। यह मांग विभिन्न सरकारी बकाया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की गई है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

अफगानिस्तान में अशरफ गनी ने फिर जीता राष्ट्रपति चुनाव

काबुल : अफगानिस्तान में तीन महीने पहले हुए चुनाव में राष्ट्रपति अशरफ गनी की जीत हुई है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक नतीजों में अशरफ गनी ने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50 प्रतिशत वोटों का आंकड़ा पार कर लिया है। गनी की स्पष्ट जीत के बावजूद उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला-अब्दुल्ला ने इन परिणामों को मानने से इन्कार करते हुए इसे चुनौती देने की बात कही है।

भयभीत विपक्ष जनता में फैला रहा है भ्रम : मोदी

सामने रखी हकीकत ▶ प्रधानमंत्री ने किया आश्वस्त, देश के सभी मुसलमानों की नागरिकता रहेगी सुरक्षित

रामलीला मैदान से कांग्रेस, ममता बनर्जी और वामपंथियों को दिखाया आईना

नीलू रंजन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर आम जनता में भ्रांति फैलाकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों को हवा देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सीएए से देश के किसी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान समेत दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों से भारत के संबंध अच्छे हैं। मुस्लिम देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दे रहे हैं। विपक्षी दलों में भय है कि कहीं भारतीय मुसलमान भी मोदी के समर्थन में न खड़े हो जाएं। इसीलिए तिलमिलाया विपक्ष जनता में भ्रम फैलाकर खुद को सुरक्षित करना चाहता है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने के लिए संसद से कानून पास कराने पर इससे लाभान्वित होने वाले 40 लाख लोगों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए रैली आयोजित की गई थी। मोदी ने कहा कि इस कानून को बनाते समय वहां रहने वाले गरीब परिवारों का धर्म, संप्रदाय नहीं पूछा, बल्कि सिर्फ उनकी गरीबी और मुसीबत देखी। इसी तरह उज्ज्वला के तहत आठ करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने, प्रधानमंत्री आवास योजना में दो करोड़ गरीबों को घर उपलब्ध कराने और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज ले चुके 70 लाख गरीबों से भी धर्म या समुदाय के आधार पर विभेद नहीं किया गया है। मोदी ने जनता को विपक्ष की ओर लगातार फैलाए जा रहे अफवाहों से सावधान करते हुए कहा कि वे विपक्ष के 'टेप रिकॉर्डर' को नहीं सुनें बल्कि सरकार के 'ट्रैक रिकॉर्ड' को देखें। हमने किसी भी देशवासी से कभी भेदभाव नहीं किया।

गांधी का काम नहीं सिर्फ सरनेम : डेढ़ घंटे से लंबे भाषण में प्रधानमंत्री ने एक-एक कर सीएए पर भ्रम फैलाने वाले विपक्षी दलों और उनके नेताओं की कलई खोली। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संसद में दिए भाषण, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से केंद्र सरकार को लिखे पत्रों के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी की असम इकाई की ओर पारित कई प्रस्तावों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित होकर आने वाले हिंदुओं व सिखों की नागरिकता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग करती रही है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों के भारत में आने की स्थिति में स्वागत करने के महात्मा गांधी के भाषण का हवाला देते हुए मोदी ने गांधी परिवार को निशाने पर लिया। कहा, राजनीतिक लाभ के लिए गांधी के सरनेम का इस्तेमाल करने वाले उन्हीं के सुझाव का विरोध कर रहे हैं।

कोलकाता से सीधे यूएन पहुंच गईं दीदी : कभी संसद में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों की मांग उठाने और अब सीएए का विरोध कर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की बात करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी मोदी ने खरी-खरी सुनाई। मोदी ने कहा कि ममता दीदी तो सीधे कोलकाता से यूएन पहुंच गईं। आखिर इन सालों में क्या बदल गया है कि वह बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को शरण देने का समर्थन करने के बजाय विरोध करने लगी हैं।

केंद्रीय कानून नहीं मानना राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पेज>>5

विपक्षी दलों पर जनता के बीच सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का लगाया आरोप

"जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं। जिनके पुरखे मां भारती की संतान हैं। उनका एनआरसी-सीएए से कोई लेना देना नहीं है। – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कौआ कान ले गया

मोदी ने एनआरसी पर विपक्ष के झूठ में फंसे लोगों पर चिंता जताते हुए 'कौआ कान ले गया' की कहावत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना कान देखने के बजाय कौए के पीछे भागने लगे हैं। बिना किसी सच्चाई के लोग मुसलमानों के लिए डिटेंशन कैंप बनाए जाने की बात कर रहे हैं। एनआरसी पर अभी सरकार में विचार भी शुरू नहीं हुआ है, उसके नियम नहीं बने हैं, लेकिन इसे लेकर लोगों को डराया जा रहा है। आम लोगों और खासकर छात्रों से विपक्ष के इस झूठे प्रचार नहीं फंसने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि इस देश के किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा।

घुसपैठिए खुद को सामने नहीं आने देते और शरणार्थी अपनी पहचान नहीं छिपाते, विपक्षी इस फर्क को स्पष्ट नहीं होने देना चाहते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सर्द हवाओं के बीच नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा की धन्यवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर फैलाए जा रहे भ्रमों का सिलसिलेवार जवाब दिया। ध्रुव कुमार

संबोधन की खास बातें

- विपक्ष की राजनीति से देश बदनाम हुआ और हमने अल्पसंख्यकों के प्रति पाकिस्तान के भेदभाव को दुनिया के सामने लाने का मौका गंवा दिया
- मुस्लिम देशों से भारत के लगातार अच्छे हो रहे संबंधों से तिलमिलाए विपक्ष को डर है कि कहीं भारतीय मुस्लिम भी मोदी के साथ न आ जाएं
- शहरी नक्सली झूठ फैलाकर समाज में बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं, इनकी झूठी और अनर्गल बातों में फंसने की जरूरत नहीं है
- मुझे प्रदर्शनकारियों के हाथ में पत्थर देखकर दुख हुआ, लेकिन यह देखकर खुशी हुई कि कुछ हाथों में तिरंगा भी है, यही बदलाव लाएंगे
- कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएए की अलोचना की लेकिन हिंसा रोकने की अपील नहीं, इससे हिंसा को कांग्रेस अध्यक्ष का मौन समर्थन झलकता है
- एनआरसी पर सरकार में अभी चर्चा भी शुरू नहीं हुई है और लोग डिटेंशन सेंटर के नाम से डराने लगे, इस तरह की बातें सिर्फ अफवाह हैं

मोदी को गाली दो, पुलिस को नहीं

मोदी ने कहा, सीएए के बहाने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जो नई बात नहीं है। दो दशक से यह कोशिश जारी है। उन्होंने 2008 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी के 'मौत के सौदागर' के बयान का भी हवाला दिया। मोदी ने कहा, जो लोग उनसे नफरत करते हैं, वे उन्हें गाली दे लें, उनकी तस्वीर जलाएं, लेकिन पुलिसकर्मियों, सार्वजनिक संपत्ति और गरीबों की झोपड़ी को निशाना नहीं बनाएं। जनता की हिफाजत करते हुए देश में 33 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों ने जान दी है। गत दिनों दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में लगी आग में भी पुलिसवालों ने बिना धर्म पूछे वहां फंसे लोगों को बचाया। उन्हें निशाना बनाना ठीक नहीं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान बस में आग लगाने के लिए पुलिस को बदनाम करने वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया पर भी निशाना साधा।

उपद्रवियों पर त्वरित कार्रवाई से उत्तर प्रदेश में हालात काबू

जेएनएन, नई दिल्ली

सीएए के विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हालात काफी सुधर गए हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार को उपद्रवियों की गिरफ्तारी से कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार दिखा। दिल्ली में भी हिंसक घटनाएं नहीं हुईं। बिहार समेत अन्य राज्यों में भी माहौल शांत रहा।

उप्र में शासन ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है। लखनऊ व आसपास के जिलों में रविवार को शांति रही। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत में हालात सामान्य रहे। सहारनपुर के देवबंद में कांग्रेस के पूर्व विधायक (अब सपा में) माविया अली ने ईदगाह मैदान में बिना अनुमति महापंचायत कर धरना दिया। यहां पर 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बागपत में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पुलिस ने सपा के युवजन सभा के पूर्व नगर अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। एएमयू में छात्राओं का बाबे सैयद पर शाम तक धरना जारी रहा। फीरोजाबाद में अफवाहों के चलते तनाव बना रहा, लेकिन अघोषित बंद के बीच दिन शांति से गुजर गया। आगरा में सोमवार शाम तक बंद इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। संभल में हजारों की संख्या में महिलाओं ने सभा की। रामपुर में हुए बवाल में 118 नामजद में से 50 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि सपा से जुड़े जिया अहमद के पास से 15 तमंचे और एक पिस्टल बरामद हुई है। उसके साथी फैजान को भी गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा में बवाल करने वालों के फोटो पुलिस ने जगह-जगह चस्पा कर दिए हैं। वाराणसी में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। हालांकि आजमगढ़ व मऊ में अब भी ठप है। इस बीच कानपुर में एक और घायल की मौत हो गई। इसके साथ सूबे में मृतकों की संख्या 19 हो चुकी है। यहां गिरफ्तार किए गए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर को शनिवार देर रात जमानत पर छोड़ दिया गया।

शनिवार को राजद के बिहार बंद के दौरान पटना में हुए उपद्रव में राजद नेता तेजस्वी यादव, जगदानंद व अब्दुल बारी समेत 27 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फुलवारीशरीफ हिंसा मामले में भी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने तीन महिलाओं सहित 40 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जेपी नड्डा बोले, सीएए पर दस लाइन बोलकर दिखाएं राहुल पेज>>6

- ▶ कानपुर में एक और घायल की मौत, उप्र में मरने वालों की संख्या 19 हुई
- ▶ राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी सुधरे हालात
- ▶ बिहार में राजद नेता तेजस्वी सहित कई के खिलाफ मुकदमा

रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तनावपूर्ण शांति रही। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने शहर में गश्त की। प्रेट्र

योगी सरकार की कार्रवाई

- 164 मुकदमे दर्ज, 879 आरोपितों को गिरफ्तार
- 5312 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई
- हिंसा, आगजनी में 288 पुलिसकर्मी घायल
- 61 पुलिसकर्मी उपद्रवियों की गोली से घायल

108 लोग गिरफ्तार किए गए हैं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने में

15344 पोस्ट को संज्ञान में लेकर हो रही विधिक कार्रवाई

नाइजीरिया में समुद्री लुटेरों के चंगुल से छुड़ाए गए क्रू मेंबर

नईदुनिया, रायपुर : नाइजीरिया में समुद्री लुटेरों के चंगुल से मालवाहक जहाज में सभी 21 क्रू मेंबरों को रिहा करा लिया गया है। इनमें रायपुर के तिवारी दंपती भी हैं। सभी 23 दिसंबर को मुंबई लौटेंगे। समुद्री जहाज के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर विजय तिवारी और उनकी पत्नी अंजू अभी नाइजीरिया पुलिस के साथ हैं। विजय के छोटे भाई पवन तिवारी ने बताया कि भाभी से बात हुई है। वे लोग सोमवार तक भारत पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व सांसद सुनील सोनी ने तिवारी दंपती को छुड़ाने में कारगर पहल की है। ज्ञात हो, 3 दिसंबर को समुद्री लुटेरों ने मालवाहक समुद्री जहाज के क्रू मेंबरों का अपहरण कर लिया था। इनमें रायपुर के विजय तिवारी और उनकी पत्नी अंजू तिवारी शामिल थीं।

भारत का 2-1से सीरीज पर कब्जा

मैच जीतने के बाद मैदान में पहुंच कर साथी खिलाड़ियों को बधाई देते विराट (मध्य में)। प्रेट्र

नई दिल्ली : भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को कटक में खेले गए सीरीज के तीसरे व निर्णायक मुकाबले में चार विकेट से जीत हासिल की। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में पांच विकेट पर 315 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 48.4 ओवर में ही छह विकेट खोकर 316 रन बना लिए। कोहली (85) भले ही शतक नहीं लगा सके, पर रोहित (63), राहुल (77) के आउट होने के बाद उन्होंने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत की वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज में लगातार 10वीं जीत है। (विस्तृत समाचार-पेज-14 पर)

विकास के लिए मुसलमानों ने खुद हटाई मस्जिद की दीवार

राज्य ब्यूरो, जम्मू

यह सही अर्थों में नया कश्मीर है। आयेदिन फसाद और आतंकी वारदातों के लिए बदनाम घाटी में विकास की खुशनुमा बयार बह रही है। लोग अमन चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं और धर्म के नाम पर लड़ने-झगड़ने की जगह विकास को तरजीह दे रहे हैं। कश्मीरियत की बड़ी मिसाल कायम करते हुए लोग झेलम नदी पर पुल निर्माण के लिए 40 साल पुरानी मस्जिद की जगह देने के लिए राजी हो गए हैं। इसी माह के शुरू में विकास कार्य के लिए ऐतिहासिक गुरुद्वारा हटाने पर सहमति बन गई थी।

ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के कमरवारी को नूरबाग से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण होना है। वर्ष 2002 में झेलम नदी पर 10 करोड़ की लागत से 166 मीटर लंबा डबल लेन पुल बनाने की परियोजना मंजूर हुई, लेकिन इस कार्य में 18 बाधाएं थीं। फायर स्टेशन, 16 आवासीय व व्यावसायिक भवन और अबु तुराब मस्जिद की जमीन इसकी राह में बाधा बनी हुई थी। सबसे मुश्किल मस्जिद हटाने के लिए लोगों को तैयार करना था। वर्ष 2018 में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की योजना के तहत प्रशासन ने जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनांस कॉरपोरेशन के जरिए इसके लिए 2.5 करोड़ की निधि जारी की, लेकिन रुकावटें बरकरार थीं। पुल का निर्माण न होने से लोगों को कई दिक्कतें हो रही थीं। आखिर श्रीनगर के जिला उपायुक्त डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने मस्जिद हटाने के लिए प्रयास शुरू किए। गत शनिवार को उन्होंने कमरवारी, नूरबाग और रामपोरा इलाके का दौरा किया। मस्जिद अबु तराब की प्रबंधन समिति के सदस्यों से बातचीत की। बताया कि इस्लाम में आम लोगों की सहूलियत और उनकी तरक्की को सबसे अधिक अहमियत दी जाती है। विचार-विमर्श के बाद मस्जिद कमेटी ने पुल निर्माण की योजना को जल्द पूरा करने के लिए मस्जिद की जमीन देने पर सहमति प्रकट कर दी। डॉ. शाहिद ने बताया कि पुल निर्माण के साथ झेलम दरिया के दोनों किनारों पर बाढ़ संरक्षण और सौंदर्यीकरण के काम पूरे किए जाएंगे। साथ सटे बाजारों की सड़कों की मरम्मत की जाएगी और पूरे इलाके में स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें स्थापित की जाएंगी।

72 साल पुराना गुरुद्वारा हटाने को तैयार हुआ सिख समाज : श्रीनगर-बारामुला राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार में जैनकूट के निकट 72 साल पुराने दमदमा साहिब गुरुद्वारा आड़े आ रहा था। वर्ष 2015 में यह मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन यहां भी बात बनी प्रशासनिक कौशल से। श्रीनगर के जिला उपायुक्त डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने सिख समाज के लोगों से बातचीत की। उन्हें परेशानी बताई और भरोसा दिया कि प्रशासन गुरुद्वारे के लिए न केवल जमीन उपलब्ध कराएगा बल्कि निर्माण में भी सहयोग करेगा। इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधन भी मान गया।

नया कश्मीर

- ▶ झेलम नदी पर पुल के लिए 40 साल पुरानी मस्जिद हटाने को तैयार हुआ मुस्लिम समाज
- ▶ धर्म के नाम पर हिंसा की जगह लोग विकास कार्यों को दे रहे तरजीह

श्रीनगर के रामपोरा स्थित 40 साल पुरानी अबू तुराब मस्जिद। पुल बनाने के लिए घाटी के मुस्लिम खुद ही इसे ढहाने को तैयार हो गए हैं। प्रेट्र

सीएए और एनआरसी

जब जनता सच्चाई समझेगी तो भ्रम फैलाने वाले राजनीतिक दल बहुत पछताएंगे

नागरिकता कानून पर भय और भ्रम का धुआं फैलाना घातक

त्वरित टिप्पणी

प्रशांत मिश्र

- ▶ हर देश को यह हक है कि वह अपने नागरिकों के बारे में पूरी जानकारी रखे
- ▶ शरणार्थियों को नारकीय जीवन से विकास की राह देना मानवतावादी कर्तव्य

पिछले एक हफ्ते से नागरिकता कानून के खिलाफ विशुद्ध रूप से भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक जमीन को गर्म करने की कोशिश कर रहे राजनीतिक दलों को तब बहुत पछताना पड़ेगा जब जनता उनके प्रभाव से हटकर इसकी सच्चाई समझेगी। पहले ही जमीन खो रहे इन दलों के लिए तब मुंह छिपाने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। अब तक वह जिस तरह समाज में डर फैलाकर अपनी रोटी सेंकने की कोशिश कर रहे हैं वह संविधान के खिलाफ जनता को भड़काने के अलावा कुछ नहीं है। हर देश को हक है कि वह अपने नागरिकों के बारे में पूरी जानकारी रखे और यह मानवतावादी कर्तव्य है कि शरणार्थियों को नारकीय जीवन से हटाकर विकास की राह दे।

पिछले दिनों में जिस तरह सड़कों पर कुछ उपद्रवियों ने अराजकता का माहौल खड़ा किया उसमें कई लोगों की जानें चली गईं। कई राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हैं और वह इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। उनका यह तर्क कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा कि वह हिंसा और सैकड़ों करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी के जिम्मेदार नहीं हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि कांग्रेस भी इन दलों के साथ खड़ी है। यह सच है कि अपनी घटती जमीन को देखते हुए उसने दूसरों के कंधे पर सवार होकर आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई है, लेकिन क्या कांग्रेस को इसका अहसास नहीं है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित होकर आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, वह राजनीति नहीं है। संविधान देश को इसका अधिकार देता है। यहां तक कि एनआरसी भी नागरिकों का एक रजिस्टर मात्र है जो हर किसी देश के पास होना ही चाहिए। यह हर देश का संवैधानिक अधिकार है और इसके खिलाफ खड़ा होना संविधान के खिलाफ है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह ने भी इसकी मांग की थी। दूसरे छोटे दलों की बात छोड़ भी दी जाए तो कांग्रेस के रणनीतिकार क्या यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा कर वह अपना हाथ ही जला रहे हैं। नागरिकता कानून को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अब खुद प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि इससे किसी भी धर्म या जाति के लोगों की नागरिकता नहीं जाएगी। यह नागरिकता देने का प्रावधान है, नागरिकता छीनने का नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और संविधान कहता है कि हर राज्य को केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्णय को स्वीकार करना ही होगा तो फिर कांग्रेस शासित राज्यों का एलान क्या उनकी विश्वसनीयता को खतरे में नहीं डालता है? कांग्रेस शासित राज्य क्या यह नहीं समझ रहे हैं कि नागरिकता कानून कोई योजना नहीं है, केंद्रीय कानून है। जब सुप्रीम कोर्ट इसे हरी झंडी दे देगा तो भी क्या कांग्रेस शासित राज्य इसे मानने से इनकार करेंगे? माना कि कांग्रेस को अपना जनाधार बढ़ाने की चिंता है, लेकिन इसका कोई उचित रास्ता ढूंढे, इस तरह छोटे दलों के बहकावे में आकर खुद के लिए मुश्किलें न खड़ी करे।

रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एनआरसी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। असम की स्थिति कुछ और थी, वहां घुसपैठ का बहुत ज्यादा प्रभाव था। छह साल तक आंदोलन चले और तब राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह समझौता हुआ था कि 1971 यानी बांग्लादेश युद्ध से पहले भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। अब अगर पूरे देश के लिए एनआरसी का फैसला होता भी है तो वह 2003-04 से लागू होगा। फिर इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताकर वे इंडिया गेट या राजघाट पर आंदोलन कर समाज में भय का वातावरण क्यों फैलाना चाहते हैं। इतिहास गवाह है जब कभी जनता भय के भ्रम से बाहर आती है तो गुस्सा अफवाह फैलाने वालों पर ही फूटता है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाक से फिर पूछे 150 सवाल

▶ **प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े मदरसों पर की गई कार्रवाई के बारे में स्पष्टीकरण मांगा**

इस्लामाबाद, प्रेट्र : दुनियाभर में आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग के मामलों पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान से फिर 150 सवाल पूछे हैं। उसे अगले साल आठ जनवरी तक इन सवालों का जवाब देना होगा। ज्यादातर सवाल प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े मदरसों पर की गई कार्रवाई से संबंधित हैं। पाकिस्तान इससे पहले भी आतंकवाद और मनी लांड्रिंग के खिलाफ उठाए गए कदमों पर एफएटीएफ को एक रिपोर्ट सौंप चुका है।

पेरिस स्थित एफएटीएफ ने पाक को अगले साल फरवरी तक ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। एफएटीएफ ने अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने 27 सवालों की सूची में से शेष 22 बिंदुओं का पालन नहीं किया तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। पाक ने छह दिसंबर को एफएटीएफ को 22 सवालों के जवाब सहित एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के जवाब में ही एफएटीएफ ने 150 सवाल पूछे हैं। इसमें कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण के साथ ही प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित मदरसों पर की गई कार्रवाई के बारे में बताने को कहा गया है। एफएटीएफ की अगली बैठक बीजिंग में 21 से 24 जनवरी तक होनी है, जहां पाक को अपना बचाव करने का मौका दिया जाएगा। इस साल मार्च में पाक के पंजाब प्रांत की पुलिस ने बताया था कि जमात-उद-दावा और उसकी संस्था फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन से जुड़े 160 मदरसों, 32 स्कूलों, दो कॉलेजों, चार अस्पतालों, 178 एंबुलेंस को जब्त कर लिया गया है। इन दोनों संगठनों से जुड़े 56 मदरसों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। हाफिज सईद के नेतृत्व वाले जमात-उद-दावा का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है।

7 जनवरी से आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर देगी। यह जानकारी पार्टी के प्रदेश संयोजक व दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने दी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 23 दिसंबर 2019

रामलीला मैदान से भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद

तैयारी ▶ ठंड और सुबह से ही चल रही शीतलहर के बावजूद बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की रैली में लोगों के जुटने से पार्टी में भारी उत्साह

नागरिकता संशोधन कानून के भ्रम को दूर करने से कार्यकर्ताओं में आई नई ऊर्जा

निहाल सिंह, नई दिल्ली

रामलीला मैदान में आयोजित रैली यूं तो अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए थी, लेकिन इस रैली से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार का शंखनाद भी हो गया। रैली के जरिये न सिर्फ भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि चुनाव में विरोधियों से दो-दो हाथ करने के लिए अब तैयार है। भाजपा इसे वर्ष 2012 में जापानी पार्क में हुई रैली से भी सफल रैली मान रही है, क्योंकि इतनी ठंड और सुबह से ही चल रही शीतलहर के बीच लोगों का रैली में पहुंचना व समापन तक टिके रहना चुनाव के मद्देनजर भाजपा के लिए सकारात्मक संकेत है।

दरअसल, पिछले दिनों कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई रैली के दौरान देशभर से जुटी भीड़ से भाजपा पर इस रैली को सफल बनाने का दबाव था। वहीं, नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद दिल्ली व देशभर में हो रही हिंसक घटनाओं के बीच लोगों को रैली में लाना भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। यही वजह रही कि भाजपा ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया था। वहीं, अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों से भी समर्थन मांगा था। इसके लिए 11 लाख लोगों से कॉलोनियों के नियमित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करने के लिए हस्ताक्षर भी कराए गए थे। इसी का परिणाम रहा कि रामलीला मैदान की रैली में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए। दिल्ली के लोगों के लिए रखी गई रैली में ही मैदान के खचाखच भर जाने से भाजपा के लोग उत्साहित दिखे क्योंकि अन्य दलों द्वारा देशभर से भीड़ जुटाए जाने के बावजूद रामलीला मैदान खाली रह जाता है।

रविवार को सुबह 9 बजे से ही लोग रामलीला मैदान पहुंचना शुरू हो गए थे। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से काफी पहले ही रामलीला मैदान पूरा भर चुका था। साथ ही बड़ी संख्या में लोग मैदान के बाहर भी प्रवेश के लिए इंतजार करते हुए नजर आए। नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के भ्रम को दूर करने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा आई है। कार्यकर्ताओं में यह भी स्पष्ट हो गया है कि वे भी लोगों के बीच इन मुद्दों को लेकर जा सकते हैं। साथ ही स्थानीय मुद्दों पर भी राज्य सरकार को घेर सकते हैं।

रामलीला मैदान में भाजपा की धन्यवाद मोदी रैली में लोगों का अभिवादन लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में (बाएं से) केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और विजय गोयल। ध्रुव कुमार

गरीब ही मेरे लिए वीआइपी : मोदी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ **अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर पीएम ने आप और कांग्रेस को बिना नाम लिए आड़े हाथों लिया**

अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बिना नाम लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर जनता ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था, उन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और महंगे इलाकों में दो हजार से ज्यादा सरकारी बंगले अवैध तरीके से करीबियों को दे रखे थे। उन्होंने दिल्ली की जनता के घरों को नियमित करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वे इस मामले को लटकाए रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये मोदी है। हमने एक तरफ वीआइपी लोगों से दो हजार से ज्यादा बंगले खाली कराए, वहीं दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों व मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दिया। मेरे लिए वीआइपी तो देश के गरीब लोग हैं।

रैली में मोदी ने कहा कि आजादी के बाद इतने वर्षों तक दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी को अपने घर को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल-कपट और झूठे चुनावी वादों से गुजरना पड़ा। कॉलोनियों के नियमितीकरण का फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के कारोबार को भी गति देने वाला है। लाखों लोगों का जीवन अवैध, अनधिकृत, जेजे क्लस्टर, सीलिंग, बुलडोजर, एक और कटऑफ डेट जैसे शब्दों के आसपास सिमट गया था। इनकी समस्या हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया। लाखों लोगों की इस चिंता को दूर करने और समस्या के स्थायी समाधान की नीयत और ईमानदारी इन लोगों (कांग्रेस और आप) ने कभी नहीं दिखाई। कॉलोनियों से जुड़ी छोटी-छोटी जानकारी जुटाने और नक्शा बनाने के लिए दिल्ली सरकार वर्ष 2021 तक का समय मांग रही थी, लेकिन समस्याओं को लटकाकर रखना हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ये हमारे संस्कार नहीं हैं, ये हमारी राजनीति नहीं है। इस वर्ष मार्च में यह काम हमने अपने हाथ में लिया। संसद के दोनों सदनों में कॉलोनियों से जुड़ा हुआ बिल पास हो गया है। इतने कम समय में तकनीक की मदद से 17 सौ से ज्यादा कॉलोनियों के सीमांकन का काम पूरा हो गया है। 12 सौ से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर डाल दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों का जीवन आसान बनाना, दिल्ली में आवागमन बेहतर करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। तमाम राजनीति और अवरोधों के बीच बीते पांच वर्षों में मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। 2014 के पहले दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में प्रतिवर्ष औसतन 14 किलोमीटर का विस्तार होता था, अब यह बढ़कर 25 किलोमीटर हो गया है। पांच वर्षों में 116 किलोमीटर नई लाइन शुरू हुई है और करीब 70 किलोमीटर नए रूट पर काम चल रहा है। यदि दिल्ली सरकार बेवजह अड़ंगे नहीं लगाती तो मेट्रो के चौथे चरण का काम बहुत पहले शुरू हो गया होता।

पीएम ने की दिल्ली सरकार के दावों की 'सर्जरी'

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्लीवासियों की प्रमुख समस्याओं को मंच से उठाने के साथ ही दिल्ली सरकार के तमाम दावों की सर्जरी भी कर दी। इस बीच उन्होंने कांग्रेस और आप पर राज्य की समस्याओं को निपटाने में बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि समस्या को लटकाए रहना विपक्षी दलों की आदत है।

सार्वजनिक परिवहन
मेट्रो निर्माण की धीमी गति के लिए दिल्ली सरकार को घेरा
कहा, 2014 से पहले दिल्ली व केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार थी। इसके बाद भी तेजी से काम नहीं हुआ।
राज्य सरकार की राजनीति की वजह से मेट्रो के चौथे चरण का काम शुरू होने में हुई देरी।
बाधाओं के बावजूद मेट्रो के निर्माण में लाए हैं तेजी
बसों को लेकर दिल्ली सरकार बहाने बना रही है।
राजधानी में बसों की हालत पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है

सड़क जाम की समस्या
केंद्र सरकार की कोशिश है कि लोगों को दफ्तर व घर आने-जाने में कम से कम परेशानी हो।
वर्षों से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का काम लटका था, केंद्र सरकार ने इसका निर्माण कार्य पूरा कर दिया है।

दूषित पानी की समस्या
दिल्ली सरकार इस सबसे बड़ी समस्या पर आंख मूंदकर बैठी है।
दूषित पानी पीने से लोग स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इन्हें झूठा साबित करने में लगी हुई है।
देश में सबसे ज्यादा वाटर प्यूरीफायर मशीनों की बिक्री दिल्ली में होती है।

वायु प्रदूषण की समस्या
ट्रकों के दिल्ली के बाहर से निकल जाने से वायु प्रदूषण में कुछ कमी आई है।
प्रदूषण कम करने के लिए पांच वर्षों में छह सौ नए सीएनजी स्टेशन लगाए गए हैं।
आठ सौ औद्योगिक इकाइयों में पीएनजी की व्यवस्था हो गई है।
हजारों ईंट भट्ठों को नई तकनीक से जोड़ा गया है।
पराली जलाने की समस्या हल करने के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को मदद की जा रही है।

अनधिकृत कालोनियों की 40 लाख आबादी को भाजपा ने ठगा : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मनीष सिसोदिया। (फाइल)

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को कांग्रेस की तरह ही भाजपा ने भी ठगा है। लोगों को उम्मीद थी कि रविवार को प्रधानमंत्री की रैली में रजिस्ट्री मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा के धोखे से अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सिसोदिया पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने ने कहा कि भाजपा के तमाम सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक रैली में शामिल हुए। इसमें बड़े-बड़े भाषण दिए। यह रैली दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने के बिल पास होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने आयोजित की थी। लेकिन यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इसमें एक भी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं दी जा सकी। यह स्थिति तब है, जबकि पिछले कई हफ्तों से भाजपा अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले कम से कम 100 लोगों को पक्की रजिस्ट्री देने का दावा कर रही थी। लोग प्रधानमंत्री को रजिस्ट्री देते हुए देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भाषणबाजी सुनकर लौट आए।

सिसोदिया ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस भी इसी तरह दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर चुकी है। उस समय चुनाव से पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए थे, लेकिन बाद में लोगों को कुछ नहीं मिला। भाजपा कांग्रेस की भांति केवल अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अरविंद केजरीवाल ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों का दर्द समझते हैं और पांच साल से यहां लगातार विकास करवा रहे हैं।

प्रधानमंत्री के घर भी जाता है दिल्ली जलबोर्ड का पानी

प्रधानमंत्री के पानी की गुणवत्ता सहित दिल्ली सरकार के कामकाज पर उठाए सवालों पर सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में आप सरकार बनने से पहले मात्र 53 फीसद कॉलोनियों में पाइपलाइन से पानी पहुंचता था। लेकिन पांच साल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की 93 फीसद कॉलोनियों में पाइपलाइन से साफ पानी भेजा जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का पानी प्रधानमंत्री के घर भी जाता है। उन्होंने कहा कि यदि हमें कोई शिकायत मिलेगी तो उसको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के मंत्री ही एनआरसी पर भ्रम फैला रहे हैं। यदि एनआरसी लागू नहीं होने की बात साफ हो जाती तो लोगों की मौत ही नहीं होती। दिल्ली में प्रदूषण घटने की बात तो अब प्रधानमंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं, यह दिल्ली सरकार के लिए खुशी की बात है। हर महीने दिल्ली सरकार सैकड़ों नई बसें सड़क पर उतार रही है। अगले छह-आठ महीनों में दिल्ली की सड़कों पर हजारों नई बसें दौड़ती नजर आएंगी।

'हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बिंदापुर में रविवार को पॉलीक्लीनिक का उद्घाटन करते (दाएं) से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के निदेशक डॉ. एके मेहता, अतिरिक्त निदेशक डॉ. एमपी चौरसिया और विधायक नरेश बाल्यान जागरण

बिंदापुर स्थित पॉलीक्लीनिक के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इशारों ही इशारों में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो कानून बनाया गया है, उसकी क्या जरूरत थी, यह समझ में नहीं आ रहा है। चारों ओर दंगे-फसाद हो रहे हैं। ये देश को एकजुट करने की राजनीति नहीं है।

उन्होंने कहा कि अगर इस कानून के बदले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाती और उसमें नौकरी बढ़ाने, फैक्ट्री लगाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाती तो इससे देश का भला होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी देश को तोड़ने की नहीं, बल्कि जोड़ने की राजनीति करती है।

उन्होंने कहा कि आज बिंदापुर में पॉलीक्लीनिक का शुभारंभ किया गया है। भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो इस पॉलीक्लीनिक में सबका मुफ्त इलाज किया जाएगा। लोगों का इलाज करने को यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। राजधानी में यह पहला चार मंजिला पॉलीक्लिनिक है। इसमें एसी, लिफ्ट सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं हैं। सरकारी अस्पताल का जिक्र आते ही लोगों के जेहन में टूटी दीवारें, चारों तरफ गंदगी का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। यहां के अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों के विकास पर पूरा ध्यान दिया गया है। 1797 में से 1281 कॉलोनियों में सड़कें, गलियां, पानी की पाइपलाइन, सीवर की लाइन, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मोहल्ला क्लीनिक बनाने का काम किया जा रहा है। शेष कॉलोनियों में भी एक-दो वर्ष के भीतर ये सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसके लिए पैसे दे दिए गए हैं। पहले बिजली का बिल देखकर लोगों के चेहरे पर मायूसी छा जाती थी, लेकिन अब बिल आते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं। लोगों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं। महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा से उनके पैसे बच रहे हैं। इन पैसों का इस्तेमाल वे घर के अन्य कार्यों में कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां कहती हैं, इतने पैसे कहां से आएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अपने लिए 190 करोड़ रुपये में हवाई जहाज नहीं खरीदे हैं। इन पैसों का इस्तेमाल लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार फिजूल खर्च और भ्रष्टाचार नहीं करती है। यह एक ईमानदार सरकार है। यह पहली सरकार है, जो लोगों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है।

केजरीवाल बोले, कच्ची कॉलोनियों में कराए काम रजिस्ट्री भी करा देंगे

जासं, नई दिल्ली : राजधानी में आम आदमी पार्टी ने कच्ची कॉलोनियों में सभी काम करवा दिए हैं। अब रजिस्ट्री भी हम करवा कर देंगे। आज उम्मीद थी कि दिल्लीवासियों को कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री की सौगात मिलेगी, लेकिन दिल्लीवासियों के साथ आज फिर धोखा हुआ। पहले कांग्रेस ने धोखा दिया और आज भाजपा ने भी दे दिया। पहले कांग्रेस झूठे वादे करती थी और अब भाजपा झूठे वादे कर रही है। ये बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सोनिया विहार और श्रीराम कॉलोनी वार्ड में सीवर पाइप लाइन बिछाने की योजना का शिलान्यास के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बड़े नाले से स्थानीय लोग बहुत परेशान रहा करते थे। क्षेत्रवासियों की मांग पर इस नाले की सफाई करवाई जा रही है। मुझे बेहद खुशी है कि जल्द ही इस नाले की सफाई का काम शुरू होने वाला है और इसके बाद इस पूरे इलाके को इस नाले की वजह से जो परेशानी होती थी, उससे मुक्ति मिल जाएगी। श्रीराम कॉलोनी और सोनिया विहार कॉलोनी के अंदर सीवर की लाइन पड़ने का काम जल्द शुरू होने वाला है।

'मालिकाना हक धोखा, सीएए से मुस्लिमों को बनाया निशाना'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने के एवज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धन्यवाद रैली पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने केंद्र सरकार के मालिकाना हक वाले बिल को भी झूठा बताया और नागरिकता संशोधन कानून को भी धर्म विशेष पर प्रहार करने वाला करार दिया है।

चोपड़ा का कहना है कि कहां तो मोदी 100 लोगों को उनके मालिकाना हक की रजिस्ट्री देने वाले थे और कहां एक को भी नहीं दी। रैली में पहुंचे लोग बेचारे ठगे से रह गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया यह बिल पूरी तरह से भ्रामक है, जो लोग पहले से ही अपनी संपत्ति के मालिक हैं, उन्हें दोबारा मालिक बनाने के नाम पर उनसे मोटी फीस भी वसूली जाएगी। चोपड़ा के मुताबिक 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से आधी कॉलोनियों में तो तकनीकी अड़चनों से मालिकाना हक देना संभव भी नहीं है। इन कॉलोनियों को पहले भी कांग्रेस ने ही नियमित किया था और आगे भी वही करेगी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चोपड़ा ने कहा कि यह कानून सीधे तौर पर एक धर्म विशेष को टारगेट करके बनाया गया है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटना चाहती है, जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कभी थी शान, आज मिटा दी पहचान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▶ **जेपी के एसडीजेड का आवंटन निरस्त होने से बुद्ध सर्किट प्राधिकरण के कब्जे में आया**

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की शान रहे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की पहचान आज प्राधिकरण ने ही मिटा दी। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ने भारत में ही नहीं बल्कि विश्वभर में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को पहचान दिलाई थी। फार्मूला वन रेस देखने के लिए देश विदेश से लोग यहां पहुंचे थे, तब वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त ढांचा तक विकसित नहीं हुआ था। आज हजारों करोड़ का बकाया होने पर प्राधिकरण ने स्पेशल डवलपमेंट जोन (एसडीजेड) का भूखंड आवंटन निरस्त कर दिया है।

औद्योगिक विकास के लिए गठित यमुना प्राधिकरण में आज तक एक भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। प्राधिकरण वर्षों से औद्योगिक गतिविधि शुरू कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है लेकिन, प्राधिकरण को शुरुआती पहचान बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, यमुना एक्सप्रेस वे से मिली। प्राधिकरण ने भी अपनी कई योजनाओं को बेचने के लिए इसे भुनाया। लोगों ने भी इनके आकर्षण में आकर प्राधिकरण की योजनाओं में निवेश किया। फार्मूला वन के कलैंडर से बाहर होते ही बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट आकर्षण खो चुका है। प्राधिकरण के लिए आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसकी नई पहचान बनकर उभर चुका है। ऐसे में 864 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान न होने पर प्राधिकरण ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के भूखंड का आवंटन निरस्त करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। जेपी समूह के खिलाफ यमुना प्राधिकरण की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। एसडीजेड का आवंटन निरस्त होने पर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट प्राधिकरण के कब्जे में आ गया है। प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने परियोजना विभाग को वहां कार्रवाई करने व प्राधिकरण की संपत्ति संबंधी सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किसी तरह के कार्यक्रम के आयोजन का अधिकार भी जेपी समूह से यमुना प्राधिकरण के हाथ में आ गया है। अगर पहले से वहां किसी कार्यक्रम के आयोजन की बुकिंग हो चुकी है तो उसे प्राधिकरण निरस्त कर सकता है। इससे आयोजकों के लिए मुश्किल हो सकती है।

नई दिल्ली में रविवार को ठिठुरन भरी सर्दी से परेशान दिखे बड़े व बच्चे। जागरण

दिल्ली में अभी और बढ़ेगी सर्दी, परेशान करेगा कोहरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर जारी है। राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से सात डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता कम रही। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह ठंड और बढ़ने की संभावना है। खासतौर पर गुरुवार को तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इस वजह से ठिठुरन बढ़ सकती है।

हालांकि तेज हवा चलने से हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 332 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी का है। यह एक दिन पहले तक गंभीर श्रेणी में था। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन में आसमान साफ रहेगा, लेकिन कई इलाकों में कोहरे का प्रकोप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 15 व न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

कोहरे के कारण 100 उड़ानें प्रभावित

जासं, नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण उड़ानों के संचालन में लगातार तीसरे दिन रविवार को भी दिक्कत आई। रनवे पर दृश्यता का स्तर कम होने से 100 उड़ानें देरी से उड़ीं और उतरीं। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक किसी भी उड़ान के रद या डायवर्ट की सूचना नहीं है। उड़ानों की लेटलतीफी के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। एयरपोर्ट मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार की आधी रात के बाद एयरपोर्ट पर कोहरा छाने लगा था। रविवार की सुबह लगभग 5.30 बजे वहां दृश्यता का सामान्य स्तर करीब 100 मीटर तक पहुंच गया था। लिहाजा कैट-3बी और कैट-3ए तकनीक से उड़ानों का संचालन किया गया। इसके कारण उड़ानों में देरी हुई और करीब 100 उड़ानें देरी से उड़ीं और उतरीं।

योजना

सेक्टर-94 में प्रस्तावित हैबिटेट सेंटर में आवासीय परियोजना भी लागू होगी, फ्लैट हैबिटेट सेंटर की ऊपरी मंजिल पर बनाए जाएंगे, फ्लोर एरिया रेश्यो के 40 फीसद हिस्से में आवासीय गतिविधि की जा सकेगी

84 मंजिला होगा नोएडा का हैबिटेट सेंटर

कुंदन तिवारी, नोएडा

सेक्टर-94 में प्रस्तावित हैबिटेट सेंटर में आवासीय परियोजना भी लागू होगी। यह परियोजना व्यावसायिक है लेकिन फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) के 40 फीसद हिस्से में आवासीय गतिविधि की जा सकेगी। यह फ्लैट हैबिटेट सेंटर के ऊपरी मंजिल पर बनाए जाएंगे। कितने फ्लैट होंगे यह परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तय करेगी। डीपीआर बनाने का कार्य सलाहकार कंपनी करेगी। हालांकि यह पूरी परियोजना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 में शामिल हो चुकी है। हैबिटेट सेंटर को 84 मंजिल का बनाया जाएगा।

नोएडा को उत्तर प्रदेश के शो विंडो के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी अलग पहचान अब तक नहीं बन सकी है। हैबिटेट एवं कंवेंशन सेंटर इसकी पहचान होंगे। हैबिटेट सेंटर को 84 मंजिल का बनाया जाएगा। इसके पास सुपरनोवा इमारत का निर्माण किया जा रहा है, जिसका 80 मंजिल का नक्शा पास है। यह नोएडा की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इसमें करीब 60 मंजिलों का निर्माण किया जा चुका है।

हैबिटेट सेंटर की ऊंचाई सुपरनोवा से ज्यादा हो सकती है। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक इस सेंटर का बॉयलाज मिश्रित भूमि का है। ऐसे में एफएआर का 40 फीसद हिस्सा आवासीय गतिविधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह योजना उसी का हिस्सा है। इसके ऊपर कुछ फ्लोर आवासीय श्रेणी के होंगे। यह श्रेणी स्टूडियों अपार्टमेंट से अलग है। इससे सामान्य आवासीय योजना के तहत ही बुक किया जा सकेगा।

हैबिटेट सेंटर के ऊपर के कुछ फ्लोर आवासीय गतिविधि के लिए बनाए जाएंगे। फ्लैट कितने होंगे डीपीआर के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस जमीन का भू-प्रयोग मिक्स है। ऐसे में इसका प्रयोग आवासीय गतिविधि के लिए किया जा सकता है।
-एससी गौड़, मुख्य वास्तुविद एवं नियोजन, नोएडा प्राधिकरण

हैबिटेट सेंटर के फीचर
मिक्स लैंड पर बनाई जाने वाली इमारत के ऊपर के कुछ फ्लोर का प्रयोग आवासीय के लिए किया जाएगा।
2050 और 750 सिटिंग क्षमता के आडिटोरियम
150 कमरों का एक होटल
आर्ट गैलरी का निर्माण
ओपन एयर थियेटर
पार्किंग व्यवस्था के लिए कांप्लेक्स
मेट्रो के जरिए सीधे प्रवेश की व्यवस्था
रिसार्ट, प्रदर्शनी के अलावा अलग से एक्टिविटी एरिया का निर्माण

पांच भागों में बंटी है पूरी योजना

योजना को पांच भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण यानी भाग-1, 2 व 3 (वेस्ट ब्लाक, सेंट्रल ब्लाक व ईस्ट ब्लाक) को मिश्रित भूखंड की श्रेणी दी गई है। इनकी नीलामी की जाएगी। कंपनियां नहीं आने पर तीनों की नीलामी अलग-अलग की जाएगी। इसके अलावा भाग-4 यानी होटल के लिए जमीन अलग से विक्रय की जाएगी। इससे मिलने वाली रकम से हैबिटेट सेंटर का निर्माण शुरू किया जाएगा। योजना को मास्टर प्लान 2031 में शामिल किया गया है। यह योजना 25 लाख लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगी। 97 हजार वर्गमीटर पर इस इमारत का निर्माण होगा। तीन मिश्रित भूखंड व होटल विक्रय से लगभग 1300 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं। इन पैसों से ही हैबिटेट एवं कंवेंशन सेंटर का निर्माण शुरू किया जाएगा।

12 फरवरी 1921 में रखी गई थी संसद भवन के नींव की पहली ईंट। इसके निर्माण में छह साल का समय लगा था और 83 लाख रुपये का खर्च आया था। संसद भवन की इमारत की संरचना सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी।

पोर्न साइट पर पूर्ण रोक मुमकिन नहीं : रविशंकर

खड़े किए हाथ ▶ बिहार के सीएम के पत्र पर केंद्रीय कानून मंत्री ने जताई असमर्थता

नीतीश ने पत्र लिखकर इस बारे में केंद्र सरकार से कड़ाई बरतने का किया था आग्रह

राज्य ब्यूरो, पटना

भारत सरकार ने पोर्न वेबसाइट पर पूरी तरह से रोक लगा पाने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हालांकि सरकार इस दिशा में हरसंभव कोशिश कर रही है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध मुमकिन नहीं हैं।

रविशंकर प्रसाद रविवार को पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री को पोर्न वेबसाइट पर पूर्व प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में लिखे पत्र के सवाल पर यह जवाब दिया। प्रसाद ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग पर गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा हैं। मैंने इसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बकौल रविशंकर,सरकार एक वेबसाइट को बैन करती है, तब तक लोग दूसरे नाम से वेबसाइट बनाकर संचालित करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर चिंता भी जताई। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में चल रहे आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में साफ किया कि सीएए न तो किसी नागरिकता छीनता हैं और न तो लेता हैं।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद रविवार को पटना स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देते हुए। प्रेट्र

जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं पर कुछ नहीं बोलेंगे

केंद्रीय मंत्री ने एनआरसी समेत विभिन्न मुद्दों पर जदयू प्रवक्ताओं की ओर से दिए गए बयान पर बोलने से इन्कार कर दिया। कहा कि हम केसी त्यागी के बयानों पर कुछ नहीं बोलेंगे। जदयू और लोजपा एनडीए का हिस्सा हैं। हम लोगों की नीतीश कुमार से बात हो जाती है। इसलिए प्रवक्ताओं के बयान पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं हैं।

राजद दें जवाब

बिहार बंद के दौरान तोड़फोड़ पर प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा बेबुनियाद हैं। इस पर चर्चा करने और जोड़ने का कोई मतलब नहीं। राजद जवाब दे कि ऑटो का शीशा तोड़ा जाता है, बंद के दौरान हिंसा फैलाई जाती है क्या वे इसका समर्थन करते हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको हैं। लेकिन हमें चाहिए आजादी, आजादी.., भारत तेरे टुकड़े होंगे और देश विरोधी नारे लगाने वालों की खैर नहीं हैं। विपक्ष प्रयोजित हिंसा फैला रहा है।

अश्लीलता रोकने में वाट्सएप जैसे प्लेटफार्म नहीं कर रहे सहयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के मुद्दे व बच्चों पर इसके प्रभावों की पड़ताल कर रहे राज्यसभा के एक पैनल को सरकारी अधिकारियों ने बताया कि वाट्सएप और सिग्नल जैसे प्लेटफार्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का हवाला देते हुए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं। यहां तक कि कानून के तहत किए गए अनुरोध का भी वे सम्मान नहीं करते हैं। बता दें कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का अर्थ है कि संदेश तक सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले की पहुंच होती है। कोई और इस बारे में नहीं जान सकता।

सांसदों का यह पैनल सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के मुद्दे और बच्चों पर इसके प्रभावों की पड़ताल कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी और बच्चों तथा समाज पर इसके प्रभाव के खतरनाक मुद्दे पर एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल में 10 राजनीतिक दलों के 14 सदस्य शामिल हैं और इसकी कई बैठकें हो चुकी हैं। पैनल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार नियामक ट्राई और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से इस बारे में चर्चा की है।

मंत्रालय के अधिकारियों ने पैनल के समक्ष कहा कि उन्हें पोर्नोग्राफी के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से जानकारी जुटाने में कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जब सूचना या जांच की बात कही जाती है तो (वे) कहते हैं कि वे मेजबान देश के कानून से संचालित हैं। गौरतलब है कि इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि समिति अगले महीने अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। पैनल के अन्य सदस्यों में अमर पटनायक, अमी याग्निक, डोला सेन, जया बच्चन, कहकशां परवीन, राजीव चंद्रशेखर, एमवी राजीव गौड़ा, रूपा गांगुली, संजय सिंह, तिरुचि शिवा, वंदना चव्हाण, विजिला सत्यनाथ और विनय पी सहस्त्रबुद्धे शामिल हैं।

सांसद प्रज्ञा ने की स्पाइस जेट की शिकायत,कंपनी की सफाई

▶ सीट को लेकर हुए विवाद में 45 मिनट देर हो गई थी फ्लाइट

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा सांसद और फायरब्रांड नेता प्रज्ञा ठाकुर ने विमानन कंपनी स्पाइस जेट के खिलाफ आवंटित सीट पर न बैठने देने की शिकायत की है। विमानन कंपनी ने रविवार को सफाई देते हुए कहा कि ठाकुर को तकनीकी कारणों से वैकल्पिक सीट उपलब्ध कराई जा रही थी, जिसके लिए वह तैयार नहीं थीं। उन्हें मनाने के तमाम प्रयास किए गए जो नाकाम रहे। इस कवायद में उड़ान में भी 45 मिनट की देरी हुई।

दिल्ली से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची प्रज्ञा ठाकुर ने हवाईअड्डे के बाहर शनिवार को मीडिया से कहा था कि उन्होंने निजी विमानन कंपनी की फ्लाइट संख्या एसजी2489 में 1ए सीट बुक की थी। लेकिन, उन्हें उस सीट पर नहीं बैठने दिया गया। यहां तक कि एयरलाइन स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं था। हवाईअड्डे के निदेशक अनिल विक्रम ने शिकायत मिलने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सोमवार को विचार किया जाएगा।

स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली-भोपाल फ्लाइट के लिए बंबाडियर क्यू400 का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पहली कतार की सीट व्हील चेयर वालों को आवंटित नहीं की जाती है। सांसद ठाकुर ने बुकिंग के समय एयरलाइन से व्हील चेयर की मांग नहीं की थी। इसलिए, स्टाफ को नहीं पता था कि वहां कौन बैठने जा रहा है। वह निजी व्हील चेयर लेकर आई थीं। ऐसे में उनसे 2बी सीट पर बैठने के लिए आग्रह किया गया। इसके लिए वह तैयार नहीं थीं। उन्हें मनाने में करीब 45 मिनट लग गए। इस बीच, दूसरे यात्री सांसद ठाकुर को फ्लाइट से उतारने की मांग भी करने लगे थे।

प्रज्ञा ठाकुर फाइल फोटो

बंगाल के नए कानून से कुलाधिपति की स्वतंत्र, निडर पहुंच पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ राज्य के विवि तक कुलाधिपति की भयमुक्त पहुंच से समझौता किया गया : धनखड़

▶ कार्यक्रम रद होने के पीछे प्रशासन द्वारा समर्थित गैर सरकारी तत्व जिम्मेदार

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विधानसभा द्वारा पारित नए कानून ने विश्वविद्यालयों के साथ उनके संवाद को प्रतिबंधित कर दिया है। इस कानून से शैक्षिक संस्थान तक कुलाधिपति की स्वतंत्र और निडर पहुंच पर रोक लग गई है। ज्ञात हो, जादवपुर विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षा समारोह को रद किए जाने पर धनखड़ पहले ही निराशा जाहिर कर चुके हैं।

राज्यपाल ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'नए कानून से कुलाधिपति की स्वतंत्र, निडर पहुंच' पर रोक लगी है। उन्होंने बिल को 'असंवैधानिक' बताते हुए कहा कि हर किसी को स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। 'नए कानून के तहत कुलपतियों के कुलाधिपति के साथ सभी संवाद विभाग के सचिव के माध्यम से होंगे।

कुलाधिपति की स्वतंत्र एवं भयमुक्त पहुंच से समझौता किया गया है।' उल्लेखनीय है कि 10 दिसंबर को पारित विधेयक के नियमों के तहत कुलाधिपति द्वारा राज्य-सहायता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किया जाने वाला संवाद (उच्च शिक्षा) विभाग के माध्यम से होगा। इस नियम के जरिये कुलपति उच्च शिक्षा विभाग के साथ विचार -विमर्श कर निर्णय लेने से जुड़े अपने सर्वोच्च निकायों की बैठकें बुला सकेंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों के रद होने के पीछे प्रशासन द्वारा समर्थित गैर सरकारी तत्व जिम्मेदार है। गौर हो कि जादवपुर विवि का विशेष दीक्षा समारोह रद होने के बारे में आधिकारिक रूप से सूचित किए जाने के बाद धनखड़ ने शनिवार को कहा था कि व्यवस्थित रूप से राज्य सरकार कुलाधिपति पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही हैं।

जगदीप धनखड़ फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को मिलेंगे 177 करोड़ रुपये

केदार दत्त, देहरादून

▶ उप्र वन निगम के पास लंबित है उत्तराखंड की 425 करोड़ की हिस्सेदारी

▶ दोनों राज्यों के मध्य परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला सुलझने की उम्मीद जगी

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य परिसंपत्तियों के बंटवारे के मसले सुलझने की उम्मीद जगी है। इस कड़ी में दोनों सरकारों के स्तर पर हुए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश वन निगम के पास जमा उत्तराखंड की 425 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी में से 177 करोड़ की रकम जल्द ही सूबे को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश ने प्रथम चरण में यह राशि देने पर सहमति जताई है। शेष धनराशि को लेकर दोनों राज्यों के बीच विमर्श चल रहा है। हिस्सेदारी की रकम मिलने से उत्तराखंड वन विकास निगम को अपनी माली हालत सुधारने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद बंटवारे में उत्तराखंड वन विकास निगम के हिस्से में 425.23 करोड़ रुपये की राशि आई थी। कार्मिकों के मामले में जो जहां कार्यरत है, उसे वहीं का मान लिया जाए, को आधार बनाया गया। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने भरोसा दिलाया था कि उत्तराखंड को उसके हिस्से की 425.23 करोड़ की रकम जल्द उसे दी जाएगी। कई दौर के मंथन के बावजूद मसला अनसुलझा ही रहा। न तो राशि जारी हुई, न इसका कारण बताया गया।

उत्तराखंड वन विकास निगम के भी लाभ में चलने के कारण इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब जबकि निगम की वित्तीय स्थिति खराब हुई तो उसने यह मसला भी प्रमुखता से रखा। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बीती 17 अगस्त को दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव स्तर की बैठक में भी ये मसला उठा।

वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत के अनुसार, उप्र से वन विकास निगम की हिस्सेदारी चरणबद्ध ढंग से मिलेगी। प्रथम चरण में वन निगम ने रिजर्व एंड सरप्लस मद में 177.04 करोड़ देने पर सहमति दी है। निगम के प्रबंध निदेशक मोनिष मल्लिक के अनुसार, बकाया राशि निगम की वित्तीय सेहत सुधारने में मददगार साबित होगी।

डॉ.हरक सिंह रावत फाइल फोटो

पुलिसवालों के शौर्य और बलिदान से ही हम रहते हैं महफूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिसकर्मियों की जमकर तारीफ की। उग्र आंदोलन के दौरान उपद्रवी तत्वों द्वारा पुलिस बलों को निशाना बनाए जाने पर उन्होंने दुख जताया और कहा कि हमें महफूज रखने के लिए ही ये जांबाज सर्दी, गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना जान को हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। जनता को सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हजारों जवान बलिदान दे चुके हैं। इंडियन पुलिस जर्नल के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 34 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं।

बहराइच में उपद्रवियों को खदेड़ती पुलिस (फाइल फोटो)

2017 में पुलिस हताहतों का विवरण (शहीद हुए)

कुल	आतंकी घटनाओं में	नक्सली घटनाओं में	एंटी डकैती ऑपरेशन	दंगों में	आपराधिक तत्वों द्वारा	खुद के हथियार से दुर्घटना	दुर्घटना
840	79	17	2	218	9	13	502
घायल हुए							
2684	95	53	77	1513	591	5	350

34 हजार से ज्यादा शहीद

आजादी के बाद से भारतीय पुलिस ने उल्लेखनीय काम किया है। इंडियन पुलिस जर्नल के अनुसार, आजादी के बाद 1957 तक देश में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 557 थी। 2018 में इनकी अब तक की कुल संख्या 34842 पहुंच गई।

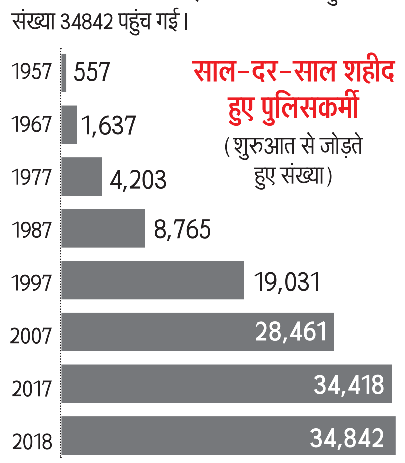

सबसे पहले प्रतिक्रिया का दायित्व

पुलिस सरकार की पहली एजेंसी है जो लोगों को जरूरत होने पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है। फिर चाहे देश में कोई आतंकी हमला हो या फिर साधारण अपराध, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति हो या फिर कोई तबाही, हर वक्त पुलिस सामने होती है। शांतिपूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है।

पुलिसकर्मियों की कमी

भारत में पुलिसकर्मियों की कमी है। संयुक्त राष्ट्र के मानक के मुताबिक प्रति एक लाख लोगों पर करीब 230 पुलिसकर्मी होने चाहिए। एनसीआरबी के 2013 के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय औसत 141 है। उत्तर प्रदेश में प्रति एक लाख जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों की संख्या 78, बिहार में 77, राजस्थान में 115, मध्यप्रदेश में 112 है। यह आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि एक पुलिसकर्मी को अपने काम को किस तरह से अंजाम देना होता है।

पुलिस में ये हैं शामिल

जब हम राज्य पुलिस की बात करते हैं तो वह संबंधित राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त अर्द्धसैनिक बल जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, आइटीबीपी, एनएसजी ऐसे बल हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने विशेष कार्यों के लिए रखा है।

अरावली में 92 लोगों ने 500 एकड़ जमीन पर बनाए अवैध फार्म हाउस

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद

▶ करोड़ों के चालान किए, कई एफआइआर दर्ज हुई, पर नहीं हो सकी तोड़फोड़

▶ नगर निगम, वन विभाग, डीटीपीई व पंचायती विभाग कार्रवाई को लेकर उलझे आपस में

अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में करीब 500 एकड़ जमीन पर 92 लोगों ने कब्जा कर लिया है। किसी ने पांच तो किसी ने 20 एकड़ तक जमीन को फार्म हाउस में तब्दील कर दिया है। इनमें से काफी लोगों पर केस दर्ज किए गए, लाखों रुपये का जुर्माना किया गया। कार्रवाई के नाम पर आजतक न तो एक रुपये की भी वसूली हो सकी। न ही अवैध निर्माण को तोड़ा जा सका। कुछ इस तरह की रिपोर्ट वन विभाग ने उच्चाधिकारियों को भेजी है। रिपोर्ट की एक प्रति सेव अरावली ट्रस्ट को भी दी गई है।

सेव अरावली ट्रस्ट ने वन विभाग से शिकायत की थी कि अरावली क्षेत्र में स्थित अंखीर, अनंगपुर, लकड़पुर, मेवला महाराजपुर और बड़खल गांव में 140 अवैध फार्म हाउस बनाए गए हैं। जवाब तलब किए जाने पर जिला वन अधिकारी ने रिपोर्ट तैयार कर आला अफसरों को भेज दी। अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के बारे में यह तर्क दिया गया है कि तोड़फोड़ की जिम्मेदारी नगर निगम की है क्योंकि मालिकाना हक निगम का ही है।

> अरावली में लोगों ने अवैध रूप से फार्म हाउस बना लिए और प्रशासन कुछ न कर सका। इसकी सूचना नगर निगम सहित मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी ताकि कार्रवाई हो सके।
>
> **– जितेंद्र भडाना, संस्थापक, सेव अरावली**
>
> अवैध फार्म हाउस तोड़ने का अधिकार क्षेत्र नगर निगम का है। नगर निगम का इस जमीन पर मालिकाना हक है। उनकी ओर से रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। जो कार्रवाई बनती थी, वह करा दी गई है।
>
> **–सुरेश पूनिया, वन अधिकारी**

पूर्व निगमायुक्त मोहम्मद शाइन ने तैयार कराई थी रिपोर्ट : पूर्व निगमायुक्त मोहम्मद शाइन ने 140 अवैध फार्म हाउस की रिपोर्ट तैयार कराई थी। जमीन मालिकों की जानकारी के लिए जिला उपायुक्त को पत्र लिखा गया था। कई माह तक इसकी जांच ही नहीं की जा सकी। इस दौरान मोहम्मद शाइन का तबादला हो गया।

सेव अरावली ने इस मामले में शासन को ढेरों शिकायतें भेजी। शिकायत में यह भी कहा गया था कि वन विभाग यह तय नहीं कर पाया है कि यहां किस-किसने कब्जा किया हुआ है और इन पर क्या-क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। इस मामले की जांच प्रिंसीपल कंजेवेटर ऑफ फॉरेस्ट (पीसीसीएफ) के पास भी चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है अवमानना नोटिस : पिछले दिनों अरावली में अवैध खनन, निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिला उपायुक्त, खनन अधिकारी व दो अन्य को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। जिला बार एसोशिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के प्रधान एलएन पाराशर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि अरावली में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अब भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरावली पर अब भी अवैध निर्माण और अवैध खनन जारी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालत का फैसला बदला

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालत के एक फैसले को पलट दिया है। सेना की कोर्ट ऑफ इनक्वायरी (सीओआइ) के तहत एक ब्रिगेडियर पर जूनियर अफसरों और ठेकेदारों से रकम मांगने और वित्तीय धांधलियां करने के आरोप लगे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेना को इस मामले में नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

ब्रिगेडियर एलआइ सिंह के खिलाफ यह मामला 2012 से चल रहा है। सिक्किम स्थित 164 माउंटेन ब्रिगेड और सुकना स्थित 33वीं कोर के ब्रिगेडियर एलआइ सिंह के बाद यह पदभार संभालने वाले सैन्य अफसर ने उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की जांच बैठाई थी। उन पर अपने आधिकारिक निवास से सरकारी संपत्ति में हेरफेर करने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट में आरोपित सैन्य अफसर ने अपील के दौरान अपने वकील मेजर सुधांशु पांडे के जरिए कहा कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में एकल पीठ ने जांच की थी और उन्हें गवाहों से पूछताछ का मौका भी नहीं दिया गया था। इसलिए इस जांच को खारिज किया जाना चाहिए। जोरहाट डकैती केस में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह ने आरोपित ब्रिगेडियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसके बाद ही वर्ष 2012 में जांच शुरू हो गई थी। जनरल दलबीर वर्ष 2014 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए थे। जस्टिस एल. नागेश्वर राव के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन मैन इन्क्वारी से जांच में कोई गफलत नहीं हुई है।

हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपितों का दोबारा पोस्टमार्टम आज

▶ एम्स ने बनाई तीन डॉक्टरों की विशेष टीम,वेटनरी डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या का मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र : एम्स ने हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपितों के शवों के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए तीन डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है। टीम सोमवार सुबह नौ बजे हैदराबाद स्थित गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में आरोपितों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी।

एम्स की तरफ से तेलंगाना के विशेष सचिव को भेजे गए पत्र के अनुसार, डॉक्टरों की टीम का नेतृत्व एम्स के फोरेंसिक प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता कर रहे हैं, जबकि इसमें डॉ. आदर्श कुमार व डॉ. वरुण चंद्रा शामिल हैं। डॉक्टरों को प्राप्त सुबूतों के आधार पर स्वतंत्र रिपोर्ट देने को कहा गया है। पोस्टमार्टम के बाद चारों आरोपितों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाए।

ज्ञात हो, 28 नवंबर को 25 वर्षीय महिला वेटनरी डॉक्टर का जला हुआ शव बरामद हुआ था। पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि छह दिसंबर को मौके पर ले जाकर पूछताछ के दौरान आरोपितों ने टीम पर हमला कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में चारों मारे गए थे। पहली बार उसी दिन मह बूबनगर के सरकारी अस्पताल में चारों आरोपितों के शवों का पोस्टमार्टम हुआ था।

हालांकि, एनकाउंटर को हत्या करार देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन पर हाई कोर्ट ने आरोपितों के शवों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद से उनके शव गांधी अस्पताल में रखे हैं। हाई कोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 23 दिसंबर से पहले चारों आरोपितों के शवों का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों की टीम से करवाए।

जांच हो अनिवार्य

हर मां-बाप अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौने देना चाहता है, इस दौरान वह अनजाने में बच्चे की सेहत को नजरअंदाज कर देता है।

आयातित खिलौनों की क्वालिटी पर मंत्रालय सख्त

नई दिल्ली, प्रेट्र: आयातित खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इन कदमों की बदौलत देश में केवल अच्छी क्वालिटी के खिलौनों की बिक्री सुनिश्चित होगी। एक अधिकारी के मुताबिक आयात के मामले में खिलौनों की खेप आधारित जांच अनिवार्य करने पर काम चल रहा है।

देश में खिलौनों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के ये सभी नियम-कायदे 'क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया' की एक अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर लागू किए जा रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए है, क्योंकि देश में बिकने वाले लगभग 85 प्रतिशत खिलौने आयातित होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक, 67 फीसदी खिलौने सुरक्षा मानकों की जांच में फेल हो गए, जबकि 30 फीसदी प्लास्टिक खिलौने सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय खिलौना उद्योग के लिए कड़े गुणवत्ता नियम लागू करने की संभावनाएं खंगाल रहा है। नियमों का उल्लंघन न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए खिलौनों की परिभाषा पूरी तरह स्पष्ट की जाएगी। घरेलू बाजार में सस्ते और घटिया खिलौनों की बाढ़ रोकने में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है।

मंत्रालय ने कहा है कि देश में केवल अच्छी क्वालिटी के खिलौनों का आयात पक्का करने के लिए हर खेप में से अपनी इच्छा से कोई भी सैंपल ले लिया जाएगा और जांच एवं मंजूरी के लिए उसे मान्यता-प्राप्त लैब भेज दिया जाएगा। यदि सैंपल जरूरी मानदंडों पर खरा नहीं उतरेगा तो वह खेप या तो वापस भेज दी जाएगी या फिर उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे खिलौनों को नष्ट करने के खर्च की वसूली आयातक से की जाएगी।

क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की स्टडी रिपोर्ट

- **67** प्रतिशत खिलौने सुरक्षा मानकों की सभी जांच में फेल
- **30** प्रतिशत प्लास्टिक खिलौने सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं
- **80** प्रतिशत खिलौने मैकेनिकल एवं फिजिकल सेफ्टी मानकों पर फेल
- **45** प्रतिशत सॉफ्ट टॉयज में स्वीकृत स्तर से ज्यादा हैवी मेटल
- **75** प्रतिशत इलेक्ट्रिक खिलौने मैकेनिकल मानकों पर फेल

प्रतीकात्मक फोटो

साहित्य अकादमी विजेता डॉ. नंजुंदन घर में मृत पाए गए

बेंगलुरु, प्रेट्र : प्रसिद्ध अनुवादक और साहित्य अकादमी विजेता डॉ. जी. नंजुंदन अपने आवास पर मृत पाए गए। वह 58 वर्ष के थे। उनका शव नगादेवनहल्ली स्थित अपार्टमेंट में शनिवार को बरामद हुआ है। पुलिस को संदेह है कि कार्डियक अरेस्ट (हृदय गति रुकने) के कारण करीब चार दिन पहले उनकी मौत हो गई होगी।

डॉ. नंजुंदन ने दर्जनों कन्नड़ किताबों का तमिल में अनुवाद किया। वही उनकी ख्याति का मूल आधार बने। अनुदित किताबों में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता यूआर अनंतमूर्ति की 'भव' और 'अवस्थे' शामिल हैं। उन्हें वर्ष 2012 में 'अक्का' के लिए अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला। यह विभिन्न कन्नड़ लेखिकाओं की लघु कथाओं का संग्रह है, जिनका उन्होंने तमिल में अनुवाद किया है। पुलिस के मुताबिक, डॉ. नंजुंदन बेंगलुरु विश्वविद्यालय में सांख्यिकी के प्रोफेसर थे और कई दिनों से पढ़ाने नहीं आए थे।

कह के रहेंगे माधव जोशी

14 जनवरी से पहले भाजपा कराना चाहती है संगठनात्मक चुनाव। इसका कारण यह है कि जहां पार्टी के चुनाव नहीं हुए हैं, उन सभी राज्यों में पार्टी प्रमुख चेहरे को प्रोजेक्ट करने में असमर्थ है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 23 दिसंबर 2019

कैबिनेट में फेरबदल की मांग से पंजाब सरकार चिंतित

सियासत ▶ कांग्रेस में अंदरखाने में खींचतान, मनप्रीत पर बिट्टू के हमले की वजह नहीं समझ पा रही कांग्रेस

वड़िंग भी कर चुके हैं मंत्रियों की परफार्मेंस के रिव्यू की मांग

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा कैबिनेट में फेरबदल की मांग को हवा देने से पंजाब सरकार चिंतित हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कहा था कि मंत्रियों की परफार्मेंस का रिव्यू होना चाहिए। सरकार की चिंता यह है कि बार-बार उठने वाली कैबिनेट में फेरबदल की मांग और प्रबल न हो जाए।

सांसद बिट्टू द्वारा वित्तमंत्री मनप्रीत बादल पर हमला करने को कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि इस तरह के हमले की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही है। इसके बावजूद बिट्टू ने मनप्रीत को वित्तीय संकट के मामलों में घसीटा, निश्चित रूप से यह बेवजह नहीं हो सकती है। अहम पहलू यह है कि बिट्टू और वड़िंग ऐसे नेता हैं जिन्होंने मनप्रीत के कांग्रेस में आने का विरोध किया था। बठिंडा से बीता लोक सभा चुनाव लड़ने वाले वड़िंग को बठिंडा शहरी विधानसभा क्षेत्र में ही करारी शिकस्त मिली थी। मनप्रीत इसी सीट से विधायक हैं।

माना जा रहा है कि सारी कवायद अगले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही है। कांग्रेस में अंदरखाते सबसे बड़ी खींचतान ही 2022 के चुनाव को लेकर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में यह घोषणा की थी कि यह उनका अंतिम चुनाव होगा। तब से ही कांग्रेस में खींचतान चली आ रही है कि अगले चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। हालांकि बाद में कुछेक मौके पर कैप्टन ने यू टर्न भी लिया है।

उन्होंने यह संकेत दिए हैं कि मौका मिला तो वह अगले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं में भविष्य का चेहरा बनने की खींचतान चल रही है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह। फाइल

फेरबदल की कोई संभावना नहीं : आशा कुमारी

कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी आशा कुमारी का कहना है कि कैबिनेट में फेरबदल का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन अभी इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। राजनीति में हरेक की इच्छा मंत्री बनने की होती है, लेकिन सभी तो नहीं बन सकते हैं। इस तरह की मांग उठती रहती है।

बिट्टू करें कैप्टन या जाखड़ से बात : मनप्रीत

सुभाष चंद्र, बठिंडा

▶ लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू के आरोपों के जवाब में बोले वित्त मंत्री

▶ कहा– अगली पीढ़ियों का भविष्य तबाह कर मौजूदा का भविष्य नहीं संवार सकते

लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के आरोपों पर रविवार को वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने जवाब दिया। बिट्टू ने कहा था कि आर्थिक मामलों में प्रदेश की खराब होती छवि के लिए वित्त मंत्री जिम्मेदार हैं।

मनप्रीत बादल ने रविवार को कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है। इसे आंतरिक तौर पर ही हल किया जाना चाहिए। रवनीत बिट्टू या मैं प्रेस से मुखातिब होकर ऐसी बातें करें, इससे पार्टी मजबूत नहीं होती। अगर बिट्टू को मेरी वर्किंग पर शक है या उन्हें लगता है कि मैं इमानदारी से काम नहीं कर रहा तो उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ या मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करनी चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज लेकर अगली पीढ़ियों के भविष्य को तबाह करके मौजूदा पीढ़ी का भविष्य नहीं संवारा जा सकता। यह कोई समझदारी नहीं है। जहां तक तीन साल के फंड की बात है, तो यह मार्च में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से पता चल जाएगा। इसमें सरकार के एक-एक पैसे का हिसाब होता है कि यह कहां से आया और कहां गया। मार्च में पता चल जाएगा कि जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सत्ता संभाली थी, तो पूर्व अकाली सरकार खजाने में क्या छोड़कर गई थी और अब क्या स्थिति है।

मनप्रीत सिंह बादल। फाइल

केंद्र पर छह हजार करोड़ का बकाया : मनप्रीत बादल ने कहा कि अभी तक केंद्र सरकार पर पंजाब का करीब छह हजार करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर का जीएसटी और कुछ एरियर शामिल हैं। या तो केंद्र सरकार जवाब दे दे कि उन्होंने यह बकाया राशि नहीं देनी है या इसका कोई समाधान निकाले। केंद्र से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसे हासिल करने के लिए किसी भी राज्य सरकार के स्तर पर क्या किया जा सकता है, इस बारे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी विचार कर रहे हैं।

पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के आरोपों पर मनप्रीत बादल ने कहा कि यह वही कोठी है, जिसमें मजीठिया रहा करते थे। मजीठिया कोठी में आकर चेक कर लें। जो एसी वह छोड़कर गए थे, वही आज भी लगे हैं। अगर एक भी नया एसी लगा हो तो वह देनदार हैं। हां यह जरूर है कि कोठी के पीछे जो छह कमरे हैं उनमें पांच एसी पौने-पौने टन के जरूर लगवाए गए हैं। इन कमरों में उनके हलके से आए लोग ठहरते हैं। इनमें पीजीआइ में इलाज के लिए आने वाले मरीज, नौकरी की तलाश में आने वाले युवा व अन्य जरूरतमंद लोग होते हैं। मजीठिया की गाड़ियों के काफिले के तेल का एक दिन का खर्च मेरे पांच साल के खर्च के बराबर है। गौरतलब है कि मजीठिया ने आरोप लगाया था कि मनप्रीत की कोठी में अनगिनत एसी लगे हैं।

झारखंड में किसके सिर पर सजेगा ताज, फैसला आज

राज्य ब्यूरो, रांची

महासमर
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

जनता-जनार्दन का फैसला खुद में समेटे ईवीएम मशीनें सोमवार 23 दिसंबर को सुबह से ही जनादेश की घोषणा करना शुरू कर देंगी। इसके साथ ही झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर भाग्य आजमा रहे 1,215 उम्मीदवारों का भी फैसला हो जाएगा। सत्ता के लिए पक्ष-विपक्ष के दावों से भी परदा हट जाएगा।

राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 29,464 बूथों पर 41,870 ईवीएम में पड़े मतों की गणना कड़ी त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच सोमवार को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। सबसे पहले तोरपा और चंदनकियारी का परिणाम आएगा, क्योंकि यहां 13-13 राउंड की ही गिनती होनी है। सबसे अधिक 28 राउंड की गिनती चतरा में होनी है। इस कारण इस सीट का परिणाम सबसे अंत में आएगा। चुनाव आयोग व संबंधित जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला मुख्यालयों में होनेवाली मतगणना के लिए ईचागढ़ को छोड़कर सभी विधानसभा सीटों के लिए एक-एक हॉल बनाए गए हैं। ईचागढ़ में दो हॉल में मतों की गणना होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। इसके बाद ईवीएम से मतों की गणना होगी। हर राउंड में मतों की गिनती के बाद उसकी घोषणा होती जाएगी। प्रत्येक विस सीट में पांच-पांच बूथों की वीवीपैट पर्ची से ईवीएम का मिलान भी किया जाएगा।

इंतजार खत्म

24 जिला मुख्यालयों में त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच सुबह आठ बजे से शुरू होगी मतगणना, साढ़े आठ बजे से आने लगेंगे रुझान

81 विधानसभा सीटों के लिए 1,215 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला

29,464 बूथों पर 41,870 ईवीएम में पड़े वोटों की होगी गिनती

ईचागढ़ में दो, बाकी सभी 80 सीटों के लिए एक–एक हॉल में होगी काउंटिंग

इन दिग्गजों पर सबकी नजर

जमशेदपुर पूर्वी : मुख्यमंत्री रघुवर दास को टक्कर दे रहे भाजपा के बागी नेता और पूर्व मंत्री सरयू राय

दुमका : झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और मंत्री डॉ. लुईस मरांडी में है कड़ा संघर्ष

धनवार : झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को टक्कर दे रहे राजकुमार यादव और लक्ष्मण प्रसाद सिंह

सिल्ली : आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो को कड़ी टक्कर दे रहीं झामुमो की विधायक सीमा महतो

तोड़ेंगे रिकार्ड या थम जाएगा जीत का सिलसिला

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड विधानसभा चुनाव के सोमवार को आनेवाले नतीजे में कई ऐसे दिग्गजों के परिणाम पर भी नजर रहेगी जो संयुक्त बिहार के समय से ही चुनावों में जीत का परचम लहराते रहे हैं। इनमें सीएम रघुवर दास, मंत्री सीपी सिंह, पूर्व मंत्री नलिन व चंपई सोरेन, प्रदीप यादव जैसे दिग्गज शामिल हैं।

... तो लगातार सातवीं बार जीतेंगे नलिन : झामुमो के दिग्गज नेताओं में शामिल नलिन सोरेन वर्ष 1990 से ही लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो के नलिन सोरेन ने जीत का छक्का लगाया था। इस बार ये जीतते हैं तो सबसे अधिक लगातार छह बार चुनाव जीतने का अपना ही रिकार्ड तोड़ेंगे।

1995 से लगातार जीत रहे चुनाव : मुख्यमंत्री रघुवर दास, मंत्री सीपी सिंह, पूर्व मंत्री चंपई सोरेन भी संयुक्त बिहार से ही लगातार चुनाव जीत रहे हैं। रघुवर दास और चंपई सोरेन 1995 से लगातार जीत रहे हैं। सीपी सिंह को 1995 के बाद हुए उपचुनाव में जीत मिली थी, जिसके बाद वे लगातार विधानसभा पहुंच रहे हैं।

पूर्व मंत्री व झाविमो नेता प्रदीप यादव भी संयुक्त बिहार से ही चुनाव जीत रहे हैं। वे वर्ष 2000 से लगातार विधानसभा पहुंच रहे हैं।

... तो चौका लगाएंगे ये

झामुमो के जगरनाथ महतो (डुमरी) इस बार चुनाव जीतते हैं तो वे चौका लगाएंगे। पिछले चुनाव में इन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी। आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी (रामगढ़) तथा विदेश सिंह ने भी पिछले चुनाव में हैट्रिक लगाई थी। इस बार चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी तथा विदेश सिंह के पुत्र देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह चुनाव लड़े हैं।

जातिवाद के कट्टर विरोधी थे पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह

जहीर हसन, बागपत

जयंती पर विशेष

▶ सामाजिक एकता के लिए शिक्षण संस्थाओं से हटवाया था जाति का ठप्पा

फूस के छप्पर से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे चौधरी चरण सिंह जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। चौधरी साहब का मानना था कि जातिवाद के चलते ही हमें सैकड़ों साल गुलाम रहना पड़ा। वह केवल कहते ही नहीं थे, करके भी दिखाते थे। मुख्यमंत्री बने तो समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश में शिक्षण संस्थाओं से जाति का ठप्पा हटवा दिया।

चौधरी साहब 1939 में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव लाए थे कि जो भी हिंदू प्रत्याशी शैक्षणिक संस्था या लोक सेवा में प्रवेश करे तो उससे जाति के बारे में कुछ न पूछा जाए। केवल यह पता किया जा सकता है कि वह अनुसूचित जाति से है या नहीं। 16 फरवरी 1951 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि कांग्रेस का कोई सदस्य स्वयं को जाति के आधार पर बने किसी संगठन अथवा संस्था से नहीं जोड़ेगा।

चौधरी साहब ने 22 मई 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी कि संविधान में संशोधन कर राजपत्रित पदों पर उन युवक-युवतियों को चुना जाए जो अंतरजातीय विवाह करें।

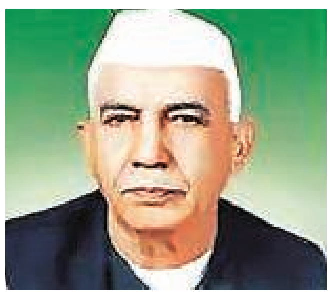
चौ. चरण सिंह। फाइल

1967 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर चौ. चरण सिंह ने शासकीय आदेश जारी किया कि जाति विशेष के नाम से चल रही शिक्षण संस्थाओं का शासकीय अनुदान बंद किया जाएगा। इसका असर यह हुआ कि जातियों के नाम पर संचालित शिक्षण संस्थाओं का नामकरण महापुरुषों के नाम पर हो गया।

पिता सुखदेव के बाद परमिंदर ढींडसा भी कर सकते हैं शिअद से बगावत

जय सिंह छिब्बर, चंडीगढ़

विधानसभा में शिरोमणि अकाली दल के विधायक दल के नेता और पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। परमिंदर ढींडसा ने अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और मीडिया के सामने नहीं आ रहे है, लेकिन उनके पिता राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींडसा अपने बेटे के बारे में बार-बार दावा कर रहे हैं कि परमिंदर पार्टी छोड़ने वाले हैं। परमिंदर ढींडसा के अकाली दल के समागमों से दूरी बनाने से भी संकेत मिलता है कि वे किसी भी समय बगावत कर सकते हैं।

परमिंदर सिंह ढींडसा ने अकाली दल के अध्यक्ष के चुनाव के लिए अमृतसर में हुई मीटिंग और स्थापना दिवस समागम से दूरी बनाए रखी। इसी तरह शनिवार को पटियाला में अकाली दल के धरने में भी वह शामिल नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि परमिंदर ढींडसा का अकाली दल से मोह भंग हो गया है।

यदि परमिंदर ढींडसा अकाली दल से बगावत करते हैं तो पार्टी को सदन में विधायक दल का नेता बनाने के साथ-साथ वित्त की स्थिति पर सरकार को घेरने के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इस समय पार्टी के पास पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और शरनजीत सिंह ढिल्लों सीनियर नेता हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया सदन में सरकार को अलग-अलग मुद्दों पर घेर कर सरकार के लिए संकट जरूर पैदा करते हैं, लेकिन यदि मजीठिया को विधायक दल का नेता बना दिया जाता है, तो परिवारवाद का एक ओर आरोप पार्टी लीडरशिप पर लगेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मुद्दे पर पार्टी पहले ही गंभीर संकट में फंसी है।

परमिंदर ढींडसा। फाइल

राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींडसा ने पिछले वर्ष अकाली दल के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, जबकि इस वर्ष 19 अक्टूबर को राज्यसभा में पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद ढींडसा ने अकाली दल की बैठकों और कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी। उनके बेटे परमिंदर सिंह ढींडसा पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे थे।

टकसाली नेता बढ़ा सकते हैं सुखबीर की मुश्किलें : पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी कह रहे हैं कि किसी नेता के जाने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी सूत्र बताते हैं कि सुखदेव सिंह ढींडसा की बगावत से पार्टी धर्म संकट में फंस चुकी है। इससे पहले माझा के अकाली नेता रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, डॉ. रत्न सिंह अजनाला और सेवा सिंह सेखवां (तीनों पूर्व मंत्री) पार्टी से बगावत कर अकाली दल टकसाली बना चुके हैं। इसी तरह पूर्व स्पीकर रविइंदर सिंह भी अकाली दल टकसाली के नेताओं के साथ संपर्क बना चुके हैं।

वेल में आने वाले विधायकों पर सख्ती के हक में हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पीठासीन अधिकारी की कुर्सी के सामने वेल में आकर विरोध प्रदर्शन और विधायी कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले विधायकों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के हक में हैं। संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ करने के लिए देहरादून में आयोजित दो दिवसीय विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक में उन्होंने भी कई सार्थक सुझाव दिए हैं। इस बैठक से लौटने के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि उन्होंने लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में भी उत्कृष्ट विधायक का चयन करने सहित दल बदल विरोधी कानून को ज्यादा व्यवहारिक बनाए जाने संबंधी सुझाव दिए हैं। गुप्ता के अनुसार वेल में आकर विधायी कार्यप्रणाली में बाधा पहुंचाने वाले विधायकों को अभी सिर्फ एक सत्र के लिए ही बाहर किया जाता है, जबकि इसके लिए और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

गुप्ता के अनुसार विधानसभा में विधायी कार्यों का प्रशिक्षण प्रत्येक विधायक को मिलना चाहिए। इसके लिए हरियाणा विधानसभा के सभी विधायकों, मंत्रियों और राज्य के लोकसभा सांसद व राज्यसभा सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जनवरी माह के अंत में किया जाएगा। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वयं प्रशिक्षण के लिए आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष बताते हैं कि एक विधायक को जब विधायी कार्यों में हिस्सा लेने का पूरा प्रशिक्षण होगा तो वह नियमों के अनुसार ही व्यवहार कर पाएगा। प्रति विधानसभा एक विधायक को उत्कृष्ट विधायक चुनने के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदन के नेता और विपक्ष के नेता की कमेटी का गठन हो। यह कमेटी दलों से ऊपर उठकर यह चयन करे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि मौजूदा दल बदल कानून की भी किसी न किसी रूप में अवहेलना हो रही है। देहरादून में पीठासीन अधिकारियों की बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हालांकि यह आह्वान किया है कि वे इस तरह के निर्णय दें कि उन्हें न्यायपालिका में चुनौती न मिले।

हरियाणा विधानासभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता। जागरण

विस को पेपरलेस करने के लिए मांगा लोस से प्रशिक्षण

विधानसभा अध्यक्ष बताते हैं कि देहरादून बैठक में पेपरलेस विधानसभा बनाने का मुद्दा जोर–शोर से उठा। हरियाणा भी इसके लिए तैयार है मगर इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण जरूरी है। इसलिए हरियाणा की तरफ से उन्होंने मांग की कि लोकसभा सचिवालय और हिमाचल प्रदेश विधानसभा इस बाबत मार्गदर्शन दें।

देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है भाजपा : प्रकाश

जागरण संवाददाता, आसनसोल : देश में पुलिस राज चल रहा है, जंगलराज कायम हो चुका है। भाजपा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसके पीछे आरएसएस है। सबसे अधिक अशांति भाजपा शासित राज्यों में हो रही है। देश में आपातकाल से भी खराब हालात हैं। देश के संविधान एवं लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए पूरे देश में सीएए एवं एनआरसी के खिलाफ आंदोलन को जारी रखना होगा। यें बातें माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात ने कही। वह रविवार को आसनसोल के रवींद्र भवन में माकपा नेता निरुपम सेन की याद में सभा को संबोधित कर रहे थे। माकपा पश्चिम बर्द्धमान जिला कमेटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीएए एवं एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में तीव्र आंदोलन हो रहा है। यह कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं कर रहा है, बल्कि देश का आम नागरिक कर रहा है। छात्र से लेकर आम जनता सभी इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में तानाशाह सरकार चल रही है, देश की जनता के पास न मौलिक न आर्थिक अधिकार है। इससे साबित होता है कि यहां एकतंत्रवाद सरकार है। एक धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं देने के लिए कानून बदला गया है।

छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम तय करेगा कांग्रेस–भाजपा के बागियों का भविष्य

नईदुनिया, रायपुर

▶ राज्य के 151 निकायों के लिए गत शनिवार को मतदान हुआ है। 24 दिसंबर को होगी मतगणना

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का भविष्य चुनाव परिणाम तय करेगा। कांग्रेस और भाजपा की साफ रणनीति है कि जहां उन्हें समर्थन की जरूरत होगी वहीं के बागियों के लिए पार्टी का दरवाजा खुला रहेगा। इसका कारण यह है कि दोनों दलों को अपना महापौर या अध्यक्ष बनाने के लिए परिषद में बहुमत साबित करना होगा। अगर, पार्टी प्रत्याशियों की संख्या कम हो जाती है, तो बागियों को साथ में रखने की मजबूरी होगी। इसके लिए कांग्रेस ने तो पहले ही रणनीति बना ली थी। भाजपा ने रविवार को रणनीति पर बात की। राज्य के 151 निकायों के लिए शनिवार को मतदान हुआ है। मतगणना 24 दिसंबर को होगी।

कांग्रेस ने बागियों को चेताया, लेकिन नहीं किया बाहर : नामांकन वापस लेने की तिथि के बाद तक कांग्रेस अपने बागियों को बैठाने की कोशिश करती रही। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की तरफ से दो बार छह साल के निष्कासन की चेतावनी जारी की गई, लेकिन एक को भी बाहर का नहीं किया गया। संगठन के प्रभारी प्रदेश महामंत्री गिरिश देवांगन का कहना है कि पार्टी ने किसी भी बागी को निष्कासित नहीं किया है। संगठन में उनकी सदस्यता अभी बनी हुई है। मतलब, साफ है कि कांग्रेस की नजर चुनाव परिणाम पर है। जिन निकायों की परिषद में कांग्रेस के पार्षद बहुमत में होंगे, वहां बागियों के लिए पार्टी का दरवाजा बंद हो सकता है। जरत के हिसाब से कांग्रेस में बागियों की सदस्यता कायम रहेगी।

मोहन मारकाम। फाइल

भाजपा कोर कमेटी का फैसला, जरूरत पड़ने पर बागियों की होगी वापसी

भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रविवार को कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें आला–नेताओं ने पार्टी के बागी प्रत्याशियों पर चर्चा की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि बगावत करने वाले पार्टी के नेताओं का निष्कासन किया गया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का नियम बदल गया है, इसलिए बागियों की वापसी भी करनी पड़ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद यह देखना होगा कि किस वार्ड में भाजपा के प्रत्याशी हारे और पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी जीते हैं। बागियों की वापसी से परिषद में महापौर या अध्यक्ष बनाने का मौका मिलता है, तो यह काम करना ही होगा।

तैयारी

सोनभद्र में 1989 में 30 वर्ष के लिए कोयला खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति मिली थी, अब मंत्रालय से नहीं मिला पर्यावरणीय क्लीयरेंस, दो वर्ष से चल रहा था प्रयास

ककरी कोल परियोजना आज से होगी बंद

जागरण संवाददाता, सोनभद्र

▶ परियोजना में लगभग 750 कर्मी और 150 अधिकारी हैं कार्यरत

▶ इस वित्तीय वर्ष में 2.1 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस न देने के कारण सोमवार को सोनभद्र की ककरी कोल परियोजना बंद हो जाएगी। परियोजना बंदी की सूचना और सैकड़ों कर्मचारियों का भविष्य दांव पर लगने से क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है।

1989 में 30 वर्ष के लिए कोयला खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति मिली थी, जिसकी अवधि रविवार को समाप्त हो गई। पर्यावरणीय क्लीयरेंस न मिलने पर परियोजना समेत कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। ककरी परियोजना में लगभग 750 कर्मी एवं 150 अधिकारी कार्यरत हैं। लगभग इतने ही संविदा श्रमिक भी परियोजना में कार्य करते हैं। ककरी परियोजना को इस वित्तीय वर्ष में 2.1 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसका समय से परियोजना द्वारा लक्ष्य को पूरा किया जा रहा था। परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस लेने के लिए अगस्त 2017 से ही प्रयास चल रहा था, लेकिन दो वर्षों से अधिक गुजर जाने के बाद भी पर्यावरण व वनविभाग द्वारा क्लीयरेंस जारी नहीं किया गया। ककरी परियोजना का पर्यावरणीय क्लीयरेंस लखनऊ शासन में ही लटका हुआ है। सरकार की इस उदासीनता पर परियोजना कर्मियों समेत क्षेत्रवासियों में रोष है।

लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा एक ओर जहां कोयला उत्पादन करने की जोर दी जाती है वहीं सरकार परियोजनाओं के समक्ष आ रही परेशानियों के निराकरण के लिए कोई ठोस पहल समय से नहीं की जाती है। इससे ककरी परियोजना बंद होने के कगार पर खड़ी हो गई है। ककरी परियोजना के महाप्रबंधक एलपी गोडसे ने कहा कि दो वर्षों से पर्यावरणीय क्लीयरेंस लेने के लिए प्रयास जारी था। आवश्यकता पड़ी तो ककरी परियोजना में कार्यरत कर्मियों को उच्च प्रबंधन के निर्देशन में अन्य परियोजनाओं में तब तक के लिए भेजा जाएगा जब तक ककरी खदान पुनः शुरू न हो जाए।

एनओसी न मिलना प्रबंधकीय विफलता : अरुण दुबे

बीएमएस के महामंत्री अरुण कुमार दुबे ने कहा कि ककरी परियोजना को पर्यावरणीय क्लीयरेंस न मिलना प्रबंधकीय विफलता है। इसमें श्रमिक संगठन और कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। पर्यावरणीय क्लीयरेंस रिनुअल कराना प्रबंधन का कार्य है। इसके लिए परियोजना में अधिकारी नियुक्त हैं। जितने दिन के लिए परियोजना बंद हो रही है, उतने दिन के लिए अस्थायी व स्थायी कर्मियों का स्थानांतरण की योजना अनुचित है। बीएमएस इसका विरोध करता है।

राज्यों के राजधानी के आसपास सिमटा विकास : तन्खा

नईदुनिया, बिलासपुर : बिलासपुर में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति की ओर से चल रहे धरना प्रदर्शन के 58वें दिन रविवार को राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने समर्थन दिया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों का विकास राजधानी के आसपास ही सिमट गया है। उन्होंने समिति को सहयोग करने की बात कही। यहां राघवेंद्र राव सभा भवन में परिसर में धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा तन्खा ने कहा कि वे शहर का दर्द समझ सकते हैं। यहां की स्थिति उनके गृहनगर जबलपुर की तरह ही है। दोनों शहरों में अपने-अपने राज्य का उच्च न्यायालय है। इसके बावजूद दोनों का विकास नहीं हो पाया। उनके साथ पहुंचे राज्यसभा सदस्य टी सुब्बारामी रेड्डी ने कहा कि मुझे रायपुर से दिल्ली आने में जितना समय नहीं लगा उससे अधिक समय रायपुर से बिलासपुर आने में लगा है।

मंगू मठ को लेकर पंजाब के दो विधायकों ने भुवनेश्वर में किया विरोध– प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

▶ कहा, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पंजाब जाकर देखें कैसे किया जाता है सुंदरीकरण का कार्य

पुरी में मंगू मठ तोड़े जाने को लेकर शनिवार को जहां सिख समाज की तरफ से वहां विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं रविवार को राजधानी भुवनेश्वर में भी प्रदर्शन किया गया। भुवनेश्वर में हुए विरोध प्रदर्शन में पंजाब के दो विधायक समरजीत सिंह एवं बलवंत सिंह भी शामिल हुए।

खारवेल नगर से मास्टर कैंटीन तक निकाली गई रैली में शामिल पंजाब के इन दोनों विधायकों ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मंदिर एवं मठों को तोड़े बगैर किस प्रकार से सुंदरीकरण कार्य किया जाता है, उसे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पंजाब जाकर देखना चाहिए। विधायकों ने कहा कि हम यहां पर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, मगर हमें मिलने का अवसर नहीं दिया गया। विधायकों ने धमकी देते हुए कहा है कि यदि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मंगू मठ के बचाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो पंजाब से लाखों की संख्या में सिख यहां पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। इस विरोध रैली में सैकड़ों की संख्या में सिख संप्रदाय के लोग शामिल थे।

गौरतलब है कि पुरी श्रीमंदिर की सुरक्षा एवं पुरी को विश्वस्तरीय शहर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने श्रीमंदिर के 200 मीटर की चौहद्दी में स्थित तमाम पुराने मठ व मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू किया है। इसे लेकर सरकार को विभिन्न संगठन एवं लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार तमाम विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए श्रीक्षेत्र धाम को अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखे हुए है।

10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का एलान किया है कर्नाटक सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन में मरने वाले दो लोगों के परिजनों को। यह जानकारी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दी।

सीएए एक कानून है जबकि एनआरसी एक प्रस्तावित प्रक्रिया

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदू सहित छह अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता की राह प्रशस्त करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है। जबकि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारतीय नागरिकों का संवैधानिक रिकॉर्ड है। यह दोनों प्रावधान एक दूसरे से एकदम अलहदा हैं। सीएए एक कानून है तो एनआरसी प्रस्तावित प्रक्रिया। जिसे पूरे देश में लागू किये जाने संबंधी नियम-कानून अभी बनाए जाने हैं। अभी यह सिर्फ असम में लागू है। इन दोनों को लेकर एक बड़े तबके के बीच भ्रम की स्थिति है। पेश है एक नजर:

सीएए के खिलाफ गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है ● प्रेट्र

भारतीय नागरिकों का दस्तावेज है एनआरसी

एनआरसी उन लोगों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो वैधानिक रूप से भारतीय नागरिक हैं। इसमें उन सभी लोगों की जनसांख्यिकी सूचना शामिल होती है जो नागरिकता कानून, 1955 के अनुसार भारतीय नागरिक हैं। यह रजिस्टर पहली बार 1951 की जनगणना के बाद बना और उसके बाद अब तक इसे अपडेट नहीं किया गया है। अब तक इस डेटाबेस को सिर्फ असम में बनाया गया है।

ये हैं भारतीय नागरिक

नागरिकता कानून, 1955 के अनुसार भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति:

1. 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन एक जुलाई 1987 से पहले
2. एक जुलाई 1987 के पहले दिन पर या उसके बाद, लेकिन नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के शुरू होने से पहले और जिनके माता-पिता भारत के नागरिक हैं उनके जन्म के समय
3. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ होने के बाद या, जहां-
   (अ) उसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, या
   (ब) जिनके माता-पिता भारत के नागरिक हैं और दूसरे उनके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं हैं, वे जन्म से भारत के नागरिक होंगे।

राष्ट्रीय एनआरसी का प्रस्ताव

असम में एनआरसी के बाद इसके राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की मांग उठ रही है। भाजपा के कई शीर्ष नेताओं जिनमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं ने एनआरसी को देश के अन्य हिस्सों में करने का प्रस्ताव किया है। यह एक ऐसा कानून होने का सुझाव देता है जिससे देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान कर जहां से वे आए हैं, वहां उन्हें वापस भेजा जा सके।

असम में एनआरसी

यह जातीय विशिष्टता को बचाए रखने के लिए राज्य आधारित कार्य है। 2013 में असम लोक निर्माण और असम सनमिलिता महासंघ व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर असम की मतदाता सूचियों से अवैध नागरिकों के नाम हटाने की मांग की। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने असम के सभी इलाकों में एनआरसी को नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता नियम 2003 के तहत अपडेट करने का आदेश दिया था। यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से 2015 में शुरू हुई और एनआरसी की मुख्य सूची 31 अगस्त को जारी हुई। करीब 19 लाख लोग इस सूची से बाहर हो गए। इस सूची से बाहर रहे कई हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि असम में फिर से एनआरसी होगी।

असम से भिन्न राष्ट्रीय एनआरसी

सरकार ने अभी तक एनआरसी को देश भर में लागू करने को लेकर कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया है। इसे लेकर प्रक्रिया अभी तक साफ नहीं है। असम में जब एनआरसी हुई थी तो नागरिकों को उनकी नागरिकता का प्रमाण राज्य भर के एनआरसी सेवा केंद्रों पर देने के लिए कहा गया था। यह अभी तक साफ नहीं है कि देशभर में यह किस तरह से अपनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त असम एनआरसी को नागरिकता अधिनियम 2003 में राज्य के लिए एक विशेष अपवाद के माध्यम से अनिवार्य किया गया था। पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अंजाम दिया गया। फिलहाल देशव्यापी एनआरसी के लिए कोई निर्देश नहीं है। यदि देशव्यापी एनआरसी की जाती है तो यह केंद्र सरकार के निर्देशन में होगी।

एनआरसी से अलग सीएए

देशव्यापी प्रस्तावित एनआरसी फिलहाल एक प्रस्ताव के रूप में है। यदि यह लागू किया जाता है तो इसके निशाने पर अवैध घुसपैठिए होंगे। हालांकि इसके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई प्रभावित नहीं होंगे, यदि वे दावा करते हैं कि वे भारत में धार्मिक उत्पीड़न के कारण पहुंचे हैं। बहुत से लोगों को यह भी डर सता रहा है कि यदि मुस्लिम नागरिकता के उचित दस्तावेज पेश नहीं कर सके तो उन्हें अवैध अप्रवासी माना जा सकता है। हालांकि सरकार ने उनकी इस आशंका को दूर करते हुए बताया है कि आसान प्रपत्रों को पेश करके वे अपनी उम्मीदवारी साबित कर सकेंगे।

केंद्रीय कानून नहीं मानना राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता

टकराव ▶ संविधान के अनुसार हर राज्य को मानने ही होंगे केंद्रीय कानून

नागरिकता और घुसपैठियों पर कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र को

माला दीक्षित, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) पर राजनीति गर्म हैं। सीएए का विपक्षी दल सड़कों पर विरोध कर रहे हैं और राजनीतिक नफा नुकसान आंकती राज्य की कुछ सरकारें बयान दे रही हैं कि वे अपने यहां सीएए लागू नहीं कराएंगी या वे एनआरसी नहीं लागू करेंगी। संसद से पास कानून और केंद्र सरकार के निर्देशों को नकारने की यह घोषणा भले ही राज्य सरकारों के लिए राजनीतिक लाभ की हो लेकिन संविधान इस बारे में साफ है कि राज्य सरकारें केंद्र के बनाए कानून या केंद्र के निर्देशों को मानने से इन्कार नहीं कर सकतीं। संविधानविदों का कहना है कि केंद्र के निर्देशों को मानना राज्य का दायित्व है और उन्हें न मानना संवैधानिक तंत्र का फेल होना माना जाता है। और उसके परिणाम भी संविधान में दिए गए हैं।

> 'संविधान के अनुच्छेद 256, 365 और 355 की तिकड़ी केंद्र को राज्यों के ऊपर असीमित शक्तियां देती है'
> –ज्ञानंत सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वकील

सीएए आ चुका है और एनआरसी की चर्चा है। अभी एनआरसी की कोई घोषणा नहीं हुई है न ही किसी को नियम कानून पता हैं। एनआरसी फिलहाल सिर्फ असम में लागू हुई है और वह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। लेकिन भाजपा की ओर से कहा जाता है कि देश भर में एनआरसी लागू की जाएगी और इसीलिए सीएए का विरोध करने वाले उसे एनआरसी से जोड़ रहे हैं। एक वर्ग के विरोध को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने सीएए और एनआरसी को न लागू करने के बयान दिए हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची में वे विषय दिए गए हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार यानी संसद कानून बना सकती है। केंद्रीय सूची की प्रविष्टि 17 में नागरिकता, न्यूट्रिलाइजेशन और एलियंस यानी बाहरी लोगों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। प्रविष्टि 18 प्रत्यर्पण के बारे में और प्रविष्टि 19 भारत में प्रवेश और इमीग्रेशन तथा भारत से बाहर निकालना, पासपोर्ट और वीजा के बारे में संसद को कानून बनाने का एकछत्र अधिकार देती है। यानी इससे साफ है कि नागरिकता के बारे में कानून बनाने और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार कहते हैं कि इन विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह उन कानूनों का पालन करें। सीएए नागरिकता से संबंधित कानून है और इसे लागू करना राज्यों की बाध्यता है। अगर राज्य इसे लागू नहीं करते तो उनका ऐसा करना राज्य में संवैधानिक तंत्र का फेल होना माना जाएगा और संवैधानिक तंत्र फेल होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है, यह संविधान में स्पष्ट किया गया है। कुमार कहते हैं कि अनुच्छेद 73 के तहत केंद्र सरकार को उन विषयों पर कोई भी कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। एनआरसी अगर लागू भी होता है तो वह नागरिकता से जुड़ा विषय होगा और उस बारे में केंद्र सरकार को कार्यकारी यानी एक्जिक्यूटिव आदेश जारी करने का अधिकार है और राज्यों के लिए उसका पालन करना जरूरी है। हालांकि एक्जिक्यूटिव आदेश की व्याख्या हो सकती है। उसके आयाम हो सकते हैं।

हमारा संविधान राज्यों की अलग सरकार की व्यवस्था के साथ ही केंद्र में निहित एकीकृत व्यवस्था का ढांचा भी पेश करता है। इसके तहत बहुत से ऐसे मौके हैं जिनमें केंद्र सरकार को राज्यों पर प्राथमिकता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 256, 365 और 355 की ये तिकड़ी केंद्र को राज्यों के ऊपर असीमित शक्तियां देती हैं।

अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह संसद के पारित कानून लागू करेंगी। इसके अलावा केंद्र राज्यों को जरूरी निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 365 कहता है कि जब कोई राज्य केंद्र सरकार के एक्जिक्यूटिव आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति का यह मानना कानून सम्मत होगा कि राज्य में सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है। अनुच्छेद 355 कहता है कि राज्य को बाहरी और अंदरूनी खतरे से सुरक्षित रखना केंद्र की जिम्मेदारी है। साथ ही केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह देखेगी कि राज्य की सरकार संविधान के मुताबिक चले। अनुच्छेद-356 राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन व अन्य कार्रवाई की बात करता है। इन सबको मिला कर देखा जाए तो नागरिकता के मुद्दे पर राज्यों के पास ना नुकुर का विकल्प नहीं है।

उप्र में हुई हिंसा को लेकर अब राजनीतिक दलों में घमासान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ अखिलेश ने भाजपा को दोषी ठहराया
▶ भाजपा ने सपा को ठहराया जिम्मेदार
▶ कांग्रेस के निशाने पर भी योगी सरकार

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उप्र में हुई हिंसा पर अब राजनीतिक दलों में घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस कर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया कि दंगा कराने वाले सत्ता में बैठे हैं तो भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सपा को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

सरकार में बैठे लोग ही हिंसा के लिए जिम्मेदार: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हिंसा के जिम्मेदार लोग सरकार में बैठे हैं। दंगों से भाजपा को लाभ होता है। उन्होंने सवाल किया कि जब मुख्यमंत्री ही 'ठोक देंगे और बदला लेंगे' वाली भाषा का प्रयोग करेंगे तो पुलिस कैसे निष्पक्ष हो सकती है? उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के सरकार के आदेश पर सपा प्रमुख ने कहा कि इसकी शुरुआत 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे के दोषियों से होनी चाहिए।

पाकिस्तान की भाषा बोल रहे अखिलेश: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्रकार वार्ता के तीन घंटे बाद ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन पर पलटवार किया। कहा कि अखिलेश पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। स्वतंत्र देव ने कहा कि कांग्रेस और सपा में मुस्लिम वोटों के लिए होड़ लगी है। इससे देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा है। सपा के सांसद, विधायक और नेताओं द्वारा लोगों को भड़का कर आगजनी और हिंसा कराने के प्रमाण मिल चुके हैं। अराजकता व गुंडागर्दी सपा की संस्कृति रही है। जब भी सपा सत्ता में रहती है तो मुजफ्फरनगर जैसे दंगे होते हैं।

भाजपा की वजह से भड़की हिंसा : कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भाजपा के लोगों की वजह से ही हिंसा भड़की और पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों का दमन किया। प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में लल्लू ने सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रदर्शन के दौरान हिंसा क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि हापुड़, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, फीरोजाबाद, कानपुर, लखनऊ समेत अन्य जिले जहां पर हिंसा की खबरें आई हैं, वहां पर तत्काल न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस की भूमिका क्या है, यह बिजनौर के पुलिस कप्तान के ऑडियो से पता चलता है। सूबे में राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं की गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता रहीं सदफ जाफर को पुलिस ने बर्बर ढंग से मारा-पीटा है। उनकी गिरफ्तारी की सूचना पुलिस ने 24 घंटे तक छिपाए रखी।

मुस्लिमों को मिले दो देश, तब कहां थे धर्मनिरपेक्षता के हिमायती : तारेक फतह

अनिल त्रिवेदी, इंदौर : तथाकथित धर्म निरपेक्षता के हिमायती उस वक्त कहां थे जब धर्म के नाम पर भारत के टुकड़े कर मुस्लिमों को एक पूरा देश दे दिया गया? इसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो एक नया मुस्लिम बहुल देश अस्तित्व में आ गया। उस वक्त भारत ने बांग्लादेश को बंगाल में क्यों नहीं मिलाया? आखिर किसी जमाने में वो बंगाल का ही तो हिस्सा था। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक दशकों से भीषण नारकीय यातनाएं झेल रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें वापस भारत की नागरिकता दी जा रही है तो इसमें गलत क्या है?

ये सीधे सवाल हैं जो पाकिस्तान में जन्मे मशहूर कनाडाई लेखक तारेक फतह ने इंदौर में आयोजित 'इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल' में रविवार को उठाए। साहित्यिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने इंदौर आए तारेक ने नईदुनिया से खास गुफ्तगू में बेबाकी से अपने खयालात और जज्बात साझा किए। उन्होंने कहा कि इसी बहाने 'गजवा-ए-हिंद' का ख्वाब देखने वाले कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं।

गंगा-जमनी तहजीब का राग छोड़ें : अब तो यहां के लोगों को 'गंगा-जमनी तहजीब' का राग छोड़कर अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। सस्ते महंगे आलू, टमाटर, प्याज की चिंता छोड़कर 'कटक से अटक' तक अपने देश के बारे में सोचिए। अगर सवा अरब लोग हर रोज कटक से अटक के बारे में सोचेंगे तो एक दिन उनका ये ख्वाब हकीकत की शक्ल अख्तियार क्यों नहीं करेगा?

सीएए और एनआरसी भारत का आंतरिक मामला : बांग्लादेश

▶ लेकिन देश में व्याप्त अनिश्चितता की स्थिति पर जताई चिंता

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश ने साफ कहा है कि सीएए और एनआरसी भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन इसके साथ ही उसने देश में व्याप्त अनिश्चतता की स्थिति पर चिंता भी जताई। उसने उम्मीद जताई कि भारत में विवादित नागरिकता संशोधन कानून पर बढ़ते प्रदर्शनों के बीच स्थिति में 'नरमी' आएगी और पड़ोसी देश इस समस्या से बाहर निकल जाएगा।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने रविवार को कहा कि सीएए और एनआरसी भारत के आंतरिक मुद्दे' हैं, लेकिन भारत में 'अनिश्चितता' की कोई भी स्थिति पड़ोसी मुल्कों पर असर डाल सकती है। मोमेन से सीएए और खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शनों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) भारत के अंदरूनी मुद्दे हैं। भारत सरकार ने हमें बार-बार आश्वस्त किया है कि ये उनके घरेलू मुद्दे हैं, वे कानूनी और अन्य वजहों से ऐसा कर रहे हैं।'

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया था कि किसी भी परिस्थिति में इसका असर बांग्लादेश पर नहीं पड़ेगा। मंत्री ने दोहराया कि उनका देश भारत पर यकीन करता है। उन्होंने कहा, 'हम भारत के नंबर वन दोस्त हैं। अगर भारत में अनिश्चितता की स्थिति है तो उसका असर उसके पड़ोसियों पर पड़ने की आशंका है। जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आती है तो इससे कई देश प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम वैश्विक दुनिया में जीते हैं। हमारा डर है कि अगर भारत में अनिश्चितता की कोई स्थिति होती है तो इसका असर उसके पड़ोसियों पर भी पड़ सकता है।'

मोमेन ने कहा, 'यह चिंता की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति में सुधार आएगा और भारत इससे बाहर निकल सकेगा। यह उनका आंतरिक मुद्दा है। यह हमारा मसला नहीं है। उन्हें इससे निपटना चाहिए।' उन्होंने हाल ही में कहा था कि बांग्लादेश ने भारत से अनुरोध किया है कि अगर उसके पास वहां अवैध रूप से रह रहे किसी भी बांग्लादेशी नागरिक की सूची है तो वह उसे मुहैया कराए और बांग्लादेश उन्हें वापस बुलाएगा। बता दें कि विदेश मंत्री ने 12 दिसंबर से शुरू होने वाली अपनी भारत की यात्रा को कुछ घंटों पहले ही रद्द कर दिया था।

हमने नहीं, गृहमंत्री ने फैलाया देश में भय व अनिश्चितता का माहौल : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ पार्टी ने भ्रम फैलाने के पीएम के आरोपों को किया खारिज
▶ राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने की उठाई मांग

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर भ्रम फैलाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि सीएए को एनआरसी से जोड़ने के गृहमंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान और भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के बयानों से विरोध मौजूदा परिस्थितियां पैदा हुई हैं। विरोध प्रदर्शन को थामने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक सीएए का कार्यान्वयन टालने और मौजूदा हालत पर आम सहमति बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने की मांग भी की है।

प्रधानमंत्री के दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस पर किए गए वार पर जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि गृहमंत्री ने खुद संसद के दोनों सदनों में सीएए के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू करने का बयान दिया था। इसी तरह भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों ने एनआरसी लागू करने के बयान दिए हैं। इससे देश में भय व अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ। शर्मा ने भाजपा को घेरते हुए यह भी कहा कि पीएम कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो फिर सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही कि असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध तीव्र क्यों है जबकि वहां तो भाजपा की सरकारें हैं। सीएए के आंदोलन को भड़काने के पीएम के आरोपों को खारिज करते हुए शर्मा ने कहा कि जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आइआइटी, आइआइएम, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस से लेकर तमाम संस्थानों के छात्र-छात्राएं इसके खिलाफ और विरोध में सामने आए हैं। फिर पीएम ने छात्रों के इस विरोध और आक्रोश का समाधान निकालने के लिए क्यों नहीं कुछ बोला। उन्होंने मांग की कि पीएम हालात पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाएं। इस मसले पर मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा कर आम सहमति बनाना जरूरी है।

शर्मा ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था और रोजगार को तबाह कर दिया है। पीएम से अपेक्षा थी कि वे अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के गंभीर संकट पर देश को कुछ राह दिखाएंगे, मगर पीएम ने केवल भटकाने वाली बातें कहीं।

मोदी और शाह ने बर्बाद किया देश के युवाओं का भविष्य : राहुल

सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। वे देश के लोगों को बांट रहे हैं तथा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नफरत के पीछे छिप रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'भारत के प्रिय युवाओं, मोदी और शाह ने आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया है। वो नौकरियों की कमी और अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर आपके गुस्से का सामना नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारे प्यारे भारत को बांट रहे हैं और नफरत के पीछे छिप रहे हैं।' राहुल ने कहा, 'हम हर भारतीय के प्रति स्नेह दिखाकर इनको पराजित कर सकते हैं।'

राजघाट पर धरना आज

कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसका खुलकर विरोध कर रही है। उसने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सोमवार को राजघाट पर सत्याग्रह करने का फैसला किया है जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

सीएए-एनआरसी रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों पर दबाव डालेगी कांग्रेस

संजय मिश्र, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध के चलते कांग्रेस ने भाजपा-राजग से मित्रता रखने वाले क्षेत्रीय दलों को इस मुद्दे पर दबाव में लाने की रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत पार्टी ओडिशा में बीजद, तेलंगाना में के.चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और बिहार में नीतीश कुमार को सीएए और एनआरसी पर घेरने का प्रयास करेगी। इस पर मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए कांग्रेस इन क्षेत्रीय दलों के सियासी रुख में बदलाव जरूरी मान रही है। सीएए के खिलाफ सोमवार को राजघाट पर होने वाले कांग्रेस के पहले बड़े विरोध-प्रदर्शन के साथ ही पार्टी इन सूबों में भी अपने इस अभियान की शुरुआत करेगी।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को विभाजनकारी बता रही कांग्रेस के राजघाट पर होने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अगुआई खुद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद कांग्रेस की राज्य इकाइयां सीएए के साथ संभावित एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) की भाजपा सरकार की मंशा पर विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला शुरू करेंगी। पार्टी की राज्य इकाइयों को इस बारे में संगठन महासचिव की ओर से जरूरी दिशा-निर्देश भी भेजा जा रहा है।

नागरिकता संशोधन कानून पर पार्टी की राजनीतिक दशा-दिशा का संचालन कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि सीएए के खिलाफ विरोध और आक्रोश के बढ़ते माहौल की वजह से ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने एनआरसी लागू नहीं करने की पहली बार बात कही है। जबकि बीजद ने सीएए के पक्ष में संसद में भाजपा के साथ मतदान किया था। पार्टी रणनीतिकारों के अनुसार सीएए को वापस लेने और एनआरसी पर मोदी सरकार के कदम रोकने के लिए बीजद का रुख बेहद अहम है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह जरूरी हो जाता है कि सूबे मे बीजद पर सियासी दबाव बढ़ाने के लिए सीएए-एनआरसी का विरोध पूरी ताकत से किया जाए।

आंध्रप्रदेश में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाइएसआर कांग्रेस ही नहीं टीडीपी ने भी सीएए में भाजपा सरकार के पक्ष में वोटिंग की थी। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि इस सूबे में सीएए विरोधी आंदोलन को मजबूती से खड़ा कर वह जगन और चंद्रबाबू दोनों को कम से कम एनआरसी पर भाजपा के साथ नहीं जाने का दबाव बना सकती है। हालांकि आंध्र में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यह है कि सूबे के बंटवारे के बाद पार्टी का आधार ही नहीं संगठन भी बेहद लचर हालत में है और पार्टी रणनीतिकारों की यह रणनीति यहां कारगर होगी इस पर संदेह है।

तेलंगाना के सीएम के.चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस ने भले संसद में सीएए के खिलाफ वोटिंग की मगर यह भी सच है कि बीते साढ़े पांच सालों में टीआरएस ने इसके अलावा उन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार का साथ दिया है जिस पर विपक्षी दल गोलबंद थे। हैदराबाद में सीएए के खिलाफ हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों ने भी कांग्रेस को बीते पांच साल के दौरान टीआरएस और भाजपा की दोस्ती को उजागर करने को प्रोत्साहित किया। सीएए के बाद कांग्रेस एनआरसी को मोदी सरकार का अगला कदम मान रही है और ऐसे में बीजद, टीआरएस और वाइएसआर कांग्रेस जैसे दल इसके खिलाफ हो गए तो फिर संसद में इसे पारित करना मुश्किल होगा। बिहार में भी कांग्रेस और राजद सियासी प्रदर्शनों के जरिये नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। सीएए को लेकर बढ़ रहे दबाव की यह वजह ही रही कि नीतीश ने पहले ही एनआरसी को 'ना' कह दिया है।

शाह को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे : चौधरी

जासं, कोलकाता : बंगाल के राज्य के पुस्तकालय मंत्री और जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सिद्दिकुल्लाह चौधरी ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि सीएए को वापस नही लिया गया तो गृहमंत्री अमित शाह को कोलकाता हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा।

दो टूक

सीएए के समर्थन में हुई रैली में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री, कहा – पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों का होता है उत्पीड़न

पाकिस्तान में हिंदू होना अपराध जैसा है : गडकरी

नागपुर, एएनआइ : पाकिस्तान में हिंदू धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। उनकी महिलाओं से दुष्कर्म होता है। उन्हें जबरन धर्मांतरण का शिकार होना पड़ता है। क्या वहां हिंदू होना कोई अपराध है? पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को यह बात कही। वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे।

गडकरी ने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कई तरह से उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। बंटवारे के समय वहां 22 फीसद हिंदू थे, जो आज घटकर तीन फीसद रह गए हैं। उन्होंने एक अनुभव साझा करते हुए कहा, 'मैं जोधपुर में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों से मिला हूं। वहां महिलाओं ने अपने साथ दुष्कर्म होने की व्यथा सुनाई। उनकी संपत्तियां लूट ली गईं और बेदखल कर दिया गया। इन उत्पीड़नों के कारण ही उन्हें पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी।'

नागरिकता संशोधन एक्ट के समर्थन में महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित रैली को संबोधित करते सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। प्रेट्र

गडकरी ने कहा कि भारत एक सहिष्णु देश है और इसकी कोई विस्तारवादी नीति नहीं है। हमने हमेशा जरूरतमंद को शरण दी है। सऊदी अरब में भारतीय मुस्लिमों को भी हिंदू कहा जाता है, क्योंकि हमारी पहचान किसी धर्म से नहीं जुड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि किसी भी तरह का खतरा महसूस करने पर पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत शरण और पहचान देगा। जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल ने भी इससे सहमति जताई थी। गडकरी ने यह भी कहा कि सीएए भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस अफवाह फैला रही है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने भी सीएए का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'लोग बड़ी तादाद में इस कानून के समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि यह देश हित में है, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं। कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और देश में अस्थिरता फैला रहे हैं।' यह स्थिति सही नहीं है। उन्हें समझना होगा कि देश में इस तरह अस्थिरता का माहौल पैदा करके वह देशवासियों का भला नहीं कर रहे हैं। लोगों को भी ऐसे लोगों और राजनीतिक दलों से दूरी बनानी होगी तभी देश का विकास होगा।

40 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है बिहार बंद के दौरान शनिवार हुई हिंसा के मामले में। इससे संबंधित चार प्राथमिकी में 101 लोगों को नामजद और एक हजार अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 23 दिसंबर 2019

सीएए के प्रावधानों पर 10 लाइन तो बोलकर दिखाएं राहुल

बोले नड्डा ▸ नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर राजनीतिक रोटियां सेंक रही कांग्रेस

विस्थापित सिंधी व सिख समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने राहुल से सवाल पूछे

नईदुनिया, इंदौर

भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को इंदौर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस व खासकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के प्रावधान पर 10 लाइन तो बोल दें। दो लाइन में बताएं कि इससे देश का क्या नुकसान हो रहा है? वह सिर्फ इतना कर दें तो देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। वे बताएं कि सीएए क्या है? दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि देश का नेतृत्व करने के लिए वे लोग आगे आए हैं, जिन्होंने बेसिक (मूलभूत) चीजों को जानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए आज मैंने बेसिक सवाल उठाए।'

नागरिका संशोधित कानून एवं नेशनल रजिस्टर ऑफ सटिजंस के समर्थन में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रविवार को रैली निकाली गई। इस मौके पर लोगों का अभिवादन करते भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एएनआइ

वह पाकिस्तान से विस्थापित सिंधी और सिख समाज द्वारा इंदौर में आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने राहुल से सवाल पूछे। पहला सवाल किया कि क्या राहुल ने विभाजन का इतिहास पढ़ा है? उनके वक्तव्य से तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने देश के विभाजन का दर्द झेलने वाले लाखों लोगों के बारे में पढ़ा है। दूसरा सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे किसी शिविर में गए हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर लोगों ने भारत में शरण ली हो? तीसरा सवाल पूछा कि एक सप्ताह से सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इसमें जनता की काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है, लेकिन कभी इसकी निंदा नहीं की, क्यों? भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तान से विस्थापित कई सिंधी और सिख समाज के लोग भी शामिल हुए। नड्डा ने सम्मेलन में मौजूद लोगों से कहा कि जो भारत का मर्म नहीं जानते हों, वे राजनीति में आते हैं तो किस तरह की राजनीति होती है, वह आपने देखा है। मैं इशारों में कह रहा हूं कि उनसे होशियार रहना जो आपके हक पर डाका डालेंगे। देश के विभाजन के समय नेहरू और लियाकत के बीच समझौता हुआ था कि दोनों देशों को अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी। हमने की है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक 28 फीसद से सिर्फ तीन फीसदी रह गए। बांग्लादेश में भी 22 से घटकर सात फीसद अल्पसंख्यक रह गए। कोई इसका जवाब देगा?

किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं जाएगी

नड्डा ने कहा कि देश में 70 साल से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बात चल रही है। कांग्रेस ने भी चर्चा की, लेकिन किसी ने इस कानून में परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छाशक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति का परिणाम है कि यह कानून पास होकर साकार हुआ है। नड्डा ने कहा कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं। बाहर से प्रताड़ित होकर हमारे जो भाई आए हैं उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले, यह कानून इसीलिए है। इससे किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं जाएगी। कांग्रेस के लिए देश नहीं, वोट बैंक सर्वोपरि है, इसलिए वह भी सीएए के विरोध को समर्थन दे रही है। पर भाजपा ने तय किया है कि वह गुमराह करने वालों को सबक सिखाएगी। देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करेगी।

लिपिस्टिक के साथ पर्स में छोटा चाकू भी रखें बेटियां : साध्वी प्राची

जागरण संवाददाता, देहरादून : साध्वी प्राची ने बेटियों को सलाह दी कि वे अपने पर्स में लिपिस्टिक-बिंदी के साथ एक छोटा चाकू भी जरूर रखें, ताकि कोई दरिंदा आंख उठाने का साहस न करे। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदुस्तानी नहीं मानते उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।

रविवार को देहरादून में हिंदू जागरण मंच के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची साध्वी प्राची ने महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें घर और घर से बाहर दोहरे दायित्व निभाने होते हैं। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि यदि कोई उनकी तरफ गंदी नजर से देखे तो उसे ज्वाला का रूप लेकर भस्म कर दो। बेटियों को ब्यूटी पार्लर भेजें या न भेजें, लेकिन बेटियों को आत्मरक्षा के गुर जरूर सिखाएं। हैदराबाद गैंगरेप मामले में उन्होंने कहा कि दरिंदों ने एक बेटी के साथ जो किया उससे बच्चे-बच्चे में उबाल था। ऐसे कृत्य करने वालों पर ना कोई दलील, न कोई अपील मौके पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। हैदराबाद में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो कुछ संगठन खड़े हो गए।

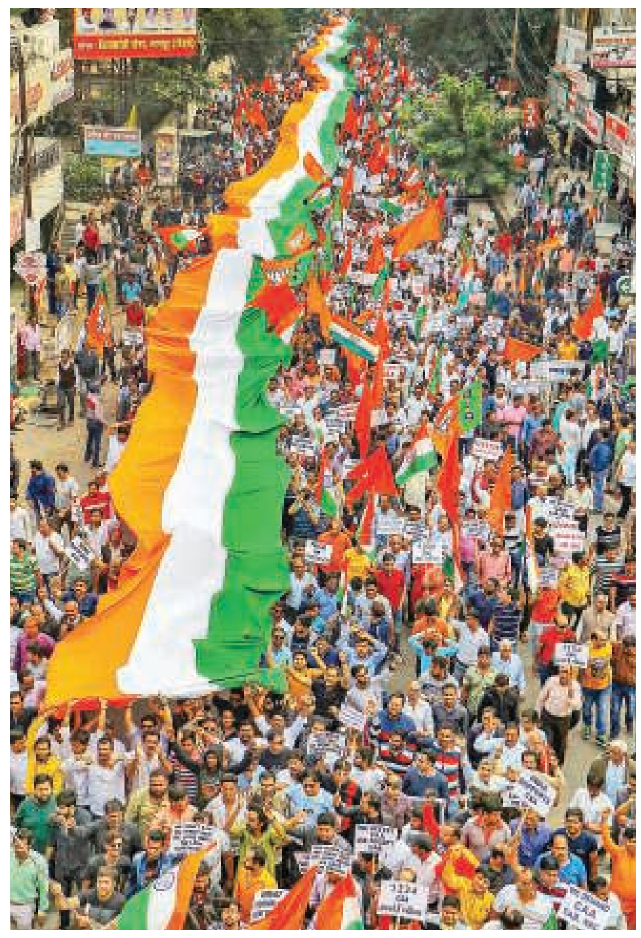

नागरिकता कानून के समर्थन में रैली

नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार को यशवंत स्टेडियम से संविधान चौक तक तिरंगा रैली निकाली। प्रेट्र

चंदे की खातिर जेल जाता है चंद्रशेखर : मायावती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का एलान कर दलितों की सियासत में हलचल बढ़ा देने वाले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने रविवार को निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए प्रदर्शन करता है और जेल चला जाता है। उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए उनके साथी भोले-भाले दलितों से चंदा एकत्र कर अपना धंधा चलाते हैं। इससे भीम नाम के अलावा दलितों की भी काफी बदनामी होती है।

मायावती। फाइल

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच मायावती के इस बयान से दलितों पर केंद्रित सियासत में बेचैनी के संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा कि दलित समाज का मानना है कि भीम आर्मी का चंद्रशेखर विरोधी पार्टियों के हाथ में खेल रहा है। बसपा के मजबूत जनाधार वाले राज्यों में चुनाव के समय धरना प्रदर्शन कर वह जबरन जेल चला जाता है ताकि वोटों को नुकसान पहुंचाया जा सके। मायावती ने कहा कि चंद्रशेखर पश्चिमी उप्र का रहने वाला है लेकिन सीएए व एनआरसी मुद्दे पर दिल्ली में जामा मस्जिद वाले प्रदर्शन में शामिल होकर जबरन गिरफ्तारी कराता है। बसपा प्रमुख ने लोगों से अपील की है कि वे चंद्रशेखर आजाद और उनके जैसे स्वार्थी लोगों से सचेत रहें। कहा कि नागरिकता कानून व एनआरसी का बसपा शुरू से विरोध करती रही है। किसी बात का विरोध शांति व लोकतंत्र के दायरे में किया जाना चाहिए।

बामसेफ नाम पर भी बने कई संगठन

चंद्रशेखर के साथ बसपा अध्यक्ष ने बामसेफ नाम से संगठन चलाने वालों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, भीम आर्मी की तरह ही बामसेफ के नाम से कर्मचारियों के कई संगठन बने हैं। ये अपने आप को कांशीराम का अनुयायी भी बताते हैं। चुनावों में हमारे लोगों के बीच जाकर उन्हें गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी तत्वों व संगठनों से सावधान रहने की जरूरत है।

'भारतीयता का सुबूत मांगने की इजाजत नहीं'

जागरण संवाददाता, बिजनौर

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा रविवार शाम अचानक उप्र के बिजनौर जिले के नहटौर पहुंच गईं। वह शुक्रवार को नहटौर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा में मारे गए अनस और सुलेमान के परिजनों से मिलीं। साथ ही घायल ओमराज सैनी के परिवार से भी मिलने पहुंचीं। प्रियंका ने परिजनों को सांत्वना दी और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने नागरिकता कानून को जनहित के विरुद्ध बताते हुए कहा कि सरकार को देश के किसी भी नागरिक से भारतीयता का सुबूत मांगने की इजाजत नहीं है।

रविवार शाम करीब चार बजे पहुंचीं प्रियंका का दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया। प्रियंका सबसे पहले मोहल्ला मिर्दगान स्थित मृतक अनस के घर पहुंचीं। उन्होंने अनस के परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली और उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद वह मोहल्ला नौधा स्थित मृतक सुलेमान के घर पहुंचीं और परिवार को सांत्वना दी। बाद में वह घायल ओमराज सैनी के घर कासमपुर लेखराज पहुंचीं। यहां उन्होंने ओमराज की पत्नी सुधा सैनी को गले लगाकर उनका हाल-चाल जाना। ओमराज के घर से निकलने पर प्रियंका ने कहा कि सरकार ऐसे गरीब और किसानों से उनके नागरिकता के कागजात मांग रही है, जो मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार पाल रहे हैं और झोपड़ी में रह रहे हैं। वे कैसे कोई कागज देंगे। क्या कांग्रेस आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी लेगी, मीडिया के इस सवाल को प्रियंका टाल गईं। उन्होंने कहा कि सरकार को नहटौर मामले की उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए।

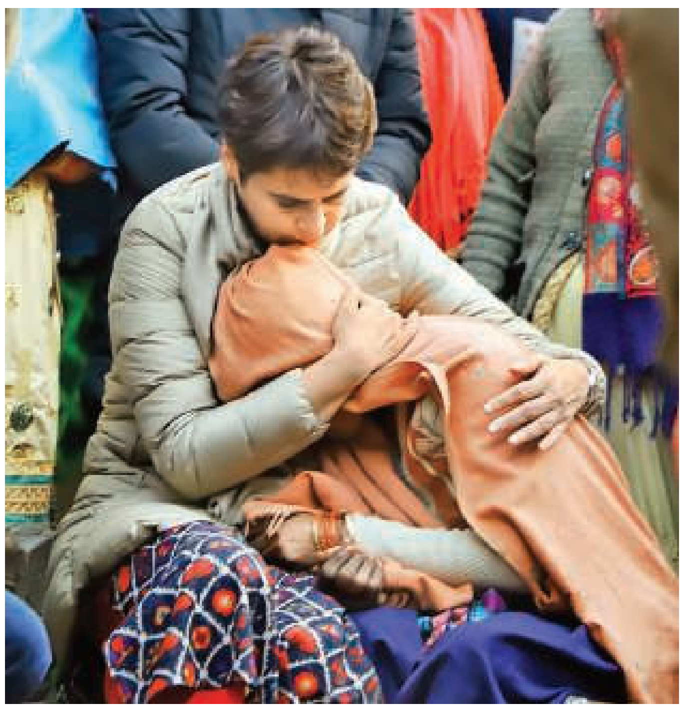

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में गोली लगने से घायल ओमराज सैनी के स्वजनों को रविवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सांत्वना दी। जागरण

एनआरसी के खिलाफ सभी मोर्चे पर आवाज बुलंद करें पर शांति से : पीके

जागरण टीम, पटना

एनआरसी पर अपने ट्वीट की वजह से लगातार चर्चा में आए जदयू नेता प्रशांत किशोर (पीके) ने रविवार को इस बारे में पुनः ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बार दो उपाय सुझाए हैं कि किस तरह से सीएए और एनआरसी को लागू किए जाने से रोका जा सकता है। प्रशांत किशोर ने पहला उपाय यह बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखें और सभी प्लेटफार्म पर अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने दूसरे उपाय की चर्चा करते हुए यह लिखा कि 16 गैर भाजपा शासित राज्य न सही पर यह सुनिश्चित हो कि इनमें से अधिकतर राज्य एनआरसी को ना कहें। प्रशांत किशोर उस समय खुलेआम अपने दल के स्टैंड के खिलाफ अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी, जब सदन के दोनों सदनों में जदयू ने सीएए का समर्थन किया। यही नहीं, कांग्रेस को भी घेरे में लेते हुए कहा था कि सीएए और एनआरसी के विरोध में हो रहे जन प्रदर्शन में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग गैरहाजिर हैं। एक समय उन्होंने एनआरसी की तुलना नोटबंदी से कर डाली थी और कहा था कि पूरे देश मे एनआरसी लागू करने की धारणा नागरिकता की नोटबंदी की तरह है।

हिंसा भड़कने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार : पात्रा

जासं, जम्मू : भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नागरिकता संशोधन कानून पर देश के विभिन्न हिस्सों में भड़की हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चाय वाला प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह अपने राजकुमार को इस कुर्सी पर बिठाने के सपने देख रही है।

नागरिकता संशोधन कानून पर समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से रविवार को जम्मू पहुंचे संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक चाय बेचने वाला अनुच्छेद 370 व 35ए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और नागरिकता संशोधन कानून जैसे बड़े-बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून में यह कोई पहला संशोधन नहीं है। इससे पहले आठ बार संशोधन हो चुका है। कांग्रेस ने वर्ष 2007 में गुजरात व राजस्थान में हिंदू शरणार्थियों को देश की नागरिकता देने के लिए संशोधन किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी से हिंदू सिखों को नागरिकता देने के लिए कानून में संशोधन करने की बात कही थी। भाजपा ने तो हिंदुओं समेत अन्य कई धर्म के शरणार्थियों को भी नागरिकता का अधिकार दिया है।

विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस का अस्पताल में घुसना चिंताजनक : आइएमए

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अस्पताल में प्रवेश संबंधी रिपोर्ट पर भारतीय चिकित्सा परिषद (आइएमए) ने चिंता जताई है। उसने इस कथित कार्रवाई को अस्वीकार्य बताते हुए अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है।

आइएमए ने एक बयान में कहा, 'चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से इन्कार की रिपोर्ट आ रही हैं। इसने आइएमए को प्रक्रिया देने पर मजबूर कर दिया है। यह अस्वीकार्य है। सभी को चिकित्सा सुविधा हासिल करने का अधिकार है।' संगठन ने कहा, 'सरकार और उसके संस्थानों का कोई हक नहीं कि वह किसी को चिकित्सा सुविधा से वंचित रखे। पुलिस द्वारा आइसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) के दरवाजे को घेरकर खड़े रहने और उसे न खोलने देने की तस्वीर नई सच्चाई और नए मानकों को उजागर करती है।'

भारत हिटलर के नाजी जर्मनी की दिशा में बढ़ रहा : महंत

▸ एजीपी नेतृत्व पर लगाया असम के लोगों से धोखा करने का आरोप

▸ कहा–नागरिकता कानून का विरोध करने पर हटाई मेरी एनएसजी सुरक्षा

गुवाहाटी, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन कानून का कड़ा विरोध करते हुए असम के पूर्व मुख्यमंत्री और एजीपी के नेता प्रफुल्ल कुमार महंत ने कहा, 'भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जैसे हिटलर का नाजी जर्मनी बढ़ा था।'

असम गण परिषद के नेता महंत ने रविवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में अपनी पार्टी के नेतृत्व का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सत्ता के लालच में मौजूदा नेताओं ने असम के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जैसे हिटलर के शासन में नाजी जर्मनी बढ़ा था।

महंत ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी एनएसजी सुरक्षा हटा ली गई है क्योंकि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री और उग्रवादियों के बीच साठगांठ हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें एनएसजी सुरक्षा हटाने की जानकारी शनिवार को ही मिली है। अक्सर राजनेताओं की सुरक्षा में बदलाव फरवरी में होता है, लेकिन यह दिसंबर है।

उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें इस कानून पर अपना रुख बदलने के लिए प्रलोभन देने, मानसिक दबाव डालने और धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन वह इस मामले में अपना रुख नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि वह हर मंच से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करना जारी रखेंगे। जबकि उनकी पार्टी ने केंद्र और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होने के नाते इस बिल का राज्यसभा में समर्थन किया था। महंत के अलावा, एजीपी के एक अन्य नेता व विधायक बृंदाबन गोस्वामी ने भी पार्टी नेतृत्व की आलोचना की।

अहमदियों को भी सीएए के दायरे में लाने का बाजवा ने किया अनुरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे अहमदिया समुदाय को भी नए नागरिकता कानून के दायरे में लाने की अपील की।

बाजवा ने रविवार को कोविंद को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया। नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बाजवा ने कहा कि सरकार को अहमदियों के लिए मानवीय कदम उठाने की जरूरत है, जिन्हें लगातार प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान से भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का 150वीं जयंती वर्ष होने के कारण, मैं आपसे इसे सरकार के ध्यान में लाने की अपील करता हूं। यह मेरी उम्मीद है कि सरकार उन लोगों की रक्षा करना जारी रखेगी, जो दबाए गए और हमारे आस-पास प्रताड़ित हो रहे हैं और इच्छा है कि आपके निर्देशों के तहत नागरिकता कानून का दायरा बढ़ाया जाए।

हिंसा खत्म कराने को आगे आएं वकील : बार कौंसिल

▸ बीसीआइ ने कहा, प्रदर्शन के दौरान पुलिस व जवानों पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं

▸ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को गंभीर विषय बताया

नई दिल्ली, प्रेट्र : बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुद्दे पर प्रर्दशन के दौरान पुलिस व सेना पर होने वाले हमलों की निंदा की है। उसने कहा है कि पुलिस व सैन्य जवानों पर हमला विधिक समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही बीसीआइ ने बार नेताओं तथा छात्रों से हिंसा को खत्म कराने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है।

बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने एक बयान में कहा, 'बार नेताओं और युवा छात्रों से आग्रह है कि वे हिंसा और व्यवधान को खत्म कराने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। हमें लोगों को बताना होगा कि उन्हें कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक लाभ के लिए बहका रहे हैं। सीएए का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए, लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'सरकारी संपत्ति को नुकसान तथा पुलिस या सेना के जवानों पर हमला गंभीर विषय है। विधिक समाज और उससे जुड़ी इकाइयों को यह कतई बर्दाश्त नहीं है। पुलिस व सैन्य जवानों के साथ बार एकजुटता से खड़ी है।'

उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन, स्टेट बार कौंसिल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ व अन्य को आगे आकर देशभर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद सुनिश्चित करनी चाहिए। यह देश में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने जनता से भी शांति बनाए रखने की अपील की है।

प्रधानमंत्री मोदी के वार से तिलमिलाई बंगाल की ममता सरकार

जागरण संवाददाता, कोलकाता : नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर कई दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बंगाल का सियासी पारा चढ़ा दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान से उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री को कठघरे में खड़ा किया तो उनके वार से पूरी ममता सरकार तिलमिला गईं। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के ठीक बाद कोलकाता में ममता सरकार के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी मोदी पर आक्रामक हो गये। पार्थ ने कहा 'ममता के साथ जनता है, इसलिए वह डरती नहीं हैं। खुद प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से भयभीत हैं। यह उनकी कमजोरी को दर्शाता है।' शाम 5 बजते-बजते ममता भी खुद को रोक नहीं सकीं और मोदी के सवालों को लक्ष्य करते हुए ट्वीट किया 'जनता तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत।' दरअसल पीएम मोदी ने नागरिकता कानून पर ममता पर निशाना साधते हुए दिल्ली की रैली में कहा 'आप किसका विरोध और किसका समर्थन कर रही हैं यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है।'

मोदी ने पिछले चार दिनों में बंगाल में ममता की रैलियों से आये उबाल पर पानी डालते हुए उन्हें सवालों से घेर दिया। उन्होंने यहां तक कहा 'ममता दीदी आप क्यों अफवाह फैला रही हैं। आपको क्या हो गया है। आप क्यों डरी हैं। बंगाल की जनता पर भरोसा करिए।' मोदी ने नागरिकता कानून और एनआरसी पर छाये धुंध को साफ करने की कोशिश तो की ही, ममता बनर्जी पर तंज कसने से भी नहीं चूके। मोदी ने कहा 'ममता दीदी नागरिकता कानून पर जनमत संग्रह कराने सीधे कोलकाता से संयुक्त राष्ट्रसंघ चली गईं, लेकिन कुछ साल पहले वह संसद में कह रही थीं कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को रोका जाए। आज वहीं नागरिकता कानून पर सवाल उठा रही हैं।'

दुखभरी दास्तां

पाकिस्तान से आए लोगों ने केंद्रीय मंत्री कटारिया को सुनाई आपबीती, कहा– धर्म परिवर्तन के लिए डाला जाता था दबाव

शव यात्रा पर मारते थे पत्थर, इसलिए छोड़ा पाक

पोपीन पंवार, यमुनानगर

हरियाणा के यमुनानगर जिले में बसे पाकिस्तान से आए 22 हिंदू परिवारों में 10 को नागरिकता मिल चुकी है। बाकी परिवार इंतजार कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून से इन्हें खुशी का आलम है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में नरक जैसे हालात थे। शव यात्रा पर पथराव होता था। धर्म परिर्वतन के लिए दबाव डाला जाता था। विरोध करने पर जेल हो जाती थी।

रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया और क्षेत्रीय भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मिले तो पाकिस्तान से आए इन लोगों का दर्द जुबान पर आ गया। नगर सुधार मंडल के पूर्व चेयरमैन लक्ष्मण दास बहल (88) बोले कि पाकिस्तान में तीन दफा जिला काउंसलर का चुनाव जीता। हर बार बहुमत मिला, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती थी। अंतिम संस्कार करने के लिए जब हिंदू के शव को श्मशान जाते थे तो शव यात्रा पर पत्थर फेंके जाते थे। धर्म परिवर्तन के लिए लंबे समय जेल में बंद रखा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। किसी तरह से परिवार के साथ यमुनानगर पहुंचे।

करोड़ों की संपत्ति हजारों में बेची : पूर्ण बहल का पाकिस्तान के कोहाट में कारोबार था। सब कुछ लूट लिया गया। बच्चों को यह भी छिपाना पड़ता था कि वे हिंदू हैं। वर्ष 1988 में जब भारत आए तो खुली हवा में सांस ली। वहां उनकी करोड़ों की संपत्ति थी, जो हजारों में बेच दी। यहां आए तो लोगों ने काफी साथ दिया। हमीदा में किराये पर मकान लिया। यहां पर भी अच्छा कारोबार है। पुराने दिनों की याद आती है तो मन घबराता है।

22 हिंदू परिवारों में 10 को नागरिकता मिल चुकी है

1988 में जब भारत आए तो खुली हवा में सांस ली। वहां उनकी करोड़ों की संपत्ति थी, जो हजारों में बेच दी।

बिना बुर्के के घर से बाहर नहीं निकल सकते

आजाद नगर में रह रहे रणजीत का कहना है कि उनके पिता दो भाई है। उनके चाचा दर्शन सिंह पहले ही यमुनानगर में आ गए थे। वे पाकिस्तान में फंस गए। परिवार की महिलाएं बुर्का पहन कर घर से बाहर निकलती थी। बिंदी भी नहीं लगा सकती थी। यदि पता चल जाए कि ये महिलाएं हिंदू हैं तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है।

ये शर्त खत्म हो

वैद्य जसबीर का कहना है कि पाकिस्तान से जब कोई हिंदू वीजा लगाता है तो उनको क्लास वन अधिकारी का आइकार्ड साथ लगाना होता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस शर्त में भी संशोधन होना चाहिए।

लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से लौटाए गए टीएमसी के नेता

जागरण संवाददाता, लखनऊ

राजधानी लखनऊ में हुई हिंसा पर राजनीति शुरू हो गई है। रविवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता हिंसा प्रभावित इलाकों का भ्रमण करने के लिए अमौसी एयरपोर्ट पहुंच गए। जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पूर्व रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी के नेतृत्व में सांसद प्रतिभा मंडल, नदीमुल हक और अधीर विश्वास फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुंचे थे।

पुलिस प्रशासन ने चारों को विमान से उतरते ही हिरासत में ले लिया। पूर्व रेल मंत्री ने बताया कि वह हुसैनाबाद में प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से हुई मोहम्मद वकील की मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। नेताओं ने प्रभावित इलाके के लोगों से मुलाकात करने की बात भी कही। हालांकि पुलिस प्रशासन ने राजधानी में 144 लागू होने और शांति व्यवस्था के मद्देनजर नेताओं को वहां जाने से रोक दिया। इस दौरान एयरपोर्ट परिसर के भीतर चारों नेताओं ने हंगामा भी किया, लेकिन उनकी एक न चली। करीब छह घंटे तक पुलिस ने परिसर के भीतर सभी को रोके रखा और रात साढ़े आठ बजे फ्लाइट से वापस भेज दिया। उधर, एयरपोर्ट के बाहर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी के नेताओं का स्वागत करने पहुंचे। पुलिस ने इन्हें बाहर ही रोक लिया। इंतजार करने के बाद सपा नेता वापस लौट गए।

78 साल बाद ताजमहल के पूरे गुंबद पर मडपैक ट्रीटमेंट की योजना बनाई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। इसके जरिये ताज के फीके पड़ रहे पत्थरों को फिर से चमकीला किया जा सकेगा। इस पर करीब 30 लाख रुपये खर्च होंगे।

न्यूज गैलरी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की एम्स में हुई स्वास्थ्य जांच

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार सुबह एम्स पहुंचे, जहां उनकी स्वास्थ्य जांच की गई। एम्स के अनुसार, वह सुबह आठ बजे नियमित जांच के लिए पहुंचे थे। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मेडिसिन, ईएनटी, कार्डियोलॉजी सहित कई विभागों के डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य जांच की। इसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एम्स का कहना है कि वह स्वस्थ हैं। (राब्यू)

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या

कांकेर : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने फिर एक निर्दोष ग्रामीण की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात उलिया ग्राम में छह वर्दीधारी हथियार बंद नक्सली रंजीत तिम्मा (24 वर्ष) को घर उठा ले गए। रंजीत पर पुलिस मित्र होने का आरोप लगाते हुए घर से कुछ ही दूरी पर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। (नईदुनिया)

छह भारतीय मछुआरों को तटरक्षक बल ने बचाया

पोरबंदर : गुजरात के पोरबंदर के करीब अरब सागर में फंसे छह भारतीय मछुआरों को तटरक्षक बल ने बचा लिया। तटरक्षक बल को शनिवार शाम आपात संदेश मिला। इसके बाद सामान्य गश्त पर सक्रिय तटरक्षक बल की नौका सी-445 को बचाव कार्य के लिए रवाना किया गया।' तटरक्षक बल की ओर से जारी बयान के अनुसार पोरबंदर से 24 नॉटिकल माइल (करीब 44 किलोमीटर) दूर अरब सागर में विस्मिता नामक नाव में पानी भर गया था। इसके कारण उसका इंजन बंद हो गया था और उसमें छह भारतीय मछुआरे फंस गए थे। तटरक्षक बल की तकनीकी टीम ने नाव के पेंदे की दरार को भरकर उसमें जमा पानी को बाहर निकाला। इसके बाद मछुआरों की नाव को सुरक्षित खींचकर रविवार की सुबह पोरबंदर बंदरगाह लाया गया। (प्रेट्र)

प्रयागराज की नैनी जेल में जमात के सदस्य की मौत

जम्मू : पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामिया के सदस्य 65 वर्षीय गुलाम मोहम्मद भट की शनिवार को प्रयागराज की जेल में मौत हो गई। उसे जम्मू-कश्मीर से वहां स्थानांतरित किया गया था। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में रहने वाले गुलाम मोहम्मद भट को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अन्य कई लोगों के साथ पांच अगस्त को हिरासत में लिया गया था। भट पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट अगले साल नौ जनवरी को खत्म होना था। भट कई बीमारियों से जूझ रहा था। उसने अंतिम सांस नैनी सेंट्रल जेल में शनिवार दोपहर बाद चार बजे ली। उसके शव को एयरलिफ्ट कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। उस पर दो केस दर्ज थे। एक साल 2016 में और दूसरा 2019 में लगाया गया था। भट की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के ट्वीटर हैंडल पर उनकी बेटी ने निंदा की और कहा कि भट पहला राजनीतिक कैदी है जिसकी राज्य के बाहर जेल में मौत हुई। (राब्यू)

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे का असर ट्रेनों और उड़ानों पर

मौसम की मार ▶ पंजाब के लुधियाना में 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान

जम्मू-कश्मीर के द्रास में माइनस 29 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान

जेएनएन, नई दिल्ली

पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। कश्मीर में भारी हिमपात के साथ कड़ाके की सर्दी का 40 दिन का दौर चिल्ले कलां दो दिन पहले शुरू हो चुका है। कश्मीर घाटी के अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। कश्मीर घाटी के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान माइनस 0.2 रहा। द्रास सबसे ठंडा चल रहा है। द्रास का न्यूनतम तापमान माइनस 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जबरदस्त ठंड का दौर जारी है। न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस के साथ पंजाब का लुधियाना सबसे सर्द रहा। फजिल्का में ठंड से एक की मौत हो गई है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में दृश्यता काफी कम रही। इसका असर ट्रेनों के संचालन और हवाई उड़ानों पर भी पड़ा।

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रविवार को जम्मू-कश्मीर के द्रास में माइनस 29 न्यूनतम तापमान रहा। वहीं श्रीनगर में ठंड से बचने के लिए अलाव ही सहारा है। एपी

दृश्यता कम होने की वजह से सड़कों पर भी यातायात बाधित रहा।

उत्तराखंड : उत्तराखंड में मौसम साफ है। इस बीच चीन सीमा तक सड़कों पर आवाजाही बहाल कर दी गई है। उत्तरकाशी जिले में सीमावर्ती क्षेत्र नेलांग और चमोली में मलारी तक सड़क से बर्फ हटा दी गई है। तापमान में सुधार के साथ शीतलहर का प्रकोप भी कम हुआ है। उत्तरकाशी जिले में भारत-चीन सीमा पर स्थित नेलांग तक सड़क से बर्फ साफ कर दी गई है। गंगोत्री से 40 किलोमीटर दूर नेलांग में आइटीबीपी की चौकियां हैं।

पंजाब : पंजाब में धुंध के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फाजिल्का में रविवार को ठंड के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली निवासी लेखराज सिविल अस्पताल के बाहर मृत हालत में मिला। रविवार को राज्य में लुधियाना सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

हरियाणा : सिरसा हरियाणा का सबसे ठंडा शहर रहा। यहां का अधिकतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करनाल, कुरुक्षेत्र और हिसार सहित कई शहर का दिन का तापमान शिमला, जम्मू और कुल्लू से भी कम रहा। शिमला व जम्मू का अधिकतम तापमान क्रमशः 13.8 और 14.1 रहा।

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में कोहरा और पाला कहर बरपाने लगा है। पाला से दलहनी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं ठंड की चपेट में आने से कौशांबी जिले में चार लोगों मौत होने की खबर है। लखनऊ में सुबह में कोहरा छाया रहा। तराई इलाकों में पाला भी पड़ने से दलहनी व तिलहनी फसलों पर असर दिखने लगा है।

बंगाल : कोलकाता में तापमान का पारा गिरने का सिलसिला जारी रहा है। रविवार को मौसम विभाग के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जो सामान्य से चार डिग्री कम है। हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और प. मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया आदि जिले में तापमान 10 के आसपास है।

हिमाचल : हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है, वहीं मैदानी इलाकों में दो से तीन डिग्री तक पारा गिरा है।

बिहार में दारोगा लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल चार अभ्यर्थी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना

▶ जमुई, नवादा और आरा के एक-एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा

▶ दूसरी पाली की परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) की रविवार को हुई दारोगा लिखित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नपत्र दिनभर वाट्सएप पर वायरल रहे। प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर आरा में अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर हंगामा किया। नवादा और आरा के दो केंद्रों से चार अभ्यर्थी गिरफ्तार भी किए गए हैं।

आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी अशोक प्रसाद ने बताया कि पहली पाली में जमुई, नवादा और आरा के एक-एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना किसी भी जिले से प्राप्त नहीं हुई है। आरा में एक केंद्र पर अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट वितरण होने के बाद लीक होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। इसी दौरान कुछ अभ्यर्थी प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट लेकर केंद्र से बाहर भी चले गए। यहां से प्रश्न पत्र वायरल होने की संभावना है।

दूसरी पाली की परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नवादा और आरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर विभिन्न कारणों को लेकर आरा से दो और नवादा से दो अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए 5.80 लाख अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। 35 जिलों के 495 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी।

10 से 50 हजार रुपये तक लगती रही बोली

प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद दूसरी पाली के अभ्यर्थियों को झांसे में लेने के लिए दलाल सक्रिय रहे। अभ्यर्थियों ने बताया कि अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर पर प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी के साथ आंसर भी उपलब्ध कराने के ऑफर दिए जा रहे थे। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र और आंसर-की के लिए 10 से 50 हजार रुपये तक की मांग की जाती रही। प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से बाहर लाने की अनुमति नहीं थी। अभ्यर्थियों को परीक्षा संपन्न होने के बाद ओएमआर शीट के साथ प्रश्न पत्र भी वीक्षक को सौंप देना था। दिलीप कुमार सहित कई अभ्यर्थियों ने बताया कि वायरल प्रश्न पत्र से पहली पाली की परीक्षा का मूल प्रश्न पत्र हूबहू मिल रहा था।

पूर्व मुखिया की हत्या पर भीड़ ने एक आरोपित को मार डाला

जासं, मधुबनी : बिहार में मधुबनी के मढ़िया गांव में रविवार को बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व मुखिया की गोली मार हत्या कर दी। इससे आक्रोशित भीड़ ने घटना में शामिल एक हत्यारोपित को भी पीटकर मार डाला। पुलिस पहुंची तो उसे भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पूर्व मुखिया की हत्या में आठ लोगों को आरोपित किया गया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी थी। मढ़िया पंचायत के पूर्व मुखिया पवन कुमार यादव (50) गांव में हुए आपसी विवाद को सुलझाने बछराजा नदी स्थित बजरंग चौक पर सुबह 9 बजे गए थे। पंचायत के दौरान दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पूर्व मुखिया की कमर व सिर में चार गोलियां लगीं। वह वहीं पर गिर पड़े। लोग उन्हें वाहन से जयनगर अस्पताल ले जाने लगे। लेकिन, रास्ते में मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने बाइक सवार अपराधियों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़ लिया गया। उसे चौक पर लाकर उग्र भीड़ ने कर मार डाला। पूर्व मुखिया को छह माह पूर्व भी गोली मारी गई थी। लेकिन, बच गए थे।

कार गहरी खाई में गिरी, पांच दोस्तों की मौत

राज सिंगला, रायपुररानी (पंचकूला)

▶ शनिवार शाम को कार में रायपुररानी से चले थे सभी

▶ ये लोग हिमाचल प्रदेश में शिमला व कुफरी घूमने जा रहे थे

कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेटघराट के पड़ोथा में एक कार के 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार सवार रायपुररानी निवासी पांच दोस्तों की मौत हो गई। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सभी शिमला व कुफरी घूमने जा रहे थे।

रविवार सुबह घास काटने के लिए जा रहे स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस टीम ने खाई से शवों को बाहर निकालकर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया। दो शव कार में इस तरह से फंस गए थे कि उसे कटर से काटकर शव बाहर निकालने पड़े। पुलिस की ओर से परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। मृतकों की पहचान गांव मीरपुर निवासी हुस्नपाल गुर्जर (42), महावीर कुमार (25), विपुल शर्मा (24), सचिन धीमान (23) और राहुल खान (22) निवासी गढ़ी कोटाहा के तौर पर हुई।

बर्फबारी देखने जा रहे थे सभी : परिजनों ने बताया कि पांचों दोस्त शिमला में हो रही बर्फबारी देखने शनिवार शाम करीब पांच बजे कार से रवाना हुए थे। हुस्नपाल, विपुल और सचिन रायपुररानी मार्केट कमेटी कार्यालय में कार्यरत थे।

कांट्रैक्ट पर कार्यरत थे महावीर और विपुल, जल्द होनी थी शादी : महावीर कुमार कांट्रैक्ट बेस पर कार्यरत था और तीन बहनों का इकलौता भाई था। नवंबर में दूसरी बहन की शादी के बाद अब परिजन महावीर की शादी की तैयारी में थे। विपुल शर्मा भी कांट्रैक्ट बेस पर कार्यरत अपने चार भाई बहनों में सबसे बड़ा था और उसकी फरवरी, 2020 में शादी होनी थी। विपुल के पिता मनोज की भी लगभग दो वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी।

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में विलाप करते कंडाघाट कार हादसे में मृतकों के परिजन। जागरण

बीटेक का छात्र था सचिन

सचिन धीमान एसआरएम कॉलेज में बीटेक का छात्र था। परिजनों ने बताया कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसी घटना हो जाएगी। राहुल खान के पिता बाबू खान मोरनी सब तहसील में रीडर पद पर कार्यरत हैं। बेटे की कोचिंग को लेकर कुछ ही दिन पहले पंचकूला स्थित सरकारी मकान में शिफ्ट हुए थे। परिजनों ने बताया कि शनिवार को गांव गढ़ी कोटाहा आए थे व राहुल अपने दोस्तों के साथ शिमला जाने के लिए निकला था। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था।

कालका-शिमला एनएच पर कार खाई में गिरी है जिसमें पांच युवकों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
डॉ. शिव कुमार, एएसपी सोलन।

जश्न के माहौल में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर रेड अलर्ट

संवाद सूत्र, रायवाला : क्रिसमस और नए साल के जश्न के माहौल में बेजुबान महफूज रहें, इसे देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जंगलों से सटे वन विश्राम गृह, होटल, रिसॉर्ट के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में खास चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। सैलानियों के लिए भी गाइड लाइन जारी की गई है।

इस दरम्यान सैलानियों की आड़ में तस्कर व शिकारियों के भी वन क्षेत्रों में घुसने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्याय में रखते हुए वन महकमे ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पार्क निदेशक ने साफ तौर पर कहा है कि वन एवं वन्यजीव सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद कर दी गई हैं। विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी मिल पाएगी। वन विश्राम गृह और वन सीमा से सटे होटल-रिसॉर्ट पर विशेष निगरानी रहेगी।

सैलानियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि जंगल व आसपास स्थित होटल व रिसॉर्ट में तेज आवाज में संगीत नहीं बजेगा और न तेज रोशनी होगी।

पुंछ में पाकिस्तान की भारी गोलाबारी नौशहरा में मिला करारा जवाब

जागरण संवाददाता, राजौरी : करारा जवाब मिलने के बाद भी पाकिस्तानी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। उसने पुंछ जिले के मेंढर और कृष्णा घाटी सेक्टर में शनिवार देर रात और रविवार दोपहर तक भारी गोलाबारी की। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भी गोले बरसाए। इसमें एक महिला घायल हो गई। यहां भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गईं।

पाकिस्तानी सेना की तरफ से मेंढर व कृष्णा घाटी सेक्टर में शनिवार रात्रि से रविवार दोपहर 12 बजे तक रुक-रुक कर गोलाबारी जारी रही। दोपहर बाद नौशहरा सेक्टर में सीमा पार से गोलाबारी शुरू हो गई। पाक सेना ने सेना की अग्रिम चौकियों के साथ रिहायशी क्षेत्रों को भी निशाना बना मोर्टार दागे। एक महिला नीना देवी पत्नी देव राज निवासी मकडी नौशहरा घायल हो गई। उसे तुरंत नौशहरा अस्पताल ले जाया गया। सीमांत क्षेत्रों में लोग दहशत में हैं। रात तक गोलाबारी जारी थी। भारतीय सेना के अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं।

गौरतलब है कि शनिवार को भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में जम्मू के प्लांवाला सेक्टर में दो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे।

किश्तवाड़ में पुलिस पोस्ट पर आतंकी हमला, दो घायल

जागरण संवाददाता, किश्तवाड़ (जम्मू)

किश्तवाड़ शहर में राज्य पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की पोस्ट पर रविवार देर रात आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस, सीआइएसएफ और सेना के जवानों ने पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि हमला हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अमीन बट उर्फ जहांगीर सरूरी व उसके साथियों ने किया है। सरूरी पर पुलिस ने 30 लाख का इनाम घोषित कर रखा है।

जानकारी के अनुसार शहर से सटी एनएचपीसी की सिमना कॉलोनी के साथ सीआइएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) का हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही एसओजी की पोस्ट है, जहां दर्जनभर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। रात करीब साढ़े दस बजे पोस्ट पर अंधाधुध फायरिंग शुरू हो गई। उस समय मौसम भी खराब था। पोस्ट पर मुस्तैद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनकी पहचान मोहम्मद सलीम और अजय कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि तीन से चार आतंकियों ने पोस्ट को घेरकर फायरिंग की, ताकि कोई बच न पाए। पोस्ट से जवाबी कार्रवाई होते ही आतंकी कोहरे की आड़ में भाग निकले। कुछ दूरी पर राइफल लेकर दौड़ रहे आतंकियों को देख एक कांग्रेस नेता के अंगरक्षक ने भी फायरिंग की। ये अंगरक्षक नेता के घर के बाहर तैनात था। इसके बाद तीन से चार आतंकी ओझल हो गए।

सुरक्षाबलों के काफिले को उड़ाने की साजिश नाकाम

राज्य ब्यूरो, जम्मू : सुरक्षाबलों ने रविवार को बारामुला-उड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैन्य वाहन उड़ाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। राजमार्ग पर लगाई गई 13 किलो की आईईडी का समय रहते पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आईईडी इतनी शक्तिशाली थी कि विस्फोट होने पर दूसरा पुलवामा हो सकता था।

अमिताभ की तबीयत खराब, राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में नहीं हो पाएंगे शामिल

मुंबई, प्रेट्र : सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब हो गई है। इसके कारण वह राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जहां उन्हें वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाना है। पुरस्कार समारोह का आयोजन सोमवार को नई दिल्ली में किया जाएगा।

77 वर्षीय अभिनेता ने रविवार को ट्वीट किया, 'मुझे बुखार है... यात्रा की अनुमति नहीं है... दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा।' दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल, एक शॉल और 10 लाख रुपये नकद प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2017 में यह पुरस्कार दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को दिया गया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विजेताओं को सोमवार को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहेंगे। परंपरागत रूप से विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाद में विजेताओं के लिए चाय पार्टी का आयोजन करेंगे।

घोटाले में जेल गए सीआरपीएफ के अधिकारी पर अब आय से अधिक संपत्ति की प्राथमिकी

राज्य ब्यूरो, रांची

▶ सीआरपीएफ के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके हैं संतोष कुमार

▶ करीब 20 लाख रुपये के घोटाले का भी है आरोप

▶ सीबीआइ की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज की प्राथमिकी

▶ आय से 54.12 लाख रुपये अधिक होने के मिले सुबूत

▶ मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के बरौनी के निवासी हैं संतोष कुमार

सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सीआरपीएफ मुख्यालय, रांची के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट संतोष कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज की है। संतोष कुमार करीब 20 लाख रुपये के घोटाले में दो माह पहले ही रांची पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। वे वर्तमान में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं। उनपर सीआरपीएफ के आइजी कार्यालय में रहने के दौरान घोटाले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब एक नई प्राथमिकी हुई है, जिसे सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज की है। सीबीआइ की प्राथमिकी में संतोष कुमार पर आय से 54 लाख 12 हजार 37 रुपये अधिक होने का आरोप है।

संतोष कुमार सीआरपीएफ मुख्यालय, रांची में निजी सचिव के पद पर एक अप्रैल 2013 से 31 अगस्त 2019 तक पदस्थापित थे। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला इसी अवधि का है। वह रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित क्वार्टर नंबर सीडी 714 में रहते थे। वे मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी थाना क्षेत्र स्थित बिहट गांव के रहने वाले हैं। रांची में सीआरपीएफ के आइजी कार्यालय से इनका स्थानांतरण असम के जोरहट स्थित सीआरपीएफ के आइजी कार्यालय में हुआ था। इसी बीच उनपर जब घोटाले की पुष्टि हुई, तो उन्हें रांची बुलाया गया और रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सीबीआइ ने दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि संतोष कुमार ने एक अप्रैल 2013 से 31 अगस्त 2019 तक कुल एक करोड़ 3 लाख 18 हजार 288 रुपये कमाए। इस अवधि में उन्होंने एक करोड़ 57 लाख 30 हजार 425 खर्च किया। इस प्रकार उन्होंने आय थे 54 लाख 12 हजार 37 रुपये अधिक खर्च किए हैं। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार असिस्टेंट कमांडेंट संतोष कुमार ने आकलन अवधि एक अप्रैल 2013 से 31 अगस्त 2019 तक 93 लाख 28 हजार 405 रुपये घरेलू काम पर खर्च किए और 64 लाख, 02 हजार 20 रुपये की चल-अचल संपत्ति बनाई। सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कांड के जांच अधिकारी सीबीआइ की एसीबी के इंस्पेक्टर राजेश कुमार बनाए गए हैं।

लापरवाही

गिरिडीह जेल में बंद दीपू पर बारूदी सुरंग लगाने का केस

पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, लेवी के लिए वाहन जलाने के मुकदमे में जुलाई से है जेल में, सितंबर में पुलिया के नीचे केन बम रखने की दर्ज करा दी गई प्राथमिकी

अश्विनी रघुवंशी, धनबाद

गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड के मडरो गांव का दीपू सिंह पुलिस के रिकार्ड में भाकपा माओवादी का हथियारबंद कैडर है। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के चिरकी गांव में लेवी के लिए ठेकेदार की गाड़ी जलाने के मामले में उसने जुलाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। तबसे दीपू सिंह गिरिडीह जेल में बंद है।

इसी बीच सितंबर में धनबाद जिले के मनियाडीह थाना क्षेत्र के नेमोरी में पुलिस ने नक्सलियों द्वारा पुलिया के नीचे लगाया गया बम बरामद किया। इस मामले में भी पुलिस ने दीपू सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा कर दिया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि दीपू ने भाकपा माओवादी के कुछ और उग्रवादियों के साथ मिल कर नेमोरी स्कूल के सामने पुलिया के नीचे केन बम रखा था। मामले का खुलासा होने के बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

बताया जाता है कि चिरकी पलमा रोड में लेवी के लिए ठेकेदार की गाड़ी जलाने का मुकदमा होने के बाद दीपू सिंह फरार हो गया था। पुलिस ने दबिश दी और मडरो गांव में जाकर उसके घर में कुर्की जब्ती भी की। परिजनों पर पुलिस का दबाव बढ़ा तो दीपू ने गिरिडीह न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। 26 जुलाई को वह गिरिडीह जेल में सीखचों के पीछे जा चुका था। इसी बीच धनबाद जिला में 25 सितंबर को मनियाडीह थाना में चिरकी हरलाडीह पक्की सड़क के नीचे पुलिया के नीचे केन बम मिला। गोपनीय सूचना के आधार पर मनियाडीह के दारोगा भैया संजय कुमार नाथ शाह ने खुद प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर अजय महतो उर्फ टाइगर उर्फ अजय दा, सब जोनल कमांडर नुनूचंद उर्फ नुनूचांद महतो, कृष्णा हांसदा उर्फ कृष्णा मरांडी, श्याम माझी, जंगल दा, बजरंगी, कार्तिक महतो एवं दीपक सिंह उर्फ दीपू ने सात आठ हथियारबंद कैडरों के साथ पुलिया के नीचे बारुदी सुरंग लगाया, ताकि पुलिस बल को क्षति पहुंचाई जा सके।

दीपू माओवादी नहीं, पुलिस ने फंसाया : कालिका : दीपू के पिता कालिका प्रसाद सिंह कहते हैं कि दीपू माओवादी नहीं है। हम लोग मडरो के जमींदार हैं। दूसरों को अपनी जमीन दी है। हां, यह सच जरूर है कि कुछ वक्त पहले तक हरलाडीह हाई स्कूल में माओवादी मीटिंग में बुलाते थे तो दीपू वहां जाता था। सिर्फ वही नहीं, इस गांव के कई लोग जाते थे। डर से जाना पड़ता था। धान की मेढ़ाई कर रहे कालिका बोले कि माओवादी खुलेआम हथियार के साथ घूमते थे। कैसे कोई उनकी बात की अनदेखी कर सकता था। दीपू के दोनों पांव टूटे हुए हैं। लंगड़ा कर चलता है। चिरकी का केस भी गलत था। बूढ़े पिता बोले कि इस उमर में कोर्ट कचहरी करना कितना मुश्किल है, कह नहीं सकता।

दीपू सिंह अपनी पत्नी जनता देवी के साथ। फाइल

जुलाई से दीपू सिंह गिरिडीह जेल में है। पुलिस ने मनियाडीह में बारूदी सुरंग लगाने का उस पर कैसे केस कर दिया, कह नहीं सकता।
कोलेश्वर पासवान, जेलर, गिरिडीह जेल

जेल में बंद दीपू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की जांच की जाएगी। अगर किसी ने गलत किया है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।
किशोर कौशल, वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद

जेल से रिहा हुआ ब्लैकमेलिंग का आरोपित विक्रम सिंह

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग का आरोपित विक्रम सिंह रविवार को जमानत पर जेल से रिहा हो गया। उसकी जमानत पहले ही मंजूर हो गई थी। रिहाई का परवाना शनिवार देर शाम पहुंचने के कारण उस वक्त रिहा नहीं किया जा सका। रविवार सुबह सवा आठ बजे वह जेल से बाहर निकल आया। पिछले दिनों हाईकोर्ट से ब्लैकमेलिंग के आरोपित विक्रम सिंह व सचिन सेंगर की जमानत याचिका मंजूर हुई थी। बीस सितंबर को चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के आरोप में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

एक दो दिन में रिहा होगा सचिन : ब्लैकमेलिंग के अन्य दो आरोपितों में सचिन सेंगर की जमानत भी मंजूर हो चुकी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विक्रम की तरह उसकी भी एक-एक लाख रुपये की दो-दो जमानतें तय करते हुए जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट गाजियाबाद से शनिवार तक नहीं पहुंच सकी थी, इसलिए उसका परवाना जारी नहीं हुआ। माना जा रहा है कि एक से दो दिन में वह भी ब ाहर आ सकता है। वहीं संजय सिंह की जमानत याचिका पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

चिन्मयानंद प्रकरण

▶ देर से परवाना मिलने के कारण शनिवार रात नहीं हो सकी थी विक्रम की रिहाई

चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के आरोपित विक्रम सिंह को कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया है। दूसरे आरोपित का जब परवाना आएगा तब उसे भी छोड़ दिया जाएगा।
-राकेश कुमार, जेल अधीक्षक, शाहजहांपुर।

दैनिक जागरण

ध्यान की दौलत से कार्य करने की क्षमता अपने आप बढ़ती है

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष नई समस्या

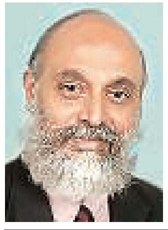

सी उदयभास्कर

सीएए विरोधी प्रदर्शनों से सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार के इस कानून से भारत का पहले से ही जटिल आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य और पेचीदा हो जाएगा

नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन और उस पर पुलिस की सख्ती के चलते करीब 25 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों घायल भी हुए। कई अशांत इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अशांत रहा। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस ने अनावश्यक सख्ती बरती। इससे आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बहुत प्रभावित हुई है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन करना आम नागरिकों का बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है।

इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में पुलिस ने जो बलपूर्वक कार्रवाई की वह मीडिया और आम नागरिकों के कैमरे में भी दर्ज हुई। यह सरकार के बेहद सख्त रवैये को दर्शाने वाली है। बेंगलुरु में महात्मा गांधी के नामचीन जीवनीकार रामचंद्र गुहा की गिरफ्तारी वाली तस्वीर भी सवाल उठाने वाली है। सीएए और उससे जुड़ी कवायद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस यानी एनआरसी को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन ने देश का एक अलग चरित्र प्रदर्शित किया है। हालांकि एनआरसी को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है और प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री बार-बार इसे लेकर आश्वस्त कर रहे हैं। फिर भी सीएए-एनआरसी के राजनीतिक निहितार्थ खासे जटिल हैं। फिलहाल आठ राज्य सीएए और एनआरसी की जुगलबंदी को लेकर अपनी असहजता जाहिर कर चुके हैं। इनमें वह बिहार भी शामिल है जहां भाजपानीत राजग के सहयोगी जदयू के नेतृत्व में गठबंधन सरकार है। वहीं असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में 'बाहरियों' को लेकर और भी ज्यादा जटिल चिंताएं हैं। इन चिंताओं की कड़ियां अगस्त 1947 में भारत विभाजन और फिर 1971 में बांग्लादेश के उदय के वक्त से जुड़ती प्रतीत होती हैं।

यहां यह भी याद दिला दें कि हालिया विरोध प्रदर्शन की लपटें सबसे पहले असम में 11 दिसंबर को तब सुलगीं जब नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कैब राज्यसभा से पारित हुआ। तब कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना की तीन टुकड़ियां तैनात की गईं। इनमें दो असम और एक त्रिपुरा में लगाई गई। हालांकि सेना की यह तैनाती बहुत संक्षिप्त अवधि के लिए हुई और जल्द ही कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को सौंप दी गई। भाजपा और सरकार से जुड़े कुछ लोगों ने भी विरोध प्रदर्शनों के बारे में अनावश्यक टिप्पणियां कर स्थिति बिगाड़ने का काम किया। इसी सिलसिले में मोदी सरकार के एक मंत्री ने कहा, 'हमें जिहादियों, माओवादियों और अलगाववादियों को लेकर चौकस रहना होगा जो छात्रों के विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं।' ऐसी बातों के भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सुरक्षा पेशेवर अक्सर ऐसी चुनौती को कम तीव्रता संघर्ष वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में देखते हैं। भारत जनवरी 1990 से ही इस चुनौती से जूझ रहा है जब पाकिस्तान की शह पर भारत के खिलाफ कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों का उभार हुआ था। भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियां दो श्रेणियों में देखी जाती रही हैं। एक तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, जिसकी जड़ें पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में बेहद गहरी थीं। या फिर मुंबई में हुए वीभत्स आतंकी हमले को इसमें गिना जा सकता है। दूसरी चुनौती माओवादी-नक्सलवाद यानी वामपंथी चरमपंथ से जुड़ी है जिसने एक लाल गलियारा चिन्हित किया था जो अब छत्तीसगढ़ के एक छोटे इलाके तक सीमित रह गया है।

अवधेश राजपूत

बीते कई दशकों में भारतीय सुरक्षा तंत्र को तमाम जटिल आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझना पड़ा। ये चुनौतियां अक्सर अवसरवादी राजनीतिक गतिविधियों या कुछ दुस्साहसिक कवायदों से उत्पन्न हुईं। इनमें सबसे कुख्यात खालिस्तान आंदोलन रहा। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शन अतीत के ऐसे अनुभवों से इतर हैं। उन्हें दबाने के लिए वैसी सरकारी कड़ी कार्रवाई की दरकार नहीं जैसी हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। ऐसे में सीएए विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए एक सवाल यही उठता है कि क्या मोदी सरकार के इस कानून से भारत का पहले से ही जटिल आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य और पेचीदा हो जाएगा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के दो अहम पहलुओं को मूर्त रूप दिया है। इसमें एक तो 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के रूप में और दूसरा 11 दिसंबर को सीएए के तौर पर किया गया। ऐसी कवायदों में मुस्लिमों को 'अलग नजरिये' से देखने की मंशा को लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले 'अल्पसंख्यक' समुदाय द्वारा ही नहीं, बल्कि संविधान में विश्वास रखने वाले सभी भारतीयों द्वारा महसूस किया जा रहा है।

कश्मीर में अब कड़वाहट और तल्खी के साथ ठहराव साफ महसूस होता है। वहां पिछले 140 से भी अधिक दिनों से इंटरनेट बंद है। अधिकांश सुरक्षा विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि आने वाली गर्मियां कश्मीर में काफी अशांत हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों में अगर मोदी सरकार ने नागरिकों की चिंताएं दूर करने के लिए सहानुभूति के साथ राजनीतिक संपर्क नहीं साधा तो देश का सामाजिक तानाबाना अस्थिर हो जाएगा। वहीं सीएए समर्थक और हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोग खतरनाक बयान देकर माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। कुछ नेता गोधरा कांड की याद दिला रहे हैं तो दिल्ली में भाजपा के एक स्थानीय नेता सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के लिए 'गोली मारो गद्दारों को' सरीखे आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस पर आरोप हैं कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल की। ऐसे में विभिन्न धर्मों के आक्रोशित नागरिक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार राजनीतिक मंशा के साथ सोचे-समझे दमन पर आमादा हो गई है।

आंतरिक सुरक्षा बहुत नाजुक और अस्थिर मुद्दा है। इसमें भारत के अनुभव भी बहुत दर्दनाक रहे हैं। इनकी शुरुआत भारत विभाजन के साथ ही हो गई थी जब हिंदू-मुस्लिम विभाजन की खाई भयावह मानवीय त्रासदी बनी। फिर 1984 में सिख विरोधी दंगे, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुई सिलसिलेवार हिंसा और 2002 के गुजरात दंगे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा एजेंसियों की कमान संभालने वालों के मुंह पर कालिख हैं।

इस प्रकार देखें तो कोई भी जिम्मेदार एवं नैतिक राजव्यवस्था ऐसे अनुभवों से सही सबक लेकर नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, भले ही उनके विचार कितने भी विरोधी क्यों न हों। संविधान की यही भावना है। उम्मीद है कि आगामी 26 जनवरी को इन भावनाओं का उत्साहपूर्वक उत्सव मनाया जाएगा।

(लेखक सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

प्रधानमंत्री का संदेश

यह समय की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता कानून और साथ ही प्रस्तावित नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर अपनी बात कहने के लिए आगे आते। दिल्ली की एक रैली में उन्होंने यही किया। उन्होंने न केवल नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का निवारण किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि जिस एनआरसी को लेकर देश भर में अफवाहों का बाजार गर्म कर लोगों को भड़काया जा रहा है उसकी तो अभी प्रक्रिया ही तय की जानी शेष है। इसमें संदेह है जिन लोगों और खासकर विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का मकसद ही लोगों को बरगलाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है उनके रुख-रवैये में कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन आम जनता को तो यह समझना ही होगा कि हकीकत क्या है? इस क्रम में उसे यह भी जानना होगा कि आज जो कांग्रेस नागरिकता कानून के साथ-साथ प्रस्तावित एनआरसी का मुखर होकर विरोध कर रही है उसके शासनकाल में ही मतदाता पहचान पत्र, पैन, आधार कार्ड आदि जारी किए गए। एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया के हर जिम्मेदार देश ने अपने नागरिकों का रजिस्टर तैयार किया है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन हो, इसकी जरूरत नागरिकता कानून में दर्ज है और इसी कारण 1951 में पहली एनआरसी तैयार की गई। क्या अब यह काम महज इसलिए नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अंधविरोध से ग्रस्त होकर या फिर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लालच में अफवाहें फैलाने में जुट गए हैं?

नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध में बिना ज्यादा कुछ सोचे-समझे सड़कों पर उतरने वालों को प्रधानमंत्री की इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या उनकी सरकार की रसोई गैस, आवास, बिजली संबंधी किसी योजना में जाति, मजहब के आधार पर भेदभाव किया गया है? यदि अभी तक ऐसा कोई आरोप विरोधी दल भी नहीं लगा सके हैं तो इसका यही मतलब है कि नागरिकता कानून के बहाने मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने का एक सुनियोजित अभियान छेड़ा गया। क्या यह किसी से छिपा है कि इस अभियान को किस तरह किस्म-किस्म के दुष्प्रचार के जरिये आगे बढ़ाया जा रहा है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि दुष्प्रचार में लिप्त इन राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक तत्वों को प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया। उन्हें इसकी तह में भी जाना होगा कि आखिर ऐसे तत्व किन कारणों से अपने इरादे में एक बड़ी हद तक सफल हो गए। यह अभियान इतना शातिर है कि जहां धरना-प्रदर्शन अराजकता से बच जा रहा है वहां तो भीड़ को श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन जहां आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है वहां सारा दोष पुलिस के सिर पर मढ़ दिया जा रहा है।

तकनीक का दुरुपयोग

तकनीक के इस युग में हर सुविधा लोगों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध होने से जिंदगी आसान हो गई है। पैसे का लेनदेन हो या कोई खरीदारी करनी हो तो मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यह स्थिति तभी सुखद है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह घातक साबित होता है। साइबर ठग तकनीक का दुरुपयोग लोगों को प्रलोभन देकर ठगने में कर रहे हैं। लोगों के खून-पसीने की कमाई को पल में हड़पा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भी साइबर ठगों के जाल में उलझता जा रहा है। कई बार एटीएम का पिन पूछने व कई बार बैंक अधिकारी का नाम लेकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लग चुकी है। प्रदेश में लोगों के साथ ठगी के मामलों की निरंतरता बताती है कि लोग चेतना खो चुके हैं। बार-बार ठगे जाने पर हायतौबा जरूर मचाई जाती है, चिंता जताई जाती है, लेकिन जागरूक बनने के प्रयास नहीं किए जाते। किरदार बदल जाते हैं, लेकिन साइबर ठगी की कहानी एक जैसी ही होती है। इन मामलों से सबक सीखने के लिए कोई भी तैयार नहीं दिखता। प्रदेश के हर हिस्से से ठगी के मामले सामने आने से साबित हो जाता है कि ठगों का नेटवर्क अपनी पकड़ मजबूत बना चुका है और लोगों की मानसिकता को अच्छी तरह से समझता है। सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए, क्योंकि लुटने वाले स्वयं तैयार बैठे दिखते हैं। हिमाचल की साइबर पुलिस ने भी कई मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल की है। इसी जांच में सामने आया है कि लोगों को ठगने के दौरान साइबर अपराधी जन-धन खातों का उपयोग कर रहे हैं। यह इतने शातिर हैं कि लोगों के खाते कुछ पैसे देकर किराये पर ले रखे हैं, जिससे ठगी के पैसे इनमें ट्रांसफर कर सकें। हैरानी इस बात की है कि आम लोगों के साथ बड़े अधिकारी भी इनके जाल से नहीं बच पा रहे हैं। साइबर पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए लोगों को जागना होगा। जब तक लोग ऐसे ठगों को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक पुलिस भी मदद नहीं कर सकती है। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बेहतर है कि पहले ईमेल करने वाले या फोन करने वाले की पहचान कर ली जाए।

साइबर ठगी के बढ़ते मामले तकनीक के दुरुपयोग का साक्षात उदाहरण हैं। लोगों को सतर्क रहकर ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए

चरण सिंह की कमी महसूस करते किसान

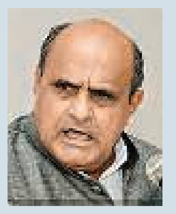

केसी त्यागी

उनके प्रयासों से ही आढ़तियों का दबदबा कम हुआ और किसानों के लिए नाबार्ड जैसी संस्था की राह बन सकी

डॉ. आंबेडकर, सरदार पटेल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तीसरे ऐसे महापुरुष हैं जिनके विचारों को उनके जीवनकाल में उतनी स्वीकार्यता और प्रसिद्धी नहीं मिली जितनी उनके निधन के बाद। आज चरण सिंह की जयंती है जिनकी स्मृति में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। एक ऐसे दौर में जब देश में किसान और कृषि क्षेत्र तमाम समस्याओं से जूझ रहा है तब जमीन से जुड़े ऐसे नेता का स्मरण और व्यवस्था में उनके योगदान को याद करना बहुत जरूरी लगता है। आज की ग्रामीण बदहाली, उपेक्षा, किसानों की आत्महत्याएं, गांवों से शहर की ओर बढ़ता पलायन, गांव-शहर के बीच बढ़ती आर्थिक-सामाजिक विषमताएं आदि विषय उनकी राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता को जीवित बनाए हुए हैं। देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसान आक्रोश का केंद्र बिंदु बने आंदोलन उनका जिक्र किए बगैर अधूरे ही रहते हैं। एक समय जब बड़े-बड़े दिग्गज पंडित नेहरू से वाद-विवाद करने से कतराते थे, उस समय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने पंडित नेहरू की नीतियों पर कटु प्रहार किया और सहकारी कृषि के विषयों को लेकर अपने भाषण में अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तालियां भी बटोरीं। उस समय नेहरू कांग्रेस पार्टी के पर्याय और कांग्रेस के वैचारिक सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते थे। कांग्रेस के भीतर उनके वैचारिक तिलिस्म को तोड़ने का यह पहला प्रयास था, जिसकी कीमत उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर होकर चुकानी पड़ी थी। आजादी के बाद कांग्रेसी सरकारों के समक्ष अपने घोषणापत्रों को अमल में लाने की भी नैतिक जिम्मेदारी हुआ करती थी। अधिकांश कार्यक्रम आजादी के आंदोलन के दौरान स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए गए संकल्प थे जिनमें भूमि सुधार एक मुख्य कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश में उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे और चौ. चरण सिंह उनके राजस्व मंत्री थे। ग्रामीण आर्थिक नीति-निर्माताओं का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसा भूमि सुधार किसी भी राज्य में संभव नहीं हो पाया। वामपंथी और समाजवादी आंदोलन के इस नारे 'जो जमीन को जोते-बोये वो जमीन का मालिक है' का क्रियान्वयन करने का दायित्व भी उन्होंने निभाया।

डॉ. लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गैर कांग्रेसवाद की जिस राजनीति की पटकथा तैयार कर रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश में परवान चढ़ाने का काम भी चौधरी साहब के जरिये ही संभव हो सका। वह उत्तर प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उनकी गिनती आज भी सबसे प्रभावी, कुशल प्रशासक और ईमानदार राजनेता के रूप में होती है। 1974 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के विरोध में एक प्रभावी विकल्प के निर्माण की दिशा में एक नए दल की रचना की जिसमें भारतीय क्रांति दल के साथ-साथ समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, स्वतंत्र पार्टी जैसे महत्वपूर्ण दल शामिल हुए। बाद में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान आपातकाल के बाद यही दल जनता पार्टी के गठन की बुनियाद भी बना। चौधरी साहब के राजनीति में प्रभावी दखल से पहले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी कोई व्यवस्था अमल में नहीं थी। केंद्र सरकार मनमाने तरीके से किसानों की फसलों के दाम घोषित किया करती थी। उनके कार्यकाल में आढ़तियों की भूमिका पर अंकुश लगा और किसानों की सहमति भी आवश्यक बनाई गई। वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने नाबार्ड की व्यवस्था की जिससे किसानों को कर्ज मिलने की प्रक्रिया आसान हुई और सूदखोरों पर लगाम लगी।

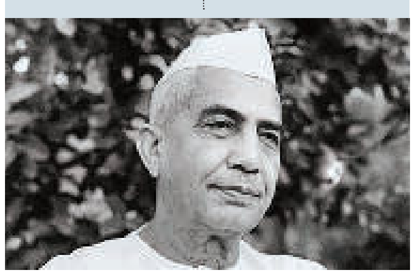

राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रवेश देरी से हुआ जिसका एक बड़ा कारण उस समय के कांग्रेस पार्टी के स्थापित नेतृत्व से लगातार वैचारिक मतभेद भी रहा। उन्होंने राजनीति के विमर्श, नारों को बदला, प्राथमिकताओं की अदला-बदली पर जोर दिया और डॉ. आंबेडकर के बाद किसानों तथा पिछड़ों की राजकाज में हिस्सेदारी से जुड़े सवाल उठाया। 1937 में ही उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय सम्मेलन में पहली बार किसानों के लिए 50 फीसद आरक्षण की मांग का मुद्दा उठाकर कांग्रेस नेतृत्व को अचंभित भी कर दिया था। उस दौर में ग्रामीण पृष्ठभूमि और खासतौर पर किसान समूहों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। बाद में उन्होंने सामाजिक-शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण की मांग उठाई। काका कालेलकर आयोग की सिफारिशें ठंडे बस्ते में कैद थीं और परिवर्तन तथा भागीदारी के लिए बेचैन इन समूहों का निरंतर संघर्ष जारी था। उन्हीं के प्रयासों से मंडल आयोग का गठन किया गया जिसमें पिछड़े वर्ग के समूहों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान था। इन्हीं सवालों की प्रखरता के कारण पार्टी में विवाद भी बढ़े और समाज के अभिजात्य वर्ग के द्वारा उन्हें जातिवादी नेता के रूप में बदनाम करने का अभियान भी चलाया गया।

ऐसे महापुरुषों की राजनीतिक विचारधारा समय काल की भी प्रतीक्षा में रहती है। आज कोई दल पिछड़े वर्गों की साझेदारी और भागीदारी को अपनी पार्टी का कार्यक्रम बनाने में गर्व महसूस करता है। सभी दलों के घोषणापत्र वंचित समूहों के आरक्षण लागू करने के संकल्प के साथ प्रारंभ होते हैं। धीरे-धीरे दलों के नेतृत्व में भी इन समूहों की हिस्सेदारी की झलक स्पष्ट दिखती है।

आज हम चौधरी साहब की 118वीं जयंती पर उनका स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने जिन सवालों को आवाज दी उसके स्वर मद्धम न पड़ जाएं, इसके लिए हमें अनवरत रूप से जागरूक रहने की जरूरत है। किसान आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। खेती मुनाफे का सौदा नहीं बची है। गांव महानगरों के उपनिवेश बन चुके हैं। कृषि पर बढ़ते बोझ को अन्य गैर कृषि कार्यों में लगाने का सिलसिला बंद है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है, लेकिन उच्च नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में उनकी उपस्थिति ठीक से दर्ज नहीं हो पा रही है। राजनीति में शुचिता और ईमानदारी उनके व्यक्तित्व के गुण थे जो आज उनके समर्थकों की कार्यशैली से लुप्त हो गए हैं। इसलिए आज एक और चौ. चरण सिंह की आवश्यकता अब महसूस हो रही है जो उसी प्रखरता, तत्परता, व्यग्रता, कुशलता के साथ उन कार्यक्रमों को अमली जामा पहना सके।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता

एक छात्र आइएएस बनना चाहता था। दुर्भाग्यवश काफी मेहनत के बावजूद भी वह अपने सपने को साकार नहीं कर पाया। वह इस असफलता को आत्मसात नहीं कर पाया और समय के साथ निराशाओं के चक्रव्यूह में फंसता गया। जीवन में सपनों के टूटने के बाद निराश होना मानवीय प्रवृत्ति है, पर प्रश्न यह उठता है कि आखिर जीवन में असफलताओं से कितना हताश हुआ जाए? क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त न करने में असफल होना जीवन को हार जाने सरीखा ही अहम होता है? महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था, 'हमारी सबसे बड़ी खासियत जीवन में कभी नहीं गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने पर हर बार उठकर खड़े होने में है।' असफलताएं सफलताओं तक पहुंचने के लिए सोपान का कार्य करती हैं। असफलताओं की कोख में ही सफलताओं के भ्रूण छुपे होते हैं। हेनरी फोर्ड के अनुसार, 'असफलता का अर्थ महज किसी कार्य को फिर और भी अधिक तन्मयता के साथ शुरू करने का एक अवसर है।' असफलता की स्थिति में निराशा से बचना आसान तो नहीं होता है, लेकिन इससे जल्दी बाहर नहीं आने पर जीवन का वजूद ही संकट में पड़ जाता है। लिहाजा जब कभी आप अपने मुकाम हासिल करने में असफल हो जाएं तो परेशान न हों, बल्कि सफल होने के लिए एक बार और गंभीरता से कोशिश करें।

यदि आप अपने जीवन में हार से कुछ-न-कुछ सीखते हैं तो आप हारे हुए नहीं हैं। प्रत्येक हार में जीवन में सफल होने के लिए अनमोल सबक छुपे होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम पराजय में छुपे हुए उन अनमोल मोतियों को पहचान ही नहीं पाते हैं। असफलता घातक नहीं होती है, पर असफल होने के बाद खुद को परिवर्तित नहीं करने की जड़ता ही हमें सफलता की राह में आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप अपने जीवन में सफलता के मुरीद हैं तो असफलताओं से भयभीत होकर रुकें नहीं, बल्कि इनमें जीवन के सबक को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि सफल होने के लिए निरंतर कोशिश में ही जीवन का वास्तविक सार छुपा होता है।

श्रीप्रकाश शर्मा

न करें अपनी संपत्ति का नुकसान

अनीश कुमार

सार्वजनिक संपत्ति देश की जनता की संपत्ति है। उसकी रक्षा करना हर राजनीतिक दल और नागरिक का भी कर्तव्य है

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हिंसा, आगजनी और अराजकता की कोई जगह नहीं है। हमने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है और हमने स्वेच्छा से मताधिकार को स्वीकार किया है। लोकतंत्र में जनता अपनी पसंद की सरकार बनाती है और कर आदि देकर उसे टिकाए रखती है। किंतु नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर कुछ दल जिस तरह से देश के कुछ क्षेत्रों में एक वर्ग के लोगों और छात्रों को भड़का रहे हैं, वह लोकशाही की मर्यादाओं के खिलाफ है।

सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति देश की जनता की संपत्ति है। हमारे-आपके दिए गए करों से बनाई गई है। उसकी रक्षा करना हर राजनीतिक दल और नागरिक का भी कर्तव्य है। यदि आप सार्वजनिक संपत्ति जैसे बस, रेल, दफ्तर आदि में आग लगाकर जला देते हैं अथवा तोड़फोड़ करते हैं तो उसकी भरपाई जनता को ही करनी पड़ती है। सरकार बस या रेल का किराया और टैक्स बढ़ाकर नई बस मंगा लेगी। उसका खामियाजा जनता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सरकार के पास पैसा कहीं आसमान से नहीं आता है। वह जनता के दिए गए करों से ही सारी व्यवस्था चलाती है। इसलिए अपनी ही संपत्ति में आग लगाकर कोई न तो अपना भला कर सकता है और न देश का भला कर सकता है। अपने ही घर में आग लगाना पागलपन की निशानी है।

सरकार की ओर से बार-बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस कानून का देश के नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं, फिर भी कुछ दल यही माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। यह देश के साथ खिलवाड़ है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्या देश के विभिन्न मुस्लिम शिक्षा संस्थानों के छात्रों को बरगलाकर सड़क पर उतरने वाले यही नहीं साबित कर रहे कि उन्हें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क बहुसंख्यकों की चिंता खाए जा रही है? अगर भारत इन देशों के बहुसंख्यकों के बजाय वहां सताए और अपमानित किए जा रहे अल्पसंख्यकों की परवाह कर रहा है तो इसे लेकर आसमान सिर पर उठाने का क्या मतलब?

इसमें कोई संदेह नहीं इन छात्रों को कुछ लोग भड़का कर अपना हित साधना चाहते हैं। यह समझने की जरूरत है कि नागरिकता कानून संसद में पारित हुआ है, जो देश की प्रतिनिधि संस्था है। इसके पीछे सरकार की अपनी सोच है, जिससे असहमत होने का अधिकार हर किसी को है। भारतीय लोकतंत्र में असहमति जताने के तरीकों की कोई कमी नहीं है। इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई है। जिसने कई कानूनों को पहले भी रोका है, और उसमें संशोधन कराया है। ऐसे में अगर कोई कहता है कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के जरिये ही किया जा सकता है तो उसकी बात पर कान नहीं देना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अंध विरोध की पराकाष्ठा

संजय गुप्त ने अपने आलेख 'अराजकता फैलाने वाली राजनीति' में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस अतार्किक विरोध की बात की है, वह एकदम सही है। नागरिकता कानून को लेकर पिछले एक हफ्ते से एक वर्ग विशेष द्वारा पूरे देश में जो आगजनी, तोड़-फोड़ और पुलिस बल पर पथराव किया जा रहा है, वह अंध विरोध की पराकाष्ठा है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना 'हम नहीं मानेंगे' की उक्ति को चरितार्थ कर रहा है। यह स्थिति तब है जब मीडिया जगत इस नागरिकता कानून के बारे में बिल्कुल सही जानकारी देकर आम जनता को गुमराह न होने की ताकीद कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी अपने संबोधन में बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस नागरिकता संशोधन कानून से देश के किसी भी धर्मावलंबी की नागरिकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई कागजी सुबूत पेश करना होगा। बावजूद इसके पिछले एक हफ्ते से बहके और गुमराह लोगों की बेकाबू भीड़ द्वारा देश को बंधक बनाने की साजिश की जा रही है। ऐसे में जहां पर पुलिस संयम बरत रही है वहां उपद्रवियों की पत्थरबाजी से घायल हो रही है और जहां इन पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग कर रही है वहां विपक्षी दलों की आलोचना का शिकार हो रही है। यह एक ऐसी अजीब स्थिति है जिससे पार पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह का अराजक विरोध और उसको शह देने वाला अंध विरोधी विपक्ष हो तो वह सत्ता पक्ष क्या करे? जो राष्ट्रहित में कुछ सकारात्मक करना चाहता है। वर्तमान का नागरिकता संशोधन कानून और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाला एनआरसी मोदी सरकार की ऐसी ही राष्ट्रहितैषी कार्ययोजनाएं हैं जो देश की असंतुलित जनसंख्या को दुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी हैं। अपने यहां की जनसांख्यिकी को संतुलित करने का अधिकार हर देश को है। भारत की वर्तमान केंद्रीय सत्ता यदि राष्ट्रहित में वही कुछ कर रही है तो विपक्ष को आपत्ति क्यों है?

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

मेलबाक्स

हिंसात्मक विरोध गलत

नागरिक संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हिंसात्मक विरोध को सही नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। हिंसा से किसी भी विवाद का समाधान नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने अपने अहिंसात्मक धरने एवं अनशन से देशहित से जुड़ी ज्यादातर बड़ी मांगों को सफलतापूर्वक मनवा लिया था। यदि मौजूदा कानून को लेकर किसी वर्ग को कोई आपत्ति है तो वो शांतिपूर्वक अपनी बात कह सकता है। नागरिकता संशोधन कानून के ताजा मसले पर लोगों व छात्रों को बरगलाया जा रहा है। हमारे मुल्क में ही मौजूद कुछ स्वार्थी तत्व देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आम नागरिकों को आपसी भाईचारे की भावना का परिचय देते हुए इस कानून की बारीकियों का अध्ययन करना चाहिए। सीएए से किसी भी मौजूदा नागरिक को कोई खतरा नहीं है। आम नागरिकों को हिंसा का मार्ग त्यागकर सरकार का सहयोग करना चाहिए।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव, दिल्ली

प्याज-आलू के भाव

प्याज के बाद अब आलू के भाव भी आसमान पर पहुंच गए हैं। दोनों ही फसलों का इस समय सीजन चल रहा है। इसके बावजूद इनके भाव कम नहीं हो रहे हैं। प्रति वर्ष इस समय आलू तो 10 से 15 रुपये किलो के बीच मिलता था, मगर इस साल 30 रुपये किलो बिक रहा है। घर-घर में इस्तेमाल होने वाले आलू को खरीदते समय एक आम आदमी को सोचना पड़ रहा है। इससे भी खराब स्थिति प्याज की है, जो सौ और 120 रुपये किलो तक बाजार में बिक रही है, जबकि हरी प्याज बाजार में आ गई है। सूखी प्याज के भाव चढ़े होने से हरी प्याज भी ऊंचे भाव पर मिल रही है।

पंकज कुमार मुखी, गुरुग्राम

जागरूक बनें

लोगों को पता ही नहीं है कि नागरिकता संशोधन कानून में क्या है। विरोध करने वालों ने जानने की भी कोशिश नहीं की। वैसे भी यदि इसका विरोध शांतिपूर्वक किया जाता तो न तो आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ता।

कशिश वर्मा, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

47 प्रतिशत भारत के लोग जलवायु परिवर्तन को एक बड़े खतरे के रूप में मानते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरुकता के संदर्भ में वर्ष 2017 में कराए गए एक सर्वेक्षण में यह नतीजा सामने आया।

आजकल

शिवानंद द्विवेदी
सीनियर रिसर्च फेलो, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

नागरिकता कानून पर अफवाहों की राजनीति

नागरिकता (संशोधन) कानून-2019 पर देश भर में कुछ खास किस्म के उपद्रवी और असामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। कई राजनीतिक दल इन उपद्रवियों को हिंसात्मक प्रदर्शन के लिए उकसा रहे हैं। नागरिकता कानून के नाम पर भ्रामक अफवाहों की राजनीति की जा रही है। वास्तविक तथ्यों को समझे बगैर तथाकथित बुद्धिजीवियों के इशारों पर जो भ्रम इस कानून के संबंध में फैलाया जा रहा है उसे भी समझने की जरूरत है

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी दिल्ली में सड़कों पर आगजनी व तोड़-फोड़ करते प्रदर्शनकारी। पीटीआइ

जर्मनी के नाजी नेता और हिटलर के करीबी गोयबल्स का कहना था कि एक झूठ को सौ बार बोलो तो वह सच लगने लगेगा। दुनिया में सूचना क्रांति का विकास जिस गति से हुआ, गोयबल्स की यह 'थ्योरी' भी खूब आजमाई गई। आश्चर्य की बात है कि भारत में 'गोयबल्स थ्योरी' का उसके मूल विचारों का धुर-विरोध करने वाले कथित प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने ही अपने आचरण में बहुधा प्रयोग किया। संसद के बीते सत्र में नागरिकता (संशोधन) कानून-2019 पारित हुआ। राष्ट्रपति की मुहर के बाद यह कानून अमल में आ गया है। किंतु इस कानून को लेकर गलत सूचनाओं का एक ऐसा अनवरत सिलसिला चलाया गया, जिसने छात्र आंदोलन के बहाने हिंसा और उपद्रव की शक्ल ले ली। वैसे तो नागरिकता कानून के प्राविधान अत्यंत स्पष्ट हैं और इसको लेकर अनेक बार बताया जा चुका है कि इससे भारत में किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति की नागरिकता प्रभावित नहीं होती है। यह विशुद्ध रूप से भारत की सीमा से सटे तीन ऐसे देशों, जो इस्लाम को अपने राज्य का मजहब घोषित कर चुके हैं, से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए वहां के अल्पसंख्यकों-हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मावलंबियों को नागरिकता देने के लिए बना कानून है। इसमें आसानी से समझ आने वाली बात है कि यह कानून एक विशेष परिस्थिति में नागरिकता देने का जरूरत है, लेकिन किसी भी हालत में यह कानून भारत में रहने वाले किसी धर्म के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पर असर डालने वाला नहीं है।

आसान शब्दों में समझे जाने वाले इस विषय को लेकर देश में ऐसी भ्रामक स्थिति का पैदा होना, चकित करता है। किंचित संदेह नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध राजनीति प्रायोजित है। संसद में जब इस कानून पर चर्चा हो रही थी तब कांग्रेस सहित अन्य विरोधी दलों ने अनुच्छेद-14 के उल्लंघन के आधार पर इस कानून को 'विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित करने वाला' बताकर असंवैधानिक सिद्ध करने का प्रयास किया। किंतु चर्चा में यह बात टिक नहीं सकी। यहां तक कि अनेक कानूनविदों ने इसे अनुच्छेद-14 का उल्लंघन मानने से इन्कार कर दिया। सीधी सी बात है कि अगर भारत के अंदर किसी खास वर्ग के लिए विशेष प्राविधान किए जाने से अनुच्छेद-14 का उल्लंघन नहीं होता है तो इस कानून से भी उल्लंघन होने का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। लिहाजा इस आधार पर इस कानून का विरोध तर्कहीन है। 'रिजनेबल क्लासिफिकेशन' की छूट अनुच्छेद-14 में मिली हुई है और इसके तहत अनेक वर्गों को विशेष प्राविधानों का लाभ संविधान सम्मत व्यवस्था में मिल रहा है। इसके बाद देश की सर्वोच्च निर्वाचित पंचायत संसद से पारित इस कानून पर रोक लगाने को लेकर 59 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गईं, किंतु अदालत ने भी पर इस पर रोक लगाने से मना कर दिया।

सही नहीं कानून की संवैधानिकता पर सवाल : नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अपने अतीत के कदमों को या तो भूल रही है, अथवा भूलने का ढोंग कर रही है। नागरिकता का यह कानून वर्ष 1955 में कांग्रेस शासन के दौर में ही बना और समय-समय पर अनेक संशोधनों से होते हुए आज यहां तक पहुंचा है। वर्ष 2003 में इसी कानून में संशोधनों के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों को गुजरात और राजस्थान के कुछ जिलों में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। राजस्थान की चर्चा करते हुए यह नहीं भूलना चाहिए कि 2009 में खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम को पत्र लिखकर हिंदू और सिख शरणार्थियों को नागरिकता देने का विषय उठाया था।

धार्मिक भेदभाव का आधार बता बनाया गया भ्रामक माहौल : मूल रूप में देखें तो नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस सहित इस कानून से असहमत दल दो सवाल उठा रहे हैं। पहला यह कि यह संशोधन सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लिए क्यों? दूसरा सवाल यह कि यह कानून धार्मिक भेदभाव करता है। इन्हीं दो सवालों के इर्द-गिर्द देश में भ्रामक वातावरण तैयार करने का प्रयास इन राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है और यह साबित किया जा रहा है कि यह कानून मुस्लिम-विरोधी है।

नागरिकता के संदर्भ में समयानुकूल बदलाव को समझने की दरकार

नागरिकता संशोधन कानून जैसे विषय पर चर्चा करते हुए हम गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई 'रिजनेबल क्लासिफिकेशन' की बात की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। 'रिजनेबल क्लासिफिकेशन' की चर्चा के क्रम में हमें पहले से चले आ रहे नागरिकता कानून में ओवरसीज नागरिकों के लिए तय कुछ प्राविधानों को देखना होगा। इस कानून के अनुसार नागरिकता के संबंध में जो प्राविधान लागू किए गए हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं।

अब सवाल यह है कि जब बाकी देशों के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्राविधान किया गया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्यों इससे बाहर रखा गया था? इसके पीछे भी कारण 'रिजनेबल क्लासिफिकेशन' का ही समझ में आता है। किंतु आश्चर्यजनक है कि वर्ष 2005 के संशोधन में खुद 'रिजनेबल क्लासिफिकेशन' के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग रखने वाले प्राविधानों को बरकरार रखने वाली कांग्रेस वर्तमान में इन देशों में रहने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की नागरिकता के लिए लाए गए कानून का विरोध कर रही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कांग्रेस के दोहरे चरित्र का द्योतक है। हमें बिना किसी भ्रम में रहे यह समझना होगा कि समय और परिस्थिति के हिसाब से अलग-अलग समय पर सरकारों ने नागरिकता कानून में जरूरत के अनुरूप बदलाव किया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को इसी 'रिजनेबल क्लासिफिकेशन' के तहत भारत की नागरिकता देने की बात की जा रही है।

कोरा भ्रम साबित हुआ जिन्ना का कथन

देश की आजादी के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने जिस देश विभाजन को स्वीकार किया, उसका आधार मजहबी था। दरअसल यहां 'मजहबी' शब्द का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मांग करने वालों में प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना का कथन, 'पाकिस्तान एक सेक्युलर, लोकतांत्रिक और आधुनिक राज्य होगा,' कोरा भ्रम साबित हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल भी इसे 'अल्पकालिक भ्रम' बता चुके हैं। दरअसल बंटवारे के बाद भारत एक 'पंथ-निरपेक्ष' लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आगे बढ़ा, जबकि पाकिस्तान ने कुछ ही वर्षों में अपने राज्य का पंथ 'इस्लाम' को घोषित कर दिया। चूंकि विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान रह गए थे और पाकिस्तान में भी गैर-मुस्लिम बड़ी संख्या में रह गए थे। अत: उनकी चिंता तत्कालीन दौर के महात्मा गांधी सहित लगभग सभी दलों के भारतीय नेताओं को थी। आजादी के तुरंत बाद के वर्षों में कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में पाकिस्तान के 'गैर-मुस्लिमों' की स्थिति पर चिंता जताई थी। तत्कालीन परिस्थिति के आलोक में ही नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था और दोनों देशों द्वारा अपने सीमा क्षेत्र के अल्पसंख्यक हितों की रक्षा का वादा संकल्प के रूप में व्यक्त किया गया।

भारत के नागरिक पर लागू नहीं : बात दूसरे सवाल की करें तो कहा जा रहा है कि इस कानून से मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है? पहली बात जो देश के हर नागरिक को स्पष्ट होनी चाहिए कि यह कानून भारत के किसी भी नागरिक पर लागू नहीं होता, लिहाजा भारत के मुसलमानों पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। मूल सवाल यह कि जब सीमावर्ती तीन देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाईयों पर यह कानून लागू किया गया है तो वहां के मुसलमानों से क्या समस्या है? आदर्शवाद के कल्पनालोक में यह सवाल निश्चित तौर पर हर उस व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है जो इसे सिर्फ एक मामूली सवाल मानकर जवाब तलाश रहा हो, किंतु इस सवाल की तहें इतनी सपाट नहीं हैं जितनी सरसरी नजर से देखने पर दिखती हैं। इतिहास और परिस्थिति के आधार पर इस सवाल का धरातल न ही समतल है और न ही सरलीकृत। यह सवाल सात दशक पहले हुए एक राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक उथल-पुथल की कोख से निकला है।

पाक-बांग्लादेश में घटती हिंदू आबादी : भारत में मुसलमानों की बढ़ी जनसंख्या और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के गिरते हुए आंकड़े बताते हैं कि भारत ने तो अपने वादे को निभाया, किंतु पाकिस्तान की तरफ से नेहरू-लियाकत समझौते की पूरी तरह से अनदेखी की गई। यह स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं कि वह समझौता पाकिस्तान में रह गए अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों के साथ एक छलावा साबित हुआ। समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने भी इस संबंध में चिंता जताते हुए लोकसभा में कहा था कि 'नेहरू-लियाकत समझौते में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में उनके साथ अत्याचार हो रहा है।' आज कानून में संशोधन लाकर तीन देशों के धार्मिक प्रताड़ना के शिकार छह अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने का बीड़ा मोदी सरकार ने उठाया है। यह भारतीय जनता पार्टी के इतर लगभग सभी दलों के नेताओं की उस दौर में चिंता रही है। आज भले ही कम्युनिस्ट पार्टी इस कानून का विरोध कर रही है, किंतु 12 फरवरी 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एच एन मुखर्जी ने लोकसभा में कहा था, 'पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बातें की जा रही हैं, जो लोग आ रहे हैं और पहले आ चुके हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। वे शरणार्थी नहीं हैं। यह देश उनका घर होना चाहिए।'

मनमोहन सिंह उठा चुके हैं मामला : इतना ही नहीं, वर्ष 2003 में खुद डॉ. मनमोहन सिंह ने विपक्ष में रहते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया था। वर्ष 2005 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री ई अहमद ने, उसके बाद वर्ष 2007 में उसी सरकार के विदेश राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने, और फिर वर्ष 2010 में लोकसभा में विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने इस मामले को सदन में उठाया था। इसके बाद वर्ष 2012 में कांग्रेस शासित राज्य असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरूण गोगोई पड़ोसी देश में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का मुद्दा उठा चुके हैं। आज जब एक ऐसी समस्या के समाधान का रास्ता मोदी सरकार कानूनी आधार पर निकाल रही है तो कांग्रेस सहित अन्य दलों द्वारा भ्रम का वातावरण तैयार करके देश के अंदर अस्थिरता की स्थिति पैदा करना उचित नहीं है। इतिहास के तथ्य इस बात के गवाह हैं कि जो निर्णय आज मोदी सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के लिए लिया है, वह किसी भी भारतीय नागरिक का अहित नहीं करता है तथा इसका समर्थन किसी न किसी दौर में लगभग सभी प्रमुख दलों ने किया है।

खरी-खरी

कौवा कान ले गया!

राजेश सेन

हल्ला मचा हुआ है कि 'कौवा कान ले गया!' कौवे को पता ही नहीं कि वह किसका कान ले गया। कान को भी पता नहीं कि उसे किस कौवे ने चुरा लिया। मगर हरकारे सबकुछ समझ-बूझ रहे हैं। वे अफवाह फैलाकर कान की झूठी चोरी का हांका कर रहे हैं। चोरी गए कान बेहद ही संवेदनशील हैं। उन्हें अपने संवैधानिक हक की चिंता सता रही है। देश में बोलने का हक है और सुनने की आजादी भी। और यही हक है जो चोरी हो गया है। नहीं...नहीं, हक नहीं...हक के पैरोकार कान चोरी हो गए हैं। सो, उन्हें अज्ञात कौवे की शिद्दत से तलाश है।

हरकारे भी बड़े ही चालाक हैं। वे कहते कुछ और हैं और चाहते कुछ और। सो वे भ्रम भी कुछ और ही फैला रहे हैं। वे लोगों के कानों में अपने मंसूबों का काना-मंत्र फूंक रहे हैं। लोग बड़े ही भोले-भाले हैं। उन्हें पता ही नहीं कि चोरी हुए कानों में दर-हकीकत के सच्चे मंत्र कैसे ठहरेंगे! वे कान की कीमत पर अपने लोकतांत्रिक विवेक की आंखें तक गंवाने को तैयार हैं। चालाक हरकारे इस हकीकत को खूब पहचानते हैं। उन्हें पता है कि कान के हस्ते विवेक भी आसानी से हराया जा सकता है। सो वे भ्रम फैलाकर निराकार कौवे की उपस्थिति का भय-गान गा रहे हैं।

कुछ कान बहरे ही नहीं अंधे भी हो चुके हैं, क्योंकि हरकारे उन्हें अपने फायदे के लिए हर जो चुके हैं। वे ऐसे लोगों के हाथ में कान की चोरी का पता बताकर पत्थर थमा रहे हैं। अक्ल के अंधे लोग कान और कौवे की तलाश में पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। अपने ही हाथों अपने देश की संपत्तियां जला रहे हैं। भाईचारे को अच्छे से पता है कि ना तो कान कहीं गुम हुआ है, ना ही निराकार कौवा कभी मिलेगा। मगर उसकी जान तो फिलहाल आफत में है।

बदहवास भीड़ अफवाह में आकर हुड़दंगी हो गई है। ये भीड़ का कैसा अजीब लोकतंत्र है। कहने को भीड़ खुद एक लोकतंत्र है, मगर भीड़ में तो कोई लोकतंत्र ही नहीं है। भीड़ भ्रांतियों का अंधा समुच्चय बनी हुई है, जिसके विवेक की चाबी नेपथ्य से भीड़ नचाते हरकारों की जेब में कैद है। हरकारे खुद स्वांग धरे भीड़ बन गए हैं, और भीड़ चोरी के कान की तलाश में है। जबकि कान अज्ञात कौवे की जद में है और कौवे ही हरकारे बनकर प्रपंच रचा रहे हैं।

कान भी हरकारा है, कौवा भी हरकारा और भीड़ भी हरकारा ही है। हरकारे अफवाहों के पर तौल रहे हैं।

ट्वीट-ट्वीट

डेढ़ घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में पीएम मोदी ने नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर तमाम आशंकाओं को पुरजोर तरीके से समाप्त करने की कोशिश की। उम्मीद यही है कि अब इस मसले पर कोई हिंसा नहीं होगी। विक्रांत यादव@ReporterVikrant

सरकार गलती भले ही न मान रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एनआरसी पर कदम पीछे खींच रही है। यह संविधान के दायरे में विरोध प्रदर्शन करने वालों की बड़ी जीत है। करुणा नंदी@karunanundy

अमित शाह ने कहा कि भविष्य में एनआरसी आएगा और नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्तमान में एनआरसी नहीं ला रहे हैं। कुछ बुद्धिमान इस पर यही कह सकते हैं कि मोदी ने शाह की बात को खारिज किया।
राहुल रौशन@rahulroushan

सीएए का विरोध कर रहे तीन चौथाई या इससे अधिक लोगों ने संभवत: संशोधन को पढ़ा भी नहीं होगा, बाकी बचे लोगों को या तो यह समझ नहीं आया या वे इसे समझना नहीं चाहते, क्योंकि यह उनके एजेंडे को रास नहीं आएगा।
विक्रम सूद@Vikram_Sood

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अफवाहों के नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया माध्यमों पर प्रतिबंध बेहतर होगा?

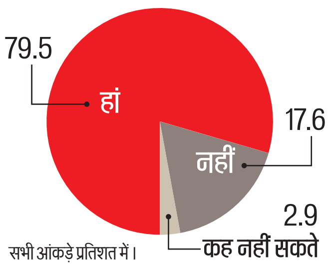

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सीएए के विरोध का दौर थमेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बिकें खिलाड़ी लग रही बोली कई करोड़,
हाय हाय देखो जरा ये मंदी का दौर!
ये मंदी का दौर प्याज का भाव रुलाए,
पर क्रिसमस का जश्न न हमसे छोड़ा जाए।
फुल हैं सभी जहाज पैक गोआ की गाड़ी,
मंदी में भी भाव चढ़ाए बिकें खिलाड़ी।
– ओमप्रकाश तिवारी

सद्गुरु शरण
स्थानीय संपादक, लखनऊ

उत्तर प्रदेश डायरी

सियासत का कारोबार चले... हम रहें, ना रहें

सियासत अपनी सत्ता लोलुपता के लिए कितने गहरे कुएं में गिर सकती है, देश देख रहा है। हिंदुस्तान को बर्बाद, बल्कि टुकड़ा-टुकड़ा कर देने की आकांक्षा जताने वाले नारे, पुलिस पर पथराव, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को आग के हवाले करके देखने का सुख, राहगीरों पर हमला... और भी बहुत कुछ। हर तरफ धुआं। मानो उन्मादी भीड़ इस मुल्क को ही मिटा देना चाहती हो। अपने कौमी सद्भाव पर इतराने वाले लखनऊ को यह सब कुछ ज्यादा ही भोगना पड़ा, यद्यपि कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बहराइच और बरेली समेत शायद ही कोई शहर बचा होगा जिसके ऊपर अराजकता का गहरा धुआं न छाया हो।

वाह री मारीच-सियासत! जो लोग नागरिकता कानून और एनआरसी का मतलब नहीं जानते, उन्हें अपने कारोबार में लगा दिया और खुद पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर बर्बादी के मंजर पर अट्टहास करती रही। एक के बाद एक चुनावों में मुल्क द्वारा नकार दिए जाने का इतना क्रूर बदला। यह भी नहीं सोचा कि जलते लखनऊ की ये तस्वीरें दुनिया में हिंदुस्तान की कैसी छवि बनाएंगी। मान लिया कि सूबे के लोग भोले-भाले हैं। जाति-धर्म में बंटे हुए हैं, पर सामाजिक सद्भाव के प्रति बेपरवाह कतई नहीं हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करिए... लखनऊ को आग के हवाले करने वाली भीड़ में लखनऊ के कितने लोग थे? गला फाड़कर हिंदुस्तान को राख कर डालने के जिहादी नारे लगा रहीं जींस-टॉपधारी बालिकाएं लखनऊ की थीं? मदिरा के नशे में लड़खड़ा रहे लड़के लखनऊ के थे? पुलिस अधिकारियों पर पत्थर बरसा रहे युवक-युवतियां लखनऊ के थे? बिल्कुल नहीं। सियासत के उकसावे पर हर वक्त हिंदुस्तान को टुकड़े-टुकड़े करने का सपना देखने वाले दिल्ली और अलीगढ़ के विवादास्पद शिक्षा संस्थानों के युवाओं के जत्थे आयात करके लखनऊ के

प्रतीकात्मक

सीने में इतना गहरा जख्म देने की साजिश शहर याद रखेगा। बेशक कई वाहन राख हो गए, पुलिस चौकियां जला दी गईं, पुलिस अधिकारियों ने पत्थर खाए, राहगीरों ने डंडे खाए, पर इससे लखनऊ मिट नहीं गया। अगली सुबह उसके आसमां पर फिर कबूतर उड़े। मस्जिदों में जुमे की अजान हुई और मंदिरों में घंटे घनघनाए। क्रिसमस की तैयारी में मग्न गिरजाघरों में रौनक लौट आई। गुरुद्वारों में लंगर लगे।

दरअसल लखनऊ उस उत्तर प्रदेश की गर्वित राजधानी है जिसने करीब डेढ़ महीने पहले को देश के सर्वाधिक जटिल अयोध्या विवाद के फैसले को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया था। चुनाव के बाद से ही खार खाए बैठे कुछ सियासी दलों को आम आदमी की इस समझदारी पर बहुत खिसियाहट हुइ थी जिसका हिसाब उन्होंने अब बराबर कर लिया। उम्मीद है कि हर तरफ धुआं देखकर इन दलों के कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। सियासत के कारोबार के लिए ऐसे मंजर शायद जरूरी होंगे, पर किसी को नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता वास्तविक जनार्दन है।

आपकी हरकतों पर जनता चुप रहती है तो आप इसे उसकी अज्ञानता, कायरता और तटस्थता मान लेते हैं। यही गलतफहमी आपको बार-बार पराजित कर रही है। हिंदुस्तान, खासकर उत्तर प्रदेश के कम पढ़े-लिखे मतदाताओं ने कई बार राष्ट्रहित में अपने लोकतंत्रीय विवेक का परिचय देकर चौंकाया है। राज्य में 2014 से 2019 के बीच हुए चुनावों में मतदाताओं ने जाति-धर्म की बंदिशों को तोड़ जो जनादेश दिया, उससे भुक्तभोगी दलों में छटपटाहट स्वाभाविक है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिसबल की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने धैर्य नहीं खोया। यह साजिशकर्ताओं की सबसे बड़ी विफलता रही। यूपी पुलिस की छवि के आधार पर शायद ही कोई अपेक्षा करेगा कि उपद्रवियों द्वारा पथराव के वक्त पुलिस अधिकारी पत्थर खाते रहेंगे। अपने साथियों के सर से खून बहता देखकर भी शांत रहेंगे। पुलिस बल धैर्य की अग्निपरीक्षा में डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण हुआ। इसका वास्तविक श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है जो अपने आक्रामक स्वभाव के विपरीत न सिर्फ खुद कूल रहे, बल्कि अपनी मशीनरी को भी संयमित रखा। सरकार के पास असीमित शक्ति होती है। वह किसी से निपटने पर उतारू हो जाए तो उससे पार नहीं पाया जा सकता। बहरहाल, सरकार ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल हालात नियंत्रित करने में किया। यह सरकार का जनपक्षीय चेहरा है, क्योंकि आम आदमी यही चाहता है। जो दल या नेता सूबे में आग और धुआं देखना चाहते हैं, वे अपना कारोबार जारी रखें और अगले जनादेश का इंतजार करें। उधर, योगी सरकार की शक्ति का असली इम्तिहान अभी बाकी है। सरकार के सामने चुनौती है कि इस साजिश के सारे मास्टरमाइंड बेनकाब किए जाएं, अराजकता फैलाने वाले सलाखों के पीछे भेजे जाएं और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संकल्प पूरा हो कि उपद्रव में संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति नीलाम करके की जाएगी। राष्ट्रहित के फैसलों में जनता हमेशा राजनीतिक नेतृत्व के साथ खड़ी रहती है, मोदी और योगी सरकार को इस विश्वास से डिगना नहीं चाहिए।

आबोहवा की चिंता

डॉ. संजय वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर
बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

जलवायु भी हो प्राथमिकता में

जलवायु परिवर्तन की समस्या से कमोबेश पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है या फिर होने की आशंका है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए गंभीर प्रयास की जरूरत है

प्रतीकात्मक

स्पेन की राजधानी मैड्रिड में दो सप्ताह से ज्यादा लंबे चले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन- कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप-25) से उम्मीदें तो बहुत थीं, पर उसका बिना किसी नतीजे खत्म हो जाना पर्यावरण को लेकर दुनिया की संजीदगी का स्तर साबित करने को काफी है। वर्ष 2020 से जलवायु परिवर्तन के लिए अहम 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने की कोशिशों के तहत कॉप-25 का नारा था- 'टाइम फॉर एक्शन,' पर अफसोस कि यह सम्मेलन एक्शन के मोर्चे पर ही विफल रहा।

ये हालात तब हैं जब पूरी दुनिया बढ़ते तापमान, सूखे, तबाही लाते तूफानों, भीषण बर्फबारी और अतिशय बाढ़-बारिश आदि मौसमी वजहों से प्रभावित हो रही है। खुद इंसान के लिए इन प्राकृतिक मौसमी बदलावों से जीना मुहाल हो गया है। लेकिन आबोहवा सुधार की कोशिशों को सिरे चढ़ाने की बात किसी के जेहन में नहीं अटक रही है।

जलवायु बदलावों पर हम कितने गंभीर हैं, यह इससे पता चलता है कि इस वर्ष पहले यह सम्मेलन (कॉप-25) चिली के सेंटियागो में आयोजित होना था, जो अपने यहां हो रहे विरोध प्रदर्शनों का तर्क देकर इसकी मेजबानी से हट गया। संयुक्त राष्ट्र की नाक बचाने को मजबूरन इसे स्पेन के मैड्रिड में आयोजित कराना पड़ा। अगर वहां कुछ ठोस हासिल होता तो यह आयोजन सफल कहा जाता। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से दांव पर लगी सभ्यता को बचाने के उपायों और विकल्पों को ही कई देशों ने गैर जरूरी मानकर खारिज कर दिया। इन उपायों को लेकर विकसित देशों ने तो और भी निराशाजनक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जलवायु आपातकाल की अभूतपूर्व स्थितियों से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन करने की अपीलों पर ध्यान देना ही उचित नहीं समझा। कुल मिलाकर इस सम्मेलन का हश्र क्या हुआ, यह ग्रेनाडा के राजदूत सिमोन स्टील के बयान से पता चल गया। सिमोन ने कहा कि पेरिस संधि के प्राविधानों को कायम रखने के लिए प्रत्येक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को एक अवसर के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह सम्मेलन तो उन प्राविधानों को नष्ट करने का ही आयोजन बन गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि मैड्रिड में दुनिया ने एक बड़ा मौका गंवा दिया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे।

हमें यह ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मानवनिर्मित संकट है, वह जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) है। इसका पूरा अंदाजा किसी को नहीं है कि ग्रीनहाउस गैसों के असर से पैदा हुई ग्लोबल वॉर्मिंग इस धरती का क्या कर डालेगी। इन चुनौतियों से बचना है तो कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाने का रास्ता फिलहाल सूझता है। लेकिन इन मुद्दों पर अमेरिका और अमीर यूरोपीय देश अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सिर ठेलने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। कॉप-25 में तो इस समस्या पर न्यूनतम चर्चा हुई ही, पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो पहले ही खुलेआम पेरिस समझौते को भेदभावपूर्ण बताकर उससे अलग होने की बात कर चुके हैं। हालांकि भारत इसे लेकर सहमत है कि वह वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में मौजूदा दर से एक तिहाई कमी ला देगा। इसके लिए कोयले से चलने वाले पावर प्लांटों में बिजली उत्पादन घटाकर जलविद्युत परियोजनाओं पर निर्भरता बढ़ाई जाएगी। हालांकि चावल की खेती और मवेशी जनित ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना भारत के लिए चुनौती है, पर जिस तरह से एक सूचकांक-सीसीपीआइ में हमारे देश की रैंकिंग सुधरी है, उससे भारत से तो एक उम्मीद जगी है।

असल में मैड्रिड में ही जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की ओर से संयुक्त रूप से पेश जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआइ) की रैंकिंग में भारत पहली बार शीर्ष दस देशों में शामिल हुआ है। इस सूची में पिछले वर्ष भारत का मुकाम 11वां था, जबकि नई सूची में वह नौवें स्थान पर आया है। यह संकेत है कि भारत में जलवायु परिवर्तन को एक आसन्न संकट मानने की एक समझ बनने लगी है। पर्यावरण को लेकर मानसिकता में बदलाव की यह सूचना दो साल पहले 2017 में कराए गए एक सर्वेक्षण से भी मिली थी जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन को 47 फीसद भारतीय बड़ा खतरा मानते हैं। पर ज्यादा बड़ी बात तब होगी, जब विकसित (धनी) देश इस मुद्दे को लेकर गंभीरता दर्शाएं। इस गंभीरता का सबसे ताजा पैमाना सीसीपीआइ रैंकिंग है।

अमेरिका की जगह इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन वाले देशों में है। अच्छे प्रदर्शन की दृष्टि से स्वीडन चौथे और डेनमार्क पांचवें स्थान पर है, जबकि चौंकाते हुए पहले के तीन स्थान खाली रखे गए हैं। इन स्थानों को खाली छोड़ने का साफ संदेश यह है कि जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर दुनिया अभी भी निर्धारित लक्ष्य से बहुत दूर है। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देशों में से एक चीन ने सूचकांक में अपनी रैंकिंग सुधारते हुए पिछले साल के 33वें के मुकाबले 30वां स्थान हासिल किया है। अमेरिका जैसे अपवादों को छोड़कर सभी देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और सबने अपने-अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रयास जरूर किए हैं। पर दुनिया का आम नजरिया यही लगता है कि जब हालात खराब होंगे, तभी कुछ उपाय किए जाएंगे।

असल में जलवायु परिवर्तन का संकट हमारे सारे अनुमानों से भी कई गुना ज्यादा भयावह है और यह बिल्कुल हमारे सिर पर आ चुका है। यही वजह है कि सीसीपीआइ में अच्छी रेटिंग पाने के बाद भी कई पर्यावरण वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि खुद भारत को भी कई और काम करने होंगे। जैसे यहां जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल-डीजल पर दी जा रही सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करने की रूपरेखा बनानी होगी ताकि कोयले पर देश की निर्भरता कम हो सके।

01 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 तक राज्य के नेशनल पार्कों, अभयारण्यों और कंजर्वेशन रिजर्व में आए 4.72 लाख सैलानियों में से 77 फीसद ने सिर्फ कार्बेट और राजाजी की तरफ रुख किया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 23 दिसंबर 2019

उत्तराखंड

बढ़ाया जाए वन्यजीव पर्यटन का दायरा

विश्व प्रसिद्ध कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में वन्यजीव पर्यटन के सबसे बड़े डेस्टिनेशन के रूप में अपनी बादशाहत बनाए हुए हैं। वन्यजीव पर्यटन के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन अन्य संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवन के दीदार को पर्यटकों की आमद अभी भी काफी कम है। राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजीव भरतरी के अनुसार कार्बेट एवं राजाजी से इतर भी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन बढ़े, इसके लिए संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों की दरें समान की जा रही हैं। कार्बेट एवं राजाजी में प्रवेश शुल्क, ठहरने की दरों में इजाफा किया जा रहा है।

जाहिर है जैव विविधता के लिए मशहूर उत्तराखंड में वन्यजीव पर्यटन आर्थिकी का अहम जरिया बन सकता है। बावजूद इसके वन्यजीव पर्यटन की मुहिम कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के इर्द-गिर्द ही सिमटी हुई है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि छह नेशनल पार्क, सात वन्यजीव अभयारण्य और चार कंजर्वेशन रिजर्व में से वन्यजीव पर्यटन का पूरा दारोमदार कार्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व ही टिका हुआ है। वन्यजीव विभाग के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। बीते सीजन यानी एक अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 तक राज्य के नेशनल पार्कों, अभयारण्यों और कंजर्वेशन रिजर्व में आए 4.72 लाख सैलानियों में से 77 फीसद ने सिर्फ कार्बेट एवं राजाजी की तरफ रुख किया। ऐसी ही तस्वीर पूर्व के पर्यटन सीजनों में रही। साफ है कि अन्य संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवन का दीदार के लिए पर्यटकों की आमद अभी भी कम है, जबकि ये भी वन्यजीव विविधता के लिहाज से खासे धनी हैं। बाघ और हाथियों के लिए मशहूर कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की बढ़ती आमद अच्छी बात है, मगर राज्य में वन्यजीव पर्यटन के दायरे को इससे आगे ले जाने की दिशा में कदम उठाने की दरकार है। असल में अन्य नेशनल पार्क, चाहे वह फूलों की घाटी हो या नंदादेवी नेशनल पार्क अथवा अस्कोट सेंचुरी समेत दूसरे संरक्षित क्षेत्र, ये सभी दुर्गम क्षेत्रों में हैं। वहीं कार्बेट और राजाजी के इर्द-गिर्द सुविधाओं के साथ ही अन्य तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से दूसरे शहर भी हैं। ऐसे में सैलानियों को वन्यजीव पर्यटन के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में जाने का अवसर भी मिल जाता है।

71 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कदम उठाने की दरकार है

राज्य के दुर्गम और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं के विकास की दरकार है। साथ ही वहां के किसी पार्क, अभयारण्य एवं कंजर्वेशन रिजर्व में जाने वाले सैलानियों के लिए नजदीकी पर्यटक स्थलों की राह भी सुगम करनी होगी। आशय यह कि कार्बेट एवं राजाजी से इतर भी संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। हालांकि अब इसके लिए हिमालयी क्षेत्र में मौजूद संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों की दरें कम और समान करने का प्रस्ताव है। इसके पीछे भी मंशा यही है कि वहां सैलानी आएं और वन्यजीवन के साथ ही कुदरत के नजारों का दीदार करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रकृति से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ किए बगैर वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने की मुहिम को धरातल पर उतारा जाएगा।

उत्तर प्रदेश

समय की मांग है अस्पतालों का थर्ड पार्टी आडिट

हाल भारतीय नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हर मोर्चे पर फेल बताया गया है। लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वाह्य रोगी-अंतः रोगी, डायग्नोस्टिक सेवाएं, चिकित्सीय उपकरण, मानव संसाधन, संक्रमण नियंत्रण एवं औषधि प्रबंधन को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। रिपोर्ट कहती है कि आधे से ज्यादा अस्पतालों में बर्न वार्ड, ट्रामा वार्ड के साथ ही डायलिसिस, फिजियेथेरेपी, मनोचिकित्सा के लिए भर्ती की व्यवस्था ही नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तो केवल सांप काटने का इलाज केंद्र बनकर रह गए हैं। जिला अस्पतालों तक में एक्सरे मशीन नहीं है। कुछ विरोधाभास भी सामने आए हैं, मसलन राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में 74 फीसद डॉक्टरों की तो कमी मिली, लेकिन नर्सों की उपलब्धता 210 फीसद अधिक थी। 50 से लेकर 86 फीसद मरीजों को पांच मिनट से भी कम समय में डॉक्टर देख रहे हैं, जो आउटडोर में मर्ज खत्म करने, उसकी जांच और इलाज के लिए मानक के अनुसार बहुत ही कम है। हृदयघात और निमोनिया के इलाज के मामले में सीएचसी के पास उपचार ही नहीं है। वे केवल रेफरल सेंटर बन कर रह गए हैं। उपचार में डायग्नोस्टिक सेवाओं की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बावजूद आधे से ज्यादा जिला अस्पतालों में एक्सरे मशीनों की कमी पाई गई है। ज्यादातर सीएचसी पर अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधा नहीं है तो सीटी स्कैन की भी एक तिहाई अस्पतालों में सुविधा पाई गई है। पैथोलॉजी जांच की सुविधा में कमी है तो जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन भी काफी नहीं हैं। यहां तक कि इस क्षेत्र में निजी एजेंसियों को लगाए जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं आया है। कैग को 22 सीएचसी में से छह में ही पैथोलॉजिकल सेवाएं मिली हैं। लेखा परीक्षक ने आइसीयू के मामले में नमूने के तौर पर 11 चिकित्सालयों की जांच की तो पाया कि लखनऊ और गोरखपुर को छोड़कर कहीं भी आइसीयू की सुविधा नहीं थी। उसे ट्रामा सेवाएं भी केवल बांदा और सहारनपुर में मिली हैं।

प्रतीकात्मक

बहरहाल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने जब यह तस्वीर दिखाई है तो अफसरों के कानों पर भी जूं रेंगी है। यह पहला अवसर होगा जब स्वास्थ्य विभाग विभिन्न जिलों में स्थित अस्पतालों का थर्ड पार्टी आडिट कराएगा। आशय है कि जो आईना कैग ने दिखाया है, उसे विभाग पहले अपने तंत्र से ही देखेगा, परखेगा और अपने स्तर पर उसमें सुधार के प्रयास भी करेगा, ताकि भविष्य में कैग की रिपोर्ट को लेकर उसे शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। जहां तक स्वास्थ्य विभाग के अपने तंत्र का सवाल है तो उसके पास भी विकल्प सीमित ही हैं। प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी राजकीय मेडिकल कॉलेजों को आडिट की जिम्मेदारी दिए जाने की बात कहते जरूर हैं, लेकिन यह भी एक सच है कि मेडिकल कॉलेजों में भी संसाधनों का बड़ा रोना है और वह अपनी इस भूमिका से कितना न्याय कर पाएंगे, यह देखने की बात होगी।

वैसे यह समय की मांग है कि अस्पतालों का थर्ड पार्टी आडिट कराया जाए, क्योंकि कैग की रिपोर्ट ने वहां के प्रबंधन को ही कठघरे में खड़ा किया है। थर्ड पार्टी आडिट से पूरे प्रदेश की तस्वीर सामने आएगी और उसके बाद एक समग्र योजना तैयार कर अस्पतालों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। यह अच्छी पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

बिहार

बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग हो समाज

बिहार में स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और मोहल्ले से बच्चों की चोरी का जो नया मामला सामने आया है, वह बेहद अमानवीय और क्रूर है। किसी मां की गोद से उसके बच्चे को छीनकर लाखों रुपये खर्च करने वाले किसी अन्य परिवार को सौंप देने का धंधा समाज की विसंगतियों को सामने लाता है। दुखद यह है कि इस धंधे में वैसे लोग शामिल पाए गए, जिन पर लोग आंख मूंदकर विश्वास करते हैं।

आज तक ऐसा कभी नहीं होता कि किसी डॉक्टर से सलाह लेने के पूर्व किसी मरीज ने उसकी डिग्री मांगी हो। उसकी जांच-पड़ताल कराई हो। ताकि यह पता चल सके कि वह जिस व्यक्ति के कहने पर दवाएं ले रहा या ऑपरेशन करा रहा, वह सच में सलाह देने योग्य है कि नहीं। मरीज तो अस्पतालों के बाहर लगे बोर्ड देखता है। पूर्व के मरीज के अनुभव से समझ बनाता है और इलाज कराने पहुंच जाता है। 10 साल से एक नन मैट्रिक व्यक्ति एक अस्पताल चला रहा है। वह धीरे-धीरे बच्चा चोरी रैकेट का मास्टरमाइंड बन जाता है और इस बीच हजारों लोग उस पर विश्वास करते हुए अपना और बच्चे का जीवन उसे सौंपते रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी व्यवस्था की गंभीर लापरवाही इससे साफ समझ में आती है। दुखद यह भी है कि उसके साथ मुजफ्फरपुर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल के कुछ चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों की संलिप्तता की जानकारी भी मिल रही है। भागलपुर से बच्चा चोरी मामले की तहकीकात में इस रैकेट के तार एसकेएमसीएच से भी जुड़े होने की जांच पुलिस कर रही है। कई चिकित्सक इसमें शामिल होने वाले चिकित्सक एवं कर्मियों के नाम सामने लाने की जरूरत जता रहे थे, वहीं कुछ चिकित्सकों के संलिप्त होने पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। उधर प्राचार्य डॉ. विकास कुमार एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एसके शाही ने कहा कि इस तरह के मामले में संलिप्त चिकित्सकों की जानकारी नहीं है। सरकार के आदेश के पश्चात इसे खंगाला जाएगा।

प्रतीकात्मक

दरअसल पुलिस ने झोलाछाप विजय, उसका साथ देने वाली दो महिलाओं और बच्चा खरीदने वालों को पकड़ा है। उनसे पूछताछ में गरीबी और मजबूरी की शिकार मां की कोख से बच्चा चुराने की जानकारियां मिल रही हैं। ऐसे कृत्य करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। साथ ही समाज में यह संदेश फैलाना भी जरूरी है कि अपने संतान सुख के लिए किसी मां की कोख सूनी करने की कोशिश घिनौनी है।

बंगाल

स्वच्छता के लिए बदलनी होगी सोच

महानगर के सौंदर्यीकरण एवं शहर में तेजी से फैल रहे प्रदूषण और गंदगी पर रोक लगाने को कोलकाता नगर निगम सड़कों पर ई-टॉयलेट लगाने की तैयारी कर रहा है। शहर में शौच के लिए महिलाओं काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसी के मद्देनजर इस व्यवस्था को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि इससे आम लोग भी लाभांवित होंगे। शहर को साफ और प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में यह अच्छी पहल है।

दरअसल पिछले पांच साल से देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। बंगाल में भले ममता सरकार पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को लेकर गंभीर न हो, लेकिन अपने 'निर्मल बांग्ला' अभियान के तहत स्वच्छता लाने की कोशिश जरूर कर रही है। बावजूद इसके आज भी गांव-शहर के गली-मोहल्ले स्वच्छ नहीं हो पाए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों की सोच में नहीं आया बदलाव है। लाखों-करोड़ रुपये के फ्लैट में रहने वाले लोग आज भी कचरा उठाकर बालकनी से सड़क पर फेंक देते हैं। ट्रेनों से लेकर बसों और रेलवे स्टेशनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी कचरा फेंकने से परहेज नहीं करते। एक तरफ केंद्र एवं राज्य सरकारें स्वच्छता को तमाम योजनाएं चला रही हैं, वहीं कुछ ऐसी मानसिक विकृति वाले लोग समाज में फैले हुए हैं, जो जहां-तहां गंदगी फैला रहे हैं। यहां तक कि वे खुले में शौच करने से भी करने से गुरेज नहीं करते। कोलकाता को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास काफी नहीं है। जब तक आम लोग नहीं समझेंगे कि हमें शहर को स्वच्छ बनाना है, तब तक ऐसा नहीं होगा।

लाखों-करोड़ रुपये के फ्लैट में रहने वाले लोग आज भी कचरा उठाकर बालकनी से सड़क पर फेंक देते हैं। अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी कचरा फेंकने से परहेज नहीं करते

हालांकि अब राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने जहां-तहां गंदगी फैलने से रोकने के लिए कोलकाता की सड़कों पर ई-टॉयलेट लगाने की योजना बनाई है। यह ई-टॉयलेट हांगकांग में लगे शौचालयों जैसा होगा। कोलकाता के मेयर एवं राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम का कहना है कि महानगर को गंदगी-मुक्त रखने के लिए कई योजनाएं तैयार की गई हैं। प्रदूषण एवं गंदगी को दूर करने के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में ई-टॉयलेट लगाने की योजना है। महानगर के विभिन्न इलाकों के बस अड्डों, मसलन देशप्रिय पार्क, रासबिहारी एवेन्यू, हाजरा मोड़, चेतला, कालीघाट, पार्क स्ट्रीट एवं टालीगंज में ई-टॉयलेट लगाए जाएंगे। यह टॉयलेट गाड़ी जैसा होगा। पांच रुपये का सिक्का डालने पर गेट खुलेगा। दरवाजा बंद होने के बाद खुद से फ्लश ऑन हो जाएगा और गंदगी साफ हो जाएगी। टॉयलेट की सफाई एवं निगरानी के लिए एक व्यक्ति तैनात रहेगा।

ऐसी व्यवस्था शुरू होने के पीछे लगातार मिल रही शिकायतें हैं, खासकर महिलाओं को काफी तकलीफ होती है। सिंगापुर की सड़कों पर ऐसे ई-टॉयलेट हैं। इससे शहर भी साफ रहता है, सुंदर दिखता है और लोगों को भी सुविधा होती है। इसके साथ ही यह देखना भी जरूरी है कि लोगों को कैसे जागरूक कैसे किया जाए ताकि वे जहां-तहां गंदगी न फैलाएं।

डाटागीरी

भारत में पांच में से तीन बच्चे एनीमिया से पीड़ित

शरीर में खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। प्रतीकात्मक

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में मौजूदा समय में छह माह से लेकर 59 माह तक के 58.5 फीसद बच्चे और 15 से 49 साल की उम्र की 53.1 फीसद महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार, एनीमिया को तीन श्रेणियों (हल्के, मध्यम और गंभीर) में विभाजित किया गया है। सरकार द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, ग्रामीण भारत में 29.8 फीसद बच्चे मध्यम एनीमिया और 40.3 फीसद महिलाएं हल्के एनीमिया से पीड़ित हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने पिछले संसद सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2018 में केंद्र सरकार ने 'पोषण' अभियान के तहत 'एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)' की शुरुआत की थी, ताकि एनीमिया के प्रसार को 2022 तक हर साल तीन फीसद तक कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि एएमबी एक 6*6*6 की रणनीति है। इसमें छह आयुवर्ग को छह तरीकों से छह संस्थानों द्वारा एनीमिया से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। छह आयुवर्ग में बच्चे (6-59 माह), स्कूल जाने वाले बच्चे (5-9 वर्ष), किशोरियां (10-19 वर्ष), किशोर (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं (15-49 वर्ष) शामिल हैं।

भारत में एनीमिया (रक्त अल्पता) का उन्मूलन बड़ी चुनौती है, वर्तमान में हालात यह हैं कि देश में पांच में से तीन बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। सरकार ने देश को एनीमिया मुक्त बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। योजना के तहत एनीमिया के मामले में 2022 तक सालाना तीन फीसद की कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया है।

इससे बचाव के छह तरीकों में प्रोफीलैक्टिक आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंट देना, समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा देना, गैर पोषण आहार की जानकारी लेना, विभिन्न बीमारियों जैसे- मलेरिया, हीमोग्लोबिनपैथिस व फ्लोरोसिस पर नजर रखना आदि है। एनीमिया के लड़ने के लिए छह संस्थानों में राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त भारत ईकाई और नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस और एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल आदि हैं।

बच्चों में एनीमिया की व्यापकता (छह से 59 माह)

	ग्रामीण	शहरी	कुल
निम्न (10.0–10.9 ग्राम प्रति डेसीलीटर)	28.2	26.8	27.8
मध्यम (7.0–9.9 ग्राम प्रति डे.ली.)	29.8	27.5	29.2
गंभीर (7.0 ग्राम प्रति डे.ली. से कम)	1.5	1.6	1.6
अन्य (11.0 ग्राम प्रति डे.ली. से कम)	59.5	56.0	58.5

महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता (15 से 49 वर्ष)

	ग्रामीण	शहरी	कुल
निम्न (10.0–11.9 ग्राम प्रति डेसीलीटर)	40.3	38.3	39.6
मध्यम (7.0–9.9 ग्राम प्रति डे.ली.)	12.8	11.6	12.4
गंभीर (7.0 ग्राम प्रति डे.ली. से कम)	1.1	0.9	1.0
अन्य (12.0 ग्राम प्रति डे.ली. से कम)	54.2	50.8	53.1

डिजिटल हस्ताक्षर न होने से अटके एक हजार करोड़

- जम्मू में रुपये न निकलने से गावों का कायाकल्प नहीं हो पा रहा है
- गांवों के विकास के लिए पंच, सरपंच 5700 करोड़ जारी करने की मांग कर रहे

राज्य ब्यूरो, जम्मू

राज्य में गांवों के विकास के लिए जारी किए गए एक हजार करोड़ रुपये डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत न होने के कारण पंचायतों के खातों में फंसे हैं। इस कारण गांवों का कायाकल्प नहीं हो रहा है। जबकि पंच, सरपंच केंद्र सरकार से 5700 करोड़ रुपये जारी करने की मांग कर रहे हैं।

रविवार को पंचों व सरपंचों ने ऊधमपुर के घोरडी ब्लॉक में प्रदर्शन कर मनरेगा के बकाया एक हजार करोड़ रुपये के साथ चौदहवें वित्त आयोग के बकाया 5700 करोड़ जारी करने का मुद्दा उठाया। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार फंड जारी कर पंचायतों के खाते में 25-25 लाख रुपये और डाले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की 4129 पंचायतों के लिए 18 जून 2019 को वर्ष 2015 से बकाया 3700 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी। इसमें से 700 करोड़ की पहली किश्त जारी हो गई थी। इसके बाद तीन सितंबर को पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट करने के बाद गृहमंत्री ने 3000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी करने की घोषणा की थी। यह राशि भी अभी जारी होना बाकी है।

फंड जारी होने में देरी से पंचों-सरपंचों का संयम जवाब दे रहा है। उनका कहना है कि नए फंड जारी होना तो दूर, उनके अकाउंट में जारी फंड भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। पंचायत कांफ्रेंस के प्रदेश प्रधान व नगरोटा के डंसाल ब्लॉक की जिंद्राह पंचायत के सरपंच अनिल शर्मा का कहना है कि पंचायत सचिव व सरपंच के ज्वाइंट अकाउंट के डिजिटल सिग्नेचर पंजीकृत न होने से पंचायतों के खातों में पड़े एक हजार करोड़ रुपये भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। उनके अकाउंट में 28 लाख रुपये हैं, जो विकास कार्यों के लिए खर्च नहीं हो पा रहे हैं।

1500 करोड़ रुपये मिल चुके, बाकी का इंतजार : शीतल नंदा

ग्रामीण विभाग की सचिव शीतल नंदा का कहना है कि 14वें वित्त आयोग के 3700 करोड़ रुपये में से करीब 1500 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। बाकी राशि जल्द हासिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायतों में डिजिटल हस्ताक्षर प्रभावी बनाए जा रहे हैं। कई जगहों पर भुगतान के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है ग्रामीण विकास को तेजी दी जाए।

ट्रेनों के ठहराव में नेता जी की नहीं चलेगी रेलवे बोर्ड छोटे स्टेशनों की समीक्षा करेगा

- मानकों पर खरा न उतरने वाले स्टेशनों से ठहराव की सुविधा छीनी जाएगी
- अधिकतर जनप्रतिनिधियों की मांग पर होता है ट्रेनों के ठहराव का निर्णय

राकेश श्रीवास्तव, वाराणसी

अब ट्रेनों के ठहराव में नेता जी की नहीं चलेगी। रेलवे बोर्ड ट्रेनों के छोटे स्टेशनों पर ठहराव की समीक्षा करेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को फरफार्मेंस दिखा जमीनी सच्चाई बताई जाएगी। इसके बावजूद मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले स्टेशनों से ट्रेनों के ठहराव की सुविधा छीन ली जाएगी। अभी तक अधिकारी रेलवे को नुकसान के बावजूद दबावों के कारण ट्रेनों के ठहराव बढ़ाते रहते थे।

ट्रेनों के ठहराव को रेलवे बोर्ड ने एक मानक निर्धारित किया है। मसलन, स्टेशन से कितने यात्रियों का रोजाना आना-जाना होता है। कितनी बर्थों का काउंटर से आरक्षण होता है। जनरल श्रेणी के कितने टिकट बिकते हैं। सामानों को पार्सल में भेजने की स्थिति क्या है? यह इसलिए कि ट्रेनों के प्रत्येक ठहराव पर रेलवे का करीब 10 हजार रुपये खर्च होता है। ऐसे में स्टेशन मानकों को अपनाकर ही अपना कद बचा पाएंगे।

ट्रेनों का ठहराव कर उसे बढ़ाते रहने का प्रचलन : छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव जनप्रतिनिधियों की मांग पर प्रयोग के तौर पर शुरू होता है। अफसर छह माह की प्रगति देख उसे आगे बढ़ाते हैं। स्टेशन के फरफार्मेंस को रेलवे के मानकों पर कसा जाता है। दूसरी तरफ वोट बैंक घटने की आशंका में इसका विरोध होता है। रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि नुकसान उठाकर किसी को खुश नहीं करेगा।

30 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट : रेलवे बोर्ड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग एमएस भाटिया जोनल रेलवे से 30 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। हालात को नियमों के मानकों पर कसने को कहा गया है।

ट्रेनों के प्रत्येक ठहराव पर रेलवे का करीब 10 हजार रुपये खर्च होता है। प्रतीकात्मक

216 दिन में चिरेका में बने 300 रेल इंजन

जागरण संवाददाता, जामताड़ा : चितरंजन रेल इंजन कारखाना ने चालू वित्तीय वर्ष के सिर्फ 216 दिनों यानी 9 महीने से भी कम समय में 21 दिसंबर 2019 की शाम तक वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 300वें रेल इंजन का निर्माण पूरा कर नया रिकार्ड कायम किया। मालूम हो कि इससे पहले वर्ष 2017–18 में 292 दिनों में 300वां इंजन का निर्माण हुआ था। लेकिन चालू वित्त वर्ष में सिर्फ 216 दिन का ही समय लगा। इस प्रकार 28 प्रतिशत कम समय में ही इस रिकार्ड को कायम कर लिया गया। चिरेका के जीएम प्रवीण कुमार मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में शनिवार शाम को चिरेका से 300वां लोको को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नियम ताक पर रख अनु मलिक को कराया गया मां बगलामुखी का दर्शन

नईदुनिया, आगर : मध्य प्रदेश के आगर जिले के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में संगीतकार अनु मलिक दर्शन के लिए आए, लेकिन मंदिर के नियमों को ताक पर रखकर मुख्य पुजारी के पुत्र भारत पंडा ने गर्भ गृह के द्वार खोल दिए। नियम के अनुसार, मंदिर के पट रात 9.30 बजे बंद हो जाते हैं। शुक्रवार रात 10 बजकर 40 मिनट पर अनु मलिक को दर्शन कराए गए।

संगीतकार मलिक द्वारा शुक्रवार रात मंदिर में हवन भी किया गया, किंतु समिति के कार्यालय में उनके नाम की हवन की ऐसी कोई रसीद नहीं मिली। मालूम हो कि आम हो या खास कोई भी व्यक्ति द्वारा यदि हवन कराया जाता है तो यहां पर सरकारी रसीद कटती है। मामला शुक्रवार का है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह अब चर्चा में आ गया। इस संबंध में पुजारी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

तहसीलदार संजीव सक्सेना ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि नियम विरुद्ध दर्शन कराए गए हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

किसान को मुआवजा नहीं देने के लिए अदालत के आदेश में की छेड़छाड़

- प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट चारधाम को रेल नेटवर्क से जोड़ने का मामला
- विजिलेंस जांच शुरू, नोटिस जारी

किशोर जोशी, नैनीताल

बदरीनाथ-केदारनाथ समेत चारधामों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा देने से संबंधित मामले में बड़ी चूक उजागर हुई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर विजिलेंस हल्द्वानी ने इस फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस ने इस संवेदनशील मामले की जांच शुरू करते हुए रेलवे प्रोजेक्ट के मुख्य परियोजना प्रबंधक, किसान समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन दिन में बयान दर्ज करने को कहा है।

दरअसल ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के टिहरी गढ़वाल के मलेथा में रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। इसके लिए रेलवे ने जमीन का अधिग्रहण किया। करीब चार हेक्टेयर भूमि को किसान अनिल किशोर जोशी ने भूमिधरों से लीज पर लिया था। जिलाधिकारी के समक्ष इस भूमि के स्वामियों ने भूमि का मुआवजा उन्हें देने व भूमि पर उगे शहतूत के वृक्ष व अन्य संपत्ति का मुआवजा किसान अनिल किशोर जोशी को देने का आग्रह किया था। जब मुआवजा नहीं मिला तो अनिल किशोर जोशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। छह मई 2019 को कोर्ट ने याचिका निस्तारण करते हुए याची को भूमि अधिग्रहण एवं प्रतिकर ट्रिब्यूनल में रेफरेंस दाखिल करने को कहा। 14 अक्टूबर को ट्रिब्यूनल ने कलेक्टर टिहरी व रेलवे को मौके पर स्थित संपत्ति को खुर्दबुर्द न करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के खिलाफ रेलवे ने ट्रिब्यूनल में रिव्यू व रिकॉल याचिका दायर की। साथ ही रेलवे ने ट्रिब्यूनल के 14 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देती याचिका दायर की। रेलवे ने याचिका में 6 मई का एक आदेश भी संलग्न किया, जबकि यह आदेश 6 मई का था। जब रेलवे की याचिका की कॉपी विपक्षी अनिल किशोर जोशी को मिली तब जाकर आदेश में छेड़छाड़ होने का शक हुआ। इस संवेदनशील मामले में एसपी विजिलेंस अमित श्रीवास्तव ने किसी तरह की टिप्पणी करने से साफ इन्कार किया है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट। फाइल

साढ़े सात लाख शहतूत के वृक्ष व अन्य का मिलना है मुआवजा: उद्यान विभाग के आकलन के अनुसार करीब साढ़े सात लाख शहतूत के वृक्ष हैं। जिनका मुआवजा उद्यान विभाग के मानकों के अनुसार प्रति वृक्ष 3400 रुपये देना है।

सैलानियों को परोसे जाएंगे परंपरागत व्यंजन

जागरण संवाददाता, मनाली : क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहाड़ों की मल्लिका मनाली तैयार है। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर शहर के होटलों में डीजे म्यूजिक नाइट के अलावा डाइन एन डांस भी होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले सैलानियों के लिए शहर में खास तैयारियां की गई हैं। बड़े दिनों की छुट्टियों ने मनाली में रौनक को बढ़ा दिया है। पड़ोसी राज्यों में हालत खराब होने से मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है।

मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी लगभग फुल चल रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल कुंजम, क्लब हाउस में कल्चर फेस्टिवल का आयोजन होगा। पर्यटन निगम सहित मनाली के होटलों में सैलानियों को परंपरागत व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहेगी। क्रिसमस ईव और न्यू ईयर पर क्लब हाउस में स्पेशल पार्टी होगी, जिसमें कपल और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। शहर के प्राइवेट होटलों में भी क्रिसमस ईव और न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया जाएगा। होटलों में बांसुरी की धुन पर कैंडल लाइट डिनर की भी व्यवस्था की गई है।

47 फीसद की कमी आई है भारत में दृष्टिहीनता के मामलों में बीते 12 सालों में। राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिबाधित सर्वे 2019 के मुताबिक देश की कुल आबादी के 0.36 प्रतिशत यानी 48 लाख लोग दृष्टिहीन हैं।

फल-फूलों की खेती को बनाया उन्नति का आधार

फलों से लदा सेब का पेड़। जागरण

टिहरी के बसाण के अपने उद्यान में बिरवान सिंह रावत। जागरण

मोहनलाल थपलियाल, टिहरी

जागरण विशेष

- उत्तराखंड में पौधों का क्लोन तैयार करवाने के एकमात्र काश्तकार हैं बिरवान सिंह रावत
- इस सीजन में बेचे दो लाख रुपये के सेब व कीवी, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद तक मांग

यह कहानी है टिहरी जिले (उत्तराखंड) के जौनपुर ब्लॉक स्थित बसाण गांव के बिरवान सिंह रावत (52) की। वह रक्षा मंत्रालय के उपक्रम में उपप्रबंधक तैनात थे। इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के लोग खेती छोड़ नौकरी के लिए महानगरों में भटक रहे हैं। सो, ठान लिया कि क्यों न खुद गांव लौटकर युवाओं की इस पीड़ा को कुछ कम करें। इसके बाद नौकरी से इस्तीफा दिया और लौट आए गांव। आज 17 साल की मेहनत से विकसित आधुनिक उद्यान उनकी जिंदगी को महका रहा है। बिरवान उत्तराखंड में अकेले काश्तकार हैं, जो फलों की पैदावार बढ़ाने को पौधों का क्लोन बनवा रहे हैं। उन्होंने बागवानी के लिए अपने खेतों के अलावा कुछ खेत ग्रामीणों से भी खरीदे हैं। 2002 से पहले बसाण में लोग धान की खेती करते थे। लेकिन बिरवान ने गांव लौटकर खेतों में फलों की पौध लगानी शुरू की और धीरे-धीरे एक खूबसूरत उद्यान तैयार हो गया। वह खेतों में सेब, कीवी व नाशपाती का उत्पादन करते हैं। जिनकी मांग देहरादून से लेकर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद की मंडी तक है। खरीदार स्वयं उनके उद्यान में पहुंच जाते हैं। चालू सीजन में बिरवान करीब दो लाख रुपये के सेब व कीवी बेच चुके हैं। साथ ही फूलों की खेती भी कर रहे हैं।

विदेशी वैज्ञानिकों के लिए भी आकर्षण : कुछ दिन पूर्व अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. सिडार के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्लोन से तैयार पेड़ों के इस आधुनिक उद्यान का दौरा किया। उन्होंने यहां उत्पादित फलों के बारे में जानकारी भी जुटाई। पुणे विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉ. श्वेता भी इस उद्यान का भ्रमण कर चुकी हैं।

बच्चे भी बंटाते हैं पिता का हाथ : बिरवान बताते हैं कि उनकी बेटी शिवाली देहरादून में बीएएमएस और बेटा हिमांशु दिल्ली में पर्यावरण विज्ञान में एमएससी कर रहा है। दोनों छुट्टियों में घर लौटने पर उनकी मदद करते हैं। सीजन में वह लगभग 15 लोगों को रोजगार देते हैं, जबकि पांच लोग नियमित रोजगार पा रहे हैं।

ऐसे तैयार होता है क्लोन : जिला उद्यान अधिकारी डॉ. डीके तिवारी बताते हैं कि इसके लिए किसी पेड़ के तने या ऊपरी हिस्से की कोशिका को प्रयोगशाला में मिट्टी के 16 पोषक तत्वों की टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। पोषक तत्वों और उचित तापमान की मदद से वह कोशिका कुछ महीने बाद अंकुरित होकर पौधा बन जाती है। इस प्रक्रिया में छह महीने का समय लगता है। इसके बाद उसे जमीन में रोपा जाता है। क्लोन पौधे को लगाने के बाद उसकी जड़ों से अन्य पौधे विकसित होते हैं, जिन्हें बगीचे में रोपा जाता है। इन पौधों की खासियत यह है कि वह तीन साल में ही फल देने लगते हैं। इसी कारण काश्तकारों में क्लोन पौधे का क्रेज बढ़ रहा है। क्लोन पेड़ 15 साल तक अपनी जड़ों से छोटे-छोटे पौधों को जन्म देता है। यह पेड़ फल नहीं देता। वर्तमान में काश्तकार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में रजत बायोटेक प्रयोगशाला से क्लोन पौधे टिहरी ला रहे हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

स्लम के बच्चों को मिली किताब तो हो गया कमाल

बदलाव ▶ जज्बे और त्याग से अनु चिनिया ने भीख मांगने वाले बच्चों की बदल दी जिंदगी

चौराहों पर दिखने वाले बच्चे अब अपनी कक्षाओं के बन गए मॉनिटर

पींकू यादव, हिसार

भीख नही किताबे दो संस्था से जुड़े बच्चों के साथ अनु चिनिया। जागरण

स्लम बस्ती में बच्चों एवं उनके परिजनों के बीच बैठी अनु चिनिया। जागरण

सुशिक्षित समाज

मुफलिसी में जी रहे लोगों के जीवन को नया मुकाम देना, मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है। आमतौर पर सड़कों पर भीख मांग रहे बच्चों को हम कुछ सिक्के देकर अपने मानवीय दायित्वों की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे नौनिहालों का जीवन पूरी तरह बदल देते हैं। ऐसा ही नेक कार्य कर रही है एक भगवाधारी युवती। वह ऐसे लोगों के बीच न सिर्फ उठती-बैठती हैं, बल्कि उनके जीवन को सुधारने के लिए खुद को समर्पित भी कर दिया है। हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की हिसार निवासी भगवाधारी अनु चिनिया की जिन्होंने अपने अथक प्रयास से भीख मांगते बच्चों के हाथ में कटोरा की जगह किताब पकड़ा दिया है।

जो बच्चे पांच साल पहले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व शहर के प्रमुख चौराहों पर भीख मांगते नजर आते थे, वे अब अपनी कक्षाओं के मॉनिटर बन गए हैं। वे न सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल कर रहे हैं, बल्कि दूसरे बच्चों के साथ खेलों सहित अन्य गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। वे मेडल भी जीत रहे हैं। इनकी प्रतिभा अब रंग ला रही है। परीक्षा के आधार पर चयनित स्लम बस्तियों के 11 बच्चे अब शहर के नजदीक तलवंडी राणा के छात्रावास में रहते हैं। आज हिसार ही नहीं, फतेहाबाद, हांसी, अग्रोहा, उकलाना सहित कई स्लम बस्तियों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। चिनिया का लक्ष्य पूरे प्रदेश के स्लम बस्तियों के बच्चों को शिक्षित कर उन्हें मुख्यधारा में लाना है। हिसार में 17 जगह स्लम एरिया है। यहां के 544 बच्चों का अनु ने सरकारी स्कूल में दाखिला कराया। बच्चे शुरुआत में स्कूल जाना बंद कर देते थे क्योंकि इन बच्चों में बाहर घूमने की बुरी आदत थी।

कदम-कदम पर आई बाधा, नहीं हारी हिम्मत : 'भीख नहीं किताब दो' संस्था की प्रमुख अनु चिनिया बताती हैं कि जब उन्होंने स्लम के बच्चों को पढ़ाने की ठानी तो उनका चौतरफा विरोध हुआ। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नौकरी छूटने से परिवार वाले खिन्न थे। स्लम में रहने वाले लोग भी मुझसे नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें। भीख को अपना पुश्तैनी काम मानने वाले लोग कहते थे कि कमाएंगे नहीं तो खाना कैसे मिलेगा। सूर्यनगर स्लम बस्ती से मैंने अपना अभियान शुरूकिया। बस्ती के पप्पू अंकल, जिनके 11 बच्चे थे, बोले-आप अच्छे घर की लग रही हैं। आप इस चक्कर में न पड़ें। लेकिन मैंने ठान लिया था- कुछ भी हो यहां के बच्चों को बदल कर रहूंगी। मैं वहां हर रोज जाती और पेड़ के नीचे सफाई कर चटाई बिछाकर बैठ जाती। छह सात दिन बाद पप्पू अंकल ने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। कुछ और बच्चे भी आने लगे। 11 दिन बाद मैंने देखा कि जिस जगह को मैं खुद साफ करती थी, उसे पहले से बच्चों ने साफ कर रखा था। फिर बस्ती के कुछ और लोग मेरे साथ आए और एक महीने में 70 से 80 बच्चों को मैं पढ़ाने लगी।

ऐसे बढ़ा मनोबल : अनु चिनिया के अनुसार, जब बच्चे अधिक हुए तो इसकी चर्चा पूरे शहर में हुई। फिर एक कार्यक्रम में मुझे आइजी अनिल राव मिले। उन्होंने मेरे काम की प्रशंसा करते हुए मदद का आश्वासन दिया। मैंने उनसे बच्चों के लिए जगह मांगी, क्योंकि बस्ती में ही रहने के कारण बच्चों का मन पढ़ाई में कम लगता था और वे भागकर घर पहुंच जाते थे। फिर उन्होंने टाउन पार्क के करीब जगह दिलाई और वहां बच्चों की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई। बाद में बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया। कुछ दिन बाद ही स्कूल से शिकायत आ गई कि ये दूसरों बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। साफ-सफाई नहीं रखते, इनको नहीं पढ़ा सकते। इससे मुझे जोर का झटका लगा। चार माह तक बच्चों को आचार-व्यवहार की ट्रेनिंग दी। जब दोबारा स्कूल भेजा तो अच्छा परिणाम आया। जब सफलता मिली तो स्लम बस्ती के लोगों की सोच में भी बदलाव आया।

बच्चों को बदलते-बदलते खुद बदल गई अनु : अनु चिनिया का उद्देश्य बच्चों के जीवन में बदलाव लाना था लेकिन वह इस काम में इस कदर खो गईं कि उन्होंने खुद को ही बदल लिया। अब वह अपने घर नहीं जातीं और आश्रम में ही रहती हैं। वह शादी भी नहीं करना चाहतीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका पति उनकी राह में बाधा न बन जाए। भगवा धारण करने का कारण पूछने पर वह कहती हैं- जींस पहनने पर समाज की दृष्टि अलग थी। इसलिए, धीरे-धीरे पहले चोला बदला तो मन भी बदल गया।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

ऐसे समझें बदलाव को

रोहन : उम्र 12 साल
काम : बस स्टैंड पर भीख मांगना
बदलाव : पढ़ाई के साथ ही दौड़ में भी अव्वल। सैनिक स्पोर्ट्स अकादमी बहवलपुर में आयोजित प्रतियोगिता में दौड़ में पहले स्थान पर रहा
लक्ष्य : पुलिस अधिकारी बनना
देवा : उम्र 12 साल
काम : कबाड़ चुनना
बदलाव : हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होता है। देर रात तक पढ़ता रहता है। स्कूल प्रबंधन ने मॉनिटर बना रखा है

देश में ही तैयार होगा कैंसर से लड़ने वाला लूटेशियम

जागरण संवाददाता, लखनऊ

- न्यूक्लियर फिजिक्स क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक अगले पांच दिन लखनऊ में
- इस वर्ष हुए शोध कार्य पर लखनऊ विश्वविद्यालय में करेंगे चर्चा

कैंसर के इलाज में कारगर लूटेशियम के लिए आने वाले समय में हमें रूस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे वैज्ञानिकों ने लूटेशियम को देश में ही तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि लूटेशियम को तैयार करने में तीन साल तक का वक्त लग सकता है, मगर भविष्य को लेकर हमारी राह जरूर आसान हो चलेगी। न्यूक्लियर फिजिक्स सेक्टर से जुड़े वैज्ञानिक कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण शोधों पर अगले पांच दिन लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली कांफ्रेस में चर्चा करेंगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिकी विज्ञान विभाग एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में डीएई, बीआरएनएस सिंफोजिएम ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स पर पांच दिवसीय कांफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन से पहले रविवार को कार्यक्रम समन्वयक व भाभा परमाणु अनुसंधान के डॉ. एलएम पंत, हेड न्यूक्लियर फिजिक्स डिवीजन डॉ. बीके नायक व स्थानीय संयोजिका डॉ. ज्योत्सना सिंह ने बताया कि पांच दिवसीय संगोष्ठी में देश-विदेश के करीब 550 से अधिक भौतिक शास्त्र से जुड़े वैज्ञानिक शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि कांफ्रेंस में न्यूक्लियर फिजिक्स के तहत एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीएक्शन, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर समेत विभिन्न पांच विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही इस वर्ष न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में हुए हालिया शोधों पर प्रमुखता से चर्चा होगी।

उन्होंने बताया कि कैंसर के इलाज के लिए लूटेशियम आइसोटोप की जरूरत पड़ती है। मौजूदा समय में उसे बाहर से खरीदना पड़ता है, जिसकी एक ग्राम की कीमत हमें करोड़ों में चुकानी पड़ती है। अक्सर कई देश लूटेशियम देने से इन्कार भी कर देते हैं, ऐसे में दूसरों पर निर्भरता समाप्त कर खुद को इस दिशा में तैयार करना होगा।

कोसी नदी का जीआइएस मानचित्र तैयार, नदी पर नजर रखना आसान

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा

- नदी के पुनर्जीवन की कवायद तेज
- कभी कोसी में 21 सहायक नदियां मिलती थीं
- 225.6 किमी लंबी कोसी अब 41.5 किमी रह गई है

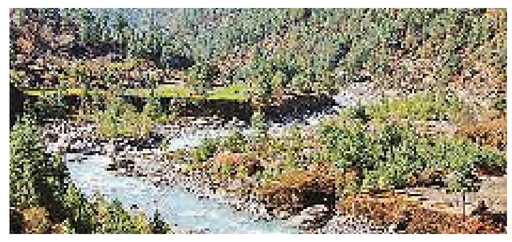

कुमाऊं के लिए जीवनदायनी मानी जाती है कोसी। प्रतीकात्मक

कोसी नदी के पुनर्जीवन की कवायद जारी है। इसी क्रम में नदी का उद्गम स्थल से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले स्थान तक का जियोग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम (जीआइएस) से मानचित्र तैयार कर लिया गया है। अब इस मानचित्र की सहायता से कोसी नदी पर नजर रखना आसान हो गया है।

कुमाऊं के लिए जीवनदायनी माने जानी वाली कोसी नदी अल्मोड़ा के भरतकोट पहाड़ी से निकलकर खैरना (नैनीताल) में प्रवेश करती है। इसके बाद नैनीताल जिले में रामनगर से होते हुए मुरादाबाद व काशीपुर के बीच रामगंगा में मिलती है। कभी कोसी में 21 सहायक नदियां और 97 जलधारे मिलते थे। 40 वर्ष पूर्व 225.6 किमी लंबी जीवनदायिनी अब सिकुड़ कर मात्र 41.5 किमी रह गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर इस नदी को पुनर्जीवन की कवायद शुरू की गई। इसके लिए नदी के आसपास बड़ी संख्या में पौधों का रोपण किया गया।

तीस साल से कोसी नदी पर शोध कर रहे अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना महाविद्यालय में प्रोफेसर और कोसी पुनर्जनन समिति के वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. जीवन सिंह रावत ने नदी का जीआइएस मानचित्र तैयार किया है। उन्होंने बताया कि मानचित्र की मदद से कोसी बचाने की राह आसान हो गई है। प्रो. रावत ने बताया कि पहाड़ों में ही नहीं, रामनगर में भी इसके तमाम सहायक जलधारे हैं, उन्हें भी पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इसके अलावा रामनगर के कोसी बैराज में भी जलस्तर घट रहा है। उन्होंने बताया कि कोसी की निर्मलता व अवरिलता को ऊधमसिंह नगर में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

आज रामनगर में जुटेंगे वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ : कोसी पुनर्जनन महाभियान को तराई भाबर में गति देने के मकसद से सोमवार को रामनगर (नैनीताल) में मंथन होगा। इसमें कुमाऊं स्तर पर गठित कोसी पुनर्जनन समिति के वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. जीवन सिंह रावत के साथ निदेशक यूसर्क प्रो. दुर्गेश पंत, प्रो. चारू पंत विभागाध्यक्ष भूगर्भ विज्ञान कुमाऊं विवि, वरिष्ठ वैज्ञानिक यूसर्क डॉ. मंजू सुंदरियाल भाग लेंगे।

ताजनगरी में कम हो गए नौ लाख देसी-विदेशी पर्यटक

जागरण संवाददाता, आगरा

- नवंबर तक 8.45 लाख भारतीय, 47 हजार विदेशी पर्यटक कम आए
- यूरोपीय देशों में मंदी, तनावपूर्ण हालात और देश के राज्यों में बाढ़ रहे कारण

वर्ष 2019 ने ताजनगरी आगरा के पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में जोर का झटका दिया है। जनवरी से नवंबर तक पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब नौ लाख देसी-विदेशी पर्यटक कम आए। इससे राजस्व पर भी काफी असर पड़ने की बात कही जा रही है। ताजनगरी में पर्यटकों की संख्या का आकलन ताज पर हुई टिकट बिक्री को माना जाता है। बता दें कि वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की अपेक्षा जनवरी से नवंबर तक ताज पर हुई टिकट बिक्री के आंकड़ों के अनुसार 8.45 लाख भारतीय पर्यटक कम आए, जबकि इसी अवधि में 47 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक कम आए।

ये मानी जा रही वजह : पर्यटकों की संख्या कम होने के पीछे लोकसभा चुनाव, देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़, अनुच्छेद 370, अयोध्या में राममंदिर मामले को बताया जा रहा है। यूरोपीय देशों में आर्थिक मंदी के चलते विदेशी पर्यटकों में गिरावट मानी जा रही है।

सीएए से सता रही सीजन की चिंता : दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन व उपद्रव हो रहे हैं। दिल्ली में फंसे विदेशी पर्यटक टूर कैंसिल कर वापसी के प्रयास में हैं। दिल्ली होकर ही पर्यटक आगरा आते हैं। इसके चलते पर्यटन उद्यमियों को सीजन की चिंता सता रही है। इस समय आगरा में पर्यटन सीजन टॉप पर होता है।

> पर्यटक शांति और सुकून भरे माहौल में घूमना पसंद करते हैं। मंदी और बाढ़ की वजह से भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी आई।
> **- राकेश चौहान, अध्यक्ष होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन**

> यूरोपीय देशों में दो-तीन वर्षों से मंदी का दौर है। इससे विदेशी पर्यटक इस बार कम आए हैं। देश में मंदी के चलते उद्योग-धंधों की स्थिति में गिरावट आने से इस बार पर्यटकों की संख्या कम रही।
> **- रमेश वाधवा, अध्यक्ष होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन**

अटल व्यक्तित्व, विराट मूर्ति...

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जिस मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, वह प्रतिमा शहर की मुख्तलिफ पहचानों में इजाफा करेगी। रविवार को लोक भवन में कर्मचारी 25 फीट ऊंची और लगभग पांच टन वजनी कांस्य की इस प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जी-जान से लगे रहे। हृदेश चंदेल

शहीद जवानों के घर की मिट्टी से पुलवामा में बनेगा स्मारक

- शहीदों के घर से मिट्टी इकट्ठी कर रहे महाराष्ट्र के उमेश जाधव
- गुरदासपुर में पुलवामा के शहीद मनिंदर के घर पहुंच परिजनों से लिया मिट्टी का कलश

पुलवामा हमले में शहीद हुए गुरदासपुर के मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री (ट्रैक सूट में) उमेश जाधव (बाएं) को अपने घर की मिट्टी का कलश भेंट करते हुए। शहीदों के घर की मिट्टी से जाधव पुलवामा में भारत के नक्शे जैसी स्मारक का निर्माण करवाएंगे। जागरण

सुनील थानेवालिया, गुरदासपुर

राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राणों की आहुति देने वाले देश के वीर सैनिकों की अमूल्य शहादत को बेशक सरकारें व प्रशासन भुला दें, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शहीदों के बलिदानों की गरिमा को बहाल रखने को अपना मिशन बना लिया है।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी उमेश गोपीनाथ जाधव पुलवामा में शहीदों का स्मारक बनाने के लिए उनके आंगन की मिट्टी इकट्ठी करने के मिशन पर निकले हैं। उमेश जाधव गत दिवस को पुलवामा हमले में शहादत का जाम पीने वाले कांस्टेबल मनिंदर सिंह के घर दीनानगर भी पहुंचे। यहां शहीद मनिंदर के पिता सतपाल अत्री, बहन लवली, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की, शहीद सिपाही जितेन्द्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही कुलदीप कुमार के पिता बंत राम ने उमेश को गौरव सम्मान से सम्मानित किया। शहीद मनिंदर के पिता सतपाल अत्री ने उमेश को घर के आंगन की मिट्टी का कलश भेंट किया तो भावुक हो उठे।

उमेश जाधव पिछले 16 वर्षों से बेंगलुरू में रह रहे हैं। इनका लुक विंग कमांडर अभिनंदन से मिलता जुलता है। इसी वर्ष 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 20 जवानों की शहादत ने उमेश के अंदर देशभक्ति की ऐसी अलख जगाई कि उन्होंने संकल्प लिया किया कि वह इस हमले में शहीद हुए 40 जवानों के अलावा देश के अन्य शहीदों के घर जाएंगे और उनके आंगन तथा उनके संस्कार स्थल की मिट्टी इकट्ठी कर 14 फरवरी 2020 को पुलवामा हमले की पहली बरसी पर पुलवामा में ही भारत के नक्शा जैसी स्मारक का निर्माण करवाएंगे। यहां शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी के कलशों को भी सुशोभित किया जाएगा ताकि स्मारक पर आने वाला हर शख्स इस मिट्टी से तिलक कर सके।

16 राज्यों में किया 47 हजार किमी का सफर : शहीदों को सम्मान दिलाने के मिशन पर निकले उमेश को 9 अप्रैल को सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर बेंगलुरु के डीआइजी सानंद कमल ने पुलवामा हमले के 40 शहीदों के घर का पत्र सौंप उन्हें शहीदों के घरों के लिए रवाना किया था। उमेश ने बताया कि वह अभी तक कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, पुडुचेरी, महाराष्ट, मध्यप्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर सहित 16 राज्यों में 47 हजार किमी की यात्रा करके पंजाब पहुंचे हैं।

पुलवामा की बरसी पर शुरू करवाएंगे स्मारक का निर्माण : उमेश ने बताया कि अब तक वह पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों के अलावा दर्जनों अन्य शहीदों के परिवार के लोगों से मिल चुके हैं। उनके इस अभियान की समाप्ति अगले वर्ष 9 अप्रैल को होगी। मगर 14 फरवरी को पुलवामा हमले की पहली बरसी पर वह वहां पहुंच कर भारत के नक्शे जैसा स्मारक का निर्माण शुरू करवाएंगे। इसके लिए वह देश भर से कई संस्थाएं उनका सहयोग कर रही हैं।

जिस शहीद के घर गाड़ी नहीं पहुंच पाती वहां साइकिल से जाते हैं उमेश : उमेश ने बताया कि इस मिशन पर वह अकेले निकले हैं तथा शहीदों के घरों के आंगन से मिट्टी इकट्ठी करने अपने एसंट गाड़ी के पीछे मारुति 800 को मॉडीफाई कर उसको रथ का रूप दिया है। इसमें शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी के कलश रखे हुए हैं। इस पर उन्होंने स्कूटी व साइकिल भी रखा हुआ है। जिस शहीद के घर पर गाड़ी नहीं पहुंच पाती और वहां स्कूटी व साइकिल से जाते हैं। रात को वह मंदिरों, गुरुद्वारों व धर्मशालाओं में रुकते हैं।

पहल

माउंट आबू प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है, भालू अभ्यारण्य बनने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की काफी उम्मीद है

राजस्थान में बनेगा देश का चौथा भालू अभ्यारण्य

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में भालू अभ्यारण्य बनाया जाएगा। यह प्रदेश का पहला और देश का चौथा भालू अभ्यारण्य होगा। भालू अभ्यारण्य को सुंधा माता क्षेत्र में करीब 444 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया जाएगा।

भालू अभ्यारण्य सिरोही जिले की माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र के 326 वर्ग किलोमीटर और जालौर के संधु माता कंजरवेशन रिजर्व के 117.49 वर्ग किलोमीटर के जंगल को मिलाकर बनाया जाएगा। इस इलाके में काफी जंगल होने से भालूओं की संख्या भी बहुत है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र के जंगल में 352 भालू हैं। वहीं संरक्षित क्षेत्र के बाहर जालौर जिले में 58 और सिरोही जिले में 63 भालू मौजूद है। इन दोनों इलाकों में भालू के अलावा बाघ, भेड़िये, लकडबग्घा और चिंकारा आदि वन्यजीव भी काफी संख्या में है। वैसे तो प्रदेश के रणथंभौर, सरिस्का और मुकंदरा हिल्स आदि सेंचुरी में भालूओं की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन उसके बावजूद भालुओं का गढ़ हमेशा से ही माउंट आबू को माना जाता रहा है। माउंट आबू प्रदेश का एकमात्र पवर्तीय पर्यटन स्थल है। वन और पर्यटन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि अब भालू अभ्यारण्य बनने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। इससे सिरोही और जालौर दोनों जिलों के लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

पहले मदारी खेल दिखाते थे : एक दौर था जब जंगल के सबसे ज्यादा बालों वाले जीव भालू का वजूद सिर्फ मदारी के डमरू तले दबकर रह गया था, लेकिन बाद में मदारियों पर भालू रखने और उसका तमाशा दिखाने पर पाबंदी लग गई। लेकिन फिर भी भालू जंगल में संरक्षण के लिए तरसता रहा। टाइगर के मुकाबले भालू को सरकारी संरक्षण नहीं मिल सका। लोगों का भी लगाव खत्म हो गया। अब इसके लिए अलग से अभ्यारण्य बनने के बाद इनकी स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। वन्यजीवों के संरक्षण के तहत राज्य सरकार ने जयपुर के झालाना में लेपर्ड कंजरवेंसी बनाई है।

उत्तराखंड में वन्यजीव पर्यटन के बादशाह कार्बेट व राजाजी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- वन्यजीव पर्यटन को 77 फीसद सैलानी इन्हीं टाइगर रिजर्व में करते हैं रुख
- अन्य राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों में सैलानियों की आमद अभी भी कम

विश्व प्रसिद्ध कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में वन्यजीव पर्यटन के सबसे बड़े डेस्टिनेशन के रूप में अपनी बादशाहत बनाए हुए हैं। वन्यजीव पर्यटन के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। गुजरे सीजन यानी एक अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 तक राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों व कंजर्वेशन रिजर्व में आए 4.72 लाख पर्यटकों में 77 फीसद ने कार्बेट व राजाजी का रुख किया। ऐसी ही स्थिति इससे पहले के सीजनों में भी रही। अलबत्ता, अन्य संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवन का दीदार को पर्यटकों की आमद काफी कम है।

कार्बेट टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व के मामले में देश के सभी टाइगर रिजर्व में अव्वल है तो राजाजी रिजर्व उत्तर भारत में हाथियों की अंतिम पनाहगाह। लिहाजा, इनका आकर्षण सर्वाधिक है। इनके नजदीक अन्य डेस्टिनेशन भी हैं। मसलन, राजाजी के इर्द- गिर्द हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे शहर हैं। ऐसी ही स्थिति कार्बेट की है। पहुंच भी सुगम होने से सैलानी इन्हें तवज्जो देते आए हैं। बीते सीजन में भी इन रिजर्व पर पर्यटकों का दबाव रहा। अलबत्ता, दुर्गम और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित अन्य संरक्षित क्षेत्रों में आसान पहुंच न होने से सैलानियों का रुख कम रहा। राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजीव भरतरी भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। उनके अनुसार कार्बेट व राजाजी से इतर भी संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन बढ़े, इसके लिए हिमालयी क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों की दरें समान की जा रहीं। कार्बेट व राजाजी में प्रवेश शुल्क, ठहरने की दरों में इजाफा किया जा रहा है।

जॉनसन एंड जॉनसन ने जीता कैंसर संबंधी मुकदमा

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिका की एक अदालत ने कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर कैंसर कारक नहीं है। इस मामले में मिसौरी की एक महिला ने कंपनी के बेबी पाउडर पर कैंसर कारक होने का आरोप लगाया था। ऐसे मामलों में यह चौथा फैसला है, जो कंपनी के पक्ष में रहा है। कंपनी ने बताया कि ज्यूरी ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर की रिसर्च का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि इसमें कैंसर-कारक तत्व नहीं हैं।

टेलीकॉम सेक्टर के लिहाज से भारत एक विश्वस्तरीय निवेश बाजार है। मुझे उम्मीद है कि विश्वस्तरीय कंपनियां आगामी टेलीकॉम नीलामी में इस मौके का फायदा उठाएंगी।

— अंशु प्रकाश, टेलीकॉम सचिव

सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता छोड़ खर्च पर फोकस करना होगा

साक्षात्कार

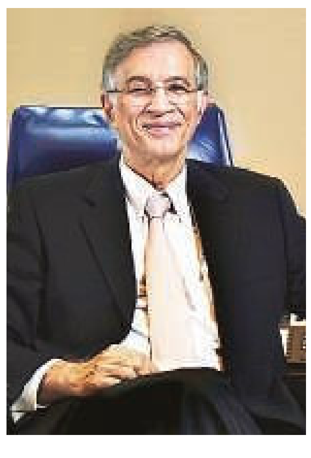

अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। आर्थिक विकास की तिमाही दर साढ़े चार परसेंट तक नीचे आ चुकी है। उद्योग बैंकों से कर्ज नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं तो सरकार बीते तीन महीने से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के प्रयास कर रही है। ऐसे वक्त में उद्योग सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उद्योग चैंबर एसोचैम के नवनियुक्त प्रेसिडेंट **निरंजन हीरानंदानी** ने पद संभालने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख **नितिन प्रधान** से बातचीत में कहा कि सरकार की तरफ से अभी और कदमों की दरकार है।

● **मौजूदा अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं और सरकार से अभी और क्या उम्मीद है?**

- सरकार लगातार उद्योगों की बात सुन रही है और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कदम उठा रही है। मेरी राय में उद्योगों के बैंक कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जिस प्रकार साल 2008 के वित्तीय संकट के दौरान उद्योगों को कर्ज के भुगतान में राहत और उन्हें अदा करने के लिए ज्यादा मोहलत दी गई थी, उसी प्रकार वर्तमान में भी उद्योगों को वक्त मिलना चाहिए। अधिकांश उद्योग इस समय संकट में हैं। चाहे वह ऑटोमोबाइल हो, रियल एस्टेट हो या एसएमई सेक्टर। मांग नहीं होने से कंपनियों की उत्पादन क्षमता सीमित हो गई हैं। कंपनियों ने विस्तार के लिए जो कर्ज लिए थे उनका भुगतान मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि कंपनियों के ये लोन एनपीए में बदलें, उससे पहले इनकी रिस्ट्रक्चरिंग का काम हो जाना चाहिए।

● **लेकिन सरकार ने उद्योगों को राहत देने के लिए कई अन्य उपाय किए हैं...**

-आपकी बात एकदम सही है। सरकार लगातार कदम उठा रही है। लेकिन जो स्थिति अभी है उसमें राहत के और भी कई उपायों की आवश्यकता है। सरकार से उद्योगों को अब तक जितना भी मिला है वह काफी नहीं है।

● **इस संबंध में आपके और क्या सुझाव हैं?**

-मेरी समझ में कुछ समय के लिए जीएसटी की दर में कम से कम 25 परसेंट की राहत देने की आवश्यकता है। यह राहत कुछ उत्पादों या सेवाओं पर नहीं, बल्कि जीएसटी के समूचे समूह पर लागू किया जाना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज करने के लिए ईंधन मिलेगा। अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होगी और उसका पहिया घूमने की गति बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो सप्लाई साइड पर भी दबाव बनेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हर कंपनी निवेश करने को तैयार है। इसलिए डिमांड बढ़ाने के लिए जीएसटी में छूट देनी चाहिए।

● **सरकार की दिक्कत यह है कि रेवेन्यू की धीमी रफ्तार उसे इस तरह के कदम उठाने से रोकती है। उसे राजकोषीय संतुलन का भी ध्यान रखना है...**

-मेरा मानना है कि सरकार को अभी अपने राजकोषीय प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो उसे बढ़ने देना चाहिए। लेकिन आज के वक्त की जरूरत सिस्टम में खर्च की रफ्तार को तेज करना है। फिस्कल डेफिसिट एक नंबर है। हमें अपने देश के लोगों को समृद्ध बनाने पर फिलहाल ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अपने लक्ष्यों को बढ़ा देना चाहिए। मसलन, देश में सड़क बनाने के लक्ष्य को दोगुना कर देना चाहिए। नई सरकारी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी मांग बढ़ेगी जिसका सकारात्मक असर सप्लाई साइड पर होगा।

● **सरकार को किन क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए।**

- देखिए, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सरकार अगर अपना फोकस बढ़ाए तो उसके नतीजे अर्थव्यवस्था में दिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें पहला इन्फ्रास्ट्रक्चर है। इसमें अगर आवास और शहरी ढांचे के विकास को भी जोड़ लिया जाए तो अर्थव्यवस्था में तेजी पैदा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार को टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। आज हमारे कई पड़ोसी देश केवल सरकारी प्रोत्साहन मिलने से टेक्सटाइल के क्षेत्र में दुनिया के बाजार में हमसे आगे निकल रहे हैं। इसी तरह पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, जहां हम दुनिया के निवेशकों से लेकर पर्यटकों तक को आकर्षित कर सकते हैं। इससे देश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। एमएसएमई और एजुकेशन व स्किल दो अन्य क्षेत्र हैं जहां अगर सरकार प्रोत्साहन दे तो नतीजे काफी सकारात्मक हो सकते हैं। इन सभी सेक्टरों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

न्यूज गैलरी

एसबीआइ नहीं लेगा ई-बीआरसी शुल्क

नई दिल्ली : निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी कर्जदाता एसबीआइ ने बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट (ई-बीआरसी) जारी करने के किए लिया जाने वाला शुल्क माफ कर दिया है। ई-बीआरसी के लिए बैंक 1,000 रुपये फीस के रूप में लेते हैं। यह शुल्क देश से एक्सपोर्ट होने वाले प्रत्येक शिपमेंट पर लगाया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसबीआइ ने यह फैसला केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के निर्देश पर लिया है। इस दौरान एसबीआइ ने कहा है कि गलती से लिया गया शुल्क वापस लौटा दिया जाएगा। (एएनआइ)

बड़ी कंपनियों और एमएसएमई से से बातचीत कर रही सरकार

नई दिल्ली : सरकार बड़े उद्योगों और एमएसएमई के कारोबार में आने वाली मुश्किलों की पहचान कर रही है। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय 25 बड़े कॉरपोरेट और 25 एमएसएमई ग्रुप्स से सलाह-मशविरा कर रहा है। इसके तहत कारोबार में आने वाली समस्याओं की पहचान करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार इस कोशिश के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे नई नौकरियां पैदा की जा सकें। इसी क्रम में टाटा, विप्रो, भारती ग्रुप और कुछ अन्य बड़े उद्योग घराने पीयूष गोयल से मुलाकात कर चुके हैं। गोयल लगातार एमएसएमई ग्रुप के साथ भी बैठक कर रहे हैं। (आइएएनएस)

देरी के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ी

नई दिल्ली : देरी और अन्य कारणों के चलते 150 करोड़ रुपये या अधिक कीमत के 377 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत में 3.94 लाख करोड़ का इजाफा हो चुका है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक 1,635 प्रोजेक्ट्स में से 377 की लागत में इजाफा हुआ है, जबकि 565 प्रोजेक्ट्स की अवधि तय सीमा से ज्यादा हो चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स की शुरुआती लागत 19,47,462.67 करोड़ रुपये थी जो देरी के कारण बढ़कर 3,41,784.84 करोड़ रुपये पहुंच गई है। इस तरह लागत में 3,94,322.17 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। (प्रेट्र)

देश के स्टील उत्पादन में लगातार दूसरे महीने गिरावट

नई दिल्ली : नवंबर में लगातार दूसरे महीने भारत के स्टील उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान यह 2.8 परसेंट गिरकर 89.34 लाख टन रहा। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 91.92 लाख टन रहा था। इससे पहले अक्टूबर के महीने में स्टील उत्पादन में 3.4 परसेंट की गिरावट देखी गई थी। उस दौरान यह 90.89 लाख टन रहा था। (प्रेट्र)

वजह ▶ आइपी-1, आइपी-2 और आइएसपी लाइसेंस का मामला

डीओटी ने गेल से मांगा करीब पौने दो लाख करोड़ बकाया

गेल का किसी भी तरह का पुराना बकाया होने से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैस यूटिलिटी कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड से 1.72 लाख करोड़ रुपये का पुराना बकाया चुकाने को कहा है। यह मांग विभिन्न सरकारी बकाया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की गई है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया कि डीओटी ने गेल को एक पत्र लिखकर आइपी-1 और आइपी-2 लाइसेंस के साथ-साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आइएसपी) लाइसेंस के संबंध में 1,72,655 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने को कहा है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कैटेगरी-1 (आइपी-1) ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर होते हैं, जो टेलीकॉम सर्विसेज लाइसेंसी को डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस और टावर जैसी चीजें मुहैया कराते हैं। गेल के पास गैस पाइपलाइन का विशाल नेटवर्क है। कंपनी ने इसके साथ ऑप्टिक फाइबर बिछा रखी है, ताकि थर्ड पार्टी को बैंडविद्थ उपलब्ध कराई जा सके। सरकार ने दिसंबर, 2005 से आईपी-2 लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। डीओटी की चिट्ठी के जवाब में गेल ने कहा है कि उसने सरकार को पहले ही सभी भुगतान कर दिए हैं और अब उस पर कोई बकाया नहीं है। कंपनी ने डीओटी से कहा है कि उसने साल 2002 में 15 वर्षों के लिए आइएसपी लाइसेंस लिया था, जिसकी अवधि 2017 में पूरी हो गई। लेकिन, उसके बाद से गेल ने उस लाइसेंस के तहत कोई बिजनेस नहीं किया और इसलिए कोई आय ही नहीं हुई, जिसके लिए भुगतान की जरूरत पड़े।

आइपी-1 और आइपी-2 लाइसेंस के बारे में गेल ने डीओटी से कहा है कि साल 2001-02 से उसे सिर्फ 35 करोड़ रुपये की आय हुई है, जबकि पिछले बकाये की गणना 2,49,788 करोड़ रुपये आय के आधार पर की गई है। डीओटी ने सभी दूरसंचार कंपनियों से 1.47 लाख करोड़ रुपये के बकाये की मांग की है। जहां तक गैर-दूरसंचार कंपनियों की बात है, विभाग ने गेल के अलावा पावरग्रिड से भी 1.25 लाख करोड़ रुपए के पुराने बकाये की मांग की हुई है। लेकिन, पावरग्रिड का कहना है कि 2006-07 से उसे 3,566 करोड़ रुपये का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) प्राप्त हुआ है। इसमें जुर्माने की रकम जोड़ने पर कुल बकाया 22,168 करोड़ रुपये बैठता है।

नेटवर्थ से तीन गुना ज्यादा की मांग : सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग गेल से जो बकाया भुगतान की मांग कर रहा है, वह रकम गेल के नेटवर्थ के तीन गुना से ज्यादा है। यह कंपनी की वास्तविक आय से भी कुछ गुना ज्यादा बैठता है।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इस साल 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि सरकार की तरफ से आवंटित स्पेक्ट्रम या वायुतरंगों के इस्तेमाल से कंपनियों को जो नॉन-टेलीकॉम आय होती है, सरकारी बकाये की गणना में उन्हें शामिल किया जाए। इस मामले में चुनौती यह है कि हो सकता है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों को सरकारी लाइसेंस के इस्तेमाल से नॉन-टेलीकॉम आय हुई हो, लेकिन गेल जैसी कंपनियों को इस तरह की कोई आय नहीं हुई है।

आर्थिक सुस्ती के बीच भी इस वर्ष मेहरबान रहे एफपीआइ

▶ पिछले छह वर्ष में सबसे अधिक रहा विदेशी निवेश

▶ 2020 में भी इस स्थिति के बने रहने की उम्मीद

इस वर्ष एफपीआइ ने अब तक एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश किया है। प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : ग्रोथ रेट में गिरावट के चलते बनी नकारात्मक धारणा को दरकिनार करते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने इस वर्ष अब तक भारतीय बाजारों में जमकर निवेश किया है। इस वर्ष अब तक एफपीआइ घरेलू बाजारों में कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। इसमें 97,250 करोड़ रुपये इक्विटी मार्केट में निवेश किए गए, जो पिछले छह वर्षों में सबसे अधिक है।

इस अवधि में एफपीआइ ने डेट मार्केट में 27,000 करोड़ रुपये निवेश किए। शेष 9,000 करोड़ रुपये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में निवेश किए गए। जानकारों का मानना है कि अगले वर्ष भी यही स्थिति बने रहने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका-चीन ने ट्रेड-वार के मामले पर पिछले दिनों कदम वापस लिए हैं। जानकार यह भी मानते हैं कि किन्हीं वजहों से इसके गहराने या घरेलू क्रेडिट मार्केट में किसी विपरीत स्थिति के पैदा होने पर हालात बदल भी सकते हैं।

बजाज कैपिटल के रिसर्च हैड आलोक अग्रवाल के मुताबिक ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के अनुकूल रहने, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती और घरेलू कॉरपोरेट मुनाफे में वृद्धि की उम्मीदों के चलते अगले वर्ष भी विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में निवेश की रफ्तार बरकरार रख सकते हैं। हालांकि ट्रेड वार, कच्चे तेल के भाव में तेजी और एनबीएफसी में नकदी संकट बने रहने से खेल खराब हो सकता है।

डिपॉजिटरी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने इस वर्ष अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपये की सकल खरीद (ग्रॉस परचेज) की है। इस दौरान उन्होंने 16.7 लाख करोड़ रुपये की सिक्युरिटीज को इक्विटी, डेट और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बेच दिया। इस तरह से 1.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश बरकरार रहा। यह पिछले पांच वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा इनफ्लो है।

जानकारों के मुताबिक कुछ ग्लोबल और घरेलू वजहों से भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेश बढ़ा है। इनमें अमेरिकी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड समझौते की उम्मीद और भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती जैसी वजहें शामिल रहीं। मार्निंगस्टार के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु श्रीवास्तव के मुताबिक मोदी सरकार द्वारा सत्ता में की गई मजबूत वापसी और आरबीआइ द्वारा ब्याज दरों में लगातार कटौती की वजह से विदेशी निवेशकों में मजबूत धारणा बनी।

बीएस-6 से डीजल और पेट्रोल पर बढ़ेगा कीमत का बोझ

▶ डीजल पर 0.80 और पेट्रोल पर 1.50 रुपये का प्रीमियम प्रस्तावित

▶ बीएस-6 ईंधन के विकास पर किया खर्च वापस चाहती हैं कंपनियां

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्र सरकार इस समय तेल कंपनियों के उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें पेट्रोल-डीजल पर प्रीमियम लगाने की मांग उठाई गई है। इससे आने वाले महीनों में डीजल-पेट्रोल के भाव में इजाफा होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक निजी और सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने सरकार से आग्रह किया है कि बीएस-6 ईंधन के विकास में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए उन्हें पेट्रोल-डीजल पर प्रीमियम वसूलने की मंजूरी दी जाए।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का यह प्रस्ताव अगर सरकार स्वीकार कर लेती है, तो अगले पांच वर्षों के लिए डीजल पर 0.80 रुपये और पेट्रोल पर 1.50 रुपये प्रति लीटर प्रीमियम लगाया जा सकता है। इससे इनकी उपभोक्ता कीमत में इजाफा होगा। पिछले कई महीनों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत में स्थिरता बनी हुई है। इसका असर तेल की खुदरा कीमत पर भी दिखाई पड़ा। इस दौरान ओएमसी द्वारा कई बार डीजल-पेट्रोल की कीमत में कटौती भी की गई है। प्रीमियम लगने के बाद ग्राहकों को अनिवार्य रूप से अतिरिक्त राशि देनी होगी।

बीएस-6 ईंधन के विकास में तेल कंपनियों ने काफी निवेश किया है। सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने इसके लिए करीब 80 हजार करोड़ रुपये निवेश किए हैं। इसके साथ ही निजी कंपनियों नयारा एनर्जी (पहले एस्सार) और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी इसमें बड़ा निवेश किया है। कंपनियां चाहती हैं कि प्रीमियम के माध्यम से इनके निवेश का कुछ हिस्सा इन्हें वापस मिल जाए। गौरतलब है कि अगले वर्ष अप्रैल से बीएस-6 ईंधन का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार बढ़ने से ऑयल मार्केट के दबाव में आने की आशंका है। ऐसे में अगर बीएस-6 ईंधन के विकास में खर्च किया गया फंड रिकवर नहीं होता है, तो तेल कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का संकेत पहले ही दे चुकी है।

रिलायंस ने अदालत में सरकार को सुनाई खरी-खोटी

▶ सरकार ने की है सऊदी अरैमको के साथ 15 अरब डॉलर की प्रस्तावित डील रोकने की मांग

▶ रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी पार्टनर कंपनियों पर 3.5 अरब डॉलर के बकाये को बनाया है आधार

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र: मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) ने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार की उस याचिका के बचाव में तगड़ी दलील दी है, जिसके जरिये सऊदी अरैमको के साथ 15 अरब डॉलर की प्रस्तावित डील रोकने की मांग की गई है। कंपनी का कहना है कि यह अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि कंपनी पर बकाये की देनदारी को लेकर कोई भी अंतिम मध्यस्थता फैसला नहीं आया है।

इस वर्ष अगस्त में आरआइएल ने कहा था कि सऊदी अरैमको ने 15 अरब डॉलर में कंपनी के पेट्रोलियम एवं केमिकल बिजनेस में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने संबंधी गैर-बाध्यकारी करार किया है। सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी थी एक एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने रिलायंस और उसके साझेदारों से 3.5 अरब डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है।

रिलायंस ने सरकार की याचिका के खिलाफ पेश हलफनामे में कहा है सरकार का यह दावा पूरी तरह गलत है। किसी भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कंपनी और उसके साझेदारों के खिलाफ कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। कंपनी ने हलफनामे में कहा है, 'याचिका कानूनी प्रक्रिया का बेजा इस्तेमाल है। इसमें कहा गया है कि कुछ रकम बकाया है और एक अंतिम फैसले के तहत उसका भुगतान किया जाना है। इस मामले में बकाया भुगतान के लिए जिस आधार पर रकम की गणना की गई है, उसका जिक्र न तो मध्यस्थ के फैसले में है और न ही याचिका में उसके बारे में कुछ बताया गया है।'

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुताबिक सरकार ने कंपनी के तेल-गैस उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी के संशोधित आंकड़े के हिसाब से खुद ही बकाया रकम की गणना कर ली है। पन्ना-मुक्ता और ताप्ती तेल-गैस क्षेत्र से उत्पादन के मामले में कंपनी पर सरकार के 3.5 अरब डॉलर लंबित बकाये को इसका आधार बताया गया है।

कानूनी पेंच

दरअसल, अक्टूबर 2016 में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक आंशिक फैसला सुनाया था। वह फैसला भारत सरकार, बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच पन्ना-मुक्ता एवं ताप्ती प्रोडक्शन शेयरिंग कांट्रैक्ट्स (पीएससी) विवाद पर आया था। उस फैसले में न्यायाधिकरण ने सिद्धांतों से जुड़े कुछ मसलों की पहचान की थी। लेकिन, उसमें किसी बकाया रकम के भुगतान का आदेश नहीं था। इस मामले में न्यायाधिकरण की तरफ से बकाया रकम (यदि निकलती हो) का निर्धारण उसी सूरत में किया जाएगा, जब तमाम संबंधित मसलों पर फैसला आ जाए।

सरकारी कंपनियों को कड़ी टक्कर देंगे रिलायंस-बीपी के पेट्रोल पंप

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटेन की कंपनी बीपी पीएलसी जियो-बीपी ब्रांड के तहत पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दे रही हैं। दोनों कंपनियां मिलकर अगले पांच वर्षों में पेट्रोल पंपों की संख्या 5,500 तक पहुंचाने का इरादा रखती हैं, जिसमें रिलायंस के मौजूदा 1,400 पंप शामिल हैं। मॉर्गन स्टेनले ने एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि इससे सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी प्रभावित होगी।

वजह

सेंसेक्स की सूची में इस सप्ताह होगा फेरबदल, बुधवार को क्रिसमस के मौके पर बंद रहेंगे बाजार, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी भी होनी है इस सप्ताह

बाजारों में इस सप्ताह सुस्ती के संकेत

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले कुछ सत्रों में लगातार बढ़त दर्ज करने के बाद इस सप्ताह देश के प्रमुख शेयर बाजारों में सुस्त कारोबार की संभावना है। इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हलचल प्रस्तावित नहीं है। हालांकि सेंसेक्स की सूची में फेरबदल के चलते स्टॉक-विशेष में उठापटक देखी जा सकती है। बुधवार को क्रिसमस की छुट्टी के कारण बाजार बंद रहेंगे।

इस सप्ताह टाटा मोटर्स, यस बैंक और वेदांता को बीएसई के बेंचमार्क सेंसेक्स से बाहर कर दिया जाएगा। इनकी जगह अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन और नेस्ले इंडिया लेंगी। जानकारों के मुताबिक इस फेरबदल के कारण कुछ स्टॉक्स के भाव में उतार-चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर अपने फोर्टफोलियो को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही गुरुवार को दिसंबर सीरीज के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) भी एक्सपायर हो जाएंगे।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के मुताबिक निवेश को आकर्षित करने के लिए आगामी बजट को में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। निवेशकों के मूड पर इसका असर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा बाजार की नजर डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत और कच्चे तेल के भाव पर भी रहेगी। पिछले सप्ताह विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में जमकर निवेश किया था और बाजारों को ऊपरी स्तर पर बनाए रखा था। इस बार भी यह निवेशक बाजार की चाल को प्रभावित करेंगे।

इस सप्ताह आरबीआइ ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के जरिये 10,000 करोड़ रुपये की सरकारी सिक्युरिटीज की खरीद-फरोख्त करेगी। निवेशकों की नजरें केंद्रीय बैंक के इस कदम पर भी बनी रहेंगी। पिछले सप्ताह बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 671.83 अंक का इजाफा हुआ।

शीर्ष 10 में आठ कंपनियों का एम-कैप बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले सप्ताह शेयर बाजार की शीर्ष 10 में आठ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 1.13 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। टीसीएस के एम-कैप में सबसे तेज उछाल आया। इसके साथ ही आरआइएल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस और एसबीआइ के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई। हालांकि एचयूल और आइटीसी के बाजार पूंजीकरण में गिरावट देखने को मिली। टीसीएस का एम-कैप 56,604.72 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ 8,33,986.26 करोड़ रुपये रहा। एचडीएफसी बैंक का पूंजीकरण 18,475.04 करोड़ रुपये बढ़कर 7,09,932.25 करोड़ रुपये हो गया।

बैंकों के पास पूंजी की कोई कमी नहीं बेहिचक कर्ज ले उद्योग : एसबीआइ

▶ चेयरमैन ने कहा – बैंकों की कर्ज देने की क्षमता अच्छी, मगर मांग नहीं

▶ चालू वित्त वर्ष के अंत तक बैंकों की क्षमता और मजबूत होने की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने उद्योगपतियों से आह्वान किया है कि वे इकोनॉमी में निवेश बढ़ाने के लिए अपनी कर्ज क्षमता को मजबूत करें। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने फिक्की के कार्यक्रम में कहा कि बैंकों के पास पूंजी की कोई कमी नहीं है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक उनके फंसे कर्ज (एनपीए) में उल्लेखनीय कमी आने वाली है। ऐसे में वे उद्योगों को और कर्ज देने की हालत में होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एसबीआइ कर्ज देने की अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि उद्योग जगत से कर्ज की मांग ही नहीं हो रही है।

कुमार ने कहा, 'निवेश बढ़ाए बगैर देश की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देना संभव नहीं है। वर्तमान में बैंकों का कुल कर्ज 96 लाख करोड़ रुपये है। इकोनॉमी को पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने के लिए इस कर्ज को कम से कम दोगुना तक पहुंचाना होगा।' उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं जहां से निवेश की मांग आ रही हो। जो थोड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वे सोलर एनर्जी, सिटी गैस और कुछ हद तक सड़क परियोजनाओं से जुड़े हैं। एसबीआइ प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मदद देने वाला सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन क्षमता का पूरा उपयोग ही नहीं हो पा रहा है।

कुमार का कहना था कि पिछले वर्ष सही मायने में बड़ा प्रोजेक्ट माने जा सकने वाले केवल दो को बैंकों ने वित्तीय मदद दी। इनमें एक राजस्थान में एचपीसीएल की परियोजना थी जिसका आकार करीब 50,000 करोड़ रुपये था। दूसरी परियोजना मुंबई नागपुर सुपर कम्यूनिकेशन एक्सप्रेसवे थी और उसका आकार भी करीब इतना ही बड़ा था।

सीमा से ज्यादा दरें घटा नहीं सकते

नई दिल्ली, प्रेट्र : एसबीआइ के चेयरमैन रजनीश कुमार का कहना है कि भारत में वित्तीय सामाजिक सुरक्षा चक्र कमजोर है। इसलिए बैंक कंपनियों को एक सीमा से ज्यादा सस्ता कर्ज मुहैया नहीं करा सकते, क्योंकि उनकी डिफॉल्ट दर बेहद ऊंची है। कुमार ने कहा, 'देश का बैंकिंग सिस्टम एक हद तक जमाकर्ताओं पर निर्भर है। अगर हम सस्ता कर्ज देते हैं, तो जमाकर्ताओं को कम ब्याज देंगे। लेकिन जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों का है, जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा बैंक जमाओं पर ब्याज से ही आता है।

2016 में सत्ता संभाली थी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने कट्टरपंथी पूर्ववर्ती इस्लाम करीमोव के निधन के बाद। करीमोव ने लगभग तीन दशकों तक शासन किया था। अब यहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं।

महाभियोग प्रक्रिया से बढ़ी मेरी लोकप्रियता : ट्रंप

मियामी, एजेंसियां : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अनुचित महाभियोग प्रक्रिया से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। फ्लोरिडा में युवाओं के एक सम्मेलन में उन्होंने ना केवल विपक्ष पर हमला बोला बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने महाभियोग से संबंधित दस्तावेजों को अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट को नहीं सौंपने के लिए निचले सदन प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी की आलोचना भी की। सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है।

फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में आयोजित युवा सम्मेलन में शनिवार को एक घंटे के भाषण में ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट के पास मेरे खिलाफ कोई सुबूत नहीं है। इसके बावजूद वे अवैध और असंवैधानिक महाभियोग चलाने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि पिछले एक महीने के दौरान उन्होंने जितना काम किया है वह किसी राष्ट्रपति ने आठ वर्षों के कार्यकाल में नहीं किया। इसमें चीन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, रक्षा खर्च और अंतरिक्ष सेना का निर्माण शामिल है। उन्होंने आगाह किया कि अगर नवंबर, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई तो देश पीछे चला जाएगा। बता दें कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद विपक्षी दल हर तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरने पर जुटा है।

महाभियोग से संबंधित दस्तावेजों को सीनेट को नहीं सौंपने के लिए नैंसी पेलोसी की राष्ट्रपति ने की आलोचना

फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच के काउंटी कंवेंशन सेंटर में टर्निंग प्वाइंट यूएसए स्टूडेंट एक्शन समिट को संबोधित करते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

अपनी किताब के जरिये भारतवंशी अमेरिकियों से जुड़ेंगे ट्रंप जूनियर

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपनी किताब 'ट्रिगर्ड' के माध्यम से भारतवंशी अमेरिकियों से जुड़ने की पहल की है। इसके तहत वह अगले साल कई शहरों में बुक टूर का आयोजन करने जा रहे हैं। इस काम में उनका सहयोग टीवी स्टार किंबरली गुइलफॉय करेंगे। नवंबर की शुरुआत में बाजार में आई 'ट्रिगर्ड' न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स में शामिल हो चुकी है।

ट्रंप जूनियर की इस कवायद को जानकार अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय मतदाताओं को लुभाने के प्रयास के तौर पर देख रहे हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले न्यूयॉर्क स्थित वैश्विक सलाहकार अल मेसन ने कहा, अगले कुछ महीनों में ट्रंप जूनियर उन सभी प्रमुख शहरों और राज्यों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं जहां भारतवंशियों की अच्छी-खासी तादाद है। इन शहरों में न्यूयॉर्क, शिकागो, ह्यूस्टन, डलास आदि शामिल हैं।

हमले तेज होने के बाद दो दिन में सीरिया से तुर्की पहुंचे 25 हजार लोग

अंकारा, रायटर : सीरिया के इदलिब प्रांत में हवाई हमले तेज होने के बाद पिछले दो दिनों में 25 हजार लोग भागकर पड़ोसी मुल्क तुर्की पहुंचे हैं। सीरिया की असद सरकार और उसकी सहयोगी रूसी सेना के हवाई हमलों से भयभीत लोग अपना घर-बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं।

तुर्की में पहले से ही युद्धग्रस्त सीरिया से भागे 37 लाख लोगों ने शरण ले रखी है, जो दुनिया के किसी देश में शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या है। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार, बीते दो माह में इदलिब से पलायन करने वालों की संख्या दो लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने इस पर चिंता जताते हुए बीते गुरुवार को कहा था कि युद्ध के कारण 50 हजार सीरियाई नागरिक उनके देश की तरफ बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, सीरिया में विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाके में रूस समर्थित सेना के हमले में इस साल सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हो चुके है, जिन्हें इलाज भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है।

आइटी सिस्टम में गड़बड़ी से सैकड़ों भारतीय कर्मियों का भविष्य बर्बाद

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में सैकड़ों सब पोस्टमास्टर आइटी सिस्टम में आई गड़बड़ी के कारण धन चुराने के मामले के आरोपित बन गए। गलत तरीके से आरोपित हुए इन कर्मियों में से तमाम भारतीय मूल के हैं।

इसी सप्ताह हाई कोर्ट के न्यायाधीश हाई फ्रेजर ने 57.8 मिलियन पाउंड की धनराशि के मामले निस्तारित किए। ये मामले पोस्ट ऑफिस लिमिटेड और 550 दावेदारों के थे। दावेदारों के अधिवक्ता ने कहा है कि अब उनके मुवक्किल आराम से सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। पता चला है कि करीब 20 साल पहले ज्यादातर सब पोस्टमास्टर पोस्ट ऑफिस में स्वतंत्र प्रबंधक के रूप में कार्य करते थे। उस समय धन की चोरी, धोखाधड़ी और झूठे लेनदेन के मामले अक्सर हो जाते थे। इसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम हॉरिजन को जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन कई मामलों में सब पोस्टमास्टर जिम्मेदार ठहराए गए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कोर्ट ने गड़बड़ी के तमाम मामलों पर सुनवाई पूरी करते हुए इसे हॉरिजन सिस्टम की खामी बताया जिसके चलते पोस्ट ऑफिस के बही खातों में विसंगति पैदा हुई।

ब्रिटिश हाई कोर्ट ने पोस्ट ऑफिस से जुड़े 20 साल पुराने मामलों को निस्तारित किया

ब्रिटिश हाई कोर्ट। फाइल

सन 1987 से पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रहे भारतीय मूल के विपिन चंद्र पटेल ऑक्सफोर्डशायर के हॉर्सपाथ गांव में तैनाती के दौरान सिस्टम की गड़बड़ी के शिकार हुए। वह कहते हैं कि सिस्टम की गड़बड़ी के कारण उन पर झूठे आरोप लगे और उनका करिअर बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा, एक समय वह समाज के स्तंभ माने जा रहे थे, बाद में उन्हें गलत ठहराकर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। गलत आरोप से लगे झटके ने स्वास्थ्य खराब कर दिया। नौकरी छूटने के बाद और बीमार पड़ने के कारण पत्नी को दुकान खोलनी पड़ी। लेकिन वहां भी ग्राहक उससे बुरा-भला बोलने से नहीं चूकते थे। चूंकि धन की चोरी का आरोप लगा था और आपराधिक मुकदमा चल रहा था, इसलिए थोड़ा ठीक होने पर भी कहीं नौकरी नहीं मिल सकी। इससे हालात में और गिरावट आई। इससे जीवन का मतलब ही खत्म हो गया और मन में आत्महत्या करने का विचार आने लगा। इसी तरह के मामले के शिकार बलविंदर सिंह गिल हुए। उन्हें और उनके परिवार को झूठे आरोप के चलते काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ीं।

न्यूज गैलरी

अमेरिकी सरकार में भारतीय को मिली अहम जिम्मेदारी

ह्यूस्टन : भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक मोनिशा घोष को अमेरिका के संघीय संचार आयोग के मुख्य तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। घोष इस अहम पद को पाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। वह आयोग के प्रमुख अजित पई को सलाह देने के अलावा अमेरिका में प्रौद्योगिकी व इंजीनियरिंग मामलों पर अपना सुझाव देंगी। (प्रेट्र)

अमेरिकी सेना का छठा अंग होगा स्पेस फोर्स : ट्रंप

वाशिंगटन : ट्रंप ने ट्वीट कर अमेरिकी सेना के छठे और सबसे नए अंग की घोषणा कर दी। उन्होंने लिखा, 'अमेरिकी सरकार के सबसे बड़े रक्षा बिल पर गत रात को हस्ताक्षर होते ही अमेरिकी स्पेस फोर्स की औपचारिक शुरुआत हो गई।' स्पेस फोर्स 1947 में वायु सेना के गठन के बाद अमेरिकी सेना का सबसे नया अंग है। फिलहाल अमेरिकी एयर फोर्स स्पेस कमांड के अंतर्गत तैनात 16 हजार जवानों को स्पेस फोर्स की टीम में शामिल किया जाएगा। (एएनआइ)

आपदा के वक्त छुट्टी पर रहे पीएम मॉरिसन ने मांगी माफी

सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे दो लोगों की मौत पर दुख जताते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने माफी मांगी है। हादसे के वक्त वह परिवार के साथ प्रशांत महासागर स्थित अमेरिका के द्वीपीय प्रांत हवाई में छुट्टी मनाने गए थे। हादसे की खबर मिलने पर वह शनिवार को ऑस्ट्रेलिया लौट आए और अगले दिन सिडनी स्थित अग्निशमन मुख्यालय का दौरा किया। (एपी)

दक्षिण यूरोप में आंधी-तूफान से आठ की मौत

पेरिस : यूरोप के दक्षिणी हिस्से के पुर्तगाल, स्पेन व फ्रांस में शुक्रवार और शनिवार को आए तेज आंधी-तूफान से आठ लोगों की मौत की खबर है। बीते दो दिनों में एक के बाद एक तेज बारिश के साथ आई प्रचंड आंधी से इन देशों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। स्पेन में 170 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के कारण कई उड़ानें रद करनी पड़ीं। (एएनआइ)

अमेरिका के लास वेगास में आग से छह की मौत

लास वेगास : अमेरिका के प्रसिद्ध लास वेगास शहर के एक अपार्टमेंट में आग की घटना में छह लोगों की मौत हो गई। शनिवार तड़के लगी आग से तीन मंजिला इमारत पूरी तरह धुएं से भर गई, जिससे दम घुटने से छह लोगों की मौत हो गई। हादसे में 13 घायल भी हुए हैं। आग के लिए बिल्डिंग में अंगीठी का जलना बताया गया है। दमकलकर्मियों ने सूचना मिलते ही बचाव का शुरू कर दिया था और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। (एपी)

अफगानिस्तान में अशरफ गनी ने फिर जीता राष्ट्रपति चुनाव

मिली विजय ▸ मुख्य प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला ने नतीजों को मानने से किया इन्कार

प्रारंभिक नतीजों में गनी को मिले 50 .64 फीसद वोट अब्दुल्ला को मिले हैं केवल 39 .52 फीसद मत

काबुल, एएफपी : अफगानिस्तान में तीन माह पहले हुए चुनाव में राष्ट्रपति अशरफ गनी की जीत हुई है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक नतीजों में गनी ने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50 फीसद वोटों का आंकड़ा पार कर लिया है। गनी की स्पष्ट जीत के बावजूद उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला-अब्दुल्ला ने इन परिणामों को मानने से इन्कार करते हुए इसे चुनौती देने की बात कही है।

स्वतंत्र चुनाव आयोग (आइईसी) के मुताबिक 28 सितंबर को हुए चुनाव में गनी को 50.64 फीसद वोट मिले हैं जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला-अब्दुल्ला 39.52 फीसद मत हासिल कर सके। अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले प्रत्याशियों के पास शिकायत दर्ज कराने का मौका होगा। लेकिन जैसे ही परिणाम घोषित किए गए अब्दुल्ला-अब्दुल्ला के कार्यालय ने कहा, 'हम अपने लोगों, समर्थकों, चुनाव आयोग और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को फिर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी टीम इस फर्जी वोटों के परिणाम को तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक हमारी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता।' प्रारंभिक चुनाव परिणाम पहले 19 अक्टूबर को आने वाले थे, लेकिन तकनीकी मुद्दों और अब्दुल्ला-अब्दुल्ला सहित कई प्रत्याशियों द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों के चलते इसमें देरी होती रही।

19 अक्टूबर को आने वाले थे परिणाम धोखाधड़ी के आरोपों के कारण हुई देरी

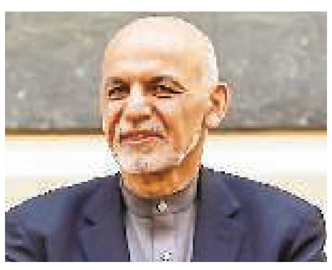
काबुल में एक प्रेस वार्ता के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। रायटर

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बायोमीट्रिक मशीनों का भी हुआ था प्रयोग

संसदीय चुनाव परिणाम की घोषणा करतीं चुनाव आयोग की प्रमुख हवा आलम नूरिस्तानी। रायटर

स्वतंत्र चुनाव आयोग की अध्यक्ष हवा आलम नूरिस्तानी ने कहा, हमने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य पूरा किया है। हमने हर वोट का सम्मान किया क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र का राज कायम हो। अफगानिस्तान में हुए इस चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए जर्मनी की एक कंपनी ने जहां बायोमीट्रिक मशीनों की आपूर्ति की थी वहीं अनियमितताओं के चलते प्रारंभिक 27 लाख वोटरों में से लगभग दस लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। यही वजह रही कि इस चुनाव में अब तक का सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा।

हाफिज पर आतंकी फंडिंग के एक और मामले में आरोप तय

लाहौर, आइएएनएस : पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद और उसके सहयोगियों पर आतंकी फंडिंग के एक और मामले में आरोप तय किए हैं। यह मामला आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) गुजरांवाला ने दर्ज किया था। सईद पर आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग से जुड़े दो दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सुरक्षा कारणों से सभी मामले लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालतों में चलाए जा रहे हैं।

हाफिज सईद।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, हाफिज सईद और अन्य आरोपितों को एटीसी जज के समक्ष पेश किया गया। अदालत में आतंकी सरगना सईद और अन्य आरोपितों ने एफआइआर में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताया। इसके बाद कोर्ट ने जेयूडी नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए और अभियोजन पक्ष को अगली सुनवाई में गवाह पेश करने के लिए कहा। अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद गत तीन जुलाई को जेयूडी के 13 शीर्ष नेताओं के खिलाफ आतंकवाद रोधी अधिनियम 1997 के तहत आतंकी फंडिंग और मनी लांड्रिंग के दो दर्जन मामले दर्ज किए गए थे। सईद को गत 17 जुलाई को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया था। बाद में अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

क्यूबा में 43 साल बाद हुई प्रधानमंत्री की नियुक्ति

मैनुएल मरेरो क्रज (मध्य में) की 43 साल बाद क्यूबा के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है। राजधानी हवाना में नेशनल असेंबसी में सत्र के दौरान उपस्थित क्रज। एएफपी

हवाना, आइएएनएस : अमेरिका के पड़ोस में स्थित क्यूबा में 43 साल बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल ने 56 साल के मैनुएल मरेरो क्रज को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देश की संसद ने शनिवार को सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर लगा दी।

कम्युनिस्ट देश क्यूबा में प्रधानमंत्री का ओहदा राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद है। इससे पहले इस पद पर अंतिम बार क्यूबा के कद्दावर नेता फिदेल कास्त्रो आसीन थे। क्यूबा में लंबे समय तक कम्युनिस्ट शासन की बागडोर अपने हाथों में रखने वाले क्रांतिकारी नेता कास्त्रो ने 1976 में प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया था। इस साल सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुआई में बने नए संविधान में इस पद को फिर से स्थापित कर दिया गया। इसके बाद इस पद पर पहली नियुक्ति क्रज की हुई है। इससे पहले तक क्रज देश के पर्यटन मंत्री थे। कास्त्रो ने 2004 में उन्हें पर्यटन मंत्री बनाया था।

क्यूबा के नए संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति के कामकाज में सहायता करेंगे। उन्हें हर दिन के कामकाज का लेखा-जोखा राष्ट्रपति को सौंपना होगा। क्यूबा के राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति कानेल का ही नाम रहेगा। लेकिन सत्ता का केंद्र कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख राउल कास्त्रो के हाथ में रहेगा।

ग्रीटिंग में चीन के कैदी की गुहार पर टेस्को ने उत्पादन रोका

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन की सुपर मार्केट कंपनी टेस्को ने चीन में अपनी एक उत्पादन फैक्ट्री में काम रोक दिया जब वहां छपे एक क्रिसमस ग्रीटिंग कार्ड में चीन में बंदी एक कार्ड बनाने वाले ने मदद और मुक्त कराने की गुहार लगाई। उस ग्रीटिंग कार्ड में बंधक विदेशी मजदूर ने लिखा था कि उसे बंदी बनाकर उससे मर्जी के खिलाफ काम कराया जा रहा है।

द संडे टाइम्स अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार लंदन की एक छात्रा (फ्लोरेंस विडीकंबे) ने जब पिछले सप्ताहांत एक ग्रीटिंग कार्ड का पैकेट खोला तो उसमें एक ग्रीटिंग में एक मजदूर के हाथ का लिखा संदेश मिला। इस संदेश में चीन के शंघाई स्थित किंगपू जेल के एक कैदी ने अपनी पीड़ा बयान की थी। उसने टेस्को कंपनी के चैरिटी कार्ड के अंदर लिखा था, 'चीन के शंघाई स्थित किंगपू जेल में हम सभी विदेशी कैदी हैं। हम सबसे हमारी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जा रहा है। कृपा कर हमारी मदद कीजिए और मानवाधिकार संगठनों को भी इसकी जानकारी दीजिए।'

टेस्को कंपनी की एक महिला प्रवक्ता ने यह प्रकरण सामने आने के बाद स्तब्धता जाहिर करते हुए कहा कि सेंटा की हैट पहनी एक बिल्ली की तस्वीर वाले ग्रीटिंग कार्ड से हकीकत सामने आने के बाद उस फैक्टरी में उत्पादन तत्काल बंद कर दिया गया है। साथ ही जांच होने वहां बनाए गए ग्रीटिंग की कार्ड की बिक्री भी रोक दी गई है। हम कैदियों से काम कराने का विरोध करते हैं और अपनी आपूर्ति प्रक्रिया में कभी भी इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि टेस्को ब्रिटेन की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है और विश्व में तीसरी सबसे बड़ी सुपरमार्केट कंपनी भी है।

ब्रिटिश कंपनी ने चीनी बंधकों से काम कराने पर जताई अनभिज्ञता

फ्लोरेंस विडीकंबे। साभार : द गार्जियन

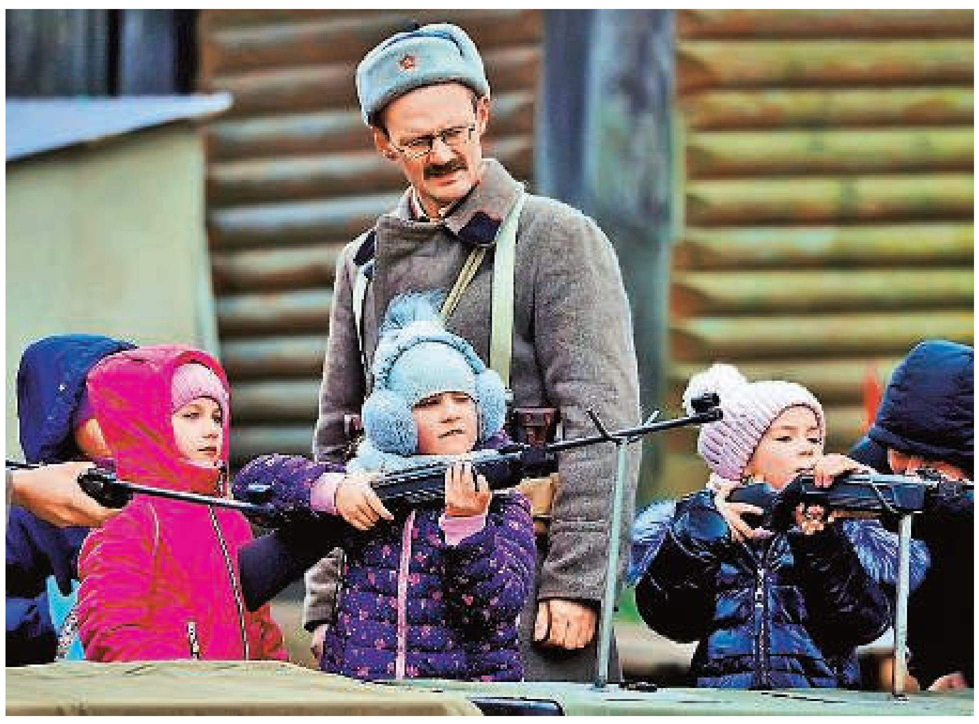

निशाने पर नजर

बेलारूस के गोरोस्की में स्टालिन लाइन स्मारक के पास न्यूमैटिक राइफल से टारगेट पर निशाना लगाते बच्चे। स्टालिन लाइन स्मारक में सैन्य शौकीनों के लिए टैंकों, मिसाइलों, हेलीकॉप्टर्स और सोवियत युद्ध के सभी अन्य तरीकों का संग्रहालय है। यहां हजारों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। रायटर

भारतीयों की मदद के लिए प्रवासी समुदाय को शामिल किया जाए

वाशिंगटन, प्रेट्र : पैसों की कमी के चलते अपने नागरिकों की मदद कर पाने में भारतीय दूतावासों की असमर्थतता को देखते हुए एक प्रख्यात प्रवासी भारतीय (एनआरआइ) ने विदेशों में संकट में फंसे भारतीयों को त्वरित आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए प्रवासी समुदाय, आइसीडब्ल्यूएफ और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों एवं व्यक्तियों को इस प्रक्रिया में शामिल करने का आह्वान किया है। भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आइसीडब्ल्यूएफ) का गठन 2009 में किया गया था। इसका मकसद संकट और आपातकाल में विदेशों में मौजूद ऐसे भारतीय नागरिकों की सहायता करना है जिन्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत हो।

भारत सरकार ने 2017 में, दूतावासों एवं वाणिच्य दूतावासों को प्रत्येक निधि की अदायगी के लिए नई दिल्ली से अनुमति लेने संबंधी निर्णय निर्धारण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कर दिया था। न्यूयॉर्क के प्रेम भंडारी ने कहा कि वह भारत सरकार से अपील करते हैं कि प्रवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीय समुदायों को आइसीडब्ल्यूएफ में खुले दिल से योगदान करने की अनुमति दे। उन्होंने यह मुद्दा विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया है।

भारत और ईरान रणनीतिक चाबहार परियोजना में तेजी लाने पर सहमत

तेहरान, प्रेट्र : भारत और ईरान रणनीतिक चाबहार परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने पर सहमत हुए और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष जवाद जरीफ के साथ पारस्परिक हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक बातचीत की।

चाबहार बंदरगाह को भारत, ईरान और अफगानिस्तान संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। इस परियोजना को तीन देशों के मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के सुनहरे अवसरों के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। जयशंकर दो दिवसीय ईरान यात्रा पर हैं। उन्होंने जरीफ के साथ 19वें संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। उनके ईरानी राष्ट्रपति हसन रुहानी से मुलाकात करने की भी उम्मीद है। जयशंकर ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि सह-अध्यक्ष विदेश मंत्री जरीफ के साथ भारत-ईरान संयुक्त आयोग की सार्थक बैठक संपन्न हुई।

उन्होंने कहा, 'अपने सहयोग के पूरे आयाम की समीक्षा की। अपनी चाबहार परियोजना की गति तेज करने पर सहमत हुए।' अमेरिका ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के मामले में भारत को प्रतिबंधों से छूट दी है क्योंकि वाशिंगटन का कहना है कि यह रणनीतिक परियोजना युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लिए भारत से मानवीय आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जीवनरेखा है। जयशंकर ने जरीफ को उनके सौहार्दपूर्ण स्वागत और सत्कार के लिए धन्यवाद दिया।

विदेश मंत्री एस जयशंकर का रविवार को तेहरान पहुंचने पर उनके ईरानी समकक्ष जवाद जरीफ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एपी

हांगकांग में उइगर मुस्लिमों के समर्थन में प्रदर्शन

हांगकांग, रायटर : हांगकांग ने रविवार को चीन की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया। लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारी चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के विरोध में सड़क पर उतर आए। एक हजार से ज्यादा हांगकांग वासियों ने हाथों में उइगर झंडे और समर्थन में नारे लगे पोस्टर लेकर शहर के मध्य स्थित आर्थिक क्षेत्र में प्रदर्शन किया। छह महीने से चल रहे आंदोलन में पहली बार उइगरों का मुद्दा शामिल हुआ है।

युवाओं और बुजुर्ग आंदोलनकारियों ने काले कपड़े और फेस मास्क लगाकर महानगर के मध्य स्थित अति व्यस्त इलाके में प्रदर्शन किया। ये लोग उइगरों को आजाद करो...हांगकांग को आजाद करो...के नारे लगा रहे थे। वे हांगकांग की स्वायत्तता को भी झूठा करार दे रहे थे। हांगकांग के प्रदर्शन में शामिल 41 वर्ष की सरनेम वांग वाली महिला ने कहा, स्वतंत्रता सभी को मिलने चाहिए। वे चाहे हांगकांग के लोग हों या किसी अन्य इलाके के। वांग अपने पति के साथ प्रदर्शन में शामिल होने आई थीं। हांगकांग में यह विरोध प्रदर्शन ब्रिटिश फुटबाल क्लब आर्सेनल के मिडफील्डर मेसुत ओजिल के उइगरों के मुद्दे पर चीन की निंदा करने के बाद हुआ है। मेसुत तुर्की मूल के जर्मन खिलाड़ी हैं।

हांगकांग में रविवार को उइगर मुस्लिमों के समर्थन में प्रदर्शन करते लोग। रायटर

चीन के सीमावर्ती प्रांत शिनजियांग में करीब दस लाख उइगर सरकारी शिविरों में नजरबंद हैं। चीन सरकार इसके पीछे उनमें कट्टरता को दूर कर राष्ट्रवाद की शिक्षा देने का कारण बताती है। अल्पसंख्यकों की नजरबंदी का मामला संयुक्त राष्ट्र में भी उठ चुका है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश चीन के इस कदम की निंदा कर चुके हैं।

भारत और अमेरिका की दोस्ती को और मजबूत बनाने वाला बिल पेश

वाशिंगटन, एएनआइ : भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती लाने के लिए एक और विधेयक अमेरिकी संसद में पेश हो गया है। प्रतिनिधि सभा में पेश इस विधेयक में शिक्षा, विवादों के निपटारे और विकास योजनाओं में सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है।

जॉर्जिया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद जॉन लेविस ने यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसके पारित होने से भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती और मजबूत होगी। दोनों देश विकास और अन्य कार्यों के लिए आपसी सहयोग को बढ़ा सकेंगे। बिल एचआर-5517 को छह अन्य सांसदों का सहयोग भी हासिल है। सभी सांसद डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जिनमें तीन भारतीय मूल के हैं। इनमें प्रमिला जयपाल भी शामिल हैं जिन्होंने प्रतिनिधि सभा में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगी बंदिशों का मामला उठाया था। हाल ही में अमेरिका गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी के चलते उनसे मिलने से इन्कार कर दिया था। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है।

प्रगाढ़ होंगे संबंध

- शिक्षा, विवादों के निपटारे और विकास योजनाओं में सहयोग बढ़ेगा
- जॉर्जिया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद जॉन लेविस ने पेश किया विधेयक

सांसद लेविस को सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग की नीतियों का समर्थक माना जाता है। भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने वाला यह विधेयक महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में पेश किया गया है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नेंसी पेलोसी महात्मा गांधी की नीतियों की बड़ी समर्थक मानी जाती हैं। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बचपन से ही पढ़ती आ रही हैं।

ये भी जानिए

शाई होप (67) ने रविवार को अपने वनडे करियर में 3000 रन पूरे किए। वह सबसे तेज इस आंकड़े पर पहुंचने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर आ गए हैं।

कोहली की कप्तानी पारी से भारत ने जीती सीरीज

भारत ने तीसरे और आखिरी वनडे में दी वेस्टइंडीज को चार विकेट से मात, विराट शतक से चूके, भारत का 2-1 से सीरीज पर कब्जा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: 2003 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का बनाया गया 360 रनों का लक्ष्य आज भी हर भारतीय की नजरों में चुभता होगा। फिर आया 2013 जयपुर में वो दिन जब भारतीय टीम के सामने एक बार फिर 360 रन का लक्ष्य था, लेकिन इस बार भारतीय टीम ने ऐसा कारनामा करके दिखाया, जिसने भारतीय टीम को लक्ष्य में माहिर बना दिया और विराट कोहली को चेज मास्टर। मात्र 43.3 ओवर में एक विकेट पर 362 रन बनाकर भारतीय टीम ने दिखाया कि अब 300 के लक्ष्य को पाने में भारतीय टीम की सांसे नहीं फूलेंगी। यकीन मानिए, भारतीय टीम ने पिछले 10 वर्षों में रविवार को 10वीं बार 300 से ज्यादा के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ कटक में खेले गए सीरीज के इस तीसरे व निर्णायक मुकाबले में कोहली (85) भले ही शतक नहीं लगा सके, लेकिन रोहित शर्मा (63), केएल राहुल (77) के आउट होने के बाद उन्होंने भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम ने 48.4 ओवर में ही 316 रनों का लक्ष्य हासिल करके चार विकेट से जीत हासिल की। इसी के साथ भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने विजयी अभियान को भी कायम रखा। भारत की यह वेस्टइंडीज के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज में लगातार 10वीं जीत है।

फिर चला रोहित-राहुल का बल्ला: रोहित और राहुल की जुगलबंदी का तोड़ इस मुकाबले में भी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के पास नहीं था। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने पिछले मैच की फॉर्म को कायम रखते हुए अर्धशतक जड़ दिए। जरूरी रन रेट से भारतीय बल्लेबाज रन बना रहे थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाज बेसब्री से विकेट का इंतजार करते रहे। दोनों ने पहले विकेट के लिए लगातार दूसरी बार शतकीय साझेदारी कर दी। रोहित जब शतक की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे तो गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल ने अपनी टीम को रोहित के रुप में पहली सफलता दिलाई। रोहित के जाते ही राहुल भी संयम खो बैठे और अल्जारी जोसेफ ने उन्हें पवेलियन भेजकर उनके शतक की उम्मीद धूमिल कर दी।

कोहली का मास्टर प्लान: कोहली अब तक कटक के इस स्टेडियम में तीन वनडे और एक टी-20 में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए थे। कोहली ने इस मैच में मैदान में बैठे दर्शकों को खुलकर अपनी बल्लेबाजी निहारने का मौका दिया। एक समय जब रिषभ पंत (07) और केदार जाधव (07) के विकेट खोकर भारतीय टीम मुश्किलों में फंस चुकी थी। उस वक्त कोहली और रवींद्र जडेजा (नाबाद 39) हार नहीं मानी। दोनों ने छठें विकेट के लिए अहम 48 रन की साझेदारी की। कोहली शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कीमो पॉल की गेंद इन साइड ऐज लेती हुई विकेटों में घुस गई। अंत में शार्दुल ठाकुर (नाबाद 17) ने कुछ आकर्षक शॉट खेलकर टीम को जीत दिला दी।

पहली बार जीता टॉस: इससे पहले सीरीज में पहली बार भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शानदार फॉर्म में चल रहे होप और इविन लुइस (21) ने पहले विकेट के लिए 15 ओवर में 57 रन जोड़कर अपनी टीम को धीमी, लेकिन अच्छी शुरुआत दिलाई। होप ने चौथे ओवर में मुहम्मद शमी पर पारी का पहला चौका मारा और फिर इस ओवर में एक और चौका जड़ा। लुइस ने भी चोटिल दीपक चाहर की जगह टीम में शामिल नवदीप सैनी पर दो चौके मारे। होप और लुइस ने 13वें ओवर में टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। लुइस हालांकि जडेजा के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे।

पंत ने छोड़े कैच: कुलदीप यादव के अगले ओवर में रोस्टन चेस (38) भाग्यशाली रहे, जब विकेटकीपर रिषभ पंत ने उनका कैच टपका दिया। इस समय चेस ने खाता भी नहीं खोला था। होप हालांकि इसके बाद शमी की सीधी गेंद को चूककर बोल्ड हो गए। उन्होंने 50 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके मारे। पंत ने जडेजा की गेंद पर शिमरोन हेटमायर (37) का भी कैच छोड़ा। हेटमायर ने कुलदीप और शार्दुल ठाकुर पर छक्के मारे, लेकिन सैनी ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। सैनी ने अपने अगले ओवर में चेस को भी बोल्ड किया।

निकोलस-कीरोन की जुगलबंदी: पूरन और पोलार्ड ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया। पोलार्ड ने धीमी शुरुआत के बाद जडेजा के ओवर में दो छक्के मारे।

स्कोर बोर्ड

टॉस : भारत (गेंदबाजी) | मैन ऑफ द मैच : विराट कोहली
परिणाम : भारत चार विकेट से जीता | मैन ऑफ द सीरीज : रोहित शर्मा

वेस्टइंडीज 315/5 (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
इविन लुइस का. सैनी बो. जडेजा	21	50	03	00
शाई होप बो. शमी	42	50	05	00
रोस्टन चेस बो. सैनी	38	48	03	00
हेटमायर का. कुलदीप बो. सैनी	37	33	02	02
निकोलस पूरन का. जडेजा बो. ठाकुर	89	64	10	03
कीरोन पोलार्ड नाबाद	74	51	03	07
जेसन होल्डर नाबाद	07	04	01	00

अतिरिक्त : (लेबा-4, वा-3) 7
कुल : 50 ओवर में पांच विकेट पर 315 रन

विकेट पतन : 1-57 (लुइस, 14.6), 2-70 (होप, 19.2), 3-132 (हेटमायर, 29.2), 4-144 (चेस, 31.3), 5-279 (पूरन, 47.5)

गेंदबाजी : शार्दुल ठाकुर 10-0-66-1, मुहम्मद शमी 10-2-66-1, नवदीप सैनी 10-0-58-2, कुलदीप यादव 10-0-67-0, रवींद्र जडेजा 10-0-54-1

भारत 316/6 (48.4 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा का. होप बो. होल्डर	63	63	08	01
लोकेश राहुल का. होप बो. जोसेफ	77	89	08	01
विराट कोहली बो. पॉल	85	81	09	00
श्रेयस अय्यर का. जोसेफ बो. पॉल	07	07	01	00
रिषभ पंत बो. पॉल	07	06	01	00
केदार जाधव बो. कॉटरेल	09	10	01	00
रवींद्र जडेजा नाबाद	39	31	04	00
शार्दुल ठाकुर नाबाद	17	06	02	01

अतिरिक्त : (लेबा-2, नोबॉ-1, वा-9) 12
कुल : 48.4 ओवर में छह विकेट पर 316 रन

विकेट पतन : 1-122 (रोहित, 21.2), 2-167 (राहुल, 29.5), 3-188 (अय्यर, 32.3), 4-201 (पंत, 34.6), 5-228 (जाधव, 38.5), 6-286 (कोहली, 46.1)

गेंदबाजी : कॉटरेल 10-1-74-1, जेसन होल्डर 10-0-63-1, कीमो पॉल 9.4-0-59-3, रोस्टन चेस 4-0-19-0, खारे पियरे 7-0-46-0, अल्जारी जोसेफ 8-0-53-1

इस वर्ष वनडे में सबसे ज्यादा शतक

बल्लेबाज	देश	मैच	रन	100
रोहित शर्मा	भारत	28	1490	7
विराट कोहली	भारत	26	1377	5
शाई होप	वेस्टइंडीज	28	1345	4
आरोन फिंच	ऑस्ट्रेलिया	23	1141	4
बाबर आजम	पाकिस्तान	20	1092	3

इस वर्ष वनडे में सबसे ज्यादा विकेट

गेंदबाज	देश	मैच	विकेट
मुहम्मद शमी	भारत	21	42
ट्रेंट बोल्ट	न्यूजीलैंड	20	38
लॉकी फर्ग्यूसन	न्यूजीलैंड	17	35
मुस्तफिजुर	बांग्लादेश	16	34
भुवनेश्वर कुमार	भारत	19	33

इस वर्ष में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन

खिलाड़ी	देश	मैच	रन	100
विराट कोहली	भारत	44	2455	07
रोहित शर्मा	भारत	47	2442	10
बाबर आजम	पाक	26	2082	06
रॉस टेलर	न्यूजीलैंड	39	1820	03
जो रूट	इंग्लैंड	37	1790	05

एक वर्ष में ओपनर के सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन

ओपनर	देश	रन	वर्ष
रोहित शर्मा	भारत	2434	2019
सनत जयसूर्या	श्रीलंका	2387	1997
वीरेंद्र सहवाग	भारत	2355	2008
मैथ्यू हेडन	ऑस्ट्रेलिया	2349	2003
सईद अनवर	पाकिस्तान	2296	1996

इस वर्ष वनडे में सर्वाधिक जीत

देश	मैच	जीत	हार
भारत	28	19	08
ऑस्ट्रेलिया	23	16	07
इंग्लैंड	22	14	05
न्यूजीलैंड	21	13	07
द. अफ्रीका	19	11	07
वेस्टइंडीज	28	10	15
पाकिस्तान	25	09	15
बांग्लादेश	18	07	11
श्रीलंका	21	07	14

2019 में भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने आठ बार 50 या इससे ज्यादा रन की साझेदारी कीं और आठों बार इसे 100 रनों की साझेदारी में बदलने में सफल रहे

10 वर्षों में भारतीय टीम ने 300 से ज्यादा रन के लक्ष्य का पीछा 10 वीं बार किया है। इसमें सात बार कोहली ने शतक लगाया। यह इस दौरान तीसरा मौका रहा जब कोहली शतक नहीं लगा सके

गावस्कर ने कहा, मुझे वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज मार्शल की याद दिलाते हैं मुहम्मद शमी

कटक, प्रेट्र: पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने रविवार को कहा कि मुहम्मद शमी कई बार उन्हें वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज मैलकम मार्शल की याद दिलाते हैं। वेस्टइंडीज के महानतम तेज गेंदबाजों में से एक मार्शल के साथ तुलना से निश्चित तौर पर भारत के इस सीनियर तेज गेंदबाज का मनोबल बढ़ेगा, जिसने पूरे सत्र के दौरान अपनी तेजी, स्विंग और उछाल से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया। शमी 2019 में वनडे में 42 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे और गावस्कर भी इस तेज गेंदबाज की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। गावस्कर से जब यह पूछा गया कि उनका पसंदीदा भारतीय तेज गेंदबाज कौन है तो उन्होंने शमी का नाम लिया। गावस्कर ने कहा कि वह मुझे मैलकम मार्शल की याद दिलाते हैं जिनके बारे में सोचकर मैं अब भी गहरी नींद से उठ जाता हूं। गावस्कर ने साथ ही भारतीय तेज गेंदबाजी में क्रांति लाने का श्रेय विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव को दिया। गावस्कर ने इससे पहले शमी की तुलना तेंदुए से की थी।

अपनी पारी के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ● प्रेट्र

एक नजर में

मेइराबा ने जीता खिताब

ढाका: भारत के मेइराबा लुवांग ने अपनी शीर्ष वरीयता के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए रविवार को यहां बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज 2019 खिताब अपने नाम किया। इस तरह उन्होंने दो महीने में दूसरा खिताब जीता। उन्होंने पिछले महीने वोनचियोन योनेक्स कोरिया जूनियर ओपन इंटरनेशनल चैलेंज में लड़कों का सिंगल्स वर्ग में अंडर-19 का खिताब जीता था। शीर्ष वरीय मेइराबा ने 38 मिनट चले मुकाबले में मलेशिया के केन योंग ओंग को 21-14, 21-18 से शिकस्त दी। मेइराबा ने सेमीफाइनल में एक और मलेशियाई एम फाजरिक मुहम्मद रिजवी को हराया था। (प्रेट्र)

थाइलैंड मास्टर्स में संयुक्त 11वें स्थान पर रहे संधू

पटाया: भारत के अजीतेश संधू ने रविवार को यहां थाइलैंड मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट के अंतिम दौर में चार अंडर-67 का कार्ड खेला जिससे वह संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर रहे। भारतीय गोल्फ के लिए साल 2019 खराब रहा, जिसमें कोई भी भारतीय अंतरराष्ट्रीय टूर में खिताब नहीं जीत सका और 2001 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। पिछले दो वर्षों (2017 और 2018) में भारतीयों ने छह खिताब जीते थे। इस टूर्नामेंट में ज्योति रंधावा संयुक्त 39वें, एसएसपी चौरसिया संयुक्त 48वें, आदिल बेदी संयुक्त 54वें, अर्जुन अटवाल संयुक्त 60वें और विराज मादप्पा संयुक्त 73वें स्थान पर रहे। वहीं जैज जानेवाटानानोंद ने यहां पांच शॉट की बढ़त से खिताब जीता। (प्रेट्र)

अहमदाबाद को अस्थायी मंजूरी

अहमदाबाद: फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 की स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) ने रविवार को टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए अहमदाबाद की अस्थायी स्थल के रूप में पुष्टि की। एलओसी टूर्नामेंट निदेशक रोमा खन्ना ने कहा, 'हमें अहमदाबाद को अस्थायी स्थल के रूप में पुष्टि करके खुशी हो रही है। गुजरात सरकार ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 को राज्य में सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता दी है। ट्रांसस्टेडिया इस समय देश में सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं वाले स्टेडियम में से एक है और हम सरकार और स्टेडियम के अधिकारियों को बधाई देना चाहेंगे कि वे भारतीय फुटबॉल के इतिहास के सबसे अहम टूर्नामेंट में से एक का हिस्सा होंगे।' यह टूर्नामेंट अगले साल दो से 21 नवंबर के बीच खेला जाएगा। (प्रेट्र)

पीसीबी का बीसीबी को इन्कार

कराची: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को स्पष्ट किया कि वह जनवरी-फरवरी में आगामी घरेलू सीरीज के दौरान उनकी तटस्थ स्थल पर मेजबानी नहीं करेगा। इस सप्ताह बीसीबी को भेजे ईमेल में पीसीबी के अध्यक्ष अहसान मनी ने बांग्लादेश से अपनी टीम 18 जनवरी से होने वाली आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दो टेस्ट खेलने के लिए पाकिस्तान भेजने से इन्कार करने के स्वीकार्य कारण बताने को भी कहा है। (प्रेट्र)

476 रन के लक्ष्य के सामने श्रीलंका के 212 रन पर गिरे छह विकेट, पाक के चार बल्लेबाजों ने जड़े शतक

एक दशक बाद घर में पहली जीत के करीब पाकिस्तान

कराची, एएफपी: पाकिस्तान के शीर्ष चार बल्लेबाजों ने यहां दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जड़े, जिसकी बदौलत घरेलू टीम ने चौथे दिन रविवार को श्रीलंका को जीत के लिए 476 रन का लक्ष्य दिया। हालांकि, एक समय चौथे दिन की पाकिस्तान की जीत नजर आ रही थी, लेकिन श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज ओशाडा फर्नांडो करियर के पहले टेस्ट शतक की बदौलत पाकिस्तान की एक दशक बाद घर में टेस्ट व सीरीज जीत को एक दिन के लिए टालने में सफल रहे।

लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने पांच विकेट 97 रन पर गंवा दिए थे, जिसके बाद ओशाडा और निकोलस डिकवेला ने विकेटों के पतझड़ को रोका और छठे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी निभाई। लेकिन, दिन के अंतिम तीन ओवरों डिकवेला और दिलरुवान परेरा पवेलियन लौट गए। डिकवेला 65 रन बनाकर ऑफ स्पिनर हैरिस सोहेल की गेंद पर रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गए और दिलरुवान को नसीम शाह ने पांच रन के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे कैच कराया। 16 साल के नसीम ने 31 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए। दिन का खेल खत्म होने पर श्रीलंका की टीम सात विकेट पर 212 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। ओशाडा नाबाद 102 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि मेहमान टीम को जीत के लिए अभी भी 264 रन और बनाने की जरूरत है। वहीं, पाकिस्तान की टीम जीत से सिर्फ तीन विकेट दूर है। पाकिस्तान की टीम 2009 में श्रीलंका की टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद से पहली बार अपनी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेल रही है। इससे पहले सुबह दो विकेट पर 395 रन से आगे खेलने उतरी पाकिस्तानी टीम ने भोजनकाल के समय अपनी दूसरी पारी तीन विकेट पर 555 रन बनाकर घोषित की। उसकी ओर से अजहर अली 118 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि बाबर आजम ने नाबाद 100 रन बनाए। इन दोनों से पहले मैच के तीसरे दिन आबिद अली (174) और शान मसूद (135) ने शतक जड़े थे और इन दोनों की सलामी जोड़ी ने 278 रन जोड़कर पाकिस्तान को मजबूत शुरुआत दिलाई थी।

नेशनल स्टेडियम की पिच पर जहां पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया तो वहीं श्रीलंका के बल्लेबाज का प्रदर्शन काफी निंदनीय रहा। चायकाल से पहले कप्तान दिमुथ करुणारत्ने 16 रन, कुशल मेंडिस बिना खाता खोले और एंजेलो मैथ्यूज 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तेज गेंदबाज मुहम्मद अब्बास ने करुणारत्ने को 10वें ओवर में विकेट के पीछे कैच कराया, जबकि नसीम ने मेंडिस को स्लिप में लपकवाया। श्रीलंका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज मैथ्यूज शाहीन शाह अफरीदी की एक शॉर्ट गेंद पर बल्ले का किनारा लगा बैठे और विकेटकीपर मुहम्मद रिजवान के हाथों लपके गए। चायकाल के बाद युवा नसीम ने दिनेश चांदीमल (02) और लेग स्पिनर यासिर शाह ने धनंजय डिसिल्वा (00) को चलता कर स्कोर पांच विकेट पर 97 रन कर दिया था।

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट की दूसरी पारी में चौथे दिन शतक लगाने के बाद जश्न मनाते पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली ● एएफपी

04 शीर्ष पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शतक जड़े। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ, जब किसी टीम के चार शीर्ष बल्लेबाजों ने शतक जड़े। इससे पहले 2007 में ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की ओर से ऐसा रिकॉर्ड बना था

संक्षिप्त स्कोर

पाकिस्तान (पहली पारी) : 191 (59.3 ओवर), श्रीलंका (पहली पारी) : 271 (85.5 ओवर), पाकिस्तान (दूसरी पारी) : 555/3 घोषित (131 ओवर), आबिद : 174 रन (281 गेंद, 21 चौके, 01 छक्का), शान मसूद : 135 रन (198 गेंद, 07 चौके, 03 छक्का), अजहर : 118 रन (157 गेंद, 13 चौके), बाबर : 100* रन (131 गेंद, 07 चौके, 01 छक्का), लाहिरु : 29-5-139-2, श्रीलंका (दूसरी पारी) : 212/7 (60.1 ओवर), ओशाडा : 102* रन (175 गेंद, 13 चौके), नसीम : 11.1-3-31-3

सौरव-सचिन ने किया कोहली-रोहित से बेहतर गेंदबाजों का सामना : चैपल

नई दिल्ली, प्रेट्र: विराट कोहली और रोहित शर्मा एक जोड़ी के रूप में रनों का अंबार लगा रहे हैं, लेकिन जब उच्च स्तर के तेज गेंदबाजों का सामना करने की बात आती है तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल का मानना है कि सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी के सामने चुनौती अधिक कड़ी थी।

चैपल ने 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' में अपने कॉलम में लिखा, 'यह तर्क दिया जा सकता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज हैं। उन्हें चुनौती देने वालों में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी होगी, जिन्होंने 15 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों को परेशानी में रखा।' चैपल ने इसके बाद उदाहरण देकर समझाया है कि गांगुली-तेंदुलकर के समय में कैसे प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय टीम के पास दो अच्छे तेज गेंदबाज थे। उन्होंने लिखा, 'उन्होंने (तेंदुलकर-गांगुली) ने अपना अधिकतर समय सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजी जोड़ियों के सामने पारी का आगाज करते हुए बिताया। पाकिस्तान के वसीम अकरम और वकार यूनिस, वेस्टइंडीज के कर्टली एंब्रोस और कोर्टनी वाल्श, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा और ब्रेट ली, दक्षिण अफ्रीका के एलन डोनाल्ड ओर शॉन पोलाक, श्रीलंका के लसित मलिंगा और चमिंडा वास का सामना करते हुए किसी भी बल्लेबाज के कौशल की असली परीक्षा होती है।'

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयान ने कहा कि विपक्षी की मजबूती को देखते हुए गांगुली-तेंदुलकर की जोड़ी भारी

चैपल ने इस संदर्भ में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इमरान खान के कथन का सहारा लिया है जिन्होंने कहा था, 'आप किसी व्यक्ति की पहचान उसके प्रतिद्वंद्वी को देखकर करते हैं।' चैपल ने कहा, 'विपक्षी की मजबूती को देखते हुए आपको तेंदुलकर और गांगुली का पलड़ा भारी रखना होगा। हालांकि, अगर आप वर्तमान आंकड़ों पर गौर करें और कोहली को भी तेंदुलकर के समान और शर्मा को गांगुली के समान पारियां दो तो फिर वर्तमान जोड़ी का पलड़ा भारी हो जाता है।'

इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान चैपल ने हालांकि माना कि कोहली और शर्मा सफेद गेंद की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है। उन्होंने कहा, 'उनका वनडे और टी-20 का संयुक्त रिकॉर्ड बेहतरीन है। विराट कोहली ने क्रिकेट के दोनों प्रारूप में 50 से अधिक के औसत से रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने बहुत कम टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं। वहीं अगर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बात करें तो जब तक यह प्रारूप लोकप्रिय होता तब तक गांगुली का क्रिकेट करियर खत्म हो चुका था।'

युवा खेलो से मिलेंगे ओलंपिक पदक विजेता : बोरगोहेन

गुवाहाटी, प्रेट्र: विश्व चैंपियनशिप में दो बार कांस्य पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेलों से भविष्य में ओलंपिक पदक विजेता निकलेंगे। बोरगोहेन ने कहा कि खेलो इंडिया युवा खेल खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मंच है जिनका आयोजन यहां 10 से 22 जनवरी के दौरान किया जाएगा।

उन्होंने कहा, 'असम के लिए खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी करना बहुत बड़ा मौका है। यह राज्य के लिए सम्मान की बात है। ऐसे काफी एथलीट होंगे जो इन खेलो इंडिया युवा खेलों की वजह से 2024 ओलंपिक में पदक जीतेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल बड़ा टूर्नामेंट है। अब कोई प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती। हर कोई अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। यह सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका है।' असम की इस मुक्केबाज ने 2018 में इंडिया ओपन में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2018 विश्व चैंपियनशिप और 2019 विश्व चैंपियनशिप प्रत्येक में वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था।

फुटबॉल | फाइनल में लिवरपूल ने फ्लेमिंगो को 1-0 से हराया, फर्मिनो के 99वें मिनट में दागा मैच का इकलौते गोल

लिवरपूल ने पहली बार जीता क्लब विश्व कप का खिताब

दोहा, एएफपी: रॉबर्टो फर्मिनो द्वारा अतिरिक्त समय में किए गए इकलौते गोल की मदद से लिवरपूल ने फ्लेमिंगो को फाइनल में 1-0 से हराकर पहली बार क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल के मैनेजर जुर्जेन क्लोप ने इस खिताबी जीत को बेहद सनसनीखेज करार दिया।

खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में शनिवार देर रात खेले गए फाइनल में निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। इसके बाद अतिरिक्त समय में खेल के 99वें मिनट में सादियो माने से मिले पास पर फर्मिनो ने फ्लेमिंगो के गोलकीपर डिएगो अल्वेस को चकमा देकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। ब्राजील के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी फर्मिनो का यह गोल उनके देश के क्लब फ्लेमिंगो के लिए दिल तोड़ने वाला साबित हुआ और इस इकलौते गोल की बदौलत लिवरपूल ने खिताब अपने नाम किया। हालांकि, इससे पहले फर्मिनो को गोल करने के कई मौके हाथ लगे, लेकिन खराब किस्मत की वजह से उन्हें गोल हासिल करने के लिए अतिरिक्त समय तक का इंतजार करना पड़ा। फर्मिनो ने इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में मोंटेरी के खिलाफ भी इंजुरी टाइम में निर्णायक गोल दागा था। इस मुकाबले में लिवरपूल को निर्धारित समय के अंदर एक पेनाल्टी किक भी मिली, लेकिन वीडियो असिस्टेंट रेफरी (वार) की मदद से उसे लेने से रोक दिया गया। इस मुकाबले में फ्लेमिंगो ने भी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं दे पाई। इससे पहले 1981 के इंटरकोंटिनेंटल कप में फ्लेमिंगो ने लिवरपूल को हराया था, लेकिन इस बार वह उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाया। उधर, मोंटेरी ने अल हिलाल को हराकर इस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया।

अब घरेलू लीग पर निगाहें: लिवरपूल ने पिछले छह महीने में तीसरा खिताब हासिल किया। क्लब विश्व कप से पहले उसने जून में चैंपियंस लीग और सत्र की शुरुआत में यूएफा सुपरकप का खिताब जीता था। अब लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग में खिताबी उम्मीद के साथ उतरेगा, जहां अभी वह शीर्ष पर चल रहा है। लिवरपूल के डिफेंडर विर्गिल वान डिज्क ने कहा कि साल 2019 लिवरपूल के लिए यादगार रहा है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें बढ़ते रहना चाहिए और खिताब जीतते रहना चाहिए।

कतर को मिली सफलता: 2022 फीफा विश्व कप के मेजबान कतर ने क्लब विश्व कप को सफल परीक्षण करार दिया है। क्लब विश्व कप के फाइनल से पहले विश्व कप की सुप्रीम कमेटी के महासचिव हसन अल थवाडी ने कहा कि यह छोटा देश भारी संख्या में आने वाले फुटबॉल के दर्शकों को संभालने के योग्य होगा।

मैनचेस्टर सिटी ने बरकरार रखी उम्मीद: इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में शनिवार को मैनचेस्टर सिटी ने लीसेस्टर सिटी को 3-1 से हराकर मौजूदा सत्र में अपनी खिताबी जीत की उम्मीदों को बरकरार रखी। सिटी की ओर से रियाद महारेज, आइकर गुंडोगन और गेब्रियल जीजस ने गोल दागे।

इंग्लैंड के विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे पीटर्स का निधन

लंदन, एएफपी: विश्व कप 1966 के फाइनल में पश्चिमी जर्मनी के खिलाफ इंग्लैंड की तरफ से दूसरा गोल दागने वाले अपने जमाने के दिग्गज फुटबॉलर मार्टिन पीटर्स का निधन हो गया। 76 वर्षीय पीटर्स लंबे समय से अलजाइमर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिनका शनिवार को निधन हो गया। इंग्लिश क्लब वेस्टहम ने पीटर्स के निधन की घोषणा की। वह इस क्लब के तीन दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल थे। उनके अलावा इस त्रिमूर्ति में कप्तान बॉबी मूरे और ज्योफ हर्स्ट शामिल थे।

क्लब विश्व कप के फाइनल में फ्लेमिंगो को हराकर खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ लिवरपूल फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी ● रायटर

इस्पोसिटो ने तोड़ा छह दशक पुराना रिकॉर्ड

मिलान, एएफपी: सबास्टियानो इस्पोसिटो इटालियन क्लब इंटर मिलान की ओर से पिछले 61 वर्षों में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। शनिवार को सीरी-ए में इंटर मिलान ने गेनोआ को 4-0 से हराया, जहां 17 वर्षीय इस्पोसिटो ने भी पेनाल्टी किक के जरिये गोल दागा। इस्पोसिटो 1958 में मारियो कार्सो के बाद गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। इस मैच में इंटर के लिए रोमेलू लुकाकू ने दो किए।

गौरव गिल ने पांचवीं बार जीती पॉपुलर रैली

कोट्टयम (केरल), आइएएनएस : भारत के रैली किंग गौरव गिल ने पॉपुलर रैली नाम से मशहूर चैंपियंस याच क्लब एफएमएससीआइ इंडियन नैशनल रैली चैंपियनशिप के अंतिम राउंड में अपनी चमक बिखेरते हुए रविवार को पांचवीं बार यह रैली जीत ली। जेके टायर द्वारा समर्थित टीम महेंद्रा के चालक गिल ने अपने साथी चालक मूसा शरीफ के साथ रैली के दूसरे दिन रविवार को एसएस9 में पहला, एसएस10 और एसएस11 में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ गौरव ने पिछले कुछ समय से चले आ रहे खराब वक्त को खत्म करते हुए खिताबी सफलता हासिल की।

गिल की टीम के डीन मास्कारेनहास और सुहेम कबीर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और पॉपुलर रैली के ओवरऑल कैटेगरी में क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया। बेंगलुरु के चेतन शिवराम ने हालांकि 2019 आइएनआरसी चैंपियन होने का गौरव हासिल किया। चेतन ने रैली ऑफ कोयंबटूर और के1000 बेंगलुरु रैली में मिली जीत के दम पर पहला स्थान हासिल किया। एमआरएफ समर्थित चालक चेतन के लिए कोट्टयम में पहला दिन बेहद निराशाजनक रहा था। आइएनआरसी-3 कटेगरी में वह हालांकि चैंपियन नहीं बन सके, क्योंकि फेबिद अहमर और उनके नेवीगेटर सनत जी ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए इस कैटेगरी में पहला स्थान पाया। फेबिद आदित्य ठाकुर और उनके नेवीगेटर वीरेंद्र कश्यप के बाद दूसरे स्थान पर रहे।

बॉक्सिंग डे टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करेंगे ब्लंडेल

मेलबर्न, आइएएनएस : टॉम ब्लंडेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। ब्लंडेल को जीत रावल की जगह टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने विक्टोरिया इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच में नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी। 29 वर्षीय ब्लंडेल ने अपने 93 प्रथम श्रेणी के मैचों में पारी की शुरुआत नहीं की है। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह इसे यहां कर सकते है।

मैंने अक्सर देखा है कि मैच के दौरान कमंटेटर गेंदबाजों के लिए अच्छा नहीं बोलते हैं।
– तबरेज शम्सी, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज

अलावेस को हराकर बार्सिलोना ने शीर्ष पर रहते हुए किया 2019 का अंत

फुटबॉल ▶ मेसी, सुआरेज, ग्रीजमैन और विडल के गोल से अलावेस को 4-1 से हराया

लियोन ने पूरे किए साल में 50 गोल, 69वें मिनट में सुआरेज के पास पर किया गोल

बार्सिलोना, रायटर : स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने शनिवार को अलावेस को 4-1 से हराकर 2019 का अंत शीर्ष पर रहते हुए किया। इस दौरान बार्सिलोना के लियोन मेसी, लुइस सुआरेज और एंटोनी ग्रीजमैन ने स्कोर किए और क्लब के इन तीनों सितारों ने संयुक्त रूप से अपने गोल की संख्या 30 पहुंचा दी।

खेल के 14वें मिनट में ग्रीजमैन ने सुआरेज के पास पर गोल करके बार्सिलोना को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद सुआरेज के ही पास पर अर्तुरो विडल ने हाफ टाइम से ठीक पहले गोल दागा और स्पेनिश चैंपियन को दोहरी बढ़त पर ला खड़ा किया। 56वें मिनट में अलावेस के मिडफील्डर पेरे पोंस ने गोल करके अपनी टीम को वापसी दिलाई लेकिन 69वें मिनट में सुआरेज के पास पर मेसी ने गोल करके बार्सिलोना की फिर से दोहरी बढ़त पर ला खड़ा किया। यह मेसी का साल का कुल 50वां गोल था जिसमें उनके क्लब बार्सिलोना और राष्ट्रीय टीम अर्जेंटीना के लिए किए गए गोल शामिल हैं। लगातार छठे साल मेसी ने 50 गोल के आंकड़े तक पहुंचने में सफल रहे। उधर तीन गोल में मदद करने के बाद 75वें मिनट में आखिरकार सुआरेज ने पेनाल्टी किक पर बार्सिलोना का चौथा गोल दागा।

अंक तालिका में बार्सिलोना 18 मुकाबलों के बाद 39 अंकों के साथ शीर्ष पर है और उसने दूसरे स्थान पर काबिज रीयल मैड्रिड पर तीन अंकों की बढ़त हासिल कर ली जिसे रविवार को एथलेटिक बिल्बाओ से भिड़ना है। अब देखना होगा कि बार्सिलोना की टीम अगले वर्ष अंक तालिका में इस बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब हो पाती है या फिर रीयल मैड्रिड उसे इस दौड़ में आने वाले वर्ष में पछाड़ देगी।

स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में अलावेस के खिलाफ मैच से पहले साल 2018 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी के साथ बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोन मेसी। रायटर

खेल नीति के मसौदे को लागू नहीं किया जा सकता : खेल मंत्री

नई दिल्ली, आइएएनएस : खेल मंत्री किरन रिजिजू ने कहा है कि खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता मसौदा 2017 को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया है कि कैसे यह भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) और राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को नुकसान पहुंचा सकता है। खेल मंत्री का मानना है कि यह सरकार और खेल मंत्रालय का काम है कि वह आइओए और एनएसएफ सहित सभी हितधारकों के लिए स्वीकार्य खेल नीति तैयार करे, ना कि अदालतों का।

एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा कि रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय ने 2017 नीति को खारिज कर दिया है और यह मसौदा देश में खेलों को बढ़ावा देने के अनुकूल नहीं है। अदालत यह तय नहीं करेगी कि संहिता कैसी होनी चाहिए। मंत्रालय को अदालत का नोटिस मिला था, इसलिए हम अदालत को (मंत्रालय के रुख के बारे में) बताने के लिए बाध्य थे। खेल मंत्री ने यह टिप्पणी तब की जब खेल सचिव राधेश्याम जूलानिया ने मंत्रालय की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। इसमें उन्होंने अदालत को मंत्रालय के खेल में सुशासन के लिए राष्ट्रीय संहिता मसौदा 2017 को स्वीकार करने के आरक्षण के बारे में सूचित किया।

निखत ओलंपिक क्वालीफायर के लिए ट्रायल के लिए चुनी गईं

मुक्केबाजी

नई दिल्ली, प्रेट्र : निखत जरीन को शनिवार को उन भारतीय महिला मुक्केबाजों में चुना गया जो 27 दिसंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में ओलंपिक क्वालीफायर के लिए होने वाले दो दिवसीय ट्रायल्स में भाग लेंगी। चयन समिति की यहां हुई बैठक के बाद तेलंगाना की निखत को 51 किग्रा वर्ग में चौथा स्थान दिया गया जिसमें छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मेरी कॉम, आरएसपीबी की ज्योति गुलिया और हरियाणा की ऋतु ग्रेवाल अन्य मुक्केबाज हैं।

मेरी कॉम को पहली रैंकिंग जबकि निखत को दूसरी रैंकिंग दी गई। वहीं ज्योति और ऋतु को क्रमशः तीसरी और चौथी रैंकिंग दी गई। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) के अनुसार पहली रैंकिंग और चौथी रैंकिंग की मुक्केबाज आपस में तथा दूसरी और तीसरी रैंकिंग की मुक्केबाज एक दूसरे से भिड़ेंगीं। इससे निखत का सामना ज्योति से जबकि मेरी कॉम का सामना ऋतु से होगा। दोनों मैच की विजेता फाइनल ट्रायल मुकाबले में पहुंचेंगी। मालूम हो कि निखत लंबे समय से मेरी कॉम के साथ ट्रायल मुकाबले की मांग कर रही थीं। निखत को बिग बाउट लीग में मेरी कॉम से भिड़ना था लेकिन मेरी कॉम ने चोट का हवाला देकर आखिरी लम्हों में इस मुकाबले से हटने का फैसला किया।

भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन। फाइल फोटो

पंजाब को हरा गुजरात ने जीता खिताब : गुजरात जाएंट्स ने शनिवार को यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में खेली गई बिग बाउट इंडियन मुक्केबाजी लीग के रोमांचक फाइनल में पंजाब पैंथर्स को 4-3 से मात दिया और इस लीग के पहले संस्करण का खिताब अपने नाम किया। पंजाब ने शुरुआती दो मैच जीत बढ़त ले ली थी, लेकिन गुजरात ने दो बार वापसी कर खिताबी जीत हासिल किया। फाइनल का आखिरी मैच निर्णायक रहा, जहां पुरुषों के 75 किलोग्राम भारवर्ग में गुजरात के अशीष कुमार ने पंजाब के यशपाल को 5-0 से मात दी।

लगातार जीत से शीर्ष पर पहुंचा एफसी गोवा

आइएसएल

फातोर्दा (गोवा) आइएएनएस : एफसी गोवा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार को ओडिशा एफसी को 2-0 से हराकर हीरो इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) के छठे सत्र की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है। गोवा की यह लगातार तीसरी जीत है। इस मैच में गोवा के लिए फेरान कोरोमिनास ने 19वें और 89वें तथा ब्रेंडन फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल किए। इस मैच से हासिल तीन अंकों को लेकर गोवा के नौ मैचों से 18 अंक हो गए हैं। गोवा ने इस सीजन की पांचवीं जीत दर्ज की है। दूसरी ओर, ओडिशा एफसी की यह तीसरी हार है। उसके खाते में नौ अंक हैं और वह सातवें स्थान पर ही बनी रहेगी।

पहला हाफ मेजबान टीम के ही नाम रहा। उसने न सिर्फ अधिक मौके बनाए, अधिक समय तक गेंद को अपने पास रखा बल्कि गोल करने में भी सफलता हासिल की। शुरुआती 10 मिनट में दोनों टीमों ने एक दूसरे को नापा-तोला और फिर हमले शुरू किए। पहला हमला ओडिशा की ओर से हुआ लेकिन कार्लोस पेना ने उसे नाकाम कर दिया। ओडिशा ने 17वें मिनट में भी एक बड़ा मौका बनाया था। लेफ्ट फ्लैंक से नंदकुमार सेकर ने एड्रियन सांटाना को अच्छा क्रास दिया था लेकिन सांटाना हेडर से इसे पोस्ट में नहीं डाल सके।

गोवा ने हालांकि दो मिनट बाद ही अपना पहला गोल करते हुए बढ़त बना ली। जैकीचंद सिंह ने बॉक्स के बाहर पहुंचे सांटाना को एक अच्छा थ्रो पास दिया। सांटाना ने इस पास को शानदार तरीके से कोरो के लिए कट किया और कोरो ने बिना किसी गलती के गेंद पोस्ट में डाल दिया। 21वें मिनट में जैकीचंद सिंह चोटिल हुए और सिमिनलेन डोंगेल उनकी जगह मैदान पर आए। 25वें मिनट में ओडिशा के गोलकीपर की गलती उसकी टीम पर भारी पड़ सकती थी। एक खराब पास को कोरो ने लपक लिया और उसे डोंगेल के हवाले कर दिया। डोंगेल का शॉट हालांकि गोलकीपर को छका नहीं सका। 29वें मिनट में हालांकि ओडिशा के लिए मार्टिन गुइदेस और सांटाना ने एक अच्छा मूव बनाया लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 37वें मिनट में गोवा ने काउंटर अटैक किया लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। 44वें मिनट में ओडिशा के फेरान डेल्गाडो को पीला कार्ड मिला।

मेहमान टीम ने 50वें मिनट में एक के बाद एक तीन बदलाव किए। हालांकि उसे इसका फायदा होता नहीं दिखा क्योंकि अगले ही मिनट बोउमोस और कोरो ने एक बेहतरीन मूव बनाया। यह अलग बात है कि वे सफल नहीं हो सके। 54वें मिनट में कोरो ने बॉक्स के बाहर से ब्रेंडन फर्नांडिस को अच्छा पास दिया। ब्रेंडन ने पलटकर शॉट लिया लेकिन गेंद सीधे कीपर के हाथों में चली गई। इसके चार मिनट बाद ओडिशा ने मूव बनाया लेकिन गोवा के गोलकीपर मुहम्मद नवाज सतर्क थे। 62वें मिनट में गोवा का एक और हमला हुए लेकिन ओडिशा गोलकीपर ने कोरो और डोंगेल के प्रयास को नाकाम कर दिया। 67वें मिनट में कोरो को गिराने के कारण ओडिश के खिलाड़ी गौरव बोरा को पीला कार्ड मिला। 74वें मिनट में गोवा के इदु बेदिया को पीला कार्ड मिला।

कोरो और बेदिया के पास 74वें मिनट में गोवा के लिए दूसरा गोल करने का शानदार मौका था। उन्हें बस कीपर को छकाना था लेकिन वे चूक गए। जवाब में सांटाना ने ओडिशा के लिए 77वें मिनट में एक बड़ा हमला किया। सांटाना को नारायण दास ने लेफ्ट फ्लैंक से अच्छा क्रास दिया था। सांटाना को बस गोलकीपर को फ्री हेडर से छकाना था लेकिन वह भी नाकाम रहे।

नडाल ने जीता विश्व चैंपियनशिप का खिताब

अबूधाबी, आइएएनएस : विश्व के नंबर एक स्पेन के राफेल नडाल ने पहला सेट हारने के बाद अगले दो सेट में वापसी करते हुए ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को हराकर विश्व टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। नडाल ने फाइनल मुकाबले में विश्व नंबर-6 सितसिपास को 6-7, 7-5, 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। 19 बार के ग्रैंड स्लेम विजेता नडाल का यह रिकॉर्ड पांचवां अबूधाबी खिताब है। नडाल ने पिछले महीने एटीपी फाइनल्स में भी सितसिपास को 6-7, 6-4, 7-5 से मात दी थी। नडाल और सितसिपास अब अगले महीने होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लेम ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलेंगे। नडाल का यह साल का अंतिम टूर्नामेंट था। अब नडाल अगले वर्ष जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले साल के पहले ग्रैंडस्लैम में उतरेंगे, जहां उनका सामना कई दिग्गज खिलाड़ियों से होना तय है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद राफेल नडाल। आइएएनएस

विविध

यूनिटेक बिल्डर को ब्याज के साथ लौटाने होंगे 69 लाख

जासं, नई दिल्ली : राज्य उपभोक्ता आयोग ने यूनिटेक बिल्डर और इसके निदेशकों को आदेश दिया है कि उपभोक्ता को उसके 68 लाख 90 हजार 210 रुपये 10 फीसद वार्षिक ब्याज के साथ वापस किए जाएं। साथ ही 25 हजार रुपये बतौर केस भी अदा किए जाएं। हरियाणा के करनाल निवासी विकास लुथरा ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग में साकेत से संचालित होने वाले यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ केस दायर किया था।

विकास ने शिकायत में कहा था कि यूनिटेक नोएडा सेक्टर-117 में बनने वाले प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया था। सितंबर 2012 में हुए अनुबंध के तहत 36 माह में फ्लैट का कब्जा मिलना था। फ्लैट की कुल कीमत में से 68 लाख 90 हजार 210 रुपये किस्तों में 2015 तक अदा करने थे। शिकायत के मुताबिक 2015 में जब हाउसिंग प्रोजेक्ट का मुआयना किया तो वहां काम अधूरा था। बिल्डर से कई बार शिकायत कर फ्लैट की स्थिति के बारे में पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। राज्य उपभोक्ता आयोग में भी बिल्डर फ्लैट में देरी के बारे में कोई सही कारण स्पष्ट नहीं कर पाया।

मां कनक दुर्गा के लाखों ने किए दर्शन

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भवानी दीक्षा समारोह के अंतिम दिन रविवार को हजारों श्रद्धालुओं ने कनक दुर्गा मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए। समारोह में भाग लेने के लिए देशभर से पांच लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। विजयवाड़ा अपने समृद्ध इतिहास के लिए प्रचलित है। इंद्रकीलाद्री पर्वत पर स्थित कनक दुर्गा मंदिर अत्यंत प्राचीन है। श्रद्धालु मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं। जिसे मेतला पूजा (सीढ़ियों का पूजन) कहा जाता है। कहते हैं कि आदि देव शंकराचार्य ने भी मंदिर में मां कनक दुर्गा के दर्शन किए थे। एएनआइ

दिल्ली में एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : दिल्ली में एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को 20 दिसंबर तक काम पूरा कर लेने का लक्ष्य को दिया था।

दिल्ली सरकार के लिए बीईएल एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे लगा रही थी। मगर काम की गति धीमी होने पर अगस्त में दिल्ली सरकार ने कंपनी को 16 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का नोटिस दिया था। जिसके तहत बीईएल को गत 22 नवंबर तक 1 लाख 40 हजार कैमरे लगाने थे।

दिल्ली सरकार ने कहा था कि कंपनी इस तारीख तक लक्ष्य पूरा नहीं करती है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और जुर्माना की राशि 32 करोड़ हो जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते कैमरे लगाने का काम भी एक माह से अधिक समय तक बंद रहा था। इसलिए कंपनी को एक माह ही मोहलत मिल गई थी। बीईएल को पिछले साल नवंबर में इस काम का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से ठेका मिला था।

'सही प्रक्रिया अपनाएं तो धान में अधिक पानी की नहीं जरूरत'

वैभव शर्मा, हिसार

देश में लगातार घटता भू-जल स्तर किसानों के साथ-साथ वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है। धान की फसल को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इस फसल में पानी की अधिक बर्बादी होती है। मगर कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर सही प्रक्रिया से धान उगाया जाए तो कम पानी खर्च होगा।

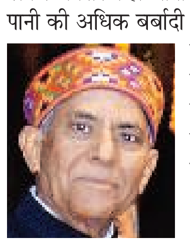

पद्मश्री वैज्ञानिक वीपी सिंह। जागरण

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में प्रिंसिपल वैज्ञानिक रहे पद्मश्री प्रोफेसर वीपी सिंह ने इस बात को साझा किया। वह रविवार को चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पूसा ने जो बासमती की किस्म विकसित की हैं, उन्हें बनाया ही इस प्रकार है कि कम पानी का प्रयोग हो। मगर कई बार अलग-अलग प्रक्रियाओं से किसान इन्हें उगाते हैं, इस कारण पानी अधिक खर्च होता है।

ऐसे बचा सकते हैं पानी

- खेतों में हरी खाद किसान जरूर लगाएं ताकि खेतों में आर्गेनिक मैटर तैयार हो। इस प्रक्रिया के जरिये किसान खेतों की सेहत सुधारने के साथ पानी को रोक सकते हैं।
- धान की रोपाई 15 जून के बाद करेंगे तो पूर्व में लगाया गया पानी ही काम में आ जाएगा। इसके साथ ही पुआल में भी कमी आएगी।
- धान को रेतीली मिट्टी में न उगाकर दोमट मिट्टी में उगाएं।
- धान की रोपाई से 45 दिन पहले चार से पांच सेंटीमीटर पानी रहेगा तो इससे खरपतवार नहीं होगी। इसके बाद खेतों में इतनी नमी रखनी है कि पैर गीला रहे। घुटनों भर पानी की आवश्यकता नहीं है।
- सीधी बिजाई जहां-जहां किसानों ने की है, वहां किसानों को सफलता मिली है।
- धान की जिस वैरायटी का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस की प्रक्रिया को सही से जांच लें।

डा. सिंह ने देश को दी हैं बासमती की पांच किस्में

खास बात है कि प्रो. सिंह को 2012 में भारत सरकार ने बासमती के क्षेत्र में बेहतर किस्मों की खोज के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। प्रो. सिंह ने देश को बासमती की पांच बड़ी किस्में दी हैं। इनमें पूसा प्रथम, पूसा 1401, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 आदि शामिल हैं। ये किस्में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू के तीन जिले, उत्तराखंड के जमीनी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों व दिल्ली के किसान उगाते हैं।

शादी की रात ही लुटेरी दुल्हन पांच लाख के जेवर लेकर भागी

जागरण संवाददाता, रुड़की

- हरिद्वार के एक मंदिर में शादी कर होटल में रुका था परिवार
- रुड़की क्षेत्र के एक गांव में किराये पर रहती है आरोपित महिला

शादी की रात ही लुटेरी दुल्हन पति और उसके परिवार के लोगों को चकमा देकर 50 हजार नकदी और पांच लाख के जेवरात लेकर भाई के साथ फरार हो गई। हरियाणा के पंचकूला निवासी एक युवक का कुछ समय पहले पत्नी से तलाक हुआ था। युवक अपने लिए दूसरी लड़की शादी के लिए तलाश रहा था। युवक की मौसी रुड़की में रहती है। युवक की मौसी की लड़की ने उसे बताया कि आरोपित महिला के पति की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। विधवा का भाई भी बहन के लिए लड़का तलाश रहा है। करीब दो सप्ताह पहले पंचकुला के युवक को उसके रिश्तेदारों ने बरेली के शहजादपुर निवासी महिला से मिलवाया।

18 दिसंबर को हरिद्वार के एक मंदिर में शादी करने की बात तय हुई। उस दिन पंचकूला निवासी युवक अपनी बहन के साथ हरिद्वार पहुंचा। मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई। रात के समय सभी लोग हरिद्वार स्थित एक होटल में कमरा लेकर ठहरे थे। अगले दिन दुल्हन की विदाई होनी थी। लेकिन रात को करीब दो बजे दुल्हन ने पति की तरफ से मिले करीब पांच लाख के जेवरात और ननद के पर्स में रखे 50 हजार रुपये निकाल लिए। माल समेटकर दुल्हन अपने भाई के साथ फरार हो गई। सुबह जब पति को कमरे से दुल्हन गायब मिली तो उसने तलाश किया लेकिन उसका भाई, जेवरात और रकम भी गायब मिली। पता चला कि दुल्हन रुड़की क्षेत्र के एक गांव में किराये पर रहती है। एसएसपी डी सैंथिल अबुदई कृष्ण राज एस का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

10वीं की छात्रा ने बच्चे को दिया जन्म आरोपित धरा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : साकेत इलाके में 10वीं की छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। इससे नाबालिग से दुष्कर्म का पता चला। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद साकेत थाना पुलिस ने नाबालिग के बयान पर केस दर्ज कर 19 वर्षीय ध्रुव पाठक को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित नाबालिग का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा।

15 वर्षीय पीड़िता अपने परिवार के साथ पुष्प विहार में रहती है। वहीं के सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ती है। शुक्रवार रात पीड़िता ने परिजनों से पेट में दर्द की शिकायत की। परिजन उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने बताया कि वह छह माह की गर्भवती है। पुलिस को नाबालिग ने बताया कि आरोपित ध्रुव ने उससे दोस्ती की और बहाने से एक कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। उसने घटना का वीडियो बना लिया। आरोपित वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से बार-बार दुष्कर्म करता रहा।

सात राज्यों का वांछित एटीएम लुटेरा दिल्ली में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आरोपित पर दो राज्यों ने रख रखा है 25-25 हजार का इनाम
- पुलिस को 15 एटीएम लूट मामले में थी आरोपित की तलाश

दिल्ली पुलिस ने लूटपाट के 15 मामलों में सात राज्यों की पुलिस के वांछित कुख्यात एटीएम लुटेरे वकील उर्फ शकील को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के पलवल स्थित हथीन निवासी वकील जमशेद गिरोह का गुर्गा है। इस गिरोह के बदमाश मेवात इलाके के हैं। गिरोह के गुर्गे एटीएम काटकर या फिर उसे उखाड़कर गाड़ी से अपने साथ ले जाते थे और बाद में उससे नकदी निकाल लेते थे।

वकील की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और चार कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपित ने एटीएम लूटपाट के रुपये से करोड़ों की कई प्रॉपर्टी भी दिल्ली-एनसीआर में खरीद रखी है।

स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर लाडो सराय इलाके में एसीपी अतर सिंह की टीम ने 20 दिसंबर को आरोपित वकील को दबोचा। गिरोह के गुर्गे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गिरोह के बदमाश बिना गार्ड वाले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे अथवा स्याही लगाकर लूट को अंजाम देते हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जमशेद गिरोह के बदमाशों ने इस वर्ष सितंबर में मध्य प्रदेश के मुरैना में एटीएम से नकदी लूटी थी। गत वर्ष दिसंबर में भी उन्होंने मथुरा स्थित एटीएम से आठ लाख रुपये उड़ाए थे। गिरोह के सदस्य अपने साथ वाहन में हथियार व पत्थर भी रखते हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य गुर्गों की तलाश में जुट गई है।

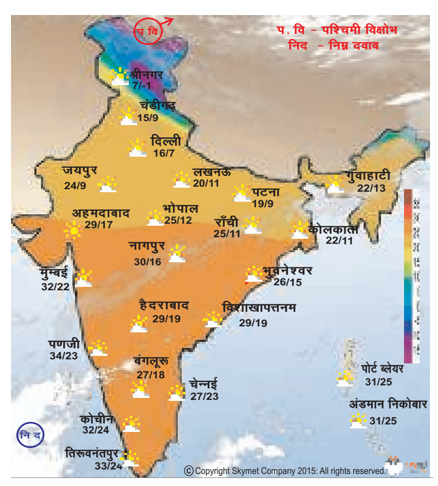

मौसम विशेष

लद्दाख व हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की वर्षा व बर्फबारी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा। रात के तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली सहित मैदानी भागों में तापमान में गिरावट के साथ ठंडी सुबह में मध्यम से घना कोहरा रहेगा। पूर्वी राजस्थान में हल्की वर्षा संभव है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	32/22/व	अहमदाबाद	26/09/आंबा
कोलकाता	23/11/आंबा	बड़ौदा	27/11/आंबा
चेन्नई	31/22/व	नागपुर	30/15/आंबा
हैदराबाद	30/18/आंबा	इन्दौर	23/10/आंबा
बंगलूरू	27/17/आंबा	राँची	19/17/व
त्रिवेन्द्रम	32/25/सा	पटना	24/15/आंबा
गुवाहाटी	19/14/आंबा	जमशेदपुर	26/19/आंबा
गंगटोक	04/-4/आंबा	पुणे	31/21/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
सोमवार 23 दिसंबर 2019
www.jagran.com

दो जीवित लोगों के बीच पहला किडनी प्रत्यारोपण

आज ही के दिन 1954 में बोस्टन के डॉक्टरों ने पहली बार सफल किडनी प्रत्यारोपण किया था। करीब पांच घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉ. जोसेफ मरे ने रोनाल्ड की किडनी को उसके जुड़वां भाई रिचर्ड के शरीर में प्रत्यारोपित किया। डॉ. जोसेफ मरे को 1990 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया।

मंडी डबवाली अग्निकांड ने लील लीं चार सौ जिंदगियां

आज ही के दिन 1995 में हरियाणा के मंडी डबवाली में एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान भीषण आग लग गई। आग में 258 बच्चों सहित कुल 442 लोगों की मौत हुई। वहीं डेढ़ सौ लोग घायल हुए।

किसानों के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह

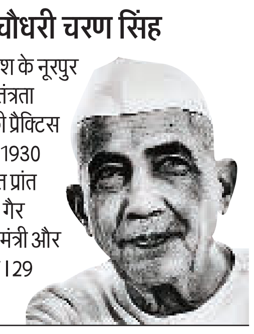

चौधरी चरण सिंह का जन्म आज ही 1902 में उत्तर प्रदेश के नूरपुर में हुआ था। गांधीजी के आदर्शों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। गाजियाबाद में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पहली बार जेल गए। 1937 में संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए छपरौली (बागपत) से चुने गए। यूपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे। 1977 से 1979 तक देश के उप प्रधानमंत्री और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 29 मई 1987 को अंतिम सांस ली।

इधर-उधर की

मां ने सफाई पर छेड़ी ऑनलाइन बहस

लंदन, एजेंसी : घर की सफाई के बारे में इन दिनों फेसबुक पेज माई यूके होम पर श्रीमती हिंच द्वारा डाली गई एक पोस्ट पर ऑनलाइन बहस छिड़ी हुई है। फेसबुक पर एक ग्राफिक्स जारी किया गया है, जिसमें घरेलू कार्यों को पांच भागों में बांटा गया है। इसमें बताया गया है कि प्रतिदिन, सप्ताह में, तीन व छह माह बाद और साल में एक बार अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एक मां बताती है कि प्रतिदिन काफी मेकर और टायलेट की सफाई करनी चाहिए और हर सप्ताह बिस्तर बदलना और पौंछा लगाना चाहिए। सलाह दी गई है कि हर महीने बर्तन धोने वाला जूना और वॉशिंग मशीन भी साफ करनी चाहिए, जहां तक फ्रिज और ओवन का सवाल है उन्हें भी साल में दो से चार बार साफ करना चाहिए। साल में एक बार चिमनी, गटर और खिड़कियों की सफाई भी जरूरी है। हिंच की पोस्ट पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

...तो तरल पदार्थों में ऐसे स्थिर रहता है झाग

न्यूयॉर्क, प्रेट्र: पेय पदार्थों में बनने वाला झाग इस बात का निर्धारण करता है कि उसकी गुणवत्ता कैसी होगी। जिस पेय में जितना ज्यादा झाग लंबे समय तक बना रहता है, माना जाता है कि उसकी ब्रिकी उतनी ही ज्यादा होती है, लेकिन यह झाग पेय पदार्थों में स्थिर कैसे रहता है? अब तक यह एक पहेली थी, जिसे अमेरिकी शोधकर्ताओं ने सुलझाने का दावा किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन से वाशिंग मशीन में डिटर्जेंट (सर्फ) के झाग को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, जहां अपेक्षित झाग नहीं बन पाता है।

अमेरिका की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिचर्ड कैंपबेल सहित कई वैज्ञानिकों के एक समूह ने सर्फेक्टंट नामक यौगिक वाले एक मिश्रण का अध्ययन किया, जो तरल पदार्थों का पृष्ठीय तनाव कम करता है। अध्ययन में यौगिकों को समझने के लिए एक नए तरीके का जिक्र किया गया है। यह अध्ययन केमिकल कम्युनिकेशन नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ और यह तरल पदार्थ बनाने वालों के लिए उसमें बेहतर झाग बनाने में मदद कर सकता है।

- अमेरिका की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने लगाया पता
- सर्फेक्टंट नामक यौगिक वाले एक मिश्रण पर न्यूट्रॉन की किरणें डालकर किया अध्ययन

यह अध्ययन जर्नल केमिकल कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

ऐसे किया अध्ययन : शोधकर्ताओं ने अध्ययन के तौर पर झाग बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए तरल पदार्थों पर न्यूट्रॉन की किरणें डालीं। शोधकर्ताओं में एक कैंपबेल ने कहा, 'जब हम प्रकाश को किसी चमकदार वस्तु से प्रतिबिंबित होते देखते हैं, हमारा दिमाग उसे उसकी मौजूदगी से पहचानने में मदद करता है। ठीक उसी तरह जब तरल पदार्थ से न्यूट्रॉन प्रतिबिंबित होता है, तो हम कंप्यूटर की मदद से उसकी सतह के बारे में अहम जानकारियां पता लगा सकते हैं। इसमें अंतर यह है कि यह जानकारी सिर्फ आण्विक स्तर पर होती है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं।'

उत्पादों की बढ़ेगी ब्रिकी : कैंपबेल ने कहा कि अभी तक शोधकर्ता तरल पदार्थों की सतह की सामान्य खूबियों के बारे में सोच रहे थे, न कि इस पहलू पर कि जब बुलबुले की सतह पर अलग-अलग अणु एकत्रित होते हैं, तो इसका ढांचा कैसे बनता है। शोधकर्ताओं मे कहा कि इस अध्ययन के फलस्वरूप भविष्य में बीयर पीने वाले हमेशा अपनी बोतल की पेंदी में बुलबुले यानी झाग का लुत्फ उठा सकेंगे। उनका कहना है कि इस अध्ययन से वाशिंग मशीन में डिटर्जेंट (सर्फ) के झाग को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, जहां अपेक्षित झाग नहीं बन पाता है। कैंपबेल का कहना है कि यह अध्ययन कई उत्पादों की बिक्री बढ़ा सकता है।

नए तरीके की खोज की

शोधकर्ताओं के मुताबिक, जब सिर्फ एक योजक के साथ तरल पदार्थों से बने झागों की प्रकृति के बारे में समझने की कोशिश की जाती है, तो अधिक योजक युक्त तरल पदार्थ (जो असल उत्पाद में इस्तेमाल होते हैं) की जानकारी भ्रामक बनी रहती है। उन्होंने इन मिश्रणों में झागों या बुलबुले बनने की प्रक्रिया का अध्ययन किया, जिन्हें उनके तरल पदार्थ के नमूने से न्यूट्रॉन को प्रतिबिंबित करके फोम फिल्म के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का प्रयोग करके एक नए तरीके की खोज की, जिसके जरिये फोम फिल्मों की स्थिरता को उसी तरीके से बरकरार रखी जा सकती है, जिस तरह योजक बुलबुले की सतह पर खुद को व्यवस्थित रखता है। उन्होंने अध्ययन किया कि आखिर इस प्रक्रिया ने बुलबुले को फूटने से बचने के लिए कैसे स्थिरता दी। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन की मदद से उत्पादक अपने उत्पाद को और बेहतर तरीके से उपभोक्ताओं को लिए पेश कर पाएंगे।

खराबी के कारण धरती पर लौटा बोइंग का अंतरिक्ष यान

वाशिंगटन, एएफपी : अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) के लिए उड़ान भरने वाला अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग का अंतरिक्ष यान अपना मिशन पूरा किए बगैर वापस धरती पर लौट आया। बोइंग स्टारलाइनर के इस यान को तकनीकी खराबी की वजह से वापस पृथ्वी की ओर मोड़ना पड़ा। मानवरहित इस अंतरिक्ष यान को बीते शुक्रवार को अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत स्थित केप केनवेरेल प्रक्षेपण केंद्र से एटलस रॉकेट की मदद से लांच किया गया था।

बोइंग कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि एक घड़ी में आई खामी के कारण यान की लांचिंग में ईंधन की खपत ज्यादा हो गई। इससे अंतरिक्ष यान का धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आइएसएस) तक पहुंचना संभव नहीं था। अंतरिक्ष यान ने मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाके व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में लैंडिंग की। इस यान में डमी भेजा गया था। माना जा रहा था कि क्रू के साथ यान को अंतरिक्ष में भेजे जाने की दिशा में यह अंतिम परीक्षण है।

शोध अनुसंधान

शरीर में वसा की अधिकता बनती है डायबिटीज का कारण

वैज्ञानिकों ने टाइप-2 डायबिटीज के कारण को समझने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हालिया शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि लिवर से पैंक्रियाज (अग्नाशय) की ओर वसा के बहाव से डायबिटीज विकसित होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि शरीर में आमतौर पर वसा त्वचा के नीचे स्टोर होती है। हालांकि हर व्यक्ति की त्वचा में वसा को स्टोर करने की क्षमता अलग-अलग होती है। जब वसा की मात्रा त्वचा के नीचे स्टोर रहने की सीमा से ज्यादा होने लगती है, तो लिवर के अंदर वसा स्टोर होना शुरू हो जाता है। लिवर उस वसा को पैंक्रियाज समेत शरीर के अन्य हिस्सों की ओर भेजने लगता है। यह अतिरिक्त वसा पैंक्रियाज में जमकर इंसुलिन के निर्माण में भूमिका निभाने वाले जीन के काम को बाधित कर देती है। यही खामी टाइप-2 डायबिटीज के विकसित होने का कारण बनती है। - आइएएनएस

ज्यादा अल्कोहल से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं दिल के टिश्यू

अल्कोहल के ज्यादा सेवन से दिल के ऊतक (टिश्यू) क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हालिया शोध के दौरान खून में मिले कुछ बायोमार्कर के स्तर से यह पता चला है। शोधकर्ताओं ने कहा, 'खून में कुछ मॉलीक्यूल के स्तर से यह सामने आया है कि ज्यादा अल्कोहल पीने वालों के दिल के टिश्यू काफी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।' अध्ययन के लिए 35 से 69 साल की उम्र के 2,525 लोगों के खून के नमूने जांचे गए थे। इनमें अल्कोहल के सेवन के अलग-अलग स्तर के हिसाब से नमूनों का विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं, उनके खून में दिल की कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने का संकेत देने वाले विभिन्न बायोमार्कर का स्तर ज्यादा होता है। अल्कोहल नहीं पीने वालों में इन बायोमार्कर का स्तर अपेक्षाकृत बहुत कम रहता है। - आइएएनएस

धीमी हो गई है वनों के पनपने की रफ्तार

चिंताजनक ▸ अमेजन के जंगलों पर अध्ययन, तेजी से बढ़ सकता है पृथ्वी का तापमान

शोधकर्ताओं का अनुमान जलवायु परिवर्तन के स्तर में हो सकती है और वृद्धि

लंदन, प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति आगाह करने वाले एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि वनों की कटाई के बाद अमेजन के जंगलों का पुनर्वसन यानी उन्हें दोबारा पनपने में पुराने अनुमानों के मुकाबले कहीं ज्यादा समय लगेगा। जर्नल इकोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने दो दशकों तक अमेजन के जंगलों के पुनर्वसन की निगरानी की और यह पता लगाया है कि बढ़ता जलवायु परिवर्तन और बड़े स्तर पर जंगलों के कटान से अमेजन को भारी नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा।

ब्रिटेन की लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अमेजन के जंगल सर्वाधित प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि बीते दशकों में पेड़ों की कटाई के बाद उनके दोबारा पनपने की दर काफी धीमी हो गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि जंगलों के पनपने की दर में वृद्धि नहीं होगी तो इसका असर हमारे वातावरण में भी पड़ेगा क्योंकि अमेजन के जंगल वायुमंडल से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ग्लोबल वॉर्मिंग को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।

ब्रिटेन के शोधकर्ताओं का यह अध्ययन जर्नल इकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

घट गई है कार्बन सोखने की क्षमता : इससे पहले एक दूसरे अध्ययन में बताया गया था कि पूरी तरह कटाई के बाद दोबारा उगने वाले वन मानव-निर्मित जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वे वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन को सोखने की क्षमता रखते हैं। इन वनों को आमतौर पर द्वितीयक वन भी कहा जाता है। हालांकि, वर्तमान अध्ययन से पता चला है कि अन्य वनों की तुलना में द्वितीयक वन केवल 40 फीसद कार्बन को सोखने की क्षमता रहते हैं।

घट रहा है जंगलों का रकबा : शोधकर्ताओं के अनुसार, यदि यही स्थिति रही तो इन जंगलों को सौ फीसद कार्बन सोखने के लिए एक सदी से भी अधिक समय लग सकता है, जिसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने की उनकी क्षमता को बहुत हद तक कम हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूखे की स्थिति में द्वितीयक वनों के कार्बन सोखने की क्षमता और कम हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण अमेजन में सूखा साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है और वनों का रकबा भी कम होता जा रहा है, जो कि चिंता की बात है।

अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर काम करने की जरूरत : ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पारा के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक फर्नांडो इलायस ने कहा, 'हमने अमेजन के जिस क्षेत्र का अध्ययन किया है, उसमें प्रति दशक 0.1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि देखी गई है और सूखे के दौरान पेड़ों की वृद्धि भी कम थी। कई अध्ययनों में भविष्य में और अधिक सूखे की स्थिति बनने के आसार हैं, इसलिए हमें द्वितीयक वनों की क्षमता के बारे में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर काम करने की जरूरत है।

गोवा के मुकाबले ज्यादा प्रदूषित हैं महाराष्ट्र के बीच

पणजी, प्रेट्र : एक नए अध्ययन के मुताबिक, गोवा और कर्नाटक के मुकाबले महाराष्ट्र के बीच (समुद्री किनारे) प्लास्टिक प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित हैं। सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म प्लास्टिक के कणों ने इसकी खूबसूरती बिगाड़ कर रख दी है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने समुद्री किनारों के पास स्थित प्लास्टिक उद्योग और पर्यटकों द्वारा लाई जाने वाली प्लास्टिक को जिम्मेदार ठहराया है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसियनोग्राफी (एनआइओ) द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि हाई टाइड (ज्वार) के दौरान गोवा और कर्नाटक के मुकाबले महाराष्ट्र के बीचों पर सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण देखने को मिला है। यहां सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म प्लास्टिक प्रचुर मात्रा में मिलना इस बात का संकेत देता है कि ये प्लास्टिक के कण पास के प्लास्टिक व पेट्रोलियम उद्योग, बंदरगाह और पर्यटन की बढ़ती गतिविधियों के कारण फैल रहे हैं।

'असेस्मेंट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो प्लास्टिक्स अलॉग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया' नामक शीर्षक वाला यह अध्ययन बीते सप्ताह नीदरलैंड्स के जर्नल केमोस्फियर में प्रकाशित हुआ है।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने बीते

▸ **सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म प्लास्टिक ने बिगाड़ी समुद्री किनारों की सुंदरता**

दो साल में देश के पश्चिमी घाट के 10 बीचों की पड़ताल की और यह समझने का प्रयास किया कि इस क्षेत्र में सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म प्लास्टिक के कारण समुद्री जीवों का कितना नुकसान पहुंचा है।

एनआइओ के वैज्ञानिक डॉ. महुआ साहा और डॉ. दुशमंत महाराणा के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में कहा गया है कि इन सभी बीचों पर शोधकर्ताओं को कई रंगों का (सफेद, पीला, भूरा, नीला, लाल) विषाक्त प्लास्टिक का कचरा मिला, जिसने समुद्री किनारों की सुंदरता भी बिगाड़ कर रख दी है।

शोधकर्ताओं ने कहा, 'प्लास्टिक के कचरे से सबसे ज्यादा समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है। यदि उन्हें बचाकर जैव-विविधता बनाए रखनी है तो इस कचरे के निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। इसमें सरकार की नीतियां सबसे ज्यादा असरदार हो सकती हैं। प्लास्टिक को फेंकने की बजाय इसकी रिसाइकिंल और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने से फायदा हो सकता है।

सांता चढ़े पर्वत

पर्वतारोहियों की सुरक्षित चढ़ाई की कामना और क्रिसमस की बधाई देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के बुखान पर्वत पर सांता क्लॉज की वेशभूषा में चढ़े पर्वतारोही। बुखान पर्वत पर एकदम खड़ी चढ़ाई है। इसकी चोटी पर पहुंचना और उतरना पर्वतारोहियों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है। यहां प्रतिवर्ष चढ़ाई के दौरान कई पर्वतारोही अपनी जान भी गवां देते हैं। एएफपी

शाही परिवार की चार पीढ़ियां

लंदन के बकिंघम पैलेस के म्यूजिक रूम में द रॉयल ब्रिटिश लीजनस के शुभारंभ अवसर पर मेहमानों के लिए क्रिसमस पुडिंग तैयार करने के लिए शाही परिवार की चार पीढ़ियां एक साथ नजर आईं। प्रिंस जॉर्ज (बाएं से दूसरे) ने पुडिंग तैयार की और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, दादा प्रिंस चार्ल्स (दाएं) और पिता प्रिंस विलियम (बाएं) ने इस काम में हाथ बंटाया। इसी के साथ क्रिसमस पर्व की शुरुआत भी हो गई है। पुडिंग एक तरह का हलवा है, जिसे क्रिसमस पर पारंपरिक रूप से खाने के साथ परोसा जाता है। एपी

स्क्रीन शॉट

अवार्ड की खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता : अमित रवींद्रनाथ शर्मा

सात सवाल

निर्देशक अमित रवींद्रनाथ शर्मा की फिल्म 'बधाई हो' को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार आज वितरित किए जाएंगे। अमित फिल्म 'मैदान' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो फुटबाल कोच सय्यद अब्दुल रहीम पर आधारित है। अमित से बातचीत :

'बधाई हो' को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी?

- उस समय मैं सुरेखा सीकरी जी को 'बधाई हो' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की बधाई दे रहा था। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि फिल्म को भी पुरस्कार मिला है। जब मुझे बताया गया कि 'बधाई हो' को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवॉर्ड भी मिला है, तो सुनने के बाद मेरी सांस चढ़ गई थी। बहरहाल, उस खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता।

नेशनल अवॉर्ड पाकर जिम्मेदारी का एहसास होता है?

- मैं कभी दबाव में नहीं आता। न चाहता हूं कि दबाव में रहूं। मुझे जो कहानी अच्छी लगेगी, वही मैं बनाऊंगा। नेशनल अवॉर्ड मिलेगा, यह सोचकर फिल्म नहीं बनाऊंगा। फिलहाल, मैं 'मैदान' की शूटिंग कर रहा हूं। उसकी पचास प्रतिशत शूटिंग पूरी हो गई है।

आपकी पहली फिल्म 'तेवर' सफल नहीं रही थी। ऐसे में दूसरी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से जीवन कैसे बदल जाता है।

- राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे लिए सबसे बड़ा अवॉर्ड है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि राष्ट्रीय पुरस्कार के करीब पहुंच पाऊंगा। दूसरी ही फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना बड़ी बात है।

आज राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए कुछ खास तरह की ड्रेस भी पहनेंगे?

- मैं बहुत ही साधारण इन्सान हूं। मेरा बस चले तो टी-शर्ट और जीन्स पहनकर ही समारोह में चला जाऊं, लेकिन फॉर्मल पहनकर जाना है।

कंटेंट के साथ फिल्म में संदेश देना कितना जरूरी मानते हैं?

- अगर कहानी के अंदर कोई संदेश हैं, तो उसे देना अच्छी बात है। कई कहानियां ऐसी भी बनती हैं, जिनमें कोई मैसेज नहीं होता है, लेकिन वे आपको जिंदगी का कोई पहलू दिखाकर जाती है। संदेश होना अच्छी बात है, क्योंकि लोग जागरूक होंगे तो अच्छी बात है। अगर हम लोगों के सोचने का तरीका थोड़ा भी बदल पाएं तो यह करना चाहिए।

फिल्म 'मैदान' की शुरुआत कैसे हुई?

- यह आइडिया मुझे निर्माता बोनी कपूर सर ने दिया। उन्होंने कहा कि हम सय्यद अब्दुल रहीम पर हम फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसका निर्देशन करें। मैंने उनके बारे में काफी पढ़ा। उस दौर के कई खिलाड़ी जीवित हैं। वे 80-85 साल के हैं। उनसे कई सारी जानकारियां मिलीं।

फुटबॉल की आपको कितनी जानकारी थी? अजय देवगन भी पहली बार स्पोर्ट्स ड्रामा कर रहे हैं... ?

- बहुत कम जानकारी थी, लेकिन अब फुटबॉल की इतनी जानकारी हो गई है कि मैं फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी और रोनाल्डो से इस खेल पर वर्ष 1952 से 1962 के बीच की सारी बातें कर सकता हूं। जहां तक अजय देवगन सर की बात है, वे इस किरदार को महसूस कर रहे हैं। यानी वह अपने किरदार में दो सौ प्रतिशत योगदान दे रहे हैं।

स्मिता श्रीवास्तव

अब मैं एमसी शेर नहीं, बंटी हूं : सिद्धांत चतुर्वेदी

अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी यशराज फिल्म्स की 'बंटी और बबली 2' में दिखाई देंगे। वह करण जौहर की एक और फिल्म में भी काम कर रहे हैं। शकुन बत्रा की इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे हैं। हाल ही में करण जौहर ने ट्विटर पर इस रिलेशनशिप ड्रामा की जानकारी दी थी। सिद्धांत कहते हैं कि इन दोनों ही फिल्मों में उनका एकदम अगल लुक सामने आएगा। 'बंटी और बबली 2' फिल्म का निर्देशन वरुण शर्मा कर रहे हैं। सिद्धांत ने जोया अख्तर की हिट फिल्म 'गली ब्वॉय' में एमसी शेर का किरदार निभाया था। सिद्धांत कहते हैं, 'अब मैं एमसी शेर के किरदार को अलविदा कह चुका हूं और आपको मुझे बंटी नाम से बुलाना चाहिए। 'बंटी और बबली 2' और शकुन बत्रा की फिल्म, दोनों में मेरे अलग किरदार हैं।' इन दोनों फिल्मों में मेल लीड का किरदार निभाने पर भी सिद्धांत किसी तरह का दवाब महसूस नहीं कर रहे हैं। वह कहते हैं, 'एमसी शेर का किरदार मेरे व्यक्तित्व के करीब नहीं था। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में स्विटजरलैंड में गानों पर परफॉर्म और रोमांस करना चाहता था, जो अब पूरा होगा।'

...इसलिए श्रीदेवी पर साड़ी में फिल्माया गया था 'मिस्टर इंडिया' का गाना

1986 में रिलीज 'जांबाज' के गाने 'हर किसी को नहीं मिलता...' को फिल्म निर्देशक फिरोज खान ने श्रीदेवी पर साड़ी में फिल्माया था। इस गाने को शूट करने के बाद फिरोज खान ने दावा किया था कि साड़ी में किसी अभिनेत्री को उनसे बेहतर कोई दूसरा फिल्मकार नहीं दिखा सकता। फिरोज खान की इस चुनौती को निर्देशक शेखर कपूर ने अपनी अगली ही फिल्म 'मिस्टर इंडिया' के गाने 'काटे नहीं कटते दिन ये रात...' में स्वीकार किया। उस गाने में श्रीदेवी ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी। 1987 में रिलीज इस फिल्म में साड़ी में श्रीदेवी का सबसे खूबसूरत रूप देखने को मिला। यह बात करण जौहर ने रविवार को मुंबई में श्रीदेवी के जीवन पर आधारित किताब 'श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन गॉडेस' के विमोचन पर बताई। इस किताब के लेखक सत्यार्थ ने बताया कि जावेद अख्तर ने उन्हें बताया था कि श्रीदेवी से पहले अभिनेत्रियां कॉमेडी करने से कतराती थीं।

अध्ययन

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने किया दावा, त्वचा को नहीं पहुंचेगा नुकसान मिलेगी सटीक रिपोर्ट

अब लेजर से भी हो सकेगा अल्ट्रासाउंड

बोस्टन, प्रेट्र: शोधकर्ताओं ने पारंपरिक अल्ट्रासाउंड के विकल्प के तौर पर आंख और त्वचा को महफूज रखने वाला एक लेजर सिस्टम विकसित किया है। यह एक ऐसी प्रणाली है, जो मरीजों के भीतरी हिस्सों की साफ तस्वीर ले सकती हैं और इसमें जोखिम भी कम है।

अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) के वैज्ञानिकों ने कहा कि पारंपरिक अल्ट्रासाउंड में यंत्रों को मरीज के शरीर से संपर्क करने की जरूरत होती है। इससे इसके प्रयोग की एक सीमा होती है, क्योंकि छोटे बच्चे, संवेदनशील त्वचा या जले शरीर वाले मरीज अच्छी तरह जांच नहीं करा पाते हैं। शोधकर्ताओं ने लाइट साइंस एंड एप्लिकेशन जर्नल में प्रकाशित मौजूदा अध्ययन में इंसानों के लिए एक लेजर अल्ट्रासाउंड छवि का जिक्र किया है। उन्होंने कई वॉलंटियर की कलाई को स्कैन किया और त्वचा के लगभग छह सेंटीमीटर नीचे तक की मांसपेशियों, वसा और हड्डियों की ऊतकों में समान विशेषताएं देखीं।

करीब आधे मीटर की दूरी से लेजर का इस्तेमाल करके वॉलंटियर की इन छवियों को लिया गया और ये सभी पारंपरिक अल्ट्रासाउंड जैसी ही थीं।

- ऊतकों की विशेषता का पता लगाने के लिए नया तरीका किया ईजाद
- शरीर को यंत्रों से छूने की भी नहीं पड़ेगी जरूरत

अध्ययन करने वाले एमआइटी के एक वरिष्ठ शोधकर्ता ब्रायन डब्ल्यू एंथोनी ने बताया कि लेजर अल्ट्रासाउंड से सफलता हासिल करने के प्रारंभिक चरण में हैं। उन्होंने कहा, 'जरा कल्पना कीजिए कितना अच्छा हो जब हम केवल एक प्रकाश के बिंदु के जरिये शरीर के विभिन्न अंगों का अल्ट्रासाउंड कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया में त्वचा को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ऊतकों की विशेषता का पता लगाने का यह एक नया तरीका होगा। इसमें हमें मरीज के शरीर से किसी यंत्र को संपर्क कराने की जरूरत भी पड़ेगी।'

ऐसे किया अध्ययन : शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान एक विशेष तरंग दैर्ध्य में लेजर के जरिये प्रकाश त्वचा में भेजा, जो रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित होता है। लेजर की वजह से गर्म होने के कारण रक्त वाहिकाएं तेजी से फैलती हैं और शांत होती हैं, फिर अपने मूल आकार में आ जाती हैं। ऐसा तब तक होता है, जब तक कि लेजर का दूसरा तरंग दैर्ध्य उसमें प्रवेश न करे। इसकी वजह से यांत्रिक कंपन ध्वनि तरंगों को पैदा करते हैं, जो वापस ऊपर की ओर आते हैं, जहां त्वचा में लगा सिग्नल पकड़ने वाला यंत्र उसका पता लगा लेता है और उसे एक छवि के रूप में बदल देता है। हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तकनीक के लिए अभी भी ध्वनि तरंगों का पता लगाने के लिए डिटेक्टर को शरीर से सीधे संपर्क कराने की जरूरत पड़ती है।